

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली

लेखक

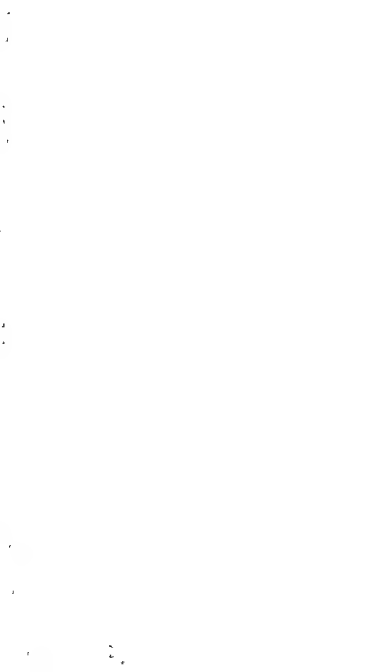
हरनारायण सिंह

एम० ए०, एम० एड०

वसुधन्त राजपूत कलियुग धाफ एडुकेशन, आगरा

विनोद पुस्तक मन्दिर

मिण्टल रोड, आगरा



स्वर्गीय संजय

का

जिह्वाकी स्मृति ही अथ

घोष है ।

स्वर्गीय संजय

वा

जिम्हारी स्मृति ही अय
रोष है ।



पुस्तक प्रकाशन में तत्परता एवं सौजन्यता का परिचय देने वाले श्री० भोलानाथ जी अग्रवाल अध्यक्ष विनोद पुस्तक मन्दिर तथा अन्य प्रकाशन संस्था के अधिकारियों का भी लेखक आभारी है, जिन्होंने अविलम्ब प्रकाशित करके अध्यापकों का उपकार तथा लेखक का उत्साह-बर्द्धन किया है ।

हरनारायण सिंह



प्राक्कथन

'तुलनात्मक शिक्षा' के अध्यापन में मैंने यह अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा में उपयोगी पुस्तकों के अभाव का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर अंग्रेजी में अनेक अत्यन्त अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, परन्तु हिन्दी में नहीं हैं। विद्यार्थियों को इसलिए इस विषय सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी अपनी परीक्षा में हिन्दी माध्यम रखते हैं। उनकी इस कठिनाई का ध्यान रखते हुए व समस्या का हल निकालने के लिए ही मैंने यह प्रयास किया है।

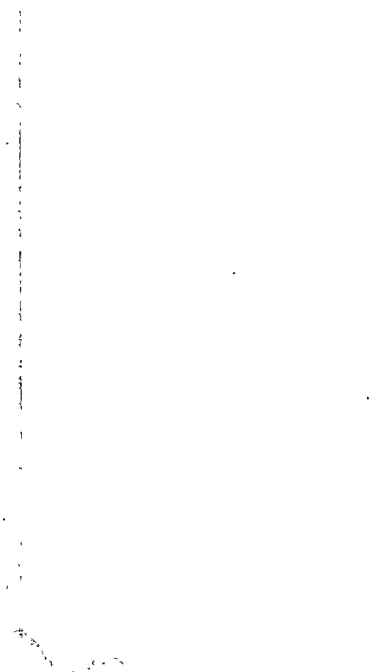
हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि 'तुलनात्मक शिक्षा' का अध्ययन एक बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। भारत में अभी स्वतन्त्रता प्राप्त की है और उसे अपने पुर्ननिर्माण के लिए अपनी समस्त संस्थाओं को समग्रानुसूल परिवर्तित करना है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थाओं के संगठन में उसे उन देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा जिन्होंने वर्षों के अनुभव के पश्चात् अपनी संस्थाओं को सौम्य और शिक्षा संगठन की ओर बनाया है। इङ्गलैंड एक ऐसा देश है जिसको हम उदाहरण के रूप में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन हमारे लिए इस कारण आवश्यक नहीं है कि हम उसकी नकल करें, परन्तु इसलिए आवश्यक है कि हम उससे से उन भिन्नान्तों व व्यवहारों को अपनावें जो हमें अपनी शिक्षा के पुर्ननिर्माण में सहायता दे सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के सिलने में मैंने इस विषय पर प्रायः सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अध्ययन किया है और यत्र-तत्र उनसे उद्धरण भी लिए हैं। पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के हेतु वाक्य-वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है और इङ्गलैंड की शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। आशा है विद्यार्थी-गण पुस्तक से लाभान्वित होंगे। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँगा जो इस पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मुझे कुछ सुझाव देंगे।

बलवंत राजगुरु कालेज
आफ एजुकेशन, आगरा
२१ मई १९६३

}

हरनारायण सिंह



विषय-सूची

अध्याय १

तुलनात्मक-शिक्षा, उसका महत्त्व. अध्ययन विधियाँ	१-११
तुलनात्मक-शिक्षा की अध्ययन विधियाँ ७।	

अध्याय २

इंग्लैण्ड की शिक्षा के आधारभूत मूल सिद्धान्त तथा शिक्षा-प्रणाली की विशेषताएँ	१२-२४
--	-------

अध्याय ३

बिडेन का शिक्षा इतिहास	२५-६७
पहला युग (प्रारम्भिक युग) २५, प्राथमिक शिक्षा ३०, दूसरा युग (१६ वीं शताब्दी) क्रमिक और चर्ने विकास युग ३०, शिक्षा समिति का काम ३७, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा ५१, शिक्षा की आर्थिक पृष्ठभूमि तथा प्रसारण ६२।	

अध्याय ४

इंग्लैण्ड का शिक्षा-संगठन	६८-७६
स्पानीय शिक्षा अधिकारी ७२, शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था ७५।	

अध्याय ५

प्रारम्भिक-शिक्षा	७७-८६
प्राथमिक शिक्षा ८८, प्राथमिक स्कूल का संगठन ८६,	

अध्याय ६

माध्यमिक-शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का मंजित इतिहास ११, तीन प्र
के माध्यमिक-स्कूल १७, डिप्लोमा की माध्यमिक शि
में विभागीय प्रणाली (प्राइमरी शिक्षा) ११२,
स्कूलों की शिक्षा-विधि की उत्तमता ११७, क्या
प्रबन्ध तथा आर्थिक-गृह्यणः देने के आधार
स्कूलों का विभाजन (प्राइमरी तथा माध्यमिक) ११८

अध्याय ७

घण्टी-शिक्षा

औद्योगिक तथा व्यापारिक-शिक्षा १३३, कृषि सम्
शिक्षा १३५, प्रौढ़ शिक्षा १३५, मूल मर्याद १
मनोरञ्जक तथा सामाजिक सुविधाएँ १३६।

अध्याय ८

विश्वविद्यालय शिक्षा

अध्याय ९

औद्योगिक-शिक्षा

अध्याय १०

अध्यापक-प्रशिक्षण

अध्याय ११

विशिष्ट सेवाएँ

अध्याय १२

१९४४ का शिक्षा-एक्ट

परिशिष्ट—१

१९४६ का शिक्षा एक्ट

परिशिष्ट—२

सन् १९४८ का शिक्षा-एक्ट

परिशिष्ट—३

परिशिष्ट—४

ब्रिटेन शिक्षा में कुछ उपयोगी होने वाले शब्दों का अर्थ	१७८-१८०
--	---------

परिशिष्ट—५

एल० टी० परीक्षा प्रश्न-पत्र १९५४	१८१-१८३
एल० टी० परीक्षा १९५५-१८२	
एल० टी० परीक्षा १९५६-१८२	
Bibliography	१८४-१८५



अध्याय १

तुलनात्मक-शिक्षा, उसका महत्व, अध्ययन विधियाँ

रिश्ते कुछ समय में तुलनात्मक-शिक्षा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। शिक्षकों और सामकों के मतानुसार विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन अपने देश की शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा-समस्याओं को भली भाँति समझने, और उनको सुलझाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षा-प्रबन्धकों तथा भावी अध्यापकों को दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणालियों तथा उनके गुणों और अवगुणों का ज्ञान होना आवश्यक है।

तुलनात्मक-शिक्षा में हमें किसी देश की केवल शिक्षा-प्रणाली, शिक्षा-संगठन, शिक्षा-व्यय तथा पाठ्य क्रम का ही अध्ययन नहीं करना है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक-अध्ययन द्वारा हम उन सभी समस्याओं और वागुणों का विश्लेषण करने हैं जिनके कारण किसी देश विशेष की शिक्षा-प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास हुआ है। इन प्रकार के अध्ययन में उन अन्तरो का भी विश्लेषण और तुलना की जाती है जो विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालियों में पाये जाते हैं। अन्त में इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम विभिन्न देशों की शिक्षा-समस्याओं का हल भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में तुलनात्मक-विधि में सबसे पहले उन अस्पृश्य (Impalpable) साध्यात्मिक, (Spiritual), और सांस्कृतिक शक्तियों (Cultural forces) को समझने का प्रयास करते हैं

जिन पर किसी देश विशेष की शिक्षा-प्रणाली आधारित है। इस प्रकार के अध्ययन में हमें सदैव उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमियों से अवगत होना चाहिए, जिन्होंने किसी देश-विशेष की शिक्षा-प्रणाली को निमित्त किया है। शिक्षालय तथा समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है और समाज में होने वाले परिवर्तन शिक्षालयों को सदैव प्रभावित करते रहे हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय परम्पराओं का भी शिक्षा-निर्माण में महान रूप में महत्व है।

किसी देश के मनुष्यों के जीवन का दर्शन ही वहाँ के शिक्षा-उद्देश्यों, शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा व्यवहार को निर्धारित करता है। उनके इस शिक्षा-दर्शन के आधार पर शिक्षा-उद्देश्य, पाठ्य-वस्तु तथा शिक्षण-विधि निर्भर रहती है। किसी राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली वह जीवित वस्तु है जो राष्ट्रीय आदर्शों, मूल्यों एवं धर्मों और संघर्षों तथा राष्ट्र की समस्याओं और कठिनाइयों की स्मृति दिलाती है। इसमें राष्ट्रीय इतिहास, परम्परा तथा राष्ट्रीय जीवन की क्रिया अन्तर्निहित रहती है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली उस देश के राष्ट्रीय-चरित्र तथा राष्ट्रीय जीवन की झोकी है तथा राष्ट्रीय-चरित्र में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने और उसे पूर्ण करने का एक माध्यम है।

वास्तव में यह हास्यास्पद बात होगी कि किसी एक देश की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देश द्वारा पूर्णरूप में अनुकरण की जाय। हर एक देश की निजी शिक्षा-प्रणाली होती है, किन्हीं दो देशों की शिक्षा-प्रणाली बिल्कुल एक प्रकार की नहीं हो सकती, यद्यपि शिक्षा-समस्याओं में कुछ समानता अवश्य हो सकती है। इसका मूल कारण है कि प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठ भूमियाँ जिसमें किसी देश की शिक्षा-प्रणाली शनैः शनैः पनपती तथा विकसित होती है भिन्न-भिन्न होती हैं। परन्तु किसी एक शिक्षा-प्रणाली का दूसरे देश में पूर्णरूप से अनुकरण या प्रतियोग्य नहीं किया जा सकता नहीं तो प्रतियोग्य की हुई शिक्षा-प्रणाली की दशा उस मुग्धभाये हुए घोड़े के समान होगी जो उपयुक्त भूमि और अजबानु पालन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संसार के शिक्षा-अभिलाष में एक देश में दूसरे देश में समस्त शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा-व्यवस्था के मूल्य स्थानान्तरण या प्रतियोग्य के उदाहरण कुछ ही मिलने हैं। अतः पर यह स्थानान्तरण सफल भी हुआ, उसका मुख्य कारण केवल दोनों देशों की समान सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थीं। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी शिक्षा-विधियाँ होती हैं जो हमें लाभदायक अनुमति देती हैं, जिन पर विचार करते, देश की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है।

प्रत्येक राष्ट्र अपने जीवन-दर्शन तथा आदर्शों के अनुसार ही शिक्षा-प्रणाली का निर्माण करता है। कुछ शैक्षिक विचारों के मफल निर्यात के लिए प्रत्येक देश में श्रेष्ठ अवश्य हो सकता है। इसका बहुत शिष्टाप्रद उदाहरण भारत और पाकिस्तान का है। भारतीय शिक्षा का इतिहास सुविख्यात है। ब्रिटेन ने अपने भारतीय साम्राज्य में अँग्रेजी पद्धति, अँग्रेजी विचार और अँग्रेजी भाषा तक स्थानान्तरित की। अँग्रेजी के निर्वहन में बड़ी सख्या में स्कूल और विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये। अँग्रेजी बोलने वाले एक नये अखिल भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की सृष्टि हुई किन्तु शिक्षा-पद्धति का स्थानान्तरण सफल हुआ या नहीं इसका उत्तर देने में अँग्रेज और भारतीय दोनों सकोच करते हैं। एक दृष्टिकोण से यह सफल हुआ क्योंकि इसने भिन्न धार्मिक परम्पराओं और भिन्न भाषा-भाषी अनेक भारतीय जातियों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया और अतः भारत सार्वभौम प्रभुता सम्पन्न देश हुआ, दूसरी ओर संगठन की नीति भारतीय साम्राज्य के भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में विभाजन को न गोक सकी, तथा भारत में बौद्धिक नेताओं ने तो अँग्रेजी उदार-नीति और राजनैतिक लोकतन्त्रवाद की विधियों को अपना लिया, परन्तु भारतीय कृषक समूह अपठ और अँग्रेजी प्रभाव से अछूता बना रहा। जब से स्वाधीनता आई भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ने दोनों से अँग्रेजी गुलामी के चिह्नों को त्यागकर अपने जातीय आधार पर संस्कृति का पुनर्निर्माण करना आरम्भ किया। पाकिस्तान ने कुरान शरीफ की ओर प्रत्यावर्तित होना और इस्लामी धर्म की नुतियाद पर भविष्य-निर्माण करने का निश्चय किया। भारत ने वैज्ञानिक शिक्षा की भारतीय पद्धति को अपनाने का निश्चय किया जिसमें वास्तव में भारतीय तत्वों की अपेक्षा विदेशी तत्व कम नहीं हैं। दोनों प्रयत्न अभी विचाराधीन हैं अतः उन पर अन्तिम निर्णय देना सम्भव नहीं है।

तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। किसी देश के प्रचलित शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा-व्यवहार का अध्ययन, उस शिक्षा-प्रणाली की दूसरे देशों की प्रणाली से तुलना और यह ज्ञात करना कि विभिन्न शिक्षा-प्रणालियाँ कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमियों से प्रभावित होती हैं, ये सभी तुलनात्मक-शिक्षा में सम्मिलित हैं। इसके अधिक शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का और भी महत्त्व है। हम विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना द्वारा ऐसे तुलनात्मक सिद्धान्त, प्रक्रियाएँ और शिक्षा-प्रवृत्तियाँ ज्ञात कर सकते हैं जिन पर किसी देश का शिक्षा दर्शन आधारित हो सकता है और एक देश के अनुभव का लाभ दूसरे देशों को हो सकता है। दूसरे देशों द्वारा शिक्षा-क्षेत्र में जो नूतनताएँ भूतकाल में की गईं, उनसे हम अपने

देश को बना सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार विश्व की बहुत सी शिक्षा-समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

शिक्षा में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पुनर्निर्माण की बहुत सी शक्तियाँ निहित हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की शिक्षा समस्याओं जटिल होनी चाहती है, परन्तु उनमें कुछ समानता तब भी रहती ही है। प्रत्येक देश की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन आश्रय के अर्थ में तथा अशांति वातावरण में लाभदायक सिद्ध होगा। यदि हम भ्रान्तनुमतिपूर्ण दृष्टिकोण से दूसरे देशों की मर्यादा, इतिहास तथा शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करें और उन विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करें तो हमारे हृदय में दूसरों की मर्यादा और आदर्शों के प्रति धन्य तथा सह-भावना अकसम ही उत्पन्न होगी। साथ ही हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा-परम्परा, संस्कृति और आदर्शों को अपनी भाँति समझ सकेंगे। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही तुलनात्मक शिक्षा का बहुत महत्व है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली एक दर्पण है जिसमें उस देश के मूल्य राष्ट्रिय चरित्र का परावर्तन होता है और इस दर्पण में हम उस देश की बहुत सी शिक्षा-समस्याओं का प्रतिबिम्ब पा सकते हैं। वर्तमान युग में तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सह-भावना उत्पन्न करने का एक प्रमुख साधन है तथा आश्रय सत्कार के सिद्धि, विपात और शीघ्र युद्ध वातावरण में राष्ट्रीय सार्वभौमिक शिक्षा समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सह-भावना तथा सहयोग द्वारा हल करके उनकी एकता के सूत्र में बाँधा जा सकता है।

शिक्षा एक सामाजिक शक्ति तथा सामाजिक प्रक्रिया (Process) है तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक देश में शैक्षिक विचारों के आदान-प्रदान का पर्याप्त क्षेत्र है, परन्तु पूर्णरूपेण अनुकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक देश की शिक्षा समस्याओं की तुलना द्वारा ऐसे आधारभूत सिद्धान्त प्राप्त किये जा सकते हैं जो सार्वभौमिक उपयोग के हो सकते हैं और संसार के विभिन्न देश अपनी शिक्षा-प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जब हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय तथा तुलनात्मक-शिक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते। सम्पूर्ण संसार में मानव-परिवार एक ही है और उस परिवार के कल्याण के साधन शिक्षा के आधार-भूत मूल सिद्धान्तों की अपेक्षा करना उपयुक्त नहीं है। तुलनात्मक शिक्षा आश्रय के संसार के अशांति वातावरण में शान्ति के अप्रदूत वा वायुमंडल को संचालित कर सकती है और विभिन्न देशों की शिक्षा में निहित प्रेम का सदेश विश्व के कोने-कोने में फैलाया जा सकता

१। राष्ट्रों में पारस्परिक व्यवबोधन, सहभावना और शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना तुलनात्मक-शिक्षा द्वारा की जा सकती है।

तुलनात्मक-शिक्षा द्वारा अनेक लाभ हैं—

(१) अनेक देशों की शिक्षा-मस्यौदाओं के विस्तरेषण द्वारा हम उन देशों की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमियाँ समझ लेते हैं। साथ ही हमें राष्ट्रों के आदर्शों का ज्ञान होता है। इनसे उन राष्ट्रों के प्रति हम में सहभावना का विकास होता है तथा हमारी विस्तरेषण-शक्ति भी विकसित होती है।

(२) अपने देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण, सुधार तथा उसे मजबूत बनाने लिए हम दूसरे देशों के अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रकार अपनी शिक्षा-प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

(३) शिक्षा दृष्टिकोण की विज्ञातता और व्यापकता के उत्पन्न करने में तुलनात्मक अध्ययन का अधिक महत्त्व है। पारस्परिक सहयोग तथा सहभावना का विकास होता है। शिक्षा का तुलनात्मक-अध्ययन प्रयत्नशील तथा सक्रिय दृष्टिकोण और प्रगतिशीलता की भावना को नष्ट करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्व प्रथम यह कार्य लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations) ने किया। अब भी प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन (International Bureau of Education) जिसेवा प्रतिवर्ष प्रत्येक देश के शिक्षा-सम्बन्धी आकांक्षी का प्रतिवर्ष प्रकाशन करता है परन्तु यह कार्य अधिक संतोषजनक नहीं रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान सांस्कृतिक मन्था ने अब हम कार्य को पूरा करने का उत्साहवर्धित किया है।

सन्तार में द्वितीय युद्ध के बाद तुलनात्मक-शिक्षा का महत्त्व प्रत्येक राष्ट्र समझने लगा है। भिन्न-भिन्न देशों ने शैक्षिक-विनिमय कार्यक्रम स्थापित किये हैं जिनके द्वारा कुछ शिक्षक दूसरे देशों में जाकर वहाँ की शिक्षा-प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने शिक्षक विनिमय योजना के क्षेत्र में गहराईपूर्ण कार्य किया है। उसी देश की फोर्ड तथा गैर-फोर्ड सरथाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता से प्रतिवर्ष विभिन्न देशों से अत्याधिक तथा विद्यार्थी वहाँ की शिक्षा-प्रणाली देखने तथा अध्ययन करने जाते हैं।

तुलनात्मक शिक्षा-क्षेत्र में १९ वीं शताब्दी में ही कुछ शिक्षा-विधि में निपुण लोगों ने प्रगतिशील कार्य किया है। सर्व प्रथम मनु १८१७ ई० में मार्क एण्डोइन कुतियन डी पेरिस ने दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की विवृत योजना के विषय में विचार किया। उनका उद्देश्य सभी

देशों की शिक्षा प्रणाली के विषय में विभिन्नराष्ट्रमक अध्ययन करना था। इन प्रकार के अध्ययन द्वारा परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन किये जा सकने थे। उनकी यह योजना बहुत समय तक जान नहीं हुई। केवल बीसवीं सताब्दी में फिर से यह प्रकाश में आई। तुलनात्मक शिक्षा अपने प्राग्भ्य काल में दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों के वर्णन तक ही सीमित रही।

उन्नीसवीं सताब्दी में दूसरे देशों के विद्वानों तथा शिक्षा-विद्वानों के विषय में वर्णन की अधिष्ठा रही। न्यूयार्क शहर के प्रोफेसर जॉन प्रिंसजीम ने शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन के लिए ब्रिटेन, फ्रान्स, स्विट्जरलैण्ड तथा इटली का भ्रमण किया। इन देशों की शिक्षा-प्रणाली को कार्यरूप में देखा। इस अध्ययन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने मई १८९८ ई० में 'योरुप में एक वर्ष' नामक पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय पश्चात् इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। इसने फ्रान्स, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। अमेरिका के शिक्षा-विद्वान ह्यूरिसमन ने ६ मास तक योरुपीय देशों का भ्रमण किया और इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी तथा हार्नैण्ड की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना, शिक्षा-प्रबन्ध, तथा शिक्षण-विधियों की दृष्टि से की।

इंग्लैण्ड में तुलनात्मक-शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्ग-दर्शन में प्रोफेसर मोर्रिस ने किया। उन्होंने फ्रान्स तथा जर्मनी के शिक्षालयों को वहाँ जाकर कार्य-रूप में देखा। इसी देश के सरमाइकल सैंडलर ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये। अमेरिका के शिक्षा-विधि में निपुण हैनरी बर्नार्ड का नाम भी इस क्षेत्र में समान रूप में उल्लेखनीय है।

दार्शनिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा-अध्ययन करने के प्रथम प्रयास का श्रेय किसी दार्शनिक तथा शिक्षक सरगियस हैसिन को है। उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा-नीति की समस्याओं का अपने अध्ययन के लिए चयन किया। प्रतिवार्य शिक्षा, शिक्षालय तथा राज्य, शिक्षालय तथा चर्च तथा शिक्षालय और धार्मिक जीवन ही इन चार समस्याओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। हैसिन ने शिक्षा के मूल मिष्ठान्तों का विश्लेषण किया और बहुत से देशों की आधुनिक कानूनी व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन इन चारों समस्याओं के विषय में किया। हैसिन ने राष्ट्रीय प्रणालियों को ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमियों से सम्बद्ध करने का प्रयास नहीं किया।

बीमवी धानाब्दी में प्रो० आई० एल० कैंडल ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया उसे शिक्षा-संसार कभी भी नहीं भुला सकता है। तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत करने और इसकी स्थायिता प्राप्त कराने का ध्येय उन्हीं को है। उनके विचार से किसी देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण में प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का बहुत महत्व है। प्रो० कैंडल के मतानुसार बहुत से देशों में शिक्षा-ममस्याएँ और उद्देश्यों में कुछ समानता मिलती है परन्तु इन समस्याओं का हल देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार में होता है। प्रत्येक देश अपनी परम्परा तथा संस्कृति से प्रभावित होकर इन समस्याओं को मुलभूतकर हल ज्ञात करता है। किसी राष्ट्र के प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सब शिक्षा-विकास में मौलिक वस्तुएँ हैं। यह सब अन्तर होने लगे भी वर्तमान युग में कुछ शिक्षा-समस्याओं में सार्वभौमिक समानता है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल तथा समाधान हो सकता है। बहुत देशों से निरक्षरता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर आदि ऐसी समस्याएँ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धिवादी तथा उन्नत देशों के सहयोग से हल की जा सकती हैं। सभी राष्ट्र अपनी शिक्षा की उन्नति द्वारा समाज की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं और मानवता के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

तुलनात्मक-शिक्षा की अध्ययन-विधियाँ

उसीसवीं धानाब्दी में ही शिक्षा-विधि में निपुण व्यक्तियों ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के भिन्न-भिन्न माधन अपनाए हैं। आरम्भ में केवल बाल्यनात्मक तथा सांख्यिकीय-पद्धति का आश्रय लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा का आरम्भ बाल्यनात्मक पद्धति से हुआ और अधिकतर बाल्य इस काम में भ्रम्य देशीय शिक्षा, शिक्षानायक तथा शिक्षा-विधियों के विषय में प्राप्त होने हैं। फोर्केनर और फिलकोव, विक्टर कजिन, हॉरेसमन, मैथ्यू चारनोव्स्की पुस्तकों में विभिन्न देशों के शिक्षानायक का बाल्य तथा उनकी समस्या आदि का उल्लेख मिलता है। इन लेखों में दूसरे देशों की उस समय की शिक्षा-प्रणाली के विषय में पर्याप्त सूचना दी गई थी परन्तु इस प्रकार के बाल्य में आत्मोपमा (Subjectivity) का आशय हमें मिलता है।

सांख्यिकीय विधि में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लिए बिंदु दिये गये गण्युक्त शिक्षा के व्यय, स्तुम-अवनों के बनवाने का मूल्य, उनकी आय तथा आयुनि, विद्याभियोग

देशों की शिक्षा प्रणाली के विषय में विद्वान्गणों का अध्ययन करना था। इन प्रकार के अध्ययन द्वारा परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन किये जा सकने में। उनकी यह योजना बहुत समय तक जात नहीं हुई। केवल बीसवीं शताब्दी में फिर से यह प्रयत्न में आई। तुलनात्मक शिक्षा अपने प्रारम्भ काल में दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों के वर्णन तक ही सीमित रही।

उन्नीसवीं शताब्दी में दूसरे देशों के विद्वानों तथा शिक्षा-विधियों के विषय में वर्णन की अधिकता रही। न्यूयार्क शहर के प्रोफेसर जीन फ्रिस्कीम ने शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन के लिए ब्रिट-ब्रिटेन, हार्लैण्ड, फ्रान्स, स्विट्जरलैंड तथा इटली का भ्रमण किया। इन देशों की शिक्षा-प्रणाली को कार्यरूप में देखा। इस अध्ययन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने मई १८१८ ई० में 'योरुप में एक वर्ष' नामक पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय पश्चात् इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। इसने फ्रान्स, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। अमेरिका के शिक्षा-विद्वान् ह्यूरिसमन ने ६ मान तक योरोपीय देशों का भ्रमण किया और इंग्लैण्ड, स्काटलैंड, आयरलैंड, फ्रान्स, जर्मनी तथा हार्लैण्ड की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना, शिक्षा-प्रवन्ध, तथा शिक्षण-विधियों की दृष्टि से की।

इंग्लैण्ड में तुलनात्मक-शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्ग-दर्शन मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया। उन्होंने फ्रान्स तथा जर्मनी के शिक्षालयों को वहाँ जाकर कार्य-रूप में देखा। इसी देश के सरमाइकल सैंडलर ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये। अमेरिका के शिक्षा-विधि में निपुण हैनरी बर्नाड का नाम भी इस क्षेत्र में समान रूप से उल्लेखनीय है।

दार्शनिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा-अध्ययन करने के प्रथम प्रयास का श्रेय रूसी दार्शनिक तथा शिक्षक सरगियस हैसिन को है। उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा-नीति की समस्याओं का अपने अध्ययन के लिए चयन किया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, शिक्षालय तथा राज्य, शिक्षालय तथा चर्च तथा शिक्षालय और धार्मिक जीवन ही इन चार समस्याओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। हैसिन ने शिक्षा के मूल निदान्तों का विश्लेषण किया और बहुत से देशों की आधुनिक कानूनी व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन इन चारों समस्याओं के विषय में किया। हैसिन ने राष्ट्रीय प्रणालियों की ऐतिहासिक वृद्धि-भूमियों से सम्बन्ध करने का प्रयास नहीं किया।

बीसवीं शताब्दी में प्रो० आई० एल० कैडल ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया उसे शिक्षा-संसार कभी भी नहीं भुला सकता है। तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत करने और इतनी व्याप्ति प्राप्त कराने का श्रेय उन्हीं को है। उनके विचार से किसी देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण में प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का बहुत महत्व है। प्रो० कैडल के मतानुसार बहुत से देशों में शिक्षा-समस्याएँ और उद्देश्यों में कुछ समानता मिलती है परन्तु इन समस्याओं का हल देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। प्रत्येक देश अपनी परम्परा तथा संस्कृति से प्रभावित होकर इन समस्याओं को मुलभूतकर हल ज्ञात करता है। किसी राष्ट्र के प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सब शिक्षा-विकास में मौलिक वस्तुएँ हैं। यह सब अन्तर होते हुये भी वर्तमान युग में कुछ शिक्षा-समस्याओं में सार्वभौमिक समानता है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल तथा समाधान हो सकता है। बहुत देशों से निरभरता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर आदि ऐसी समस्याएँ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धशाली तथा उन्नत देशों के सहयोग से हल की जा सकती है। सभी राष्ट्र अपनी शिक्षा की उन्नति द्वारा संसार की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं और मानवता के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

तुलनात्मक-शिक्षा की अध्ययन-विधियाँ

उन्नीसवीं शताब्दी से ही शिक्षा-विधि में निपुण व्यक्तियों ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के भिन्न-भिन्न साधन अपनाये हैं। आरम्भ में केवल वर्णनात्मक तथा सांख्यिकीय-वृद्धि का आश्रय लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा का आरम्भ वर्णनात्मक वृद्धि से हुआ और अधिकतर वर्णन इस काल में अन्य राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षालयों तथा शिक्षा-विधियों के विषय में प्राप्त होते हैं। फोर्केनर जीन प्रिंसकोप, बिस्टर कजिन, हीरेसमन, मॅप्पु आरमोन्ड की पुस्तकों में विभिन्न देशों के शिक्षालय का वर्णन तथा उनकी संख्या आदि का उल्लेख मिलता है। इन लेखों में दूसरे देशों की उस समय की शिक्षा-प्रणाली के विषय में पर्याप्त सूचना दी गई थी परन्तु इस प्रकार के वर्णन में आत्मोपलब्धि (Subjectivity) का आभास हमें मिलता है।

सांख्यिकीय विधि में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लिए किये हुये सम्पूर्ण शिक्षा के व्यय, स्कूल-भवनों के बनवाने का भूतल, उनकी नाप तथा आवृत्ति, विद्यालयों

की संस्था, उनकी औसत उपस्थिति, विभिन्न स्तरों पर उनकी सफलता तथा अशिक्षितों की मरुता आदि के विषय में सांख्यिकीय-सूचना दी गई है। यह विधि उपयोगी अवश्य है परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि संस्थाओं में एक रूपता (Uniformity) हो तथा संस्थाएँ ऐसी हो जिससे एक देश की शिक्षा-संस्थाओं की तुलना दूसरे से सुविधापूर्वक की जा सके।

पूर्णवृत्तान्त सम्बन्धी अध्ययन विधि (Case-study method) का अनुसरण भी दूसरे विषयों तथा मनोविज्ञान के समान तुलनात्मक-शिक्षा-क्षेत्र में किया गया है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा के विषयों में घूरा-घूरा वृत्तान्त इसलिए ज्ञात किया जाता है, जिससे शिक्षा की आधुनिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस विधि को समस्या-विधि (Problem method) भी कहा गया है क्योंकि इस विधि में शिक्षा-समस्याओं के सुलझाने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

विश्लेषणात्मक पद्धति—का अनुसरण मुख्यरूप से माइकल सीडलर, पील मुनरो तथा आई० एस० ब्रैन्डल ने किया है। इन शिक्षा-शास्त्रियों के मत में उन ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय कारणों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है जिनके फलस्वरूप किसी देश की विशिष्ट शिक्षा-प्रणाली उत्पन्न तथा विकसित होती है। इन कारणों के विश्लेषण बिना शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन अधूरा है। किसी शिक्षा प्रणाली पर विचार करने समय वहाँ के प्राचीन इतिहास, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परम्पराओं को भी नहीं भुलाया जा सकता है। दो शिक्षा-प्रणालियों पर यदि ज्ञान बार्नी विभिन्नताओं तथा समानताओं का विश्लेषण भी शिक्षा का सत्य रोचक विषय है।

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान काम में विश्लेषणात्मक विधि उपयोगितावादी विधि का प्राधान्य है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली की प्रगति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारणों के विश्लेषण करने के बाद उस शिक्षा-प्रणाली के गुण और खराब गुण ज्ञान किए जाते हैं। शिक्षा-प्रणाली की अच्छाइयों तथा उमें कसौटी बनाने वाली वस्तुओं का उपयोग निर्वाह प्रणाली के सुधारन में सहायक सिद्ध हो सकता है। वही शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण तथा अक्षम है, उनसे दोष निवारण का गुण तथा प्रतिदान प्राप्त जा सकता है। दूसरे देशों के अनुभवों द्वारा सामाजिक-नैतिक शिक्षा संबंधी दुर्घटनाओं का सुधार जा सकता है। यह अध्ययन विधि इस बात का ध्यान करती है कि विभिन्न देश एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। इस सम्बन्धी विचारों का स्वतन्त्र रूप से एक दूसरे देश में आदान-प्रदान

हो, सभी देश एक दूसरे से सीखें और अपने ज्ञान-भंडार को बढ़ाएँ, अन्न में मानव-जाति के कल्याण के लिए उत्तम शिक्षा-प्रणालियों तथा शिक्षा-विधियों का अनुसंधान करे। इस विधि में राष्ट्रीय प्रेम, सहयोग भातृत्व, तथा सद्-भावना की प्रधानता होनी चाहिए नभी शिक्षा द्वारा उनका कल्याण हो सकता है।

हम बीसवीं शताब्दी में तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की विभिन्न विधियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता पाने हैं।

१—प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-समस्याओं का उनकी राष्ट्रीय पृष्ठ-भूमि के प्रसंगानुसार परीक्षण।

२—राष्ट्रीय पृष्ठ-भूमि में पाए जाने वाले ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों की एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाली क्रिया देखना और शिक्षा-प्रणालियों के विकास में उनका योग।

३—शिक्षा के मौलिक एवं आधारभूत सिद्धान्तों को निर्धारित तथा सीमा-रहित करना अर्थात् अन्तर्निहित मूल सिद्धान्तों को निर्धारित करना।

४—शिक्षा-प्रणालियों की समानताओं और विभिन्नताओं की तुलना करना।

५—विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों की शक्तियाँ और दुबलताओं को ज्ञान करना तथा शिक्षा-समस्याओं का हल ज्ञान करना।

६—ऐसे मौलिक आधारभूत सिद्धान्तों को ज्ञान करना जो सार्वजनिक तथा सार्वभौमिक उपयोग के हैं और जो अपने देश के लिए लाभदायक सिद्ध हों।

तुलनात्मक-शिक्षा विकास में संसार के तीन मुख्य केंद्रों का अधिक महत्व है जहाँ अब तक इस प्रकार के अध्ययन की प्रवृत्ति देखा गया है - (१) इंग्लैंडमेंशनल एड्युकेशन शूरी, जिनेवा (२) इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एड्युकेशनल साइंस यूनिवर्सिटी, (३) टीचर्स कॉलेज कोलम्बिया यूनिवर्सिटी।

संसार के विभिन्न देशों में विद्यार्थी इन तीनों केंद्रों में बाहर शिक्षा के तुलनात्मक क्षेत्र के विषयों का अध्ययन करने रहते हैं। प्रति वर्ष इन केंद्रों में संसार के विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी अध्ययनों तथा शिक्षा-समस्याओं का उत्सव होता है और इन प्रकार तुलनात्मक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार होता रहता है।



वर्तमान युग में तुलनात्मक-शिक्षा-क्षेत्र में विश्लेषणात्मक तथा उपयोगितावाद अध्ययन-विधियों की प्रधानता है। मूलतः देशों की शिक्षा-प्रणालियों के अध्ययन में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था, इसलिए दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन केवल नीरस और अस्थिर पिंजर सदृश बना रहा। अतः अब इस क्षेत्र में कुछ गवेषणात्मक अध्ययन अधिक सफल नहीं हो सके।

सत्य तो यह है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की कोई एक विधि पर्याप्त नहीं है। सफल अध्ययन के लिए हमें सभी उपयुक्त विधियों को अपनाना होगा और उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। वर्णनात्मक, सांख्यिकीय, तथा विश्लेषणात्मक सभी विधियों का सम्मिश्रण करके ही हम सफल अध्ययन कर सकते हैं।

आज कल के युग में ऐसे शिक्षा-दलों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालियों की इन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमियों को समझ सकें और शिक्षा को वास्तव में सार्थक बना सकें तथा उसे जीवन प्रदान करें। प्रत्येक शिक्षा-दिशा में उनकी विचारधारा रचनात्मक तथा गवेषणात्मक हो। तुलनात्मक शिक्षा इस दिशा में अधिक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय हो सकती है और विश्व के राष्ट्रों में सहृदयता तथा भ्रातृता का संदेश पहुँचा सकती है।

अथवा :

शरीर की शिक्षा के आधारभूत मूल सिद्धांत
तथा शिक्षा-प्रणाली की विशेषताएँ

[illegible][illegible]

संगठन और प्रबन्ध की दृष्टि से इंग्लैंड और वेल्स की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणाली से कई प्रकार से भिन्न है।

विशेष रूप में शिक्षा संगठन के क्षेत्र में शक्ति, उत्तर-दायित्व तथा नियंत्रण का विकेंद्रीकरण (Decentralisation) हुआ है। शिक्षा का प्रबन्ध केन्द्र तक ही सीमित नहीं है, स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी^१ को पर्याप्त अधिकार तथा उत्तर-दायित्व दिया गया है। केन्द्र तथा स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारी के मध्य शक्ति, अधिकार, तथा कर्त्तव्यों का उचित रूप से वितरण हुआ है। केन्द्रीय-शिक्षा-मंत्रालय शिक्षा-क्षेत्र में उचित सहयोग परामर्श तथा प्रोत्साहन देता है और मंत्री-पूर्व सन्धे पय-प्रदर्शन का कार्य करता है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने शिक्षा का रूप निर्धारण नहीं करती है और न अब तक इंग्लैंड के शिक्षा-इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जब शिक्षा-मन्त्री ने अकारण ही स्थानीय शिक्षा अधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप किया हो। यद्यपि १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार शिक्षा-मन्त्री को अधिक अधिकार तथा शक्ति प्रदान की गई और केन्द्रीय-शिक्षा-मन्त्री का कर्त्तव्य शिक्षा का नियन्त्रण^२ और निर्देशन^३ तक बढाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा बाहरी क्षेत्रों में यह मन्त्रेय द्रष्ट किया जाने लगा कि केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के इतने विस्तृत अधिकार शिक्षा-क्षेत्र में केन्द्रीकरण कर लाना चाहती न उत्पन्न करें और केन्द्र शिक्षा-प्रगति तथा उन्नति के स्थान पर बाधा न पहुँचाये। परन्तु समय ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा के केन्द्रीकरण और केन्द्र लाना चाहती तथा हस्तक्षेप का भय निमूल तथा निराधार था। इंग्लैंड के केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने सर्वत्र ही राष्ट्र की भलाई के लिये शिक्षा के विभाग में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी मईव से ही शिक्षा-मंत्रालय द्वारा सहयोग तथा सन्धे पय-प्रदर्शन पाने गये हैं। शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी ने शिक्षा-क्षेत्र में सहकारिता की भावना में कार्य किया है और दोनों के सम्बन्ध सहकारिता, सहयोगिता तथा मंत्री-पूर्व पय-प्रदर्शन पर आधारित है।

(१) उत्तर-दायित्व और नियन्त्रण का विकेंद्रीकरण-इंग्लैंड में शिक्षा-क्षेत्र में शक्ति तथा अधिकारों का विकेंद्रीकरण अवश्य हुआ है, परन्तु उम सीमा तक नहीं पहुँचा है जैसा 'संयुक्त राष्ट्र अमेरिका' में है। संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्दिष्ट विकेंद्रीकरण-नीति तथा शिक्षा-क्षेत्र में अत्यन्त स्वतन्त्रता ने किसी सीमा तक शिक्षा-मन्त्र को दियार दिया है। बहुत से व्यक्तियों ने यह समझने के

1. Local Education Authorities. 2. Control
3. Guidance

सोभ के कारण निम्न-स्तर के विश्वविद्यालय खोलकर और जाली तथा निम्न स्तर की सरकारी डिग्रियां प्रदान कर शिक्षा-क्षेत्र में बड़ा अहित किया है। इस देश के कुछ निम्न स्तर के विश्व विद्यालयों को 'डिप्लोमा बनाने के कारखाने' कहना अनुचित न होगा।

इसके विलकुल विपरीत मोडियन संघ (U. S. S. R.) में शिक्षा का पूर्ण रूप से केन्द्रीकरण है क्योंकि पूरे मोडियन संघ में सभी उच्च शिक्षात्मयों का नियन्त्रण वहाँ के उच्च शिक्षा-मन्त्रालय (Ministry of Higher Education) से होता है।

प्रजातांत्रिक देशों में केवल 'फ्रांस' ही ऐसा देश है जिसने राजनैतिक-स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हुये भी शिक्षा-क्षेत्र में 'केन्द्रीकरण' अपना रखा है। फ्रांस की राजधानी 'पेरिस' में स्थिति शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यालय में बँटकर यह सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है कि देश के विद्यालयों में किम ममय क्या विषय तथा पाठ्य-पस्तु पढ़ाई जा रही है।

इंग्लैण्ड में सर्वत्र ही मध्य का स्वस्थिम-मार्ग अपनाया है तथा व्यक्तिगत और प्रजातांत्रिक स्वतन्त्रता की रक्षा की है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक-स्वाधीनता 'अंग्रेजों की सम्पत्ति' है। राज्य की ओर से अनावश्यक हस्तक्षेप वहाँ के निवासियों को रुचिकर नहीं है। इस देश के निवासियों ने केवल राजनीति में ही नहीं बरन् शिक्षा-क्षेत्र में भी 'राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, (Laissez-Faire) इस नीति को धारण किया, है केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य 'राष्ट्रीय माप-दण्ड तथा स्तरों को स्पष्ट करना है। केन्द्र स्थानीय-मर्यादा तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी, तथा स्वेच्छा से किये जाने वाले शिक्षा उन्नति के प्रयास तथा स्वेच्छा-मर्यादों में मंत्रीपूर्ण सहयोग तथा सहकारिता की भावना पाई जाती है। राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करते हुये शिक्षकों को स्वेच्छा से कार्य करने वाली मर्यादों को उनके पूर्ण अधिकार, शिक्षाक्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोत्साहन, तथा स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। ब्रिटिश सरकार के पूरे ढाँचे को देखने में हम में मंत्रीपूर्ण सहयोग का अनुमान ठीक प्रकार लगाया जा सकता है।

(२) इंग्लैण्ड में शिक्षा-विकास तथा उन्नति में प्राचीन समय से अब तक ऐच्छिक रूप या स्वेच्छा से कार्य करने वाली शिक्षा-संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आरम्भ में धार्मिक मर्यादों, परोपकारी तथा उदार लोगों ने देश में शिक्षा की उन्नति के लिये बहुत सराहनीय कार्य किया और नेतृत्व प्रदान किया। आरम्भ में अवस्था में शिक्षा ऐच्छिक मर्यादों द्वारा मुख्य रूप से धार्मिक मर्यादों द्वारा आरम्भ हुई थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि

इंग्लैण्ड की शिक्षा चर्च और 'मोनास्टरीज की मन्तान है'। राज्य ने शिक्षा क्षेत्र में केवल १६ वीं शताब्दी में प्रवेश किया, और धीरे धीरे कार्य किया। बहुत समय तक केवल अनिवार्य तथा कम से कम सुविधायें ही प्रदान कीं। इंग्लैण्ड के चर्च द्वारा बहुत से नर्सरी स्कूल, प्राथमिक और मानसिक में दुर्बल बालकों के लिये स्कूल, प्राइमरी, माध्यमिक, टीचर्स ट्रेनिंग तथा विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। यहाँ हमें इन स्केन्डा में काम करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। किंग स्कूल कैंटरबरी तथा मॉन्टगोमरी स्कूल, योर्क दोनों ही शिक्षालय दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर ही आरम्भ हुये। कैंटरबरी तथा योर्क दोनों ही स्थानों पर ७ वीं शताब्दी में महान् महान् पादरी रहा करते थे। ८ वीं शताब्दी में ऐम्बा-मैक्सम मोनास्टरीज का तथा विद्वता की प्रसिद्ध केन्द्र थी। बाद में चर्च तथा मोनास्टरीज द्वारा ११ वीं शताब्दी में दान द्वारा स्थापित किये हुये ग्रामर स्कूल शिक्षा-क्षेत्र में स्वेच्छा काम करने वाली संस्थाओं के उदाहरण है। ऐच्छिक संस्थाओं के कार्य करने की इस प्रवृत्ति के कारण शिक्षा-क्षेत्र में विभिन्नता के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ सभी ऐच्छिक संस्थाएँ स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का समर्थन करती हैं। यद्यपि बहुत कुछ सीमा तक सम्पूर्ण शिक्षा का सार्वजनिक नियन्त्रण (Public Control), अब भी ऐच्छिक संस्थाएँ शिक्षा के आयोजन प्रबन्ध तथा अर्थ व्यवस्था में ऐच्छिक संस्थाएँ अब तक महत्वपूर्ण कार्य करती रही हैं। इसके साथ ही परम्परागत स्वतन्त्रता जो प्राचीन समय से ही ऐच्छिक संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप से पहले ही स्थापित की थी, अब भी सार्वजनिक शिक्षालयों में उनका समावेश किया जा रहा है।

इंग्लैण्ड की महान शिक्षा-संस्थाएँ ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा स्थापित तथा प्रयत्नों के फल-स्वरूप विकसित हुई हैं। इंग्लैण्ड 'महान् पब्लिक-स्कूलों' की स्थापना तथा उन्नति और विस्तार में ऐच्छिक संस्थाओं ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया।

(३) शिक्षालयों प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता—ब्रिटिश शिक्षालयों के विचार में प्रत्येक शिक्षालय को स्वायत्त शासन का अधिकार होना चाहिये, और वे हमेशा ही इस स्वायत्तता (Autonomy) की रक्षा करने में उत्तम रहते हैं। प्रत्येक शिक्षालय को अपने प्रादुर्भाव के अनुसार सामूहिक तथा सामाजिक-जीवन के संगठन तथा निर्देशन करने का पूर्ण अधिकार रहना है। प्राइमरी स्कूलों की स्वतन्त्रता तथा

स्वायत्तता (Autonomy) की रक्षा, 'बोर्ड आफ मैनेजर्स'^१ (Board of Managers) द्वारा तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्वतन्त्रता की रक्षा गवर्नर्स^२ द्वारा की जाती है।

इन दोनों प्रकार की बोर्डों का कर्त्तव्य विद्यालयों के विभिन्न हितों का ध्यान रखना और उनके दिन प्रतिदिन के जीवन पर सरक्षक के समान दृष्टि रखना है। बोर्ड के सदस्य कोई येतन नहीं पाते हैं, उनकी सेवायें ऐच्छिक होती हैं परन्तु सेवा को विशेष गौरव तथा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। व्यवस्थित स्कूलों (Maintained schools) के विषय में ये बोर्ड स्थानीय अधिकाधी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और अपने अधिक उत्तरदायित्व का भाग प्रधानाध्यापक को सौंप देते हैं। सामान्य रूप से प्रधान अध्यापक को विद्यालय की व्यवस्था का नियोजन तथा निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाविधि, अनुशासन-सम्बन्धी तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन करने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती है। बोर्ड के सदस्य तथा गवर्नर्स प्रधानाध्यापक से आशा करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में नई नई बातों का सूत्रपात करें, और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखने और उनका विश्वास-पात्र बनकर अपने गवर्नात्मक विचारों को क्रियात्मक रूप दे और अपनी दृष्ट्यानुसार शिक्षाविद्यों के हित में ही शिक्षा का प्रवर्धन करें। ठीक इसी प्रकार प्रधानाध्यापक भी शिक्षकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं और यह आशा करते हैं कि शिक्षक भी उत्साहित होकर शिक्षा क्षेत्र में नवीन कार्य आरम्भ करने की शक्ति का विकास स्वयं से करें। कक्षा में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करें और विद्यालय की पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाओं का प्रवर्धन करने में अपने आप कार्य आरम्भ करने की शक्ति का परिचय दें। प्रधानाध्यापक अपने सहायक शिक्षकों को कभी भी तानाशाही विधि से आज्ञा नहीं देते हैं। किसी विषय की शिक्षण विधियाँ या स्कूल के सार्वजनिक-जीवन का प्रवर्धन शिक्षक स्वयं ही करते हैं। विद्यालय में तानाशाही-विधिवाँ कभी भी पसन्द नहीं की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक तामदायक परामर्श अपने महयोगी शिक्षकों को देते हैं और वे उसे सहृदय स्वीकार करते हैं।

सन् १९४४ तक विद्यालय की स्वायत्तता तथा शिक्षक की स्वतन्त्रता प्राइमरी विद्यालयों की अपेक्षा माध्यमिक विद्यालयों में अधिक स्पष्ट रूप से

1. Board of Managers for Primary schools.

2. Board of governors for secondary schools.

देखने मिलती थी। परन्तु शिक्षाणय की स्वायत्तता (Autonomy) तथा शिक्षा की व्यवसायिक स्वतन्त्रता सबसे पूर्ण तथा स्पष्ट रूप में विश्वविद्यालयों में देखने को मिलती है। विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतन्त्र तथा स्व-शासित मर्यादों और पार्लियामेंट के अतिरिक्त किसी बाहरी अधिकारी से नियन्त्रित नहीं होते हैं। पार्लियामेंट भी केवल विश्वविद्यालय की प्रार्थना पर भी कभी-कभी हस्तक्षेप करती है। विश्वविद्यालय या शिक्षण सम्बन्धी नियुक्तियों में राजनैतिक हस्तक्षेप कभी नहीं होना है। विश्वविद्यालय लगभग अपनी आय का ३-भाग सरकारी सांख्यिकीय कोष में पाने हैं परन्तु इनका होने का भी स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त है।

माध्यमिक-स्तर तथा अन्य स्तरों पर भी गवर्नर के शिक्षक पाठ्य-क्रम शिक्षा-विधि पाठ्य पुस्तकों आदि आदेशों द्वारा किसी से नियंत्रित नहीं होते जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक उच्च अधिकारियों की बाह्य आज्ञा से असंशयित नहीं होते हैं। शिक्षक विभिन्न विषयों को अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समझने वाली विधियों से पढ़ाते हैं, और स्वतन्त्रतापूर्वक पाठ्य पुस्तकों को चुनकर करते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। इंग्लैण्ड में प्रत्येक शिक्षालय प्रधानाचार्यक तथा शिक्षक की व्यक्तिगत स्वाधीनता के प्रति परम आदर दिखाई पड़ता है। प्रधानाचार्य स्वतन्त्र रूप से अपने जहाज में कप्तान के स्वरूप होता है। पाठ्य-क्रम तथा समय-सारिणी भी वह अपने सहायक अध्यापकों की सहायता से तैयार करता है। किसी शिक्षालय में पाठ्यक्रम भारत की तरह थोपा नहीं जाना है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न शिक्षण विधियाँ अथवा शिक्षण-नियम देखने मिलते हैं। शिक्षक कोई भी शिक्षण-विधि अपनाने को स्वतन्त्र होता है शिक्षा मन्त्रालय से समय समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव उन्हें मिलते रहते हैं। शिक्षक द्वारा बनाई हुई उपयुक्त योजनाएँ शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा स्वेच्छा-पूर्वक स्वीकार करली जाती हैं। शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा शिक्षा की नवीन विधियों, तथा नवीन विभाग के संगठन तथा मौलिकता को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) हम देश में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्नता है यहाँ के निवासियों को बाहर से थोपी हुई एक रूपता (Imposed uniformity) को सदैव पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि से देखा है। शिक्षालयों में, पाठ्यक्रमों में और शिक्षा विधियों में विभिन्नता मिलती है और हर समय शिक्षा-क्षेत्र में नये नये अनुसन्धान और गवेषणाएँ होती रहती हैं। हम तथा दूसरे सानासानाही देशों के समान शिक्षा के क्षेत्र में राज्य द्वारा थोपी हुई एकरूपता नहीं मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्नता पाये जाने के कई कारण हैं, पर निम्नांकित मुख्य हैं—

(घ) प्रधानाध्यापको, शिक्षको, स्थानीय शिक्षा, प्राधिकारियों तथा ऐच्छिक संस्थाओं को शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग, अनुसंधान तथा गवेषणा करने की पूर्ण स्वतंत्रता या स्वायत्तता तथा शिक्षा-सुधार के लिये कार्य करने के लिए प्रत्येक अवसर पर प्रोत्साहन मिलता है।

(ङ) शिक्षा क्षेत्र में सभी ऐच्छिक संस्थाओं तथा राज्य का सहयोगी भावना से कार्य करना।

(च) विभिन्न धार्मिक तथा ऐच्छिक संस्थाओं ने शिक्षा-सुधार की अपने विशेष विधियाँ अपनाई हैं जो एक, दूसरे से उद्देश्यों की आधारभूत एकता रखते हुये भी बाह्य रूप में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं। ऐच्छिक प्रयत्नों तथा शिक्षा—स्वतंत्रता में घनिष्ट सम्बन्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही ऐच्छिक संस्थाओं को अपनी पूर्ण क्षति उत्साह तथा सामर्थ्य से कार्य करने का अवसर मिलता है। कभी कभी राज्य द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण शिक्षा की प्रगति तथा विकास में बाधा पहुँचाते हैं। इंग्लैण्ड, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका दोनों ही गुप्तार की वो बड़ी शिक्षा प्रयोगशालायें हैं जहाँ प्रति-क्षण शिक्षा, और मनोवैज्ञानिक विषयों पर महत्वपूर्ण गवेषणाएँ होती रहती हैं। दोनों की प्रयोग-विधि में अन्तर अवश्य है, इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है।

इंग्लैण्ड कमिक—उन्नति वाला देश है^१। यहाँ की राजनैतिक संस्थाओं में स्थिरता है। अचानक राजनैतिक उत्थान तथा क्रांतिकारी परिवर्तन (Revolutionary changes) यहाँ के निवासियों का स्वचर नहीं हैं। तीव्र परिवर्तनों में उन्हें धुला है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इस देश के निवासियों का यह दृष्टिकोण शिक्षा सुधार में किसी भीमा तक बाधक हुआ है, और सुधारों की प्रगति धीमी रही है। इस देश में मौलिक तथा नवीन विचारों की मनातनी विचारों पर विजय पाने में समय लगता है। यहाँ सुधार अवश्य होने हैं परन्तु उनकी व्यावहारिकता का ध्यान रक्खा जाना है, और पुराने सुधारों से समन्वय तथा सामञ्जस्य स्थापित करना पड़ना है।

(५) इंग्लैण्ड की शिक्षा-अणुओं का विकास अभिवृद्धि (Accretion) द्वारा हुआ है। रूस तथा चीन आदि देशों के समान क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए हैं। राष्ट्र की यह विशेषता है कि सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार उसने प्राचीन-शिक्षा-अणुओं में आवश्यक परिवर्तनों का समावेश कर

लिया। समयानुसार तथा नवीन परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा-प्रणाली में अनुकूलन (Adaptation) के वहाँ असंख्य उदाहरण मिलते हैं। इस देश के निवासियों का प्राचीन संस्कृति, इतिहास, प्राचीन परम्परा तथा विचारों के प्रति अगाध प्रेम है। राष्ट्र ने मदैव ही इस अमूल्य निधि की रक्षा की है। नये शिक्षा-अनुसंधानों और नई परम्पराओं का आदर तो होता ही है, परन्तु प्राचीन वस्तुओं के प्रति उनको मदैव थप्पा बनी रहती है। प्राचीनता में नवीनता का समावेश करके सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अर्थात् नवीनता की भटक में पकड़ोप में नहीं पड़ते हैं, परन्तु उसे व्यावहारिक-ज्ञान पर प्राचीन परम्परा तथा संस्कृति की कसौटी पर बस कर ही उसे स्वीकार करते हैं। यदि कोई सिद्धान्त व्यावहारिक है और प्राचीन परम्परा में मेल माना है तो उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है।

प्राचीनता तथा नवीनता में सामंजस्य स्थापित करने वाले इस देश में हमारे शिक्षा का विभाग सदैव बने हुआ। वहाँ की समस्याओं ने कभी भी भली-भाँति से अपना सम्बन्ध बिच्छेद नहीं किया, और मदैव ही स्वयं को समझ, नई परिस्थितियों, सामाजिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुसार परिवर्तित तथा अनुकूल बनाया है। यहाँ के निवासी सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक पसन्द करते हैं। यहाँ की शिक्षा-प्रणाली में वर्ग-भेद की भावना अवश्य दृष्टिगोचर होती है परन्तु अब वह धीरे-धीरे बदल रही है।

आज का ब्रिटेन में १९ वीं शताब्दि के बाद तथा पश्चिम-यूरोप और १९४४ के शिक्षा-वर्ष के अनुसार स्थापित मॉडर्न स्कूल (Modern School) पाये जाते हैं। शिक्षा के प्रवेश क्षेत्र में प्राचीन तथा नवीन का सामंजस्य ही इंग्लैण्ड के शिक्षा-इतिहास का मुख्य गुण है। इंग्लैण्ड की समस्याएँ कभी भी प्राचीन वस्तुओं में अपना सम्बन्ध बिच्छेद नहीं करती हैं परन्तु समझावण और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उन प्राचीन वस्तुओं की नई परिस्थितियों के अनुकूल बना दिया जाता है। यह उचित हो कहा गया है कि, "ब्रिटेन-शिक्षा प्रणाली में एक प्रकार की शिक्षा-मर्यादा को बर्बाद करने के विपरीत नया समन्वय करने के विपरीत स्थान नहीं है, परन्तु आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने तथा परिस्थितानुकूल बनाने के लिए बहुत शेष है।"

"The whole English educational system has grown by general adaptation, by 'mending and not by ending'."

(१) अगर आज शिक्षा का आदर्शन और ये आवश्यकता की शिक्षा के विषय में विचार केवल १९ वीं शताब्दी में ही आरम्भ हुए।

(७) इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली में बाल-मनोविज्ञान का बहुत महत्व है और बच्चा ही शिक्षा का केन्द्र है। उनकी अवस्था, बुद्धि और विशेष रुचि का बहुत ध्यान रखा जाता है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट की एक धारा के अनुसार उनकी अवस्था, बुद्धि और रुचि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अधिक ध्यान दिया जाना है। बौद्धिक-भिन्नताओं को ध्यान में रखते दृष्टे ही उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलताओं वाले बच्चों के लिये अलग प्रबन्ध है जिन्हे विशेष स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।

(८) इंग्लैण्ड की शिक्षा में चरित्र-निर्माण और चरित्र-विकास पर अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र-विकास है। देशों के भिन्न-भिन्न जीवन-दर्शनों के अनुसार ही वहाँ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अमेरिका के लोग शिक्षित-मनुष्य की उपयोगिता पर अधिक जोर देते हैं। The English man would often put the question, "What type of man is he?" The American would ask, "What can he do?" The French would ask, "What diploma does he hold?" The German would ask, "What does he know?"¹

(९) इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली प्रशान्तिप्रिय है। प्रशान्ति को जीवन रखने, तथा उन्नति के लिये शिक्षा मुख्य माध्यम है। इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली प्रजातांत्रिक इस दृष्टि में भी है कि उसमें विचार-विमर्श,वाद-विवाद का महत्व-पूर्ण स्थान है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है।

(१०) इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली में धार्मिक-विभिन्नताओं के लिये अधिक स्थान है। धार्मिक-शिक्षा और मर्यादों के प्रति इंग्लैण्ड की यह उदारनीति उल्लेखनीय है। १९४४ एक्ट की धारा २१ की अनुसार "प्रत्येक विद्यालय का कार्य सामूहिक-धार्मिकता के बाद होना है।

(११) शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का पूर्ण विकास है शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास सभी आवश्यक हैं। इस मन के अनुसार पाठ्य-क्रम की शिक्षाओं के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम महत्त्वों शिक्षाओं भी शिक्षाविदों का आवश्यक अंग है। क्रीडा, शारीरिक व्यायाम तथा मनोरंजन शिक्षाओं भी शिक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। ये पाठ्यक्रम के अभिन्न अङ्ग हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण में माध्यम है। सामाजिक दृष्टि में भी इनका बहुत महत्व है,

इनमें भाग लेने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा उनका चरित्र निर्माण होता है।

इस प्रकार की क्रियाएँ नरमगी अवस्था से आरम्भ होकर मनुष्य के जीवनपर्यन्त तक होनी चाहिये। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, उनके विचार एवं भावों में उदारता आती है और छात्र अपने-अपने बानावरण के अनुकूल बनाना सीखता हुआ अपने चरित्र में एक सामान्य अनुकूलना लाता है। इस मतानुसार प्रौढ़ शिक्षा को भी अब अधिक महत्व दिया जाने लगा है तथा यहाँ के विश्वविद्यालयों ने प्रौढ़ों में शिक्षा-प्रसार का कार्य बड़े ही उत्साह से किया है।

कुछ समय से कुछ सीमित विषयों में आवश्यकता से अधिक शास्त्र-विषय शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा है और उनके परिणामस्वरूप परीक्षाओं पर भी अधिक जोर दिया जाने लगा है।

(१२) इस देश में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों का ध्यान रक्खा जाना है। राष्ट्र के सुदृढ़ बनाने, उसके हित और कल्याण का शिक्षा एक आवश्यक साधन है और राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक पुर्ननिर्माण का एक मुख्य अङ्ग तथा साधन है। इंग्लैण्ड ने सदैव से ही शिक्षा के महत्व को सभी भाँति समझा है, यही कारण है कि विद्यार्थी भर्षकर और विषमकारी युद्ध के होने लगे भी १९४४ के एक्ट द्वारा शिक्षा में महान-सुधार की बात सोची। पहले युद्ध (१९१४-१८) के बाद देश में शिक्षा-एक्ट (१९१८) द्वारा शिक्षा-सुधार किया गया। १९४४ एक्ट के ड्वेन-पत्र (White Paper) में यह घोषित किया था, “इस देश के व्यक्तियों की शिक्षा पर ही इस देश का भविष्य और भाग्य निर्भर है।” देश की समृद्धि के मामले में १९४४ का बिल उस समय आया जब कि इंग्लैण्ड के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों पर नार्सी शक्तियों द्वारा हमला की जा रही थी। शिक्षा-सुधार और शिक्षा-निर्माण की इनकी उद्घाट अभियानों के बहुत कम दिनों में सिमती है, कि इनकी विषम और अशांत परिस्थितियों में भी शिक्षा-निर्माण और सुधार की ओर ध्यान रहे।

युद्ध से उद्भूत राष्ट्र ने सदैव अपने को शिक्षा-सुधार का एक सफल बनाने का प्रयत्न किया है। आर्थिक के दीर्घ परिचर्चनकारी युद्ध में यहाँ के निवासी प्रोत्साहित होकर सदैव शिक्षा-सुधारों की ओर अपना ध्यान लगाते रहे हैं।

संसार में कहा जा सकता है कि इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली की सफलता का कारण उसकी अनुकूलता (Adaptability), स्पष्टता, लचीलापन (Flexibility) और पुर्नता है।

इंग्लैण्ड की शिक्षा में कुछ आपुनिक-प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हो गई हैं। द्वितीय युद्ध के समय में ही नगरपालिकाओं की स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। सम्मान भी स्वयं नगरपालिकाओं की स्थापना करने तथा उन्हें अधिक सहायता देनी है। युद्ध के समय ऐसी परिस्थिति आई थी कि ब्रिटेन को निजों को भी राष्ट्र-सेवा के लिये युद्ध में भाग लेना पड़ा था तथा फौजदारियों में कार्य करना पड़ा। वास्तविकता में काम करने वालों की शिक्षा की अनुपस्थिति में वेचन नगरपालिका ही उनके बच्चों की देख-भाल कर सकते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में युद्ध के पश्चात् नगरपालिकाओं में अंतर-विद्यार्थी-संस्थाएँ नए की शिक्षा की इच्छा महसूस हुई तथा जिसमें स्कूल में भोजन का प्रकाश, विद्यार्थी का प्रकाश, पुस्तकें और पोशक के कार्य और सारीश्वर और मानसिक दुर्बलताओं वाले बच्चों के लिये 'विद्यार्थी-संस्था-विद्यालय' आदि सम्पत्ति है।

उपरोक्त शिक्षा-विवेचनाओं के निरीक्षण में हम अंग्रेजों के राष्ट्रीय चरित्र के मुख्य वातावरण होता है जो उनमें पाये जाते हैं। उनके पौरुषाधिक-गुण, सार्वजनिक काम तथा सार्वजनिक, व्यावहारिक सामर्थ्य, धर्मता, परमार्थ न होने की भावना, सत्यता तथा पवित्रता, स्वायत्तता स्वच्छ वादना आदि के सब गुण अंग्रेजों की अमूल्य सम्पत्ति हैं।

उपरोक्त शिक्षा विवेचनाओं को हम और भरी भरी सम्मान सकते हैं अगर अंग्रेजों की समाज के विषय में कुछ आवश्यक जाने जाते हैं। इंग्लैण्ड एक विनिष्क तथा विभिन्नताओं का देश है। उनका प्राचीन इतिहास है, परम्पराएँ हैं, अपनी मान्यताएँ हैं और भविष्य की महत्वाकांक्षाएँ भी हैं और शिक्षा द्वारा इंग्लैण्ड ने जीवन रक्षने का प्रयास किया है।

अंग्रेजी समाज का ऐतिहासिक-परम्पराओं के साथ-साथ स्वतन्त्र रहने का अभ्यास है तथा उन्होंने स्वतन्त्रता की जीवित रूढ़ि के लिये को विद्वत् युद्ध लड़े, साथ ही साथ अनेक विद्वत् मन्त्रियों में भाग लेकर दूसरे देशों के साथ सहानु-भूति प्रदर्शन किया। अपने विचारों में सदैव वे मानवीय रहे। वारेन हेस्टिंग जैसे क्रूर व्यक्ति को यदि जन्म उन्होंने दिया तो एडमंड बर्क जैसे मानवीय सहानुभूति वाले व्यक्ति को भी उन्होंने जन्म दिया। इंग्लैण्ड ने, सदैव ही स्वतन्त्र विचारकों की सारण दी है। उपनिवेशों को स्वतन्त्रता देने में भी हम देश की प्रथम श्रेणी हैं। आज भी उनका ईश्वर में विश्वास है। गिरजाघरों को उदारता पूर्वक दान मिलता है, विचार को योग्य प्रार्थना मिलती है। आज भी लोग राष्ट्रीय युद्धरत हैं और महारानी के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर रहे हैं। विद्वत् में सबसे स्वतन्त्र प्रेम इंग्लैण्ड का ही है। हाइड्रोजन बम की विस्फोटन के स्थान में कोई किसी भी विषय पर।

इंग्लैण्ड एक समृद्ध मित्रित्व तथा हितवश देश है। बुनि तथा उद्योगों में काफी उन्नत है। बड़ा बड़े-बड़े पार्क तथा सुन्दरालय हैं। विज्ञान दिनों में इंग्लैण्ड काफी बढ़ी होकर है।

मरीच में इंग्लैण्ड घनी देश है, व्यवस्था को अत्यन्त प्रेम करता है। यह पारम्पर्य वाली देश है, और कठोरता के साथ उदारता का तथा प्राचीनता के साथ आधुनिकता का सम्बन्ध स्थापित करना मुश्किल मानता है।

अध्याय ३

ब्रिटेन का शिक्षा-इतिहास

इंग्लैंड और वेल्स के शिक्षा-विभाग के इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : (१) पञ्चाशम शताब्दी महान युग से १८वीं शताब्दी के अन्त तक का है (२) दूसरा समय १९वीं शताब्दी का समरुद्ध, शरीर शरीर तथा धीमी शरीर के विभाग का युग है । (३) तीसरा युग बीसवीं शताब्दी का धीमता में विस्तृत विभाग होने वाला युग है ।

पहला युग (प्रारम्भिक युग)

पहले समय का शिक्षा-इतिहास मुख्य रूप से प्राचीन विश्वविद्यालयों^१ तथा अनुदान द्वारा स्थापित शिष्य ग्रामर स्कूलों का वृत्तान्त है । आक्सफोर्ड तथा कैंब्रिज विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रमशः ११९८ ई० और १२०९ ई० में हुई । यूरोप के सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इनकी गणना है ।^२ अपनी प्राचीनता, इतिहास तथा परम्परा के कारण इंग्लैंड के शिक्षा इतिहास में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण योरोप के शिक्षा इतिहास में आक्सफोर्ड और कैंब्रिज का अद्वितीय स्थान है । इस समय शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करने वाली मर्यादों तथा धार्मिक मर्यादों की अधिकता थी ।

1. Ancient universities like Oxford and Cambridge.

2. Endowed grammar schools.

इंग्लैण्ड की शिक्षा के विकास का इतिहास बहुत प्राचीन है और शिक्षा के विकास में परम्परा का बहुत महत्त्व है। राज्य ने प्रागैमिक काल में शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया, इस समय जनता को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ दान करने का भार धार्मिक तथा स्वेच्छा से काम करने वाली परोपकारी स्थाओं तथा उदार लोगों ने अपने ऊपर ले लिया था। ७ वीं शताब्दी में मठारो और चर्च में दो शिक्षानायो को स्थापना हुई जो आज तक विद्यमान हैं। ऐंग्लो-सैक्सन (Anglo-Saxon) मठ (Monasteries) अपने ज्ञान के लिये प्रसिद्ध रही।

८ वीं शताब्दी में वाइकिंग (Viking) आक्रमणों ने बहुत से मठों की नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ सैक्सन (Wessex) जैसे साम्राज्यों का अभ्युत्थान था। जब बादशाह अल्फ्रेड ने वेनपाक के निवासियों के विरुद्ध संघर्ष करके अपने देश को सुरक्षित कर लिया, तत्पश्चात् उसने अपने देश के निवासियों को शिक्षा करने का कार्य आरम्भ किया। उसने स्कूलों की स्थापना की, स्वयं दृष्ट पुस्तकें लिखी और कई स्कूल ऐसे स्थापित किये जो आज तक विद्यमान हैं। उसने अपने एक पुत्र को बिनचेस्टर (उन समय सैक्सन की राजधानी) का जहाँ पर पाँच शताब्दी पहले प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई।

मध्य-युग में विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्र अधिकतर अपनी पहली शिक्षा घास स्कूलों या गिरजाघर से सम्बन्धित स्कूलों में पाने थे। दोनों ही तरह के स्कूलों का विकास चर्च की मरदानगी में हुआ था। इनमें सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे कबल रईम लोगों के बच्चे या तो घरों या वे धर्म के रईमों के मठों में पढ़ते थे। सन् १३८२ ई० में बिनचेस्टर के नगर ने अपने नगर में ऐसे बालिक की स्थापना की जिसका उद्देश्य आसपास के स्थापित गरीब बालिक के लिये शिक्षा को देना था। बिनचेस्टर में स्थापित इस बालिक में ७० निर्यत विद्वानों का प्रवेश करना था जो एक सामुदायिक जीवन जीते करें, संविन प्रभावशाली तथा रईम लोगों के पुत्र भी प्रवेश पाते थे। विश्वविद्यालय से सम्बन्ध, सामुदायिक-जीवन, व्यवस्था छात्रों को प्रदानित देना, निर्धन तथा धनी व्यक्तियों का सम्पर्क आदि इस शिक्षात्मक की विशेषताएँ थीं। बिनचेस्टर की इसी विशेषताओं पर आजकल के पब्लिक स्कूल भी आधारित हैं।

बिनचेस्टर के ६० वर्ष पश्चात् छत्रे हेनरी द्वारा इंग्लैण्ड के सबसे प्रसिद्ध स्कूल (Eton) बालिक की स्थापना हुई। बिनचेस्टर के उदाहरण का अनुकरण करने और भी पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई।

[illegible][illegible]

यद्यपि इत समय बहुत से वैदिक-ग्रन्थ और कुंभ-ग्रन्थ थे । परन्तु अनिशाना को कुछ करने में वैशिष्टी तथा गण्डे वगैरों का अधिक प्रयोग था ।

आधुनिक अमेरी गिफ्टा का विज्ञान हूँ की बातोंकी मे प्राप्ति होना है। हाँ हूँ मे "प्रेमकेयन हूँ की शिक्षा मेपूरी" मे हूँ मे गीन मुक्त चरण बगल है—प्राप्ति, कीर्ति, गल, उपयोगि, उप गल की कीर्ति—

1. Dame schools. 2. Charity schools. 3. Ragged schools. 4. Sunday schools. 5. Shrewsbury, Christ's Hospital, Repton and Rugby Grammar schools. 6. Winc-
Lester. 7. Eton. 8. Canterbury.

जक क्रान्ति ने समकामीन व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न कर दिये थे। यद्यपि धार्मिक शक्तियों का ह्रास नहीं हुआ था फिर भी उनका ज्ञान उपयोगितावादी प्रवृत्तियों के सम्मुख कुछ कम अवश्य हो गया था। किन्तु उन संस्कारों के कथनानुसार न तो उस समय इंग्लैण्ड में शिक्षा न्यायलक्ष्य ही था और न कोई राष्ट्रीय जन-शिक्षा ही। आक्सफोर्ड और कैंब्रिज अंग्रेजी चर्च के बन्दे थे ये दमनिये प्रायः विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के अंग्रेजी उच्च स्नातक विद्वानों जैसे स्काटलैंड तथा हार्लेण्ड में शिक्षा प्राप्त करते थे। विरोधी मतवाल्म्वियों (अंग्रेजी चर्च के विरुद्ध) ने अपनी अकादमी खोली जो आक्सफोर्ड तथा कैंब्रिज दोनों के टनकर की थी तथा जिनमें आधुनिक शिक्षा के विषयों का प्रबन्ध था। इस समय के पब्लिक स्कूल, जिनमें ईटन तथा वेस्टमिनिस्टर मुख्य थे, धनी तथा उच्च वर्ग के छात्रों को शिक्षा देते थे। इस प्रकार विरोधी चर्च खाने लोगों के नये अपने पुत्रों स्कूल खोलकर शिला देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। इन्हीं स्कूलों (विरोधी चर्च वाले) में आधुनिक उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था यद्यपि उक्त पब्लिक स्कूल भी इस दिशा में कभी कभी कदम डालते थे। इस युग में स्त्री शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई थी—कुछ प्राइवेट स्कूलों के अतिरिक्त उनकी शिक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध न था। दोनों विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का प्रबन्ध अच्छा न था। ट्रेविलियन महोदय ने अपनी 'थाल हिस्ट्री' नामक पुस्तक में विश्वविद्यालयों की दशा का वर्णन करते हुये सौचनीय बताया है। उनके विचार में वहाँ प्रोफेसर अपना कार्य नहीं करते थे, छात्र केवल धन का अध्ययन तथा जीवन का आनन्द लेने के लिये ही आते थे, तथा कोई परीक्षा तक का प्रबन्ध न था। उनके मत से कैंब्रिज का स्तर आक्सफोर्ड के बराबर कभी नहीं गिरा। लेकिन इसका यह अर्थ ही कि देश में योग्य व्यक्तियों का अभाव था। अन्तिम बात से सहमत होते हुये भी डा० हेन्स ने दोनों विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को कम नहीं बताया। उनका कथन था कि उक्त बात केवल कुछ ही छात्रों के विषय में ही है क्योंकि अन्य छात्र (प्रायः साइजर्स जो काम करते तथा पढ़ते) देश के विषय में काफी ध्यान देने थे। वह तो इस समय के विश्वविद्यालयों कोटिक स्तर की प्रशंसा करते हैं और बहुत से विषयों के अध्ययन का ज्ञान भी इसी समय में होना वननाते हैं जैसे आक्सफोर्ड में रसायन-शास्त्र (Chemistry) १७०४, एनेटोमी (Anatomy) १७०७, बोटेनी (Botany) १७२४, आदि। हमारे मत से बात दोनों ही ठीक है दृष्टिकोण का बल (Stress) का अन्तर है। उस समय साहित्यिक सांस्कृतिक तथा

दार्शनिक विषय अधिक लोकप्रिय थे यद्यपि विज्ञान की ओर रुचि का सूत्र-पात्र हुआ था।

माध्यमिक तथा उच्चतर की शिक्षा में अकादमियों ने विशेष योग दिया। यह भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा देती थी जैसे व्यावसायिक, तकनीकी, साहित्यिक आदि। इन अकादमियों के छात्र मुख्यतया नये धनी वर्ग के व्यवसायी लोगो के बच्चे थे। किन्तु कभी कभी अन्य लोग—अंग्रेजी चर्च वाले तथा पुराने धनी घरानो के व्यक्ति भी इनमें छात्र भेजते थे। इन अकादमियों ने इसी शिक्षा की ओर भी प्रगति के पथ उठाये। लेकिन औद्योगिक क्रांति इनका मुख्य उत्साह का स्रोत थी।

प्रौढ शिक्षा जो उक्त विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में हो जाती थी कभी कभी अन्य व्यक्तियों द्वारा भी प्रोत्साहन पा जाती थी। जैसे देसागुलिये (Desaguliers) ने १७१२-१३ में मशीनो तथा प्रयोगात्मक दर्शन पर भाषण दिये। इस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों में बेंजामिन वोरस्टर (Benjamin Worster), एडम वाकर (Adam Walker), बेंजामिन डान (Benjamin Don) आदि थे। डा० हिगिन्स (Higgins) नायक व्यक्ति में भी इस विषय में सराहनीय प्रयत्न किये। मेसोनिक क्लबो (Masonic Clubs) तथा लोगो की व्यक्तिगत गोष्ठियों में शिक्षा के प्रयत्न अनवरत रूप से होते रहे। डा० हेन्स ने निष्कर्ष निकालते समय आश्चर्य प्रकट किया है कि इन सब चेष्टाओं के बाव भी हक्सले (Huxley) स्पेंसर (Spencer) आदि को १९ वी सताब्दी में विज्ञान के प्रति लोगो का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रयत्न करने पड़े।

१८ वी सताब्दी के आरम्भ में हमें शिक्षा की ओर उन्मुख करती कई शक्तियों का आभास मिलता है। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैण्ड के समाज को नये रूप में ढाल दिया था। नये धनी वर्ग का जन्म हुआ था। वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। विरोधी चर्च वाले ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये अकादमियों द्वारा अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करके शिक्षा के क्षेत्र में नया मार्ग दिखाया था। इन स्थानों की पढ़ाई का स्तर तथा विषय उच्च तथा आधुनिक थे। धर्मार्थ व्यक्तियों के लिये जीवन का नवीन मूठ पलट रहा था। ऐसे युग में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा दोनों ही के क्षेत्र में कुछ विशेष कारण उत्पन्न हुये जिन्होंने शिक्षा को नया रूप दिया तथा राष्ट्रीय-शिक्षा-व्यवस्था की ओर अग्रसर किया।

इनके अतिरिक्त अपने देश तथा विदेश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा दार्शनिकों के लेख और वक्तव्य जन-शिक्षा की आवश्यकता की ओर ध्यान केन्द्रित करने में

सहायक निद्व हुये । १७ वीं शताब्दी में लॉक, (Locke) १८ वीं में एडम स्मिथ (Adam Smith), मैथ्यूज (Mathuse), टामस पेन (Thomas Payne), आदि ने इस विषय में महत्वपूर्ण बातें कही तथा लिखी । ला शालोते (La Shalote) ने कहा, "मैं राष्ट्रीय शिक्षा की राजकीय व्यवस्था चाहता हूँ क्योंकि मुख्यतया शिक्षा राज्य का ही कार्यक्षेत्र है राज्य के अपने राज्य के सदस्यों द्वारा ही शिक्षित होने चाहिये ।" इनके विरोधियों की मकदमा भी कुछ कम नहीं थी किन्तु बदलते समय ने उनकी आवाज को मद्धिम कर दिया था ।

(घ) प्राथमिक शिक्षा

१८ वीं शताब्दी के इस स्कूल (बुद्धियों के स्कूल) जहाँ ७ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा होनी थी और जहाँ की फीस नहीं के बराबर थी, निर्पत्नों के बच्चों को वर्गाधारी तथा प्राथमिक हिमाक का ज्ञान देने का कार्य करने थे । इनके अनिर्गल ब्रिटीश स्कूल (बन्दे द्वारा गरीबों के लिये स्थापित) तथा गवर्ने स्कूल (जहाँ केवल इनका के दिन पढ़ाई होनी) भी थे । वेल्स में गवर्नेस्कूल स्कूल (बनने लगे स्कूल—जहाँ अध्यापक घूम घूम कर छोटे समय के लिये शिक्षा का प्रकाश करने थे) १८ वीं शताब्दी में अत्यधिक लोकप्रिय हुये—ग्रिफिथ जोन (Griffith Jones) तथा बाद में मैडम बेवन (Madam Bevan) ने यह गराहनीय स्कूल बनाये तथा वेल्स में शिक्षा के प्रति स्नेह तथा उनकी आवश्यकता अनुभव करवायी ।

घमें तथा मानवता के प्रेम पर आधारित यह शिक्षा देने के उक्त विभिन्न माध्यम अपना कार्य तो करने है किन्तु निम्नलिखित बड़ी हुई आवश्यकताओं तथा बदलती हुई अवस्थाओं के अनुसार वास्तविक निर्धारण तथा शिक्षण में समर्थन रहे । इस वृद्ध-भूमि में चार्ल्स बर्चिनौघ (Charles Barchenough) का कथन (हिन्दी भाषा लॉरेन्स लुकेन्स) लक्ष्मण मा ही प्रमाण होता है कि प्राथमिक शिक्षा का इतिहास विरोधाभासों पर वास्तविकता का स्वीकार है । जो शिक्षा सभी दान-स्वभाव की होती जाती की तब तक अधिकांश का मन ने खुदी है और शिक्षा की समान सुविधा में सामाजिक स्तर के अनुसार ही सब सभी शिक्षा का स्थान ले रही है ।

दूसरा युग (१९ वीं शताब्दी) क्रमिक और शर्त विज्ञान युग—

१९ वीं शताब्दी का अन्तर्गत में औद्योगिक क्रांति ने शिक्षा-विज्ञान में अत्यन्त महत्त्व की । यह प्रभाव और महत्त्व परीक्षा ही का क्योंकि पहले कुछ वर्गोंवाली क्रांति ने शिक्षा का मानकीय कार्य दिया, उन्ही के कारण में

ब्रिटेन का शिक्षा-इतिहास

पर्याप्त परिचय दिया। कारखानों और खानों का दूषित प्रभाव बालकों के स्थान पर जब इन परोपकारी व्यक्तियों ने देखा तो उनका हृदय दया में पिघल गया, कारखानों और खानों के मालिकों के कार्य इन ईमानदार और परोपकारी व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगे। इन परोपकारी व्यक्तियों ने शिक्षा के पवित्र कार्य का बीड़ा उठाया। शिक्षा-मुधार मैगोडिस्ट और इवेंजेलिकल रिवाइवलिस्ट^१ के प्रोत्साहन द्वारा हुआ। १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रिफॉर्म एक्ट (Reform Act), द फर्स्ट सबस्टान्शियल फैक्ट्रीएक्ट (The First substantial Factory Act) और ब्रिटिश राज्य में गुलामी प्रथा का अन्त आदि एक्टों का आगमन हुआ। सन् १८३३ ई० में पारसी बार संसद ने शिक्षा के लिये धन-राशि की स्वीकृति दी।

नये विश्वविद्यालय—लन्दन में यूनीवर्सिटी कालेज (गवर्न-स्ट्रीट) का सन् १८२९ में आरम्भ हुआ। लन्दन-विश्वविद्यालय जो बहुत समय तक एक परी-शाला-मठवा ही रही, सन् १८३६ में इसकी स्थापना हुई।

सन् १८४० के बाद दूसरे प्रांतीय विश्वविद्यालय स्थापित हुये, जिनमें से बहुतों के विषय वैज्ञानिक और औद्योगिक थे। मानचेस्टर (Manchester), लिवर्पूल (Liverpool), लीड्स (Leeds), बर्मिंघम (Birmingham), शेफील्ड, (Sheffield), ब्रिस्टल (Bristol) विश्वविद्यालयों का विकास इसी प्रकार हुआ।

माध्यमिक शिक्षा—१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में लोगों में शिक्षा-मुधार की उत्कट अभिप्राया थी। इसलिए विश्वविद्यालयों के समान ही ग्रामर और पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई। माध्यमिक-शिक्षा के मुधार में मुख्य लोग टायम आरनोल्ड (रगबी), एडवर्ड थ्रिंग (Edward Thring), और हेग ब्राउन (Haig Brown), के नाम उल्लेखनीय हैं।

टायम आरनोल्ड ने माध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मराहनीय कार्य किया; उन्होंने 'रगबी' की स्थापना करके पब्लिक स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन दिया; स्कूलों और पाठ्य-क्रम दोनों का ही उन्होंने पुनर्-व्यवस्था किया। इतिहास-शिक्षण के दृष्टिकोण बचने तथा कृषि और परित्यक्त के प्रवेशन कराने का धर्म उसी को है। प्रयासकों की उत्तर-दायित्व देने की विधि, तथा चरित्र-विकास और निर्माण के लिए सुसंगठित भेदों का प्रयोग पब्लिक स्कूलों की मुख्य विशेषताएँ थीं।

ऐसे ही अग्रगामी प्रयास अध्यापकों के कार्य के कारण पुराने पब्लिक स्कूलों

ने अपने कार्य का स्तर सुधार लिया और नये पब्लिक स्कूलों जैसे मार्तबरो, वेल्थिंग्टन, हैलीवरी और क्लिफ्टन की स्थापना हुई। इस समय तीन मुख्य कमीशनों की नियुक्ति हुई। पब्लिक-स्कूल कमीशन¹ (१८६१—१८६४) ने १ बड़े पब्लिक स्कूलों के प्रबंध के विषय में खोजबीन की। दो स्कूल इनक्वायरी कमीशन² ने दूसरे माध्यमिक-विद्यालयों के बारे में जांच की। सबसे महत्वपूर्ण ब्राडस-कमीशन था जिसने इंग्लैंड की माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली को सुसंगठित बनाने की विधियों पर विचार किया। ब्राडस-कमीशन की बहुत सी शिफारिशों पर शिक्षा में बहुत से होने वाले मुख्य सुधार और विकास आधारित थे।

स्त्री-शिक्षा—क्वीन्स-कालेज की स्थापना सन् १८४८ में की गई थी। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला ही कार्य था। लन्दन में और भी बहुत से ऐसे कालेजों की स्थापना की गई। वेस्टपोर्ट कालेज लन्दन की स्थापना के द्वारा सबसे पहले स्त्री-शिक्षा का आयोजन किया गया। परन्तु केवल सन् १८२० में ब्रॉक्मफोर्ड में और सन् १८४७ में कैम्ब्रिज में स्त्रियों की विद्यालयों के पूर्ण अधिकार दिये गये।

प्रारम्भिक शिक्षा—१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वरोगकारी स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं का अधिक महत्व रहा। इस प्रकार से कार्य करने वाली ब्रिटिश और विदेशी स्कूल समिति थी और दूसरी राष्ट्रीय समिति थी जिन्होंने निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इंग्लैंड के वर्ष के निदाताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की। दान दिये घन में ये स्कूल चलाये गए। इन दोनों संस्थाओं ने देश में स्कूलों का जाल गाँपना दिया था। सन् १८१३ में संसद ने शिक्षा के लिए सबसे पहली सहायता दी। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निवर्तमान अधिक-सहायता का आयोजन किया गया। सन् १८३६ में प्रिवी काउंसिल की एक विदेश कमेटी की स्थापना हुई जिसने शिक्षा को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विषय में खोज-बीन की। इस कमेटी के सबसे पहले मंत्री सर जेम्स के-शटल वर्ध³ थे। यद्यपि उन्होंने थोड़े समय तक कार्य किया परन्तु उन्हीं की इंग्लैंड की प्राथमरी शिक्षा की नींव डालने का श्रेय है।

इस शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष सन् १८७० था, जिसमें प्राथमरी शिक्षा एक्ट⁴ पास हुआ। इस एक्ट के द्वारा जनता द्वारा चुने हुए स्कूल बोर्डों की स्थापना हुई जिन्होंने बहुत से स्कूलों की स्थापना की। ये स्कूल ऐसे स्थानों

1. Public Schools Commission (1851-1864)

2. The Schools Enquiry Commission.

3. Sir James Kay-Shuttleworth.

4. Elementary Education Act 1870.

में स्थापित किये गये जहाँ पर स्वेच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा पाठ-शालाएँ प्रारम्भ नहीं की गई थीं। इसी समय शिक्षा में द्वि-प्रणाली (Dual System) का सूत्रपात हुआ।

समय व्यतीत होने के साथ प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगई और इस सनाम्दी के अन्त तक अधिकांश बालक इससे लाभ उठाने लगे। सन् १८६६ में शिक्षा एक्ट के अनुसार 'शिक्षा-बोर्ड' (Board of Education) की स्थापना की गई जिसका उत्तरदायित्व इंग्लैण्ड और वेल्स का शिक्षा-सम्बन्धी आयोजन और शिक्षा निरीक्षण था। आगामी सन् १८७० में शिक्षा-क्षेत्र में और भी अधिक महान विकास हुये।

१६ वीं सनाम्दी की यवनिका डा० बेल की मन्त्रालय व्यवस्था के ऊपर लेल से खुलती है। १८३३ तक बहुत सी शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों के फलस्वरूप राज्य कोष से शिक्षा के लिये धन मजूर हो जाता है। राबर्ट ओवेन (Robert Owen) जेम्स मिल (James mill), कवि बर्ड्स वर्थ द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकाशित होते हैं। जेम्स मिल ने कहा, "हम जैसे धनी तथा निधन में समान न्याय, समान माना में धैर्य, समान माना में सत्य की चेष्टा करते हैं, जैसे ही हमें उनमें समान सामान्य बुद्धि उत्पन्न करने की चेष्टा करनी चाहिये।" ऐसे युग में जिसमें मशीन तथा व्यापार में स्वतन्त्रता के विचार प्रिय थे—मोनीटरी द्वारा शिक्षा जो डा० बेल (Bell) तथा लन्कास्टर (Lancaster) के प्रयत्नों के फलस्वरूप आई अनायास ही लोकप्रिय बन गई। कारण स्पष्ट है, इस शिक्षा के तरीके को जनता ने सामयिक मशीनों के आविष्कारों से मिलता-जुलता तरीका समझा।

उपयोगितावादी बेन्थम (Bentham) के अनुसार यह प्रश्न कि क्या लोगों को शिक्षित होना चाहिये या नहीं, ठीक ऐसा ही प्रश्न है "कि लोगों को प्रसन्न रहना चाहिये या दुःखी।" स्वाभाविक है कि उसके अनुयायी पार्लियामेंट में शिक्षा के लिये राज्य द्वारा धन की स्वीकृति मांगते। राबर्ट ओवेन विलकुल ही अलग प्रकार का व्यक्ति था। वह अपनी कर्मठता के कारण धनी हुआ था और शिक्षा का जन-साधारण में प्रसार देखने का इच्छुक था उसने कहा, "सबसे अच्छा प्राप्ति राज्य वह है जिसमें सबसे अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है।"

गरीबी की दशा के सुधार के लिये चैरिटी सोसाइटी (१७६६), तथा सण्डे स्कूल्स यूनियन (१८०३) के अतिरिक्त डा० बेल तथा लन्कास्टर के स्कूल १६ वीं सनाम्दी के प्रारम्भ में गरीबों की शिक्षा के साधन थे। डा० बेल

पादरी या और मद्रास में रहकर उमने बीनीटों का शिक्षा देने के लिये के मकसद प्रयोग किये थे। लन्कास्टर दृष्ट करके था उमने भी मियना-युन तरीका निकाला था। इस शिक्षा की विशेषता अपने ही मकसद के लिये कागज़ों में थी। यह नया तरीका कम खर्च पर अच्छे परिणाम दे सकता था। एक छात्र का शिक्षा का खर्च मात्र ७ शिलिंग था और यदि छात्रों संख्या बढ़ा दी जाती तो यह घट कर ६ शिलिंग ही रह जाता। इसमें अध्यापक को कुछ अच्छे छात्रों की पढ़ाना पड़ना; बड़े जाकर अन्य छात्रों को वही विषय पढ़ा देने। यद्यपि इसमें व्यक्तिगत शिक्षा का अवसर न मिलता लेकिन प्रारम्भिक पढ़ाई का कार्य मजबूत अवसर हो जाता था। कहना होगा कि योहन् तथा भारत के लिये यह पढ़ाने का तरीका अभी भी नया था। युगों से इस प्रकार हम गाँवों में छात्रों को पढ़ाते रहे हैं।

इंग्लैण्ड में इन दोनों व्यक्तियों ने असम-असम सन्ध्या में मोती तथा चन्द्रिका किया। इनकी सफलता अद्वितीय रही। १८०७ में मेमुब्रन व्हाइटब्रेड (Samuel whitebread) ने ब्रिटिश संसद में एक दिन बोल किया इस अनुसार ७ से १४ वर्ष की आयु के बीच २ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के लिये आयोजन था। इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें प्रत्येक पाउण्ड में १ शिलिंग के का की माँग की गई थी। यद्यपि हाउस आफ साइंस ने इस बिल को पाम नहीं किया। इसने जन-शिक्षा की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित कर दिया।

डा० बेल की पद्धति के पक्ष में जनमत काफी था। वह इंग्लैण्ड की चर्च के अनुयायी थे इसलिये इस पद्धति को दोनों विश्वविद्यालयों का आश्रय मिला। १८११ में इस पद्धति के प्रसार तथा विकास के लिये एक सोसाइटी की स्थापना हुई। डा० बेल ने अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये भी बाल्डविन गार्स स्कूल खोला। लन्कास्टर की अव्यवसायिक प्रवृत्ति के कारण तथा उनके विरोधी धर्म के होने के कारण उनकी पद्धति की उन्नति में बाधा पहुँची। लेकिन ब्रूहा (Brougham), जेम्स मिल (James Mill), तथा फ्रान्सिस प्लेस (Francis Place) जैसे व्यक्तियों ने कार्य भार सम्भाल लिया तथा 'द ब्रिटिश एण्ड कोरेन सोसाइटी' की स्थापना १८१४ में कर डाली। इस प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्य में उनकी प्रगति डा० बेल से कहीं अधिक हुई। इन स्कूलों में धार्मिक वस्तुओं की पढ़ाई बिना किसी टीका के होती थी इस प्रकार इसने भावी कूपर-टेम्पल पारा को पहले से ही कार्य रूप में परिणित कर दिया था। १८१६ तक लगभग ३०० स्कूलों में लन्कास्टर पद्धति के २०५ स्कूलों में छात्रों तथा

अन्य छात्राओं की माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध हो गया। इस पद्धति में शिक्षा भी पीछे नहीं रही।

राज्य के हस्तक्षेप का प्रथम उदाहरण १६ वीं शताब्दी में १८०२ एंग्लिस एक्ट द्वारा मिला। इसके अनुसार राज्य ने एंग्लिसों के काम तथा पढ़ाई के घंटे निश्चित कर दिये। ब्रह्म के परिणामों के फलस्वरूप पार्लियामेंट की एक सलेक्ट कमेटी ने शिक्षा की अवस्था के विषय में १८१८ में २ वर्ष के परिधम के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। कमेटी ने विभिन्न उदार-सभाओं के दान तथा स्कूलों के कार्य की प्रशंसा की, किन्तु उन्होंने दान के धन प्रबन्ध में गड़बड़ होने की बात कही, तथा उसके उचित प्रबन्ध के लिये प्रार्थना की। उसने कर के आधार पर चलाने के लिये स्कूलों के लोभने की सिफारिश की तथा स्कूल की इमारतों के लिये धन की मंजूरी की भी सिफारिश की तथा धार्मिक शिक्षा के विषय में उन्होंने एक धारा बनाई।

१८२० में ब्रह्म ने इंग्लैंड तथा वेल्स के निर्धन बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिये एक बिल पार्लियामेंट के सम्मुख पेश किया। इसके द्वारा शीर्षीय (Parochial) स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था सोची गयी। इन स्कूलों में फीस २ से ४ पेंस प्रति सप्ताह होती थी। निर्धन बच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधा थी। अध्यापकों का वेतन २० से ३० पाउण्ड प्रति वर्ष होता निश्चित किया गया। इसके अनिश्चित उन्हें रहने का स्थान मुफ्त दिया जाता था। पाठरिषों द्वारा पाठ्य-क्रम का निर्माण होता था। शिक्षा के लिए ही गई संपत्ति नाम द्वारा समस्त धन का आंशिक धन देने की भी व्यवस्था थी। ब्रह्म ने कहा कि वह इस बिल को केवल इसलिए पेश कर रहा था ताकि शिक्षा के प्रति स्वतन्त्र इच्छाओं का हनन न हो। उस समय स्कूल जाने वालों की संख्या का अनुपात १—१५ इंग्लैंड में और १—२० वेल्स में था। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि जनसंख्या १० में से १ को स्कूल जाने योग्य मान लिया तो प्रत्येक ३ में से १ के लिये स्कूल व्यवस्था नहीं थी। बैसे, ब्रह्म की उक्त संख्या में हजारों बच्चे जो वास्तव में डेम स्कूलों या अन्य अनजान स्थानों पर पढ़ रहे थे सम्मिलित नहीं थे। यद्यपि इस बिल को शीघ्र ही लागू नया पड़ा किन्तु इसने शिक्षा के सम्बन्ध में रचित तथा उत्पाद उत्पन्न कर दिया।

१८३३ में चर्च का बिल पार्लियामेंट के सम्मुख आया जिसमें शिक्षा की शीघ्रनीय अवस्था का वर्णन था और इसके द्वारा प्रत्येक ग्राम, तथा नगर के

स्कूलों की व्यवस्था की योजना का तथा अध्यापक प्रशिक्षण के प्रबन्ध की बातों की सोची गई। शिक्षा को एक केन्द्रीय मन्त्री के हाथ में देने की सलाह दी गयी तथा टैक्स तथा दान द्वारा इन स्कूलों को चलाने की व्यवस्था का आयोजन किया गया। स्पष्ट है, कि यह बिल अनेक समय से काफ़ी आगे था। इसलिये इसे वापस लेना पड़ा किन्तु लार्ड अल्ट्रोप (Lord Altrop) ने २०,००० पाउण्ड की धनराशि स्वीकृति अवश्य करा दी।

इस पृष्ठ-भूमि में १८३३ में अमेजी पार्लियामेंट ने २०,००० पाउण्ड शिक्षा के लिये स्वीकृत किये। परन्तु राज्य में यह राशि केवल ऐच्छिक संस्थाओं को दी जो उस समय इन क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं। उसने अपने स्कूल नहीं खोले। इस प्रकार यह धन की स्वीकृति यद्यपि राज्य की शिक्षा में सहायता का प्रथम कारण थी और कार्लाइल, डिकेन्स, मिल जैसे व्यक्तियों के विचारों के फलस्वरूप दी गई थी। शिक्षा की अवस्था में हमने विशेष सुधार नहीं हुआ।

इस राशि के स्वीकृत होने का एक परिणाम हुआ—शिक्षा के क्षेत्र में कार्यवाही सरगर्मी के साथ बढ़ गई लेकिन यह शिक्षा ऐच्छिक लोगों तथा संस्थाओं पर निर्भर होने के कारण उसी व्यवस्था में ही अच्छी थी और न राष्ट्रीय-क्रम में। पाठकों को ध्यान रहे कि 'ब्रिटिश एण्ड कोरेन सोसाइटी' लॉन्गस्टर पद्धति की मानने वाली थी और धार्मिक उदारता के कारण अधिक लोकप्रिय थी। इस समय विभिन्न मतों में खुसो पर आधिपत्य जमाने के लिये भगड़ा उत्पन्न हो गया। इसलिये महारानी ने 'शार्डर इन काउन्सिल' द्वारा एक प्रिवी काउन्सिल की विशेष समिति बनाई जिसमें लार्ड प्रेसीडेंट, प्रीबो, मील, चान्सेलर ऑफ एक्जचेंकर, मेन्ट्री होम डिपार्टमेंट तथा मास्टर ऑफ मिंट सम्मिलित थे। यह समिति १८३६ में बनी और वेन्चरिल शिक्षा का कार्य-भार इसकी नींव दिया गया। इसी वर्ष अध्यापक-प्रशिक्षण के लिये स्कूलों की व्यवस्था का प्रश्न उठा। मजबूत मुद्दाव जो इस सम्बन्ध में आया उसका इस कुरी तरह विरोध हुआ कि पार्लियामेंट ने १०,००० पाउण्ड इस कार्य के लिये मेन्सल एण्ड ब्रिटिश कोरेन सोसाइटियों को दे दिये। उसी समिति का भी विरोध हुआ क्योंकि लोगों ने सोचा कि इससे शिक्षा की स्वतन्त्रता मराना हो जायगी और उन वर्ष की २०,००० पाउण्ड की स्वीकृति भी केवल २ बोट में मिल सकती।

रोमन कैथोलिक भी शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक स्वतन्त्रता के कारण आये। इस प्रकार इस क्षेत्र में और अधिक प्रोत्साहन मिला।

१८६३ में साहू ने एक बिल पेश किया जिसमें अनिवार्य शिक्षा आधिकारिक में लाने की बात की गयी थी। यह बिल उस वर्षों पर लागू होना था

जो मिलों में भजदूरी करते थे। इसमें स्कुलो के खोलने के लिये राज्य से कर्ज देने की बात भी थी। ब्राह्म का बिल अन्य सुधारों की व्यवस्था के पश्चात् भी पास न हो सका। १८४४ में एक अन्य बिल पास हो गया जिसकी धाराओं के विषय में मतभेद न था। लेकिन यह बिल केवल उन जिलों के बच्चों के लिये था जो सूत के कारखानों में काम नहीं करते थे।

शिक्षा समिति का कार्य :—

१८३२ में जन्म लेने के पश्चात् इसने अपना कार्य बड़े सभास कर प्रारम्भ किया। इसने धार्मिक शिक्षा को प्रधानता दी और अधिक से अधिक मत वालों में मतभेद दूर करने की चेष्टायें की। इनके कार्य-क्रम के कारण बहुत सी अनुविधायें दूर हो गईं—स्कूल की आवश्यकतायें, सहायता की मांग, अच्छे शासन तथा शिक्षा वाले स्कूल आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। यह कार्य समिति अपने निरीक्षणों से करवाती थी। रिपोर्टों के आधार पर यह पता लगा कि बिना और धन के अच्छी शिक्षा व्यवस्था सम्भव नहीं—किन्तु धार्मिक हस्तक्षेप की सम्भावना के कारण राज्य द्वारा अधिक धन की स्वीकृति का विरोध हुआ। लेकिन निरीक्षकों के चुनाव में अब बच्चों की राय ली जाने लगी यह विरोध धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

१८४६ में इस समिति ने शिक्षकों, स्कुलो, भवनो तथा अन्य बातों के सुधार का कार्य हाथ में ले लिया। अब प्रत्येक संस्था को राज्य द्वारा धन मिल सकता था यदि उसमें धार्मिक पढ़ाई होती हो; लेकिन इस धार्मिक पढ़ाई के भेदों को दूर करने के लिये बहुत सी धारायें समिति ने बना दी।

इसी वर्ष डा० हुक (Hook) का एक पत्र प्रकाशित हुआ उसमें इस बात को कहा गया था कि ऐश्विक शिक्षा व्यवस्था असफल रही है तथा एक ऐसी व्यवस्था लिये बल दिया गया जो जनता के कर पर निर्भर हो और जिसमें धर्म निरपेक्ष (Secular) शिक्षा राज्य द्वारा दी जाय तथा जहाँ विभिन्न मतों की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो। इन स्कुलो के वाक्य-क्रम को विस्तृत होना था तथा अध्यापकों की राजकीय सर्टीफिकेट के बाद ही नियुक्ति मिलनी चाहिये थी। १८५० में पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ जो बहुत सी धाराओं के सम्बन्ध में १८७० के अधिनियम जैसा था। उस बिल के अन्तर्गत शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति होनी थी और उनका कार्य अपने-अपने क्षेत्र की शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का पता लगाना था। सरदाशत्रों को स्कूल खोलने का अधिकार तथा ७ में १२ वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिये कर सभाने का अधिकार भी दिया गया था। यह बिल पास न हो सका। लेकिन इसी वर्ष में 'लवडाशायर स्कूल ऐमोसियेशन' ने अपने को नेशनल एश्विक

ऐसोसियेशन में बढस लिया । मेनचेस्टर तथा सेलफोर्ड कमेटी ने कर लगा धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया तथा धर्म निरपेक्ष शिक्षा का विरोध कर प्रारम्भ कर दिया । १८५३ में जान रसेल ने शिक्षा-बिल पेश किया जो केवल नगरों के लिये ही था । इन्होंने काउन्सिलों को अधिकार दिये जिससे वह अपने आमदनी बढा सकते थे, तथा उन्हें अनुदान भी मिल सकता था । यह बिल पास न हो सका । अन्य बिल भी जो इसके पश्चात् पेश किये गये, इसी प्रकार असफल रहे । लेकिन उक्त बातों के कारण शिक्षा की अवस्था के प्रति जनकारी तथा रुचि अवश्य बढी । परिणाम स्वरूप न्यू कासिल (New Castle) आयोग १८५८-६१ में बैठा जिसके द्वारा शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँच तथा प्रत्येक स्तर के लिये सस्ती किन्तु ठोस शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह माँगी गयी । इसके प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—(१) धार्मिक प्रवृत्ति के कारण शिक्षा के विस्तार में सहायता मिली है । (२) १ : ८ के अनुपात से जन-संख्या स्थूल जाने लगी है । (३) स्कूल समय से पहले छोड़ने तथा कम हाजिरी शिक्षा के दुर्गुण हैं । (४) निरीक्षित स्कूलों की दशा अन्य स्कूलों से अच्छी है । (५) छात्राध्यापक-व्यवस्था (जिसके द्वारा छोटे बच्चे एक छात्र किसी एक अध्यापक के साथ काम करने पर अध्यापक बन जाता) ठीक थी । (६) काउन्सिल की कमेटी द्वारा संचालित शिक्षा-व्यवस्था जटिल तथा लचीली है । आयोग ने सिफारिश की कि राज्य द्वारा अनुदान परीक्षा के परिणामों के आधार पर मिलना चाहिये । यह परीक्षा राजकीय निरीक्षकों से । उन्होंने स्कूल की फीस समाप्त करने की सिफारिश नहीं की और अनिवार्य शिक्षा की बातचीत ही । हाँ, उनके अनुसार शिक्षा के लिये बच्चों को स्कूल छोटी उम्र से जाना था, क्योंकि ११ वर्ष के पश्चात् कम बच्चे स्कूल में रहते थे । आयोग के मत के अनुसार स्कूल के व्यवस्थापकों को दिया जाना चाहिये । आयोग मुख्यतया अनुदान की सीमा को बढाने के पक्ष में था । राज्य के अनुदान लेने के लिये खैरीय-मंडल होने चाहिये तथा उन्होंने गुमाव दिया कि अनुदान केवल उन्हीं स्कूलों को मिले जिनके लिये निरीक्षण-पत्र अपनी राय दें ।

इस बिल का विरोध काफी हुआ, आयोग के आँकड़ों के माध्यम से लोगों में सन्देह किया तथा इसीलिये इस पर आधारित कोई अधिनियम नहीं बना । इंग्लैण्ड की आर्थिक दशा भी खीमियन युद्ध के कारण अच्छी न थी जिसका प्रभाव आयोग के प्रतिवेदन तथा अधिनियम के न बनने पर पड़ा ।

मिस्टर मो की मनोविधि महिला (और बहुत सी प्रचलित कानूनों (Mistress) पर आधारित थी) ने १८६१ में प्रत्येक छात्र के ऊपर कुछ

अनुदान व्यवस्थापकों को देना प्रारम्भ किया। इस कोड ने अध्यापकों को पेन्शन स्कीम मजबूत कर दी तथा "परीक्षा के परिणामों के अनुसार अनुदान-Payment by result" व्यवस्था लागू कर दी। (इस नुस्खे प्रथा का अन्त १८६५ की शिक्षा संहिता की एक धारा द्वारा हुआ जिसके अनुसार स्कूलों का निरीक्षण बिना पूर्व-सूचना के होने की व्यवस्था लागू की गई।) निरीक्षकों द्वारा परीक्षा प्रारम्भ हो गई। कन्याओं के लिये सीने-बुनने का काम मिलाया जाने लगा। स्थानीय सहयोग फीस तथा दान के अनुपात से अनुदान मिलने के कारण बढ़ गया। अध्यापक, प्रिन्सिपल के लिये अनुदान बढ़ हो गये तथा एक निम्न प्रकार का मर्तीयुक्त प्रारम्भ हो गया। इस संहिता का विरोध हुआ लेकिन इसके कारण छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई तथा राज्य का ध्येय भी बल हो गया। अच्छे स्कूलों को अधिक धन तथा अल्प को कम धन मिलने लगा। ६ वर्ष में कम के बच्चे परीक्षा से मुक्त थे लेकिन उनके परचातु कोई मियाद न थी और कोई छात्र एक ही परीक्षा में दो बार नहीं बैठ सकता था। मैग्नो कार्नाल्ड की शाय में इस व्यवस्था से शिक्षा अच्छी हो गई। १८६७ में इस कोड में संशोधन हुये जैसे अधिक अनुदान छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये तथा अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति के लिये आदि।

१८६७ में 'द मेन्चेस्टर एजुकेशन बिल कमेटी,' तथा 'द अधिनियम सींग' और १८६६ में 'द मेन्सल एजुकेशन यूनिवर्स' की स्थापना हुई। यह सब एक व्यापक अधिनियम चाहते थे जिसमें धार्मिक शिक्षा के लिये धारा के माध्यम-धर्म निरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था हो। १८६७ के 'रिकार्म एक्ट' (सुधार अधिनियम) ने एक व्यापक अधिनियम की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार १८७० का प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम उक्त चोटियों का स्वाभाविक परिणाम था। उस समय १० साल ६ से १० वर्ष तक की उम्र के, तथा १० साल १० से १२ तक की उम्र के बच्चों के लिये कोई शिक्षा व्यवस्था न थी। इसलिये इन बच्चों ने देश को बाल्यादी तथा स्कूल संघों (इन्डिस्ट्रियल बोर्ड तथा विभिन्न वेरिजेज) में जाकर शिक्षा प्राप्त की। इन परिणामों को अपने क्षेत्र की कमियों को पूरा लगाकर पूरा करने के अधिकार दिये गये। विभिन्न मतों को अपने स्कूलों को दीव करने का अधिकार दिया गया। लेकिन निविद्यन समय के परचातु उनमें स्कूलों को कोई धारा में लेने का अधिकार दे दिया गया। धार्मिक मतवालों द्वारा स्वीकृति पर निरीक्षकों की नियुक्ति मजबूत हो गई। धार्मिक साहचर्य तथा अनुदान में सम्मिलन मोड़ दिया गया। तथा एक धारा द्वारा धार्मिक धर्म-न्यायन को बिना लेने रहने देने की व्यवस्था की गई। शिक्षा में फीस मजबूत नहीं की गई।

लेकिन निपटों को मध्य भाग महायना का प्रवर्णन कर दिया गया। इस प्रकार यह अधिनियम एक समझौता था जिसके द्वारा ऐच्छिक तथा स्थानीय बुने हुये स्थापितों द्वारा सहायित बोर्ड स्कूल दोनों को ही रहने दिया गया। इसमें धर्म को न पूने के कारण वाम पंथी व्यक्तियों को छोड़कर अन्य लोगों को प्रमत्त किया गया। इस अधिनियम में दूर-दृष्टिपूर्ण भाग का संगोपन सम्मिलित कर लिया गया जिसके द्वारा किसी भी विशेष धार्मिक शिक्षा की स्कुलों में मनाही कर दी गई जो कर द्वारा महायना प्राप्त करते थे। लेकिन बिना टीका के बाइबिल का पढ़ाना वही मान लिया गया। सरकार ने धार्मिक स्कुलों को कर द्वारा सहायता देने वाली धारा अधिनियम में निर्यात दी। इस प्रकार विरोध के होते हुये भी यह विधायन अधिनियम बन गया।

१८७० के अधिनियम ने ऐच्छिक अधिकारियों तथा बोर्ड स्कूलों के मध्य स्पष्ट अन्तर उत्पन्न कर दिया। बोर्ड स्कूल स्वर तथा योगदान के सम्बन्ध में निरन्तर बढ़ते गये जबकि अन्य स्कूलों धन की कमी के कारण अर्द्ध अध्यापक रखकर अध्यापन का स्तर बढाने और धन कमाने में विद्यवा हुआ पाने लगे।

१८५१ की प्रदक्षिणी के पश्चात् से विज्ञान तथा वन विभाग अच्छा कार्य करने लग गया था। १८६७ की पेरिस प्रदक्षिणी ने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। १८८० में सङ्घन में एक गिल्ड की स्थापना हुई और कुछ ही दिनों में जिसके कारण तकनीकी शिक्षा पर आयोग बैठा। लेकिन इस विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक कहेंगे।

१८७० अधिनियम के पश्चात् धार्मिक तथा अन्य लोगों में शिक्षा के लिये होड़ सी होने लगी। बहुत से लोग अब भी राज स्कूल जाने की बात को अर्ध-हीन समझते, वस्तुतः बहुत से व्यक्तियों को शिक्षा में ही अधिक गुण दिखाई न देता इसलिये स्कूलों में उपस्थिति अच्छी नहीं हो पाती थी। मद्यपि उपस्थिति के लिये फौवटरी अधिनियम जो १८३३ में बना था सहायक था, इसी प्रकार के अन्य अधिनियम भी उपस्थिति पर जोर देते। उनमें प्रमुख था १८७६ का लांड सङ्घन का अधिनियम जिसके कारण १० वर्ष से कम के बच्चों को नौकरी पर रखना जुर्म था। केवल राजकीय निरीक्षक के सर्टीफिकेट के पश्चात् कि अमुक छात्र ने दर्जा ४ की योग्यता प्राप्त कर ली है १० ने १४ की आयु में नौकरी करने की आज्ञा मिल सकती थी। १८८० का मण्डला का अधिनियम तथा क्रास आयोग की रिपोर्ट से छात्रों की उपस्थिति की दशा में बहुत सुधार हुआ। १८६३ में छात्र ११ वर्ष की आयु के बाद स्कूल आना बन्द कर सकते थे। १८६६ में १२ तथा १८०० में स्थानीय शिक्षा अधिकारी १३ या १४ तक

आयु बढ़ा सकते थे, और आर्थिक दशा के सुधार के पश्चात् यह आयु १५ तक बढ़ाई जा सकती थी।

१८७१ के कोड (संहिता) के अनुसार स्कूलों के अच्छे शासन के अनुसार अनुदान को घटाया बढ़ाया जा सकता था। उदार पाठ्य-क्रम को प्रोत्साहन दिया जाने लगा तथा सम्बन्ध-कालीन स्कूलों को ४ शिर्षिक छात्रों की उपस्थिति तथा २॥ शि० पास होने पर अनुदान मिलने लगा। १८७३ में निरीक्षकों द्वारा स्कूलों के अचानक निरीक्षण का प्रबन्ध कर दिया गया। इस प्रकार स्कूलों का शासन, तथा अनुशासन दोनों में ही सुधार हुआ।

१८८३ में बढ़ाते हुये शिक्षा के व्यय के कारण ऐच्छिक अधिकारियों को सरकार के सामने एक आवेदन (Memorandum) रखना पड़ा जिसे प्रधान मन्त्री मैडिस्टन ने ठुकरा दिया। लेकिन १८८८ में क्रांस आयोग बँठा जिसको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के शासन, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, तथा प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा का सम्बन्ध आदि के विषय में जाँच करने का अधिकार मिला। आयोग की रिपोर्ट में दो मत हो गये १५ एक ओर ८ दूसरी ओर। इस मतभेद के कारण धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी विचार तथा स्थानीय कर द्वारा ऐच्छिक स्कूलों की सहायता करते थे। एक मत होकर आयोग ने निम्न सिफारिशों की : (१) स्कूलों में स्वास्थ्य रक्षा का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। स्कूलों में अच्छे अध्यापक तथा निश्चित वेतन, और अध्यापक प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिये। (२) ११ वर्ष में पहले किसी को भी नौकरी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये तथा स्कूल से भागने वाले बच्चों (Truants) के लिये स्कूल-व्यवस्था होनी चाहिये। (३) पाठ्य-क्रम में पर्याप्त हकिर्षों के बिना प्रबन्ध होना चाहिये। 'परीक्षा पर अनुदान' व्यवस्था की कमियों को यदि दूर कर दिया जाय तो आयोग को उसमें कोई एतराज न था। इन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अधिक आयु वाले छात्र छोटी परीक्षाओं में बैठने लायिक नह अनुसील न हों। (४) बहुमत धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था। (५) तथा बहुमत पालियामेंट द्वारा निर्धारित अनुदान के पक्ष में था। (६) पूरे आयोग की राय में सम्बन्धकालीन स्कूलों का चलना उचित था। इन स्कूलों में १२ में १८ या २१ तक के छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों से विज्ञान तथा तकनीकी उच्च शिक्षा की आशा की जाती थी। टाउन्ट आयोग ने १८६४-६७ में माध्यमिक स्कूलों को अधिक प्रजातन्त्रीय बनाने पर बल दिया था तथा माध्यमिक स्कूलों को स्कूल छोड़ने की आयु के आधार पर तीन ख्रेणियों में बाँटा था : १४, १६ तथा १८ या १९ के यह स्कूल क्रमशः घाम, ५००० जनसंख्या में अधिक के पक्ष में तथा २०,००० जनसंख्या से अधिक के नगरों के

लिये स्थापित किये जाते थे। १८७० के पश्चात् इन स्कूलों का कार्य प्रगति करने लगा। इन में प्राथमिक शिक्षा दी जाती तथा बहुत में विषयों में एक या अधिक में माध्यमिक परीक्षा पास करना हो तो इस प्रकार इन्हें बोर्ड तथा विज्ञान तथा कला विभाग दोनों से ही अनुदान मिल जाता। फिर इस विभाग द्वारा ३ वर्षीय विज्ञान की शिक्षा के निम्ने पढ़ाने के लिये भी सहायता दी जाती। क्लाय आयोग ने उक्त व्यवस्था के पक्ष में मत दिया लेकिन यह चाहते थे प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में स्पष्ट अन्तर हो जाय और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर दी जाने लगे।

इस आयोग के फलस्वरूप १८६० के कोड (संहिता) ने प्राथमिक कक्षाओं में Drawing अनिवार्य कर दी तथा विज्ञान तथा शारीरिक कसरत को प्रोत्साहन दिया। अध्यापक-प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये भी प्रबन्ध हुआ। १८६३ की संहिता के अनुसार सम्स्था-बालीन स्कूल के छात्रों को २१ वर्ष तक की अवस्था तक अनुदान देने के लिये गिना जाने लगा। इसी वर्ष ७-१६ तक के अथवा अधिक बच्चों की शिक्षा भी अनिवार्य हो गई। १८६६ तक अन्य शारीरिक कमियो वाले छात्रों की शिक्षा भी अनिवार्य हो गई। १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने स्थानीय शासन व्यवस्था में सुधार कर दिये। इंग्लैण्ड भर में वाउन्टी तथा काउन्टीबोर्न काउन्सिलों की स्थापना हो गई। १८८६ में लन्दन की शिक्षा अधिनियम ने इन काउन्सिलों की लन्दन की तथा हम्पशायर की शिक्षा देने का अधिकार भी दे दिया। १८६० में इन काउन्सिलों को निर्दिष्ट कर मिल गया जिसमें वह अधिक सहाय्य हो गये। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं की लोकप्रियता बढ़ गई और स्कूल बोर्ड कम लोकप्रिय हो गये जिससे पण्यस्वरूप उनको १९०२ में समाप्त कर दिया गया।

ऐच्छिक तथा धार्मिक विद्यालय (Bodies) ने बढ़ने शुरू करने के कारण १७३६ सि० की अनुदान सीमा को समाप्त करने की प्रार्थना की। १८६६ में सरकार ने एक दिन डायर ऐसा करने की चेष्टा की। उन्होंने समस्त शिक्षा को एक ही स्थानीय शिक्षा अधिकार (L.E.A.) माना चाहता था। बोर्ड के स्कूलों को ४ सि० की प्रतिशत अनुदान देने की कोशिश की। बोर्ड को २० सि० प्रति छात्र में अधिक कर लगाने के अधिकार पर रोक लगानी चाही। किन्तु यह दिन पास न हो सका। अगले वर्ष १७३६ सि० की सीमा समाप्त हो गई तथा ५ सि० की अधिक सहायता और देने की व्यवस्था की गई जिससे निम्ने एक ऐच्छिक अनुदान बनता हो इस अनुदान के बाँटने का कार्य करना।

बीसवी सताब्दी — इस सताब्दी का शिक्षा-विकास की दृष्टि से बहुत

महत्त्व है। सन् १९०२ का शिक्षा एक्ट राज्य शिक्षा-प्रणाली का मुख्य स्तम्भ रहा। इसके द्वारा स्कूल-बोर्डों की समाप्ति हो गई और काउन्टी काउन्सिल्स और काउन्टी बोरोज की स्थापना हुई। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी की इसी समय स्थापना हुई। स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयों में सहायता की गई, इस एक्ट के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की सीध स्थापना की गई जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी संस्था द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। औद्योगिक-शिक्षा तथा अध्यापक-प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी संस्था से सहायता प्राप्त करते थे।

बी फिशर-एक्ट^१—सन् १९१८ के शिक्षा-एक्ट द्वारा शिक्षा की अनिवार्य-अवस्था १४ वर्ष तक बढ़ा दी गई। इस सुधार का अर्थ शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एच० ए० एल० फिशर (H.A.L. Fisher) को है। स्थानीय शिक्षा-अधिकारी अब अधिक अवस्था वाले बालकों की व्यावहारिक-शिक्षा^२ भी देने लगी, और १४ वर्ष से १८ वर्ष तक के बालकों के लिए आंशिक-समय शिक्षा का आयोजन करने लगी। परन्तु युद्धोत्तर आर्थिक-संकट के कारण इसकी बहुत सी धारायें कार्यान्वित नहीं हो सकी।

बी हैबो रिपोर्ट^३—इस रिपोर्ट ने शिक्षा-संगठन पर बहुत प्रभाव डाला। इसके अनुसार ११ वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों को अलग स्कूलों में भेजने का आयोजन किया गया। ये स्कूल अधिक अवस्था वाले बच्चों (अर्थात् ११ वर्ष से अधिक आयु) की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। बच्चों की स्कूल छोड़ने की अवस्था अब १४ वर्ष कर दी गई जिससे ११ वर्ष की अवस्था के बाद कम से कम ४ वर्ष स्कूलों में रह सकें। इसके बाद स्पेन्स रिपोर्ट^४ का सूत्रपात हुआ।

शिक्षा का महान् विल — (एजुकेशन एक्ट १९४४): इसे बटलर एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका आगमन उस समय हुआ जबकि राष्ट्र के ऊपर द्वितीय महायुद्ध का भीषण संकट छाया हुआ था और नाजी शक्तियाँ इंग्लैंड पर आक्रमण और बमबाजी कर रही थी तथा लोग सुरक्षा के स्थानों को हटाय जा रहे थे। इस एक्ट द्वारा इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पुनर्निर्माण का सूत्रपात हुआ। पूरे देश में इस व्यापक बिल का स्वागत हुआ

1. The Fisher Act.

2. Practical Training.

3. The Harrow Report (1926).

4. Spens Report.

और इंग्लैंड के सामाजिक, धार्मिक पुनर्निर्माण की गति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।

इसके द्वारा शिक्षा बोर्डों की शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया और इसके अध्यक्ष का नाम प्रेसीडेंट के स्थान पर 'मिनिस्टर' रखा गया, उनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया और पहली बार शिक्षा में राष्ट्रीय नीति के विकास के लिए उनको अधिकार दिये गए। अनिवार्य शिक्षा की अवस्था को १४ वर्षों में बढ़ाकर १५ वर्ष तक कर दिया गया और यह अवस्था अधिक माधमों के मुलम होने पर १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी। सम्पूर्ण शिक्षा का तीन भागों में विभाजन करके—प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षा-क्रिया को एक अनवरत-विधि माना गया और बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षताओं द्वारा शिक्षा दी जाने लगी जिसमें उनकी अवस्था, बुद्धि, योग्यता और रुचि का ध्यान रखा जाने लगा। औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि की गई और काउन्टी कालेजों की स्थापना के प्रस्ताव द्वारा आगे की शिक्षा तथा प्रौढ-शिक्षा का आयोजन किया गया।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी मंत्रालयों द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षा-मुक्त समाप्त कर दिया गया और विद्यालयों को छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया।

इस धारा के अनुसार शिक्षा-मन्त्री दो केन्द्रीय सलाहकार कमिटीयों की नियुक्ति करेगा जो उसे इंग्लैंड और वेल्स की शिक्षा-विधियों और शिक्षा-सम्पत्तियों के विषय में उन्हें परामर्श देंगी। इस धारा द्वारा इंग्लैंड का पूरा शिक्षा-संगठन सुलभ और समझने योग्य बना दिया है। उसकी मुख्य धाराओं का सरासरी इस प्रकार है—

—“बोर्ड आफ एजुकेशन के अध्यक्ष” को शिक्षा-मन्त्री का नाम दिया गया और उनका कार्य इंग्लैंड और वेल्स की जनता के लिए शिक्षा-उन्नति और देश के प्रत्येक भाग में व्यापक शिक्षा-सेवा का आयोजन करना बताया गया। इस धारा के अनुसार शिक्षा-मन्त्री को बहुत अधिकार दिए गए इंग्लैंड और वेल्स दोनों की केन्द्रीय सलाहकार समिति का काम शिक्षा-मन्त्री को सलाह देना था।

—हर एक काउन्टी के लिए स्थानीय-शिक्षा अधिकारी काउन्सिल आफ दो काउन्टी होगी और काउन्टी बरो के लिए काउन्सिल आफ दो काउन्टी बरो होगी।

- १—पहले शिक्षा का आयोजन दो भागों में किया जाता था । प्रारम्भिक तथा उच्च-शिक्षा । परन्तु १९४४ की धारा ने शिक्षा को स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित कर दिया था—प्राइमरी,^१ माध्यमिक और आगे की शिक्षा के नाम सम्मिलित किए गए ।
- ४—स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर उत्तम शिक्षा आयोजन करें, जनता को आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक-विकास का मार्ग प्रस्तुत करें, जिससे उन क्षेत्र की जनता की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।
- ५—हर एक बच्चे को उसकी अवस्था, योग्यता, रुचि तथा व्यक्तिगत भिन्नता द्वारा शिक्षा दी जायगी । हर एक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे की शिक्षा-प्राप्ति का उचित आयोजन करे ।
- ६—५ वर्ष से १५ वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई । यह अवस्था ठीक अवसर पर १५ से १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी ।
- ७—२ साल से ५ साल के बच्चों के लिए तसरी स्कूलों का आयोजन किया जाना चाहिए ।
- ८—प्राइमरी और माध्यमिक-शिक्षा के लिए असम-असम विद्यालयों का आयोजन होगा ।
- ९—शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों तथा उनके लिए विशेष शिक्षा-विधि का आयोजन किया जाना चाहिए ।
- १०—नगरी विद्यालयों में २ वर्ष से ५ वर्ष के बच्चों को भेजना मरक्षकों की स्वेच्छा पर निर्भर है, परन्तु ५ वर्ष से १५ वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है । इस अवस्था की सीमा उचित आर्थिक साधन, इमारत और अध्यापक सम्बन्धी साधन मिलते ही १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी । पिछले प्राप्त समाचारों के अनुसार कुछ काउन्टीज में यह अवस्था १६ वर्ष तक बढ़ गई है ।
- ११—उन नवयुवकों के लिए जो १८ वर्ष की अवस्था से पहले स्कूल छोड़ गये हैं, काउन्टी बालेजों की स्थापना करना, आंशिक रूप से उनकी उपस्थिति अनिवार्य है । वर्षानु १५ वर्ष से १८ वर्ष के विद्यार्थियों की आवश्यकता के लिए 'काउन्टी-बालेजों' की स्थापना करना ।

१. The word 'Primary' was substituted for 'Elementary.'

१२—आगे की शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें शिक्षा के लिए पर्याप्त और सुसंगठित सुविधाएँ सम्मिलित हैं। प्रौढ़-शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक-शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक-शिक्षा और मनोरंजन, सुविधाओं में भी वृद्धि की जायगी।

१३—१८ साल तक की अवस्था तक बालकों तथा नवयुवकों के लिए शारीरिक तथा साधारण भलाई और कल्याण के लिए आयोजन किया जायगा।

१४—वह स्कूल जिनको राज्य में आर्थिक सहायता नहीं मिलनी थी, अब तक उनका राज्य द्वारा अनिवार्य निरीक्षण और देख-भाल नहीं हुआ करती थी। परन्तु इस धारा द्वारा ऐसे सभी स्कूलों का अनिवार्य निरीक्षण हुआ करेगा और केन्द्रीय-विद्यालय में उनकी रजिस्ट्री होगी।

१५—स्कूल-भवन आदि बनाने के नये सिद्धान्त और भाग-दंड केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये और स्वेच्छा-संस्थाओं द्वारा बनाने वाले स्कूलों को इन नई शर्तों को पूरा करना चाहिये।

१६—हर एक प्राथमरी और माध्यमिक स्कूल का कार्य साप्ताहिक-प्रार्थना के बाद आरम्भ होगा।

१७—हर एक स्वतन्त्र स्कूल का निरीक्षण और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

१८—आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी संस्थायें छात्रालय स्थापित कर सकती हैं।

१९—माध्यमिक शिक्षा तीन प्रकार के विद्यालयों (ग्रामर, टैक्नीकल और माडर्न स्कूलों) में दी जायगी। इनमें प्रवेश होना परीक्षा के ऊपर निर्भर रहेगा। इस परीक्षा में अच्छे की बुद्धि-परीक्षा मुख्य होगी।

२०—विद्यार्थियों की विक्रिस्ता, भोजन, दूध, कपड़े, पुस्तकें और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्रदान किया जायगा। दूर रहने वाले विद्यार्थियों को वातायात की सुविधा भी प्रदान की जायगी। इसके लिये उन्हें धन आदि नहीं देना पड़ेगा।

२१—निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति द्वारा पढ़ने की सुविधा हर प्रकार देना और विश्वविद्यालय तक पहुँचने में योग्य विद्यार्थियों को हर सम्भव ढंग में सहायता करना।

२२—अध्यापक-शिक्षण-सुविधाओं की वृद्धि।

२३—माध्यमिक-विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में सुधार।

इंग्लैंड का १९४४ का शिक्षा-एक्ट मसार के महान् एक्टों में से है जिसने

शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिपूर्ण सुधार किए हैं। दुर्भाग्यवश हममें सोची हुई बहुत सी बातें पूरी नहीं हो सकी हैं, उसका मुख्य कारण है कि देश द्वितीय सप्ताह-युद्ध के बाद बहुत भयंकर परिस्थिति में से गुजरा। आर्थिक-संकट उनमें प्रधान था जिसके कारण स्कूल छोड़ने की आयु १५ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष तक नहीं की जा सकी। धनाभाव के कारण स्कूल-भवन और अध्यापकों का अभाव रहा, उनके प्रशिक्षण की सुविधाओं की भी कमी रही।

काउन्टी कॉलेजों की स्थापना भी धन, स्कूल-भवन और अध्यापकों के अभाव में नहीं हो सकी, और १८ वर्ष तक के नवयुवकों की शिक्षा के लिये अधिक साधन नहीं जुटाये जा सके हैं। समालोचकों का कहना है कि शिक्षा एक्ट की प्रगति बहुत धीमी रही है। परन्तु यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह एक्ट इंग्लैंड के शिक्षा इतिहास का एक स्तम्भ है जिसपर पूरी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आधारित की जाती है और देश ने पूरा प्रयास किया है कि सभी धारों में समता पूर्वक कार्यान्वित हो सकें, परन्तु आर्थिक संकट के कारण यह संभव नहीं हो सका है कि यह पूर्ण रूप से सफल हो सकना। देश जैसे ही उन संकटों से मुक्त होगा वैसे ही इन एक्ट द्वारा इंग्लैंड में शिक्षा उन्नतिशीलता से होगी।

शिक्षा—इन एक्ट के गुण और दोष देखने से पहले इसका इतिहास देखना आवश्यक है।

यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध (१९१४-१८) के कारण देश की सामाजिक तथा आर्थिक दशा में परिवर्तन हो गया था, असंख्य लोगों को सैनिक सेवा के लिये जाना पड़ा था, लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने शिक्षा के प्रति विशेष चिन्ता के कारण सैफ़ोल्ड विश्वविद्यालय से मि० फिशर को बुलाकर शिक्षा मण्डल का प्रधान नियुक्त कर दिया। उनकी कल्पना के आधार पर १९१८ का अधिनियम बना जिसमें उक्त मि० पीज के बिल की बहुत सी बातें सम्मिलित थी। फिशर अधिनियम ने शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने की चेष्टा की।

(१) इसके द्वारा अनुदान प्रणाली में सुधार हुआ—विशिष्ट अनुदान प्रणाली को समाप्त करके “एक पुञ्ज अनुदान प्रणाली” (Block grant system) लागू की गयी जिससे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारों को उच्च शिक्षा के प्रति व्यय किये गये धन का अधा भाग तक अनुदान में मिल सकता था।

(२) फिशर अधिनियम ने सप्ताह में तीन दिन पढ़ने वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा १४ वर्ष से पूर्व किसी भी छात्र को स्कूल छोड़ने की आज्ञा बन्द कर दी तथा १२ वर्ष तक किसी बालक को नौकरी करना अवैध

धोपिय कर दिया। इसमें ऊपर केवल रविवार के २ घंटे नौकरी करने की अनुमति दे दी। लेकिन ६ बजे सुबह तथा ८ बजे शाम के बाद नौकरी की अनुमति नहीं थी।

(३) स्वास्थ्य-निरीक्षण तथा उपचार का विस्तार 'महायन्त्र-प्राप्त स्कूलों' को छोड़कर सभी स्कूलों में हो गया। तथा प्राधिकारों को शारीरिक दोष वाले छात्रों का पता लगाने तथा उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य सौंपा गया।

(४) प्रारम्भिक शालाओं में मुक्त समाप्त कर दिया। लेकिन निर्धन छात्रों को माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य सौंपा गया।

(५) प्रारम्भिक शालाओं में मुक्त समाप्त कर दिया गया। लेकिन निर्धन छात्रों को माध्यमिक शिक्षा-काल में आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई।

(६) सातव्य (Continuation) स्कूल खोलने तथा उनमें १४ से १८ के छात्रों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य-भार प्राधिकारों को सौंपा गया। इनमें छात्रों को वर्ष में ३२० घंटे की उपस्थिति अनिवार्य थी। तथा उन छात्रों के लिये जो १४ वर्ष की आयु के पश्चात् भी पढ़ना चाहते थे उनके लिये अर्ध-कालीन (Part-time) शिक्षा का प्रबन्ध करने की व्यवस्था भी की गई।

(७) इस अधिनियम ने द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के प्राधिकारों को ज्यों का र्यों रहने दिया। लेकिन अध्यापक-प्रशिक्षण, उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं आदि के लिए यदि वह चाहे तो उनके मंडल में मिल जाने की व्यवस्था कर दी। १९२१ के बिल द्वारा उक्त शिक्षा बिल में संशोधन (Amendment) के लिये प्रयत्न हुये जिनके द्वारा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न का हल किया जाना सम्भव हो जाता। इस बिल की धाराओं ने प्राधिकारों के हर प्रकार के स्कूल प्रशिक्षण में सब अधिकार दे दिये। किसी भी अध्यापक को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देने के लिये अब बाध्य नहीं किया जा सकता था। स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तर पर धार्मिक शिक्षा के सुझाव देने के लिये समितियाँ बनाई जाने की व्यवस्था भी और बाहरी व्यक्तियों (Visiting teachers) का इस धार्मिक शिक्षण के लिये पढ़ाने जाने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन यह बिल अधिनियम नहीं बन सका।

शिक्षा का पुनर्संरुद्धन १९१८ के अधिनियम ने कर दिया। २-११ तक पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक तथा उसके पश्चात् १४ या १६ तक शिक्षा का

प्रबन्ध हुआ। जिन छात्रों की शिक्षा में ११ की अवस्था पर तोड़ (Break) सम्भव नहीं था उनके लिये ९ पर इस तोड़ की व्यवस्था कर दी गई। ११ से ऊपर के छात्रों के लिये, जिनके लिये स्थानीय या केन्द्रीय स्कुलो में कोई व्यवस्था नहीं थी, अलग से शिक्षा के प्रबन्ध की भी व्यवस्था हुई।

बर्नहम समिति १९१९-१९२० में दि० पिशा ने एक समिति अध्यापकों के वेतन में सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिये स्थापित की। प्रथम अध्यक्ष लार्ड बर्नहम थे और इसलिये इस समिति का नाम उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी यह समिति उसी नाम से मशहूर है यद्यपि अध्यक्ष अब कोई अन्य व्यक्ति है। १९४४ के शिक्षा अधिनियम ने इस समिति की स्थापना स्थायी कर दी। इस समिति ने अध्यापकों के वेतन में वृद्धि के लिये सुधार पेश किये। इनके द्वारा दी गई वेतन श्रेणी (Payscale) देश भर के अध्यापकों पर लागू हो गई। लेकिन इससे पूर्व अध्यापकों को भिन्न भिन्न प्राधिकारों तथा स्कूलों के प्रबन्धकों से अपने वेतन के लिये लीदेबाजी करनी पड़ती थी। इसका परिणाम स्पष्ट था—अच्छे, धनी स्कूलों में अच्छे अध्यापक तथा अन्य स्कूलों में साधारण अध्यापक आने लगे। साधारण अध्यापकों की दशा प्रथम विश्व-युद्ध की महंगाई ने खराब कर दी थी। उनकी दशा सुधारने के लिये केन्द्र ने १९१७ में १ लाख पाउण्ड का अनुदान भी दिया लेकिन अवस्था में विशेष सुधार न हुआ। बर्नहम समिति ने अध्यापकों के लिये ३ श्रेणियाँ क्षेत्रों के आधार पर बनाई तथा सन्दन के लिये अलग श्रेणी बनाई। लार्ड बर्नहम की अध्यक्षता में माध्यमिक तथा तकनीकी समितियों ने भी सुधार तथा वेतन श्रेणी अनिश्चित की। यह समस्त वेतन श्रेणियाँ १९२१ में लागू हो गईं।

१९२१ तक आते आते देश की आर्थिक दशा खराब हो गई। इसलिये सर एरिक गेड्डेस की अध्यक्षता में एक समिति ने खर्च कम करने के सुझाव दिये जिनसे शिक्षा-विस्तार बड़े दिन के लिये रुक गया। इस समिति के सुझावों को “गेड्डेस का कुल्हाड़ा” (Geddes axe) कहते हैं। इसने १९२८ के अधिनियम के अनुसार निर्धारित अनुदान प्रणाली को बन्द कर देने का सुझाव दिया। ६ वर्ष से कम के बच्चों की स्कूल आने की आवश्यकता को खचीला बताया, तथा अध्यापकों की पेन्शन में सुधार किये। परिणामस्वरूप शिक्षा का व्यय एक तिहाई कर दिया गया।

१९२४ तक बढ़ती हुई माध्यमिक शिक्षा के कारण आवश्यकता महसूस होने लगी थी कि इस स्तर की शिक्षा में सुधार किये जायें। डा० टानी (Tawney) के लेख ‘सेकेन्डरी एजुकेशन फार आल’ ने इस विषय पर निश्चित

प्रकाश होना तथा प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग नहीं एक ही प्रक्रिया के दो स्तर के रूप में बनाया। १९२६ की हेडो रिपोर्ट ने 'प्रारम्भिक शिक्षा' के स्थान पर 'प्राथमिक शिक्षा' शब्द को उचित माना क्योंकि इस प्रकार 'प्राथमिक' तथा 'माध्यमिक' शिक्षा में केवल स्तर का अन्तर रह जाय न कि अन्ध जोई। १९१० के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने की सीमा निर्दिष्ट कर दी। उन्होंने ५ वर्ष से पूर्व उन बच्चों के लिये जिनके घर की दशा ठीक न थी, शिक्षा-दानाओं की खोलने का सुझाव दिया। १९१८ के शिक्षा अधिनियम ने इनकी व्यवस्था की थी किन्तु भाषिक कारणों से इनका खोलना देश व्यापी स्तर पर सम्भव नहीं हो पाया था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ५—७ तथा ७—११ में बाँट दिया। इसके अनिर्दिष्ट अष्टके स्कूल प्रवर्तन, शिक्षा पद्धति, अध्यापक-नियुक्ति आदि के विषय में भी सुझाव दिया। प्रोजेक्ट पद्धति तथा स्त्री-मुख्य अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में उन्होंने सलाह दी।

१९३६ के शिक्षा अधिनियम ने उक्त समिति की बातों को मानकर, विभिन्न सुधार किये। इन अधिनियम ने पाठशाला-व्याप-आयु १४ से १५ वर्ष कर दी। कुछ छात्रों को यद्यपि इस नियम से मुक्त किया जा सकता था। यह उम्र १ सितम्बर १९३६ से लागू होनी थी ठीक उसी दिन द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३६—४५) के दौरान में शिक्षा सम्बन्धी विचार विमर्श बन्द नहीं हुये यद्यपि इंग्लैण्ड पर जर्मनों हमले एक साधारण दिन-धर्म से बन गये थे। सामाजिक जीवन उन दिनों लगभग अस्तम्भर हो गया था तथा ऐसी दशा में आर्थिक कठिनाइयाँ भी स्पष्ट थीं। ऐसे समय में भविष्य में युद्धोपरान्त शिक्षा के लिये आदर्श-प्रणाली बनाने के लिये चेष्टायें हुईं।

१९४१ में शिक्षा मण्डल की ओर से एक प्रस्तावनी प्रकाशित हुई जिसने शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा अंगों की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार एकाग्र किये। इस प्रस्तावनी के हरे आवरण के कारण इसका नाम 'ग्रीन बुक' पड़ गया। यद्यपि यह गुप्त रूप से वितरित की गई थी लेकिन धीरे धीरे इसकी विषय-वस्तु सर्व-विदिन हो गई। न केवल स्थानीय शिक्षा अधिकार, अध्यापक-संघ तथा अन्य शिक्षाविद जिनके लिये यह प्रस्तावनी बनी थी, वरन् अन्य लोगों ने भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करने प्रारम्भ कर दिये। १९४३ के शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ। तथा इसी के आधार पर १९४४ का शिक्षा-अधिनियम अधोपल्लु युद्ध का काली द्रुपि के नीचे प्रकाश-मुञ्ज के रूप में बना।

(ब) माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा :—

इंग्लैण्ड की उत्तर प्रारम्भिक शिक्षा १० वीं शताब्दी में वैसेल या राज्य भवन स्कूलों तथा मठों के स्कूलों से प्रारम्भ होकर जिनमें केवल उच्च वर्ग के छात्र तथा कभी कभी छात्राये पढ़ती थी, आज के सावजनिक माध्यमिक स्कूलों के रूप में आ गई है। उक्त स्कूलों में उदार क्लासों की शिक्षा दी जाती थी जो क्लासिकल या पुराने समय की यूनानी तथा रोम की शिक्षा पर आधारित थी। इनके अतिरिक्त भी शिक्षा का प्रवण था, जो दान दिये गये धन द्वाय कलती, तथा जिम्हे चैरिटी (Chartry) स्कूल कहते हैं। किन्तु इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य शिक्षा का प्रवण न था।

धार्मिक आधार पर होते हुये आवश्यकफंड (११८७) तथा केम्ब्रिज (१२२६) लन्दन के कोनाहल तथा राज्य और धार्मिक प्रभावों से दूर पूर्णरूपेण स्वतन्त्र तथा प्रजातामिक मिडान्तों द्वारा प्रेरित उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। मठों की भाँति यहाँ भी निबन्ध अनिवार्य था लेकिन शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम मठों में भिन्न था। केवल पादरियों के जैसा चौगा (Gown) पहनना मात्र मठों के जैसा था, जो प्रथा आज तक प्रचलित है।

धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खुलने लगे। विन्चेस्टर १३८७, तथा ईटन १४४१ में स्थापित हुये। इनको राज्यकोष से सहायता मिलती तथा इनके स्नातक विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त करते। इन स्कूलों में क्लासिकल शिक्षा पर बल दिया जाता था। लेकिन आवश्यकतानुसार अन्य स्कूल सेम्टपास, धूमरी, मेस्टमिस्टर, मरकेन्ट टेजर्स, रब्बी, हुँरो तथा चार्टर हाउस आदि उक्त दो स्कूलों का अनुकरण, पाठ्यक्रम तथा विद्वविद्यालयों के लिये स्नातक तैयार करने के लिये, करने लग गये। यह स्कूल अठारहवीं शताब्दी तक पब्लिक स्कूल बन गये यद्यपि इनमें जन साधारण के नहीं बल्कि केवल धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियों के पुत्र ही पढ़ने जा सकते थे। लेकिन इन स्कूलों ने सम्म्राट हेनरी के मठों के स्कूलों के अन्त कर देने के परचा शिक्षा का अद्वितीय तथा सफल कार्य किया। यद्यपि इनमें मठिय शिक्षा व्यवस्था का अनुकरण नहीं था।

धनी मध्य-वर्ग तथा अन्य लोगों की शिक्षा के लिये जिनमें उक्त स्कूलों के अतिरिक्त विषय भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे, एक नये प्रकार के स्कूलों का जन्म हुआ जिम्हे चामर स्कूल कहते लगे। इनमें निवास अनिवार्य नहीं था, तथा यहाँ छात्रों को विद्वविद्यालयों में जाने के लिये विरोंप परीक्षा की तैयारी करवायी जाती थी। जमींदारों ने भी अपने स्कूल खोले जो इन्हीं स्कूलों के जैसे थे। इनमें कुछ स्कूल धार्मिक तथा कुछ गैर धार्मिक थे।

१८ वीं शताब्दी के अन्त तक अन्ध शिक्षा की भाँति इस स्तर की शिक्षा में भी परिवर्तन प्रारम्भ हो गये थे । विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिर गया था जैसा हम ऊपर देखा आये है । पब्लिक स्कूलों की शिक्षा समय के साथ बदनी न थी और आलोचना का केन्द्र बन गई थी । लेकिन प्रो० आर्थर ने अपनी पुस्तक "मेकेन्ड्री एजुकेशन इन दी नाइनटीथ सेंचुरी" में इस आलोचना को तर्क संगत नहीं बताया । उनका कथन है कि पब्लिक स्कूलों की स्थापना चार्टर (Foundation Statutes) के अनुसार नवीन विषयों का पढ़ाना अवधानिक था । तथा १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक प्राप्य विज्ञान, रीति और पारमन जैसे ये जो प्राचीन विषयों में पारमन थे और लैटिन तथा ग्रीक विद्या को प्रमुखता देते थे, साथ साथ इन्हीं विद्वानों को आदर्श माना जाता था । फिर उस समय तक बुल्क जैसे माहिर के अलोचक, गेटे जैसे दूरदर्शी, नाइबुर् (Niebuhr) जैसे इतिहास वेत्ता भी उत्पन्न न हो पाये थे । परिवर्तन तो उक्त विद्वानों के कारण ही सम्भव हो पाया क्योंकि इनके कारण अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की नींवें तक हिल गई । प्रो० आर्थर का मत है कि इन पब्लिक स्कूलों की शिक्षा विश्वविद्यालयों से अच्छी थी क्योंकि उनके स्नातक लैटिन तथा ग्रीक को भली भाँति जानते थे । हाँ, वह इतना अवश्य मानते हैं कि पब्लिक स्कूलों के बोर्डिंग हाउस अच्छे न थे तथा उनके यहाँ नीतिवत्ता का स्तर अच्छा न था । इस परिवर्तन के लिये ग्रिग आर्नल्ड, न्यूमेन, बटलर जैसे हेड मास्टर्स की आवश्यकता थी जो १९ वीं शताब्दी में पूरी हुई । शिक्षा अनुशासन तथा चरित्र के क्षेत्रों में इन महानुभावों के विचार तथा व्यवहार अद्वितीय थे और इसीलिये १९ वीं शताब्दी में एकदम परिवर्तन सम्भव हो गया । लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि परिवर्तन आसान तथा बिना विरोध के हो गया । साहित्यिक तथा बलामिक शिक्षा ने नई शिक्षा, जिसमें हाथ कौशल भी सम्मिलित था, से कड़ी टक्कर ली । अन्त में विषय समय के परिवर्तन, आवश्यकता तथा नवीन विचारों की हुई ।

लेकिन योरोप के विभिन्न देशों तथा उनके तत्कालीन विद्वानों का प्रभाव भी इस परिवर्तन के लिये कम जिम्मेवार नहीं । इनमें प्रमुख प्रशिया (Prussia) की शिक्षा की राजकीय व्यवस्था थी जिसके प्रशासकों ने इंग्लैण्ड में बहुत से लेख, भाषण आदि द्वारा नवीन शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया । यैसे हम पहले कुछ पृष्ठों पर १८ वीं शताब्दी की अकादमियों का वर्णन भी कर आये हैं जो कई रूप से इस १९ वीं शताब्दी की शिक्षा की पृष्ठ भूमि का काम करता है ।

इंग्लैण्ड में १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ की तकनीकी तथा औद्योगिक

शिक्षा की बात करते हुये प्रो० स्नो ने कहा है कि जर्मन स्तर इस विषय में बहुत ऊँचा था और जर्मन जब इंग्लैण्ड या अमरीका में इस ज्ञान के साथ पहुँचे तो उन्होंने बहुत घन कामाया। इंग्लैण्ड इस विषय में जर्मनी से बहुत पीछे था और यह बात कई पीढ़ियों तक सत्य रही। इससे स्पष्ट है डा० निकोलस इस का कथन कि १८ वीं शताब्दी में अकादमियों ने बहुत काम किया तथा प्रभाव डाला, पूर्ण सत्य नहीं है। प्रो० नेफ ने इस विषय में यह कहा है कि औद्योगिक क्रांति के लिये केवल कोयले या पानी की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि यह तो इंग्लैण्ड में सर्वत्र से ही थे; परन्तु परिष्कृत मशीनक तथा अनेकों वैज्ञानिकों की सेवाओं की आवश्यकता थी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों से यह क्रांति सम्भव कर दी। साथ-साथ १७ वीं या १८ वीं शताब्दी के व्यक्तियों का भौतिकवाद बनना इस क्रांति का प्रथम तथा प्रमुख चरण था। लेकिन इस परिवर्तन का मूल स्रोत इन्मानी इच्छा थी जिसके कारण मनुष्य समय तथा देश से ऊपर जाकर इतिहास में परिवर्तन ला देता है।

सैंट इंग्लैण्ड की शिक्षा का ध्रुव से चली—विश्व-विद्यालय तथा पब्लिक स्कूल—शोध का रिक्त स्थान धनी: शर्न, बरा। इस शिक्षा व्यवस्था पर विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने प्रकाश डाला तथा सरकारी अवस्था का पूर्ण विवर प्रस्तुत किया।

पब्लिक स्कूलों के दोषों (जिनकी समालोचना एडिनबरा रिव्यू तथा वेस्टमिनिस्टर रिव्यू में होती रहती थी), उनके पाठ्य-क्रम की कठिनायिता तथा अत्यधिक लचके के कारण लार्ड पामस्टन ने क्वेरेन्डन के सभापतित्व में एक आयोग की स्थापना १८६१ में की, जिसने ६ बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों की जाँच की तथा सरकारी नमस्त्राओं पर विचार प्रकट किये। इस आयोग की केवल दो स्कुलों के अनिश्चित अग्र स्कुलों में प्रवेश तक नहीं मिला। इसलिये आयोग ने मुख्याध्यापकों को प्रस्तावली भेजकर तथा माशियों से भेंट करके इन स्कुलों के विषय में मागही एकत्र की। यद्यपि इस आयोग ने सामग्री ६ स्कुलों के विषय में एकत्र की थी लेकिन अधिनियम बनाने पर उसे केवल ७ पर लागू किया। यबेन्ट टेलर्स तथा सेन्टपाल को छोड़ दिया गया। आयुक्तों के सम्मुख जर्मन माध्यमिक स्कुलों (जिम्नेजिया) का आदर्श था।

इन पाठशालाओं में आयोग ने (१) पाठ्य-क्रम में लचीलेपन का अभाव (२) आतसी स्वभाव के छात्र उत्पन्न करना, (३) मास्त्रों के विषयों में अपूर्ण मकनना, (४) आयुक्त भाषाओं, गणित, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों को महत्व न देना आदि दोष बताये। आयोग की इन पाठशालाओं में (१) अध्ये-

अभिषम आदि) ने 'हायर सेन्ट्रल स्कूल' खोले तथा परीक्षा लेकर उच्च बधाओं में शिक्षा देना प्रारम्भ किया। इनको भी अनुदान दोनो ही केंद्रीय विभागों में मिल जाता था। थोड़े समय पश्चात् विज्ञान तथा कला विभाग ने अनुदान अर्जन के लिये गणित, ज्योमिति, रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा कृषि आदि विषय का अध्ययन निश्चित कर दिया।

उक्त पब्लिक स्कूल आयोग की सीमा से बाहर के उच्च स्कूलों की जाँच के लिये एक आयोग १८६४ में बैठा। इसके सम्मति टोन्टन व इसलिये इस आयोग को शिक्षालय जीव या टोन्टन आयोग कहते हैं। इस आयोग ने ४ वर्ष के परिधम के पश्चात् देश-विदेश की शिक्षा-व्यवस्था का अध्ययन करके १८९८ में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने ६०० से ऊपर स्कूलों की जाँच की। वह इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की सीमाओं का ज्ञान लोगों को कम है। माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था दीर्घपूर्ण अपर्याप्त तथा असंगठित है। शिक्षण विधियाँ असम्तोषजनक हैं। छोटे तथा प्राचीन भवनों की दशा बुरी है। पाठ्यपुस्तकों के भागों के परीक्षण के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है। शिक्षार्थी आमर स्कूल के अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा प्रबन्ध शोचनीय दशा में है, और यहाँ भी उम्र शिक्षा का १४ वर्ष की अवस्था तक ही प्रबन्ध है।

उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना (१) दान-व्यवस्था, (२) स्कूलों के हिसाब की जाँच आदि के लिये निवारिण की। उन्होंने परीक्षा परिषद की स्थापना का भी सुझाव दिया जो विद्यालयों तथा शिक्षकों की परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देगी हो। आयोग ने विभिन्न सामाजिक स्तरों के आधार पर विद्यालयों को तीन समूहों में बाँट दिया तथा उनी आधार पर स्कूलों की स्थापना की प्रार्थना की। (१) जहाँ शिक्षालय छोड़ने को उम्र १८ या १९ हो, जो विरक्तिमान्यो तक खैरी शिक्षा दें। (२) जहाँ सीमित साधनों वाले अभिभावकों के १६ वर्ष के बच्चों के लिये—विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य को लेकर मैट्रिक, पलित, मातृभाषा, प्राकृतिक विज्ञान आदि विषयों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाय। (३) तथा, जहाँ निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों के लिये धार्मिक या व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध हो और जहाँ शिक्षा-मय सोरने की आयु १४ वर्ष हो।

टोन्टन आयोग ने पाठ्यपुस्तकों के साधन, अर्थो, बुरे अध्यापकों के अल्पतर तथा दुर्गम बालों शिक्षा आदि को बन्ध निवारित भी की।

इस आयोग का अविवेदन बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसमें भविष्य की माध्यमिक शिक्षा के पुनर्वसन के बीज बोझूद हैं। लेकिन यह भ्रम शिक्षा

व्यवस्था तथा उसके सुझावों में स्पष्ट रूप से झलक रहा था। इस आयोग की सिफारिशों का कोई विशेष परिणाम तो अवश्य नहीं हुआ लेकिन १८६२ में धर्मप्रहार दान शिक्षालय अधिनियम (Endowed Schools Act) अवश्य बन गया, जिसमें इस विषय में दिये गये आयोग के समस्त सुझाव अपना लिये गये।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रायल कमीशन ने जो इस शिक्षा की जाँच करने के लिये १८८२-८४ में बैठे, अपनी दो रिपोर्टें पेश की। इनमें दूसरी रिपोर्ट ने अपरोक्ष रूप से उच्च ग्रेड स्कूलों को स्थान मजबूत करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम मार-मुक्त बनाने में बड़ी सहायता की। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य को माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का अन्तर मान लेना चाहिये। प्राथमिक कक्षाओं में प्रारम्भिक विज्ञान की जो व्यवसायों से सम्बन्धित हो, शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। उन्होंने बर्मिंघम के उच्च स्कूल की प्रशंसा करते हुये रॉफोल्ड तथा मेनचेस्टर जैसे उच्च प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की। जहाँ इच्छुक माता-पिता अपने बच्चों को १४ या १५ वर्ष की अवस्था तक रख सकते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हस्त-कौशल को प्राथमिक कक्षाओं में प्रारम्भ कर देना चाहिये तथा ब्राइंग को साधारण तथा उच्च ग्रेड स्कूलों में धार्मिक तथा ज्योमिति ब्राइंग में गृह-सम्बन्धित कर देना चाहिये।

आयोग की अधिकतर सिफारिशें तकनीकी प्रशिक्षण अधिनियम में जो १८८६ में बना अपना ली गई। इस अधिनियम में १८८८ के अधिनियम में बनी गई समस्याएँ काउन्टी काउन्सिलों को तकनीकी शिक्षा के प्रबन्ध के लिये जिम्मेवार ठहराया।

काम आयोग की अन्तिम रिपोर्ट (१८८८) ने केन्द्रीय प्रारम्भिक स्कूलों के पक्ष तथा विपक्ष में बहुत सी बातें कहीं। अधिकतर आयुक्तों (Commissioners) ने इन स्कूलों को अच्छा बनाया, तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उनका अपरोक्ष रूप से सम्मिलित रहना हानिकारक होगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर को मान लेने के लिये कहते हुये उन्होंने कहा इन उच्च प्रारम्भिक स्कूलों को एक सीमा में ही रखना चाहिये। नियंत्रण छात्रों के लिये इन स्कूलों में विशेष प्रबन्ध होना उचित है तथा इस प्रकार की शिक्षा को माध्यमिक प्राथमिक स्कूल की अन्तिम कक्षा, जिसमें कक्षा ७ में ऊपर के विद्यार्थी अध्ययन कर सकें, जोड़ देना चाहिये। कुछ आयुक्तों ने इन उच्च ग्रेड स्कूलों के प्रचार

तथा प्रोत्साहन का सुझाव दिया तथा यहाँ से छात्रों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिये तैयार करने की सिफारिश की।

यद्यपि अगले दशक में उक्त स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में वृद्धि अवश्य हो गई।

१८६५ में ब्राइस आयोग की नियुक्ति हुई जिसने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करने लिये भविष्य में सुधार के तरीके बताये। यहाँ यह कहना उचित है कि ओरेन्ट जैसे शिक्षा मण्डल के प्रधान के कारण ही १९०२ के शिक्षा अधिनियम में इस आयोग के अभिस्ताव अपना लिये गये अग्यथा यह भी पहले मायोरो की सिफारिशों की भाँति ही निरपेक्ष पड़े रह जाते।

इन समय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में (१) पब्लिक स्कूल जो धनी तथा उच्च वर्ग के बच्चों के लिये थे (२) ग्रामर स्कूल जो मध्यम तथा नये-उत्पन्न धनी वर्ग के बच्चों के लिये किन्तु इनमें कभी-कभी निम्न वर्ग के मेधावी छात्र भी आ जाते थे। तथा (३) तकनीकी और उच्च ग्रेड स्कूल—जिनको बोर्ड तथा विज्ञान और कला विभाग चलाते तथा जिनमें प्रायः निम्न तथा मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। लाटें गोशेन (Goschen) ने 'हिस्की कर' को तकनीकी शिक्षा की प्रगति के लिये देकर १८६० के उपरांत उसे अपूर्व बल तथा स्तर प्रदान किया था। हम लाउन्सेस (Lowndes) महोदय की पुस्तक 'दो साइलेंट रिबोलूशन' के आधार पर उस समय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या २१८ लगा सकते हैं। किन्तु इनमें कदाचित् उक्त उच्च ग्रेड स्कूल सम्मिलित नहीं हैं। वैसे हमें यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि उस समय तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न स्तर नहीं थे तथा एक के पश्चात् दूसरे में छात्र का पढ़ने जाना स्वाभाविक नहीं था। उस समय तक निरीक्षण का भी विशेष प्रबन्ध न था। यद्यपि १२-१३ की अवस्था के पश्चात् अब अधिक छात्र स्कूल में रुकने लगे थे किन्तु उचित पाठ्य-क्रम का प्रदान नहीं हो पाया था। सन् १८८७ में सर फिलिप मेपनस ने उक्त प्रारम्भिक स्कूलों के उचित संगठन की आवश्यकता महसूस कर हेरो प्रतिवेदन को ४० वर्ष पूर्व ही देख (Anticipate) लिया था फिर भी इन दिनों में मराहनीय काम नहीं हो पाया था।

ब्राइस आयोग ने 'इमैलेंट में माध्यमिक शिक्षा की सुसंगठित प्रणाली स्थापित करने के लिये सर्वोत्तम रीतियों' पर विचार किया तथा इसके लिये कुछ आयुक्तों को अन्य देशों में भी भेजा। उन्होंने टोन्टन आयोग के सुझावों को अवहारिक रूप में न माने पर दुसरा प्रकट करने लगे शिक्षा के दो दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया—(१) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की

समय में केन्द्रीय स्कूलों की स्थापना १९११ में प्रारम्भ हुई इन स्कूलों में बहुत से साधारण तथा उच्च प्रारम्भिक स्कूलों तथा संगठित विज्ञान स्कूलों में परिवर्तित हुये थे। इनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को स्कूल के पढ़ाने की सीख के लिये तैयार करना था (The chief object of the Central Schools is to prepare girls and boys for immediate employment on leaving School)। मेन्चेस्टर में ६ स्कूल इसी प्रकार के खोले गये।

इन स्कूलों के अतिरिक्त 'डे टू ड स्कूल' (दिवा-व्यवसायी शिक्षालय), १९०० में पश्चात् में खुलना प्रारम्भ हुए। १९१३ के पश्चात् शिक्षा मंत्रालय ने कुछ वापस बनाये जिनके द्वारा निम्न तकनीकी स्कूलों की स्थापना हुई तथा उनके लिये अनुदान देने की योजना बनाई गई। इन स्कूलों में १३ या १४ वर्ष की अवस्था के छात्र आते थे।

१९१४ के शिक्षा अधिनियम की धारा (Section) २ (१) ने प्रारम्भिक शिक्षा के पढ़ाने के स्कूलों को एक नया मोड़ प्रदान किया जिसने द्वारा उचित आयु पर शिक्षण था। योजना के अनुसार व्यावहारिक शिक्षा (Practical Training) तथा प्रारम्भिक स्कूलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को स्थापित किया। फलस्वरूप शिक्षा मंत्रालय ने अपने उच्च प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी वापस वापस में लिये।

हेरो प्रतिवेदन (१९२६) तक आज आने उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के उच्च स्कूल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने लगे थे। इनमें माध्यमिक स्कूलों (ग्रामर स्कूल) में २५% प्रतिशत मेधावी विद्यार्थी नियत अवधियों के लिये सुरक्षित मुक्त-मुक्त स्थानों की व्यवस्था भी हो चुकी थी। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि इस क्षेत्र में काफी कार्य हो चुका था, हमने लिये केवल स्पष्ट उद्देश्य का निष्कर्षोत्तरण तथा शिक्षा का दिलनाना मान रहा गया था।

हेरो प्रतिवेदन में स्कूल छोड़ने की आयु १५ वर्ष बनाई। उन्होंने 'प्रारम्भिक शिक्षा' के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा शब्द को उचित माना तथा इन १५ वर्ष की शिक्षा का अन्त ११ वर्ष की आयु पर निश्चित किया। ११ की आयु के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिये तथा हमने दो प्रकार के स्कूल होने चाहिये। (१) ग्रामर तथा (२) माध्यमिक स्कूल। पहली प्रकार की स्कूलों में सभी प्रकार के प्राचीन अध्ययन स्कूल, वाउन्ट्री की इन्विजिबल स्कूल आदि सम्मिलित होने चाहिये तथा इनके छात्रों को १६ वर्ष की आयु तक अध्ययन करना चाहिये। मन्चेस्टर में केन्द्रीय स्कूलों को स्थापन करने के माध्यमिक स्कूल स्थापित कर देने चाहिये। उक्त

पाठ्य-क्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बनाना चाहिये। इनका पाठ्य-क्रम व्यावहारिक तथा वास्तविक (Practical and realistic) होना चाहिये। यहाँ छात्रों को १५ वर्ष की आयु तक रचना चाहिये।

हेडो समिति ने प्रारम्भिक पाठशालाओं में नगी हुई उच्च कक्षाओं में छात्रों को लेने की सिफारिश भी की। उन्होंने तत्कालीन 'डे ट्रेड स्कूलों' में १३ वर्ष की आयु के पश्चात् कुछ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजने का भी सुझाव रखा। उन्होंने १९०२ अधिनियम द्वारा स्थापित तृतीय भाग के प्राधिकारों की समाप्ति के लिये भी अभिस्ताव रखा। इनके अतिरिक्त उन्होंने ११-वर्ष की आयु पर छात्रों की शिक्षा के लिये योग्यता, क्षमता तथा रसिक के अनुसार छोड़ने की बात भी कही। समिति ने इस बात पर बल दिया कि माध्यमिक स्कूलों का स्तर समान होना चाहिये।

इस प्रकार हेडो प्रतिवेदन ने साउडेम्स महोदय के शब्दों में माध्यमिक शिक्षा के प्रति विचार को ही बदल दिया तथा उन्होंने आर्थिक पृष्ठभूमि से मुक्त चुने हुये योग्य व्यक्तियों की एक 'औद्योगिक प्रबानन्त्र' के लिये आवश्यकता को मान लिया। (Hadow report in 1926 changed the very conception of secondary education and the need for an industrialised democracy of an elite chosen irrespective of economic background of the parents) शिक्षा मंडल ने उक्त प्रस्तावों में से स्कूल छोड़ने की आयु सम्बन्धी आयु के सुझाव के अतिरिक्त अन्य सुझाव मान लिये। लेकिन बहुत से प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये १९४४ के शिक्षा अधिनियम तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन हेडो प्रतिवेदन में निम्न दोषों के

प्रति कुछ लेखकों ने ध्यान आकर्षित किया है—(१) ग्रामर तथा आधुनिक स्कूल छोड़ने की भिन्न भिन्न आयु द्वारा अमानता की उत्पत्ति तथा (२) ११-वर्ष की अवस्था पर छोड़ का सुझाव देकर मनोवैज्ञानिक भूल करना।

१९३६ के शिक्षा अधिनियम में उक्त अभिस्ताव को स्वीकार करके यह निश्चय किया गया कि १ मितम्बर १९३६ से स्कूल छोड़ने की आयु को १५ वर्ष कर दिया जायगा। कुछ 'विशिष्ट समझौते वाले स्कूलों' (Special Agreement Schools) को सर्व्व का ७५% घन ज्येष्ठ बच्चों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध करने हेतु देना स्वीकृत हुआ। इन स्कूलों की आर्थिक दशा असन्तोषजनक थी इसलिए वह घन राशि स्वीकृत हुई थी। एक धर्म मन्मत पाठ्य-विषय (Agreed syllabus) तैयार किया गया था। यह उन बच्चों के लिये था जिनके माना-गिला साम्प्रदायिक शिक्षा के विरुद्ध थे।

स्पेन्स प्रतिवेदन १८३८ ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया तथा 'आधुनिक-स्कूलों' पर अधिक ध्यान दिया उन्होंने हेमो प्रतिवेदन के माध्यमिक स्कूलों में एक प्रकार के स्कूल और जोड़ दिये। उन्होंने (१) ग्रामर स्कूल, (२) आधुनिक स्कूल तथा (३) औद्योगिक स्कूल को माध्यमिक शिक्षालय माना तथा उनके समान आदर (Parity of esteem) पर बल दिया। स्पेन्स प्रतिवेदन ने औद्योगिक स्कूलों में "निर्गोप-स्थान-परीक्षा" द्वारा प्रवेश पर बल दिया। इन स्कूलों के प्रथम दो वर्षों में ग्रामर स्कूल के पाठ्य-क्रम तथा बाद में औद्योगिक अध्ययन का सुझाव दिया उन्होंने १३-+ पर परीक्षा द्वारा छात्रों के स्कूल परिवर्तन की सिफारिश भी की।

इस प्रतिवेदन में बहुपार्श्व (Multilateral) विद्यालयों की विशेष स्थानों पर आवश्यकता बताई गई जिनमें सभी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा दी जाती हो जिनमें छात्र-संख्या ८०० में कम न हो। उन्होंने व्यापार स्कूलों को इन स्तर की शिक्षा से अलग हो रखने का सुझाव दिया तथा तृतीय भाग के प्राधिकारों के प्रशासन के लिए विभागीय या अन्तर्विभागीय-समितियों का निर्माण करने का सुझाव दिया ताकि विभिन्न स्तरीय शिक्षालयों के सम्बन्ध अच्छे हो जायें।

१८४३ की गौरवुड समिति जो युद्ध की विधौपिका के नीचे बँठी, स्पेन्स समिति की पूरक थी क्योंकि इसने विभिन्न उत्तर-प्राथमिक शिक्षा के रूपों में सम्बन्ध स्थापित करने की बात पर विचार किया। समिति ने छात्रों को तीन श्रेणियों में बाँटा तथा उनके लिए तीन प्रकार के स्कूल उचित बताये, (१) अधिक पुस्तक वाले छात्रों के लिए ग्रामर (२) औद्योगिक या दम्तों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए तकनीकी (३) तथा व्यावहारिक कर्मों के लिए आधुनिक माध्यमिक स्कूल। तीनों स्कूलों को समान आदर देने पर बल दिया। उन्होंने छात्रों को ११-+ से १३-+ तक निम्न कक्षा में रखना इस समय तक समान पाठ्य-क्रम पढ़ाना तथा उसके पश्चात् उपयुक्त स्कूल में भेज देने आदि के सुझाव दिये। उन्होंने ११-+ पर सुझाव तथा सामान्य बुद्धि के पता लगाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा प्रारम्भ करने की सिफारिश की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को ६ भास की लोफ़ मेडा के लिए भेजने की भी सिफारिश की। उन्होंने परीक्षा को पूर्णतया स्कूलों का आन्तरिक मापला बनाने का सुझाव दिया तथा जब तक ऐसा न हो परीक्षाओं तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार पूर्ववत् ही होनी रहनी चाहिये। उन्होंने व्यवस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कारण १८ वर्ष में ऊपर की आयु वाले छात्रों के लिये वर्ष में २ परीक्षाओं के लेने की आवश्यकता बताई तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये स्थानीय तथा राज्य

की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की निष्कारिण की। इसके अतिरिक्त उन्होंने निरीक्षण (Inspectorate) को सम्राट या साम्राज्ञी की निष्ठा सलाहकार सेवा नाम से पुनार देने की मनाह दी। इस समिति की सबसे बड़ी देन माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की सीमा से निकाल कर निदान रूप देना है।

(स) शिक्षा की आर्थिक पृष्ठ-भूमि तथा प्रशासन—

शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि राज्य की ओर से अनुदान १८३३ में प्रारम्भ हो गया था लेकिन १८३६ से पूर्व सरकार की अपनी कोई संस्था न थी जो इस अनुदान के प्रयोग की देख-रेख करती। १८३६ में “ग्रांडर इन काउन्सिल” द्वारा प्रिंसी काउन्सिल की एक समिति को यह कार्य-भार सौंपा गया। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि राज्य का शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप केवल कुछ प्रगतिवादियों को छोड़कर जर्मन-व्यवस्था का अनुकरण सा लगता था। इसलिये उसका काफी विरोध था। इस समिति की स्थापना का विरोध हुआ तथा समय समय पर इसके प्रस्तावों के प्रति रोष प्रकट होता रहता था। १८४६ में शिक्षा विभाग की स्थापना एक अन्य “ग्रांडर इन काउन्सिल” द्वारा हुई। इस विभाग का जन्म विज्ञान तथा कला के प्रोत्साहन देने के लिये हुआ था। यद्यपि ब्रूहम एक “वास्तविक शिक्षा विभाग” तथा साइड डर्बी एक मंत्री की मरसता में शिक्षा का प्रबन्ध चाहते थे किन्तु यह प्रस्ताव समय से बहुत पहले होने के कारण पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति प्राप्त न कर सके। १८७० के शिक्षा अधिनियम ने इस विभाग को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी तथा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया—अब यह प्रारम्भिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार का कार्य करने लगा। इस अधिनियम ने स्थायी स्तर पर स्कूल बोर्डों की स्थापना की। यह बोर्ड केवल उन्हीं रिक्त स्थानों के लिये थे जहाँ ऐच्छिक सच कार्य मफलता से नहीं कर रहे थे। १८७२ से लेकर १८६६ तक के अधिनियमों द्वारा शिक्षा विभाग का प्रशासन-क्षेत्र बहुत बढ़ गया। दो शिक्षा समितियों ने शिक्षा विभाग के कार्य-क्षेत्र पर काफी प्रकाश डाला। दूसरी समिति ने १८६८ के लगभग यह सुझाव दिया कि शिक्षा का कार्य एक मंत्री के द्वारा सम्भाला जाना चाहिये। उसका पार्लियामेंट में सचिव होना चाहिये तथा प्रिंसी काउन्सिल के कुछ सदस्यों को समय समय पर इस मंत्री को महायना प्राप्त होनी चाहिये।

१८६६ में पूर्व शिक्षा विभाग साइड प्रेसीडेंट की अध्यक्षता में चलता किन्तु प्रशासन का वास्तविक काम उप-मुख्याध्यक्ष करता जो प्रेसीडेंट द्वारा अपने अन्य समिति के सचिवों की तरह नियुक्त होना। विज्ञान तथा कला

विभाग प्रेसीडेंट तथा उप-मुख्याध्यक्ष द्वारा संचालित होता लेकिन इस विभाग का सम्बन्ध समिति से नहीं था—इस विभाग की समिति अफसरों की थी तथा उनका एक स्थायी मंत्री था। १८८४ में इसके लिये एक अलग से मंत्री होने लगा।

इस विभाग का कार्य केवल विज्ञान तथा कला की उत्तर-प्रारम्भिक शिक्षालयों को अनुदान देना था। यह एक विशिष्ट विभाग था। इस विभाग ने अपना सम्बन्ध स्थानीय संस्थाओं से जोड़ रखा था जो दान आयुक्तों तथा तकनीकी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करती थी। यद्यपि शिक्षा विभाग की भाँति यहाँ भी अनुदान परीक्षा के परिणामों पर निर्भर थे, लेकिन इस विभाग ने ऐच्छिक स्त्रियों को भी बहुत बल दिया। कभी-कभी इस विभाग का कार्य शिक्षा विभाग के क्षेत्र में भी होने लगता था। उदाहरण के लिये, एक स्कूल अपनी प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये शिक्षा-विभाग तथा उसके पश्चात् विज्ञान की कक्षाओं के लिये जो उत्तर-माध्यमिक स्तर तक की थी, विज्ञान तथा कला विभाग से अनुदान ले सकता था। इस प्रकार शिक्षा विभाग तथा विज्ञान तथा कला विभाग स्वतन्त्र रूप से एक ही स्कूल को सहायता दे सकते थे।

१८९९ में सरकार ने एक केन्द्रीय सत्ता को जन्म दिया। क्योंकि इसके बिना स्थानीय स्तर पर उचित प्रबन्ध असम्भव था। इस सत्ता में विज्ञान तथा कला, शिक्षा, अग्रहार विभाग सभी मिल गये। इस शिक्षा बोर्ड में एक मुख्याध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव, साहें आर्थ ट्रेजरी, तथा चान्सेलर आर्थ एक्सचेंजर सदस्य नियुक्त हुए। अभ्यापक रजिस्टर की स्थापना, एक सलाहकार समिति की नियुक्ति तथा निरीक्षण के विषय में भी नियम कार्य आदि १८९९ के अधिनियम द्वारा हुए।

वाकरटन निर्णय के पश्चात् १९०२ के शिक्षा अधिनियम ने इस समस्या को बढ़ते बढ़ते मुलभाने का प्रयत्न किया। इस अधिनियम ने स्थानीय प्राधिकारों को जन्म दिया। इससे पूर्व ऐच्छिक संस्थाएँ तथा स्कूल बोर्ड शिक्षा कार्य करते थे। हम ऊपर देस आये हैं कि यह व्यवस्था अच्छी न थी लेकिन १९०२ के अधिनियम में बहुत से दोष रहने दिये। बोर्ड की शक्तियों का स्पष्टीकरण तथा उनका स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्ध वही भी प्रकट रूप में वर्णित नहीं था। पन के ऊपर कच्चे के कारण बोर्ड स्थानीय संस्थाओं पर जोर डाल सकता था लेकिन इस अधिनियम में शिक्षा को साझे के रूप (Partnership) में माना गया था जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय मर्यादों दोनों ही सम्मिलित थे। इस अधिनियम के पश्चात् निरीक्षकों को विभिन्न शिक्षा तथा भौगोलिक क्षेत्रों

के अनुसार बाँट दिया गया। उक्त व्यवस्था में सुधार १९४४ के शिक्षा अधिनियम में पूर्व नहीं हुए। (देखिये, 'द बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन' लेखक एल० ए० मेल्वी-विज)।

१८३४ के पूअर ला ऐक्ट में पूर्व इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन के विषे नगरों में स्थानियल कोर्पोरेशन्स, जो कुछ विशिष्ट हितों—जैसे व्यापारी—की रक्षा के लिए थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जस्टिस ऑफ द पीस नामक निर्वाचित शासनाधिकारी थे लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरों की जन-संख्या बढ़ गई थी। नये घनों वगैरह का जन्म हो गया था। गाँवों की आबादी घट गई थी। नगरों में नए प्रकार की समस्याओं का जन्म हो चुका था। 'ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट' में पिस्टर के० वी० स्मिथ ने लिखा है—अब गाँव के बाम्बटेविम (मिथाही) को नगर के गुच्छों में तथा जमींदार को नये फैक्टरी के मालिक से आदर की आशा रखना भूल थी। उक्त अभिनिर्देश (१८३४) ने निर्धनों की समस्या सुझाते तथा उमरी देव-देव के लिए एक स्थानीय व्यवस्था की जन्म दिया। १८३५ में स्थानियल कोर्पोरेशन एक्ट बना जिसने बरबा के विषे शासन व्यवस्था बनाई—यह अधिनियम एक आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अब स्थानीय चुने व्यक्तियों की एक काउन्सिल द्वारा जिसके निधे समग्रत सभी करदाना मतदान कर सकते थे, स्थानियल क्षेत्र का प्रशासन होने लगा। प्रथम बार शासन को व्यापक रूप से अलग किया गया। १८३० के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चुने हुए व्यक्तियों (Ad hoc bodies) द्वारा शिक्षा का कार्य का होने लगा।

१८८० में इंग्लैण्ड के स्थानीय क्षेत्रों की नीचाये अनिश्चित थी तथा प्रशासन भी डंढा-डंढा था। स्पेंडरटन ने १८८४ में सुधार विधेयक पेश करने हुए कहा कि आधुनिक राज्य की शक्ति उसकी प्रतिनिधि प्रणाली में है। १८८८ में यह विधान सभागत क्षेत्रों में लागू हो गया। १८९२ में यह विधान नगरों में लागू हो चुका था। अब चुनी हुई काउन्सिलों द्वारा कामों का प्रशासन होने लगा। इसी प्रकार ग्रामीण, नगरों तथा शहरों की अलग काउन्सिलों ने स्थानीय प्रशासन कार्य सम्भाल लिया। १८९४ में नगरों के शासन को और भी आसान कर दिया गया तथा कामों के शासन में भी सुधार कर दिए। प्रशासनाधिकार आधार और भी विस्तृत तथा व्यापक हो गए। १८३० के शिक्षा अधिनियम तथा १८८९ के मजदूरी की शिक्षा अधिनियम के आधार पर प्रारम्भिक तथा उच्च प्रारम्भिक शिक्षा दी जाने लगी थी। मेरिट इनके संघ तथा प्रशासन अधिकारी प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष थे। १९०१ के फाइनल रिपोर्ट तथा उसके कारण पार विधेयक १९०२ के शिक्षा

अधिनियम ने द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के प्राधिकारों को जन्म दिया (देखिये पृष्ठ १५)। पी० जी० रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक 'डेसिगेशन इन लोकल गवर्नमेंट' में इस अधिनियम को सिडनी वेब के प्रसिद्ध पेम्पलेट 'द एजुकेशन मॉडल एण्ड द वे आउट' (१९०१) से प्रभावित कहा है। वास्तव में इस पेम्पलेट से मुभावो को १९४४ के अधिनियम में आंशिक रूप से माना गया। यद्यपि १९०२ के अधिनियम पर भी उसका प्रभाव पड़ा माना जा सकता है क्योंकि इसने शिक्षा के समस्त अधिकारों को काउन्टी बोरो या काउन्टी काउन्सिलों को देने का मुभाव दिया था तथा काउन्टी काउन्सिलों को अपने अधिकार एक जिम्मेवार समिति को प्रत्येक नगरी क्षेत्र (Urban district) तथा नान-काउन्टी-बोरो में दे देने का मुभाव दिया गया था। कुछ भी हो, इन अधिनियम ने ३२०० स्कूल बोर्डों के स्थान पर ३२८ स्थानीय प्राधिकारों को बना दिया जिससे प्रशासन कार्य आसान हो गया।

लेकिन १९३६ तक आते-आते डूँट शासन प्रणाली आर्थिक कारणों से आलोचना का केन्द्र बन गई। दस वर्ष मई समिति (May Committee) ने आभस्ताव किया कि स्थानीय प्राधिकारों की समस्या घटा देनी चाहिये तथा आर्थिक योग्यता के आधार पर यह निर्दिष्ट होना चाहिये कि अमुक तृतीय प्रकार के प्राधिकार को समस्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार देने चाहिये या नहीं। युद्ध के कारण इन मुभावों को अधिनियम का स्वरूप न दिया जा सका। १९४१ की हरी पुस्तक ने जबकि केन्द्रीकरण पर जोर दिया, १९४३ के हवेल पत्र में स्वर बिल्कुल बदला दिया और विकेन्द्रीकरण को प्रमत्तता दी गई। इस पत्र ने स्थानीय शिक्षा में रुचि को प्राथमिकता दी तथा प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक काउन्टी को क्षेत्रों में बाँट देना चाहिये तथा किसी इलाके को जिसमें १०,००० जनसंख्या हो या जहाँ ७००० बच्चे स्कूल जाने योग्य हों वहाँ शिक्षा के लिये अलग क्षेत्र बनाने का अधिकार होना चाहिये। १९४४ के अधिनियम ने इस विषय में कई महत्वपूर्ण कार्य किये।

१९०२ से पूर्व आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में केन्द्र तथा स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध अस्पष्ट थे। १८७० में पूर्व शिक्षा पूर्ण तथा ऐच्छिक संस्थाओं के हाथ में थी। १८७० में अनुदान तथा कर संग्राने की प्रथा को कानूनी बना दिया। यद्यपि अनुदान अब भी ठीक उसी प्रकार का था जैसा ऐच्छिक स्कूलों को दससे पूर्व दिया जाता था। विशिष्ट सहायता का हितरे बसे हुये इलाकों का प्रबन्ध १८७६ के अधिनियम ने कर दिया। १८८६ में तृतीय शिक्षा अधिनियम ने उच्च शिक्षा के लिये कर तथा गिद्दस्की कर दे

दिया। १९०२ के अधिनियम ने आर्थिक सहायता को सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया तथा अनुदान का निश्चित तरीका बतलाया। १९०१ के आर्थिक अधिनियम ने एक 'पुंजीय अनुदान (Block grant) व्यवस्था' सुझाव दिया था। १९०२ में विनिश्चित अनुदान बन्द कर दिया गया किन्तु १९०६ में आर्थिक कारणों से इसे पुनः चालू करना पड़ा। १९११ में सरकार ने सर जॉन केम्प (Sir John Kemp) की अध्यक्षता में विभागीय समिति को अनुदान व्यवस्था पर विचार करने को कहा। १९१४ में अपने प्रतिवेदन में इस समिति ने सरकार में सीधी अनुदान व्यवस्था (Direct grant) स्थापित करने को कहा। इसके लिये उन्होंने एक जटिल हिसाबी तरीका (Formula) निकाला। मुद्र ने इस अभिस्ताव को कार्यान्वित करने से रोका। लेकिन १९१७ तक सप्लीमेंटरी अनुदान व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के लिये दी जाने लगी थी। शिक्षा-मन्त्रालय की १९५० की अर्थ-व्यवस्था (finance) की रिपोर्ट ने उक्त अनुदानों में दो बातें बताई हैं। (१) केम्प के हिसाब में मसोषन हो चुका था और इसका आधार केम्प समिति के सुझाव ही थे। (२) और, अब अनुदान का आधार स्कूल नहीं समस्त स्थानीय प्रारम्भिक शिक्षा थी।

१९१८ के अधिनियम ने अनुदान व्यवस्था में पूर्ण सुधार किये। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये इस अधिनियम ने भी केम्प तरीके (Formula) को अपनाया। लेकिन १९२१ में गेड्डेस (Geddes) समिति ने निश्चित (fixed) अनुदान व्यवस्था का सुझाव दिया। इसका कारण आर्थिक व्यवस्था बनना नहीं बल्कि धन के व्यय को रोकना था। १९२४ में इस व्यवस्था के स्थान पर 'पुंजी अनुदान' प्रणाली को लाने के प्रयत्न हुये तथा १९२६ में इसे कानूनी रूप मिला गया। १९४४ तक इस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

शिक्षा में निरीक्षण १८३६ में प्रारम्भ होता है। १८३६-४३ के बीच में ऐच्छिक ऐसीसियेशनों ने अपने-अपने निरीक्षण नियुक्त किये थे। १८४३ में डा० एटिलवर्थ ने निरीक्षण का एक प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार प्रत्येक १३३ स्कूल पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होनी थी। इसकी नियुक्ति एच पादरी (Archbishop) की सलाह से होनी थी। शिक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को मान दिया। १८६१ की लो संहिता (Lowe's Code) ने अनुदान को परीक्षा के फल पर देना निश्चित किया। अनुदान अध्यापकों के बराबर स्कूलों को दिया जाने लगा। जिसमें ४ शि० प्रति छात्र की उपस्थिति तथा ८ शि० प्रति छात्र के परीक्षा फल पर अनुदान दिया जाने लगा। फलस्वरूप निरीक्षकों का कार्य बहुत बड़ गया।

१८७० के अधिनियम के पश्चात् ८ सीनियर निरीक्षकों की नियुक्ति हुई

जो १० क्षेत्रों वाले प्रत्येक इलाके के अधिकारी बनाये गये। १८८४ में जान एस० हेरिस की पुस्तक 'ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्स्पेक्शन एंड एडाइनैमिक प्रोसेस' के आधार पर २६१ पुरुष तथा १ स्त्री निरीक्षकों की संस्था थी। लेकिन लो की संहिता ने निरीक्षकों तथा अभ्यापकों के मध्य एक भय की दीवार खड़ी कर दी जो शिक्षा के लिए हानिप्रद थी। साइंस आयोग के सुझावों के आधार पर बने १८९९ के अधिनियम ने केन्द्र में तथा १९०२ के अधिनियम ने स्थानीय स्तर पर एक सुव्यवस्था लाने की चेष्टा की। १९०२-५ में निरीक्षकों का संगठन हुआ। पूरे इंग्लैण्ड को ९ भौगोलिक भागों से बाँटा गया तथा शिक्षा को पाँच हिस्सों में—प्रारम्भिक, माध्यमिक तकनीकी, अभ्यापक-प्रशिक्षण तथा कला। प्रत्येक शिक्षा के अंग के लिये एक मुख्य निरीक्षक, नियुक्त हुआ। प्रत्येक भौगोलिक भाग में एक डिप्टीजनरल निरीक्षक प्रारम्भिक शिक्षा के शासन लिये नियुक्त हुआ और तकनीकी शिक्षा के लिये पाँच डिप्टीजनरल निरीक्षक नियुक्त हुए। मुख्यतया शिशु तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्त्री निरीक्षकों की अलग नियुक्ति हुई।

१९२२ तक इस संगठन में तनिक से ही परिवर्तन हो पाये थे। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अब ५ डिप्टीजनरल निरीक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर के नीचे एक मुख्य डाक्टर, स्त्री सलाहकार डाक्टर, तथा अन्य लोगों ने स्कूलों के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रारम्भ कर दिये। १९२६ में निरीक्षण-विभाग का पुनर्गठन हुआ जिसमें पूरे विभाग को एक कर दिया गया। अब प्रारम्भिक, माध्यमिक, तकनीकी शिक्षा के लिए तीन मुख्यनिरीक्षक होने लगे जिनमें एक सीनियर बाकी दो उसके नीचे काम करने लगे। डिप्टीजनरल इन्स्पेक्टर अब एक दूसरे को अधिक सहयोग देने लगे तथा उनका सीनियर मुख्य निरीक्षक से भी घा सम्बन्ध हो गया। अभ्यापक प्रशिक्षण का कार्य अब भी अलग रहा। १९१३ से सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ हो गई। १९२२-२३ तक निरीक्षण इस प्रकार हो गया था—स्कूल का निरीक्षण, उनका प्रशासन, स्कूल-भरिखा कार्य तथा सलाह देना। प्रायः निरीक्षकों को विशेषज्ञों के रूप में लिया जाता था। इन उच्च कामों के अतिरिक्त निरीक्षक गण स्कूलों की अन्य रिपोर्टों के सम्बन्ध में भी काम करते थे।

१९४४ में एक विभागीय समिति ने कुछ सुझाव रखे उनके आधार पर यह विभाग अब पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है।

अध्याय ४

इंग्लैण्ड का शिक्षा-संगठन

शिक्षा-संगठन और प्रबन्ध की दृष्टि में ब्रिटेन की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देशों की प्रणाली से तीन मुख्य विषयों में भिन्न है। इसकी ये विशेषताएँ हैं जिनका कि पहले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। (१) शिक्षा का विकेन्द्रीकरण (२) शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाली आर्थिक संस्थाओं का महत्व और (३) अध्यापकों को उच्च अधिकारियों के पाठ्य-क्रम, शिक्षा-विधि सम्बन्धी निर्देशों से स्वतन्त्रता है। वह इन बातों में बाहरी अधिकारी वर्ग से निर्धारित नहीं होते हैं।

शिक्षा के लिए, इंग्लैण्ड और वेल्स में केन्द्रीय-अधिकार शिक्षा मंत्रालय की है। सन् १९४४ से पहले इसे 'शिक्षा-बोर्ड' कहा जाता था, और इसका अध्यक्ष 'बोर्ड अध्यक्ष' के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु अब १९४४ के एक्ट के अनुसार 'शिक्षा बोर्ड' का नाम 'शिक्षा मंत्रालय' तथा उसके अध्यक्ष को अध्यक्ष के स्थान पर 'शिक्षा मंत्री' का नाम दिया गया है। मंत्री की महादत्ता ■ लिए एक 'महा-मन्त्रि' होता है। विभाग में स्थायी सरकारी नौकरों का एक दल

1. Board of Education. 2. President of the Board, 3. Parliamentary Secretary.

होता है जिसका प्रधान स्थायी अधिकारी होता है। कार्यकारी दल में प्रधान तथा अन्य अधिकारी होते हैं जिसका प्रधान कार्यालय 'नन्दन' में है। इसके निर्दिष्ट 'विद्या निरीक्षक' जिन्हें 'हूज मैनेस्टीज इन्स्पेक्शन' कहते हैं, व शिक्षा सचिव तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के बीच सम्पर्क-अधिकारियों का काम करते हैं और मुख्य रूप से उन्हें स्थानीय शिक्षा-अधिकारी के साथ में काम करना पड़ता है।

शिक्षा-सचिव को इंग्लैंड और वेल्स के शिक्षा मन्त्रालयों द्वारा निर्देश देने के लिए दो केन्द्रीय मन्त्रालय सम्पादक होते हैं। शिक्षा सचिव द्वारा कुछ एवं शिक्षा-मन्त्रालय प्रदत्तों का उत्तर देना तथा शिक्षा-मन्त्रालय और विद्वानों के विषय में सम्पर्क देना भी इन मन्त्रालयों का कर्त्तव्य होगा। इन मन्त्रालयों के नियुक्ति शिक्षा-सचिव ही करना है, और इसी मन्त्रालय में से एक मन्त्रालय इन मन्त्रालय का सचिव और शिक्षा सचिव का एक अलग इन मन्त्रालय का कार्य करना है।

शिक्षा-सचिव जिन वर्ष अपनी रिपोर्टें मन्त्रालय के मन्त्रालय प्रस्तुत करेगा जिसमें उनके शिक्षा-मन्त्रालयों का पूर्ण उत्प्रेषण होगा। शिक्षा-सचिव का कर्त्तव्य मन्त्रालय में इंग्लैंड और वेल्स की जनता की शिक्षा की उत्प्रेषण करना तथा शिक्षा-कार्य में लगे हुए मन्त्रालयों की उत्प्रेषण तथा सहायता करना और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा मन्त्रालयों में शिक्षा-मन्त्रालयों राष्ट्रीय-नीति का पालन कराना है। शिक्षा-सचिव का कार्य मन्त्रालय द्वारा शिक्षा-प्रसार में सहायता तथा उनकी उत्प्रेषण करना है। यह साफ़ है कि मन्त्रालय का है कि शिक्षा-सचिव की स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के प्रति परामर्श, सहयोग और संचालन भावना रहनी है, अतः ही निष्कर्ष की जायता रही। शिक्षा-सचिव अधिकार और शक्ति होने हुए भी अतः ही सहायता नहीं करना। स्थानीय-शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा उत्प्रेषण के क्षेत्र में शिक्षा सचिव से सम्बन्धित उचित निर्देश सहायता तथा परामर्श और सहायता पानी है। शिक्षा-सचिव अपने तथा अपने विभाग के शिक्षा-मन्त्रालयों का जो के लिए मन्त्रालय के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के सम्बन्धों के सम्बन्ध है। शिक्षा के विवरण-मन्त्रालय पूर्ण सहायता है और 'यूनिवर्सिटी-ग्रांट्स कमीशन' की निर्धारित के अनुसार सीधे राजस्व-स्रोत से उन्हें सहायता मिलनी है। शिक्षा-सचिव का किसी भी शिक्षा-मन्त्रालय पर अधिकार निश्चित नहीं है।

1. Her Majesty's Inspectors 2 Education Officers.

3 Two Central Advisory Councils (one for England and the other for Wales, 4 University Grants Commission

समय-समय पर शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्थानीय शिक्षा अधिकारी को आदेश भेजे जाते हैं। ये आदेश स्थान-नियमों और मन्त्रों विधियों के रूप में होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय का यह परामर्श अध्यापकों के काम के लिए ही होता है। स्कूलों के संगठन और पाठ्य-क्रम सम्बन्धी विषयों में उसका बहुत कुछ प्रभाव रहता है। मंत्रालय के विचार विभिन्न प्रकार से अध्यापकों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों तक पहुँचते रहते हैं।

हर मजिस्ट्रीज इन्स्पेक्टर—शिक्षा-मंत्रालय और शिक्षा अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापना का कार्य करते हैं व मुख्य मन्त्रों स्थापित करने वाले होते हैं। ये निरीक्षक स्कूल के कार्य को देखकर उनका विवरण स्कूल अधिकारियों के पास केवल भेज ही नहीं देते, परन्तु निरीक्षण करते समय अध्यापकों की शिक्षण-विधि आदि के विषय में अलग-अलग परामर्श भी देते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी अनेक विषयों पर शिक्षा-मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकाशन होते रहते हैं जिनमें स्कूल का संगठन, मुख्य विषयों की शिक्षण-विधि और शिक्षा में किसे क्या प्रयोग होते हैं। 'हैंड बुक आफ सजेसन्स फार द टीचर्स' (Hand book of Suggestions for the teachers) आदि लाभदायक प्रकाशन शिक्षा-मंत्रालय द्वारा किये गये हैं।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के विषय में भी शिक्षा-मंत्रालय का बहुत उत्तर-दायित्व है।

शिक्षा-मंत्रालय में और भी अफसर होते हैं जिनमें उप-सचिव, छा' प्रधान सहायक सचिव, एकाउण्टेंट जनरल, वैधानिक परामर्शदाता, सीनियर चीफ इन्स्पेक्टर और चीफ मैडीकल अफसर भी होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय की मुख्य शाखाएँ जिनमें से प्रत्येक एक प्रधान सहायक-सचिव के अधीन होती है, इस से प्रारम्भिक, माध्यमिक अग्रिम, शिक्षा (Further Education), अध्यापक-प्रशिक्षण, अध्यापकों का वेतन, पेंशन और डाक्टरी सेवाएँ आदि हैं।

वेल्स के लिए असल से एक निरीक्षण विभाग है जो अपने मुख्य निरीक्षक के अधीन होता है। इसके निरीक्षणों का भी कर्लैण्ड इंग्लैण्ड के निरीक्षकों के समान ही है, अर्थात् शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण, शिक्षा-सिद्धान्तों और प्रयोगों के विषय में परामर्श देना।

शिक्षा-मन्त्री आज्ञा न पालन करने वाली स्थानीय-शिक्षा अधिकारी को मुधार करने के लिए बाध्य कर सकता है और अपने क्षेत्रों में उन्हें पर्याप्त प्राइमरी माध्यमिक पाठशालाएँ स्थापित करने का निर्देश दे सकता है। 'अग्रिम-शिक्षा' के आयोजन के लिए उसकी अनुमति आवश्यक होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अध्यापक-प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने का आदेश शिक्षा-मन्त्री

दे सकता है। शिक्षा-मंत्री को अधिकार है कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए हुए सार्टीफिकेट को रद्द करदे और उन्हें दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छाताघान की सुविधा का प्रबन्ध करने का आदेश दे। स्थानीय शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्रबन्धकों के मझों या निबटारा करे। किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य का निरीक्षण कराने की आज्ञा शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा दी जा सकती है। यदि मन्त्रालय किसी स्थानीय शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनुचित समझे तब वह उसे रद्द कर सकता है या शैक्षिक अनुमोदन के लिए वह स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी को आर्थिक-सहायता भी दे सकता है। निर्धन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा-आयोजन तथा छात्रवृत्ति भी मन्त्रालय द्वारा दी जाती है, और स्वतन्त्र स्कूलों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी शिक्षालय कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा-मंत्री कभी-कभी स्थानीय शिक्षा अधिकारी को आवश्यकतानुसार विशेष आर्थिक सहायता भी दे सकता है। यदि शिक्षा-मंत्री उचित समझे, तो वह अपने अधिकारों द्वारा दो या उससे अधिक काउन्टी और काउन्टी बोरो काउन्सिल को शिक्षा के हितों के लिए मिला दे और एक संयुक्त शिक्षा-बोर्ड बनादे जिसमें सम्मिलित की हुई कौन्सिलों के प्रतिनिधि हों।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा-मंत्री को हटने अधिकार और नियन्त्रण-शक्तियाँ दी गई परन्तु उन्होंने सभी शक्तियों का शिक्षा-विकास के लिए उचित उपयोग किया। लोगों का आश्चर्य का यह सन्देह कि 'इंग्लैण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-मंत्री कहीं तानाशाही का व्यवहार कर मनमानी न करने लगे', यह भय और सन्देह निराधार और निर्मूल ही रहा। शिक्षा-क्षेत्र में सदैव से पूर्ण स्वतन्त्रता रही, और शिक्षा-शक्ति का विकेन्द्रीकरण ही रहा है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-मन्त्रालय प्रौढ़-शिक्षा, कुछ अशायद्वचरों को आर्थिक सहायता, स्कूलों में भोजन, दूध तथा स्वास्थ्य सेवा आदि की व्यवस्था करने में भी धन सम्बन्धी सहायता देता है। शिक्षा-मन्त्रालय का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध केवल अभ्यापकों के प्रशिक्षण, प्रौढ़-शिक्षा का प्रबन्ध तथा सरकारी छात्रवृत्ति देने तक ही है। इति और टैक्नीकल शिक्षा के प्रति कृषि और शिक्षा मन्त्रालय की सम्मिलित जिम्मेदारी है। विक्टोरिया, अलबर्ट, यूनिवर्सल और नेशनल धीन यूनिवर्सल शिक्षा-मन्त्रालय के अधीन है, जो सी० ई० एम० ए० (संयुक्त और जमा की उन्नति के लिए परिषद्) द्वारा सरकारी बोर्ड से लब्ध भित्तों पर धन के लिए भी समर्थन के प्रति उत्तरदायी है। कुछ बड़े पुस्तकालयों को सहायता भी मन्त्रालय ने मिली है। सभी सार्वजनिक शिक्षा-संस्थाएँ केन्द्र

से आर्थिक सहायता और परामर्श लेकर स्थानीय प्रबन्धकों के अधीन रहती हैं।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी

सन् १९०२ के एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में लोकल एजुकेशन अथोरिटी (Local Education Authorities) की स्थापना हुई।

इंग्लैंड और वेल्स में स्थानीय शिक्षा अधिकारी संस्थाओं की संख्या इस समय १४६ है। इनमें से ६२ काउन्टी काउन्सिल्स और ८३ काउन्टी बरी काउन्सिल्स हैं, इनके अतिरिक्त एक जोइन्ट बोर्ड है जो काउन्टी और बरो दोनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके बनाई गई है। यह कौन्सिलें जनमत से निर्वाचित की जाती हैं। प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी एक या उससे अधिक शिक्षा-समिति स्थापित करके उसे शिक्षा-कार्य देती है। परन्तु कुछ धन सम्बन्धी आय-देन का ब्यारा अपने पाम रखती है। व्यवहार रूप से एजुकेशन-मार्मिंतयो में बहुधा शिक्षा-क्षेत्र में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह काउन्सिल के मेम्बर हों। सन् १९४४ एक्ट के अनुसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र में पूर्ण विस्तार में शिक्षा मुविधा का तीनों स्तरों, प्राथमरी, माध्यमिक और उच्च-शिक्षा, पर प्रबन्ध करे। यूनीवर्सिटी-शिक्षा का आयोजन इसका कर्तव्य नहीं है। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी स्कूल बनानी तथा उन्हें आर्थिक सहायता देनी हैं और शिक्षा-मन्त्रालय के सहयोग और निर्देश के अनुसार शिक्षा का आयोजन तीनों स्तरों (प्राथमरी, माध्यमिक, उच्च-शिक्षा) पर करनी है।

शिक्षा-समिति का मुख्य पदाधिकारी 'चीफ एजुकेशन अफसर' या 'माइनिस्टर ऑफ एजुकेशन' कहलाता है। उसका पद महत्वपूर्ण है, यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्धारण शिक्षा-मन्त्रिणी ही करती है, परन्तु उसका प्रभाव उस नीति पर पर्याप्त रहता है।

यही नीति अधिकारियों गाविसामिट, विनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तथा लोकल एजुकेशन अथोरिटीज के विषय में उम्मेद्व आशयक है। मन्त्रिणी में यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिणी यह निर्दिष्ट करती है कि क्या शिक्षा-कार्य करना है, और शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय-नीति का निर्धारण करती है।

लोकल एजुकेशन अथोरिटीज उस शिक्षा-कार्य को करती है तथा शिक्षा मन्त्रालय यह देखता है कि वह कार्य सबके प्रयोग में

और ठीक प्रगति के साथ किया जा रहा है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के हितों के कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता है और अकारण ही उनके कार्य में मिनिस्ट्री बाधा नहीं पहुँचाती। स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों तथा स्कूलों में पारस्परिक सहायता व सहयोग से राष्ट्र की शिक्षा उन्नति की भावना रहती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के मुख्य निम्नांकित कर्तव्य हैं :—

- १—अपने क्षेत्रों में विद्यार्थियों के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्राइमरी, माध्यमिक, अग्र-शिक्षा (Further Education) का तीनों स्तरों पर पर्याप्त स्कूलों का शिक्षा-आयोजन करना जिससे उस क्षेत्र के निवासियों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताये पूरी हो सकें। पर्याप्त स्कूलों से यह अभिप्राय है कि वह मर्याद और आवश्यक शिक्षा-सामग्री तथा स्तर की दृष्टि से इस प्रकार के हों कि वहाँ के बच्चों की अवस्था, बुद्धि और हवि की भिन्नता के अनुसार उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा कर सकें।
- २—५ साल से कम अवस्था के बच्चों के लिए शिशु-शिक्षालयों (Nursery Schools) की स्थापना आवश्यक क्षेत्रों में करना।
- ३—शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल तथा विशेष शिक्षा चिकित्सा का आयोजन। जिन बच्चों को छात्रावास में रहने की आवश्यकता सरक्षकों और स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा ठीक समझी जाती है, उनके लिए उचित छात्रावास का प्रबन्ध करना।
- ४—स्वैच्छा-संस्थाओं के द्वारा स्थापित किये हुये स्कूलों को आर्थिक सहायता देना।
- ५—हर एक क्षेत्र की भविष्य और वर्तमान-शिक्षा आवश्यकता का अनुमान लगाकर 'विकास-योजना' (Development Plan) शिक्षा-मंत्रालय को एक नियत विधि तक दे देना।
- ६—अपने कर्तव्यों को पूरा करने में होने वाले आय और व्यय का हिसाब।
- ७—मुख्य शिक्षा अधिकारी (Chief Education Officer) की नियुक्ति।
- ८—स्वास्थ्य-मंत्री और शिक्षा-मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर विशेष विवरण प्रस्तुत करना।
- ९—गिरा-मंत्री के आदेशानुसार अध्यापक शिक्षण-कालेज और बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ स्थापित करना।
- १०—आवश्यकतानुसार बालकों के लिए यात्रायात के साधनों की व्यवस्था

करना और उनका गानापात-अप्य देना (उन बालकों के लिए जो स्कूल में अधिक दूरी पर रहते हैं) ।

११—स्कूल-शिविर, खेलने के मैदान, नैरन के गानाव, व्यायामशाला (Gymnasium), मनोरजन के दूसरे माधनो को स्थापित करना । निर्धन बालको के बीमारी के कीटाणुओ म प्रभावित वस्त्रो को स्वच्छ करना ।

१२—नियम के अनुसार स्कूलो और काउन्टी कालेजो के छात्रो के लिए भोजन और दूध का प्रवन्ध करना ।

१३—बालकों के स्वास्थ्य-निरीक्षण और निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करना ।

१४—अग्रिम-शिक्षा के लिए काउन्टी कालेजो की स्थापना उन नवयुवकों के लिए करना जो १५ वर्ष की अवस्था से अधिक हैं और नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ने हैं । १५ से १८ वर्ष की अवस्था तक के लिए बहुधा कालेज स्थापित किये जायें । नवयुवक अवस्था के लोगों के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजनक कार्यों का आयोजन ।

१५—अनिवार्य-शिक्षा-अवस्था (५ से १५ वर्ष तक) वाले बालको के सरक्षको को यह निर्देश करना कि वह अपने बालकों को उचित और पूर्ण समय के लिए पाठशाळाओ में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने भेजें ।

१६—हर एक काउन्टी-स्कूल में स्वीकार किए हुए पाठ्य-क्रम के अनुसार सामूहिक प्रारंभ तथा धार्मिक-शिक्षा का आयोजन करना ।

१७—यह देखना कि शिक्षा-मन्त्री के आदेशानुसार स्कूल-भवन और दूसरो आवश्यक शिक्षा-सामग्री और शिक्षा-स्तर ठीक से रक्खा जा रहा है, अथवा नहीं ।

१८—उन काउन्टी और बोलेन्टी स्कूलों का प्रवन्ध जिन्हें शिक्षा-मन्त्री की आज्ञा द्वारा विशेष रूप से बताया गया है ।

१९—अपने आर्थिक आय-अप्य का ब्यौरा मन्त्रि-मण्डल को दिखाना । मन्त्रि-मण्डल कुछ विषयो को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार रखता है ।

२०—हर मंजिस्ट्रीज इन्स्पेक्टरों के द्वारा अपनी कठिनाइयो को शिक्षा मंत्रालय तक पहुँचाना ।

प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड, 'बोर्ड आफ गवर्नर्स'^१ और प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय का बोर्ड, 'बोर्ड आफ मैनेजर्स'^२ होता है । नये एक्ट के अनु-

1. Board of Governors for Secondary Schools. 2. Board of Managers for Primary Schools.

मार इनकी संख्या छ' से कम नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों की रचना भिन्न-भिन्न स्कूलों के अनुसार विभिन्न होती है लेकिन सभी स्त्री और पुरुष जो इस बौंड में बैठते हैं, प्रभावशाली और स्वाति-श्राप्त होते हैं और स्कूलों के हितों का सर्वत्र ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए पुराने ग्रामर स्कूलों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसके गवर्नरम को पर्याप्त उत्तर-दायित्व होता है, और उन्हें पर्याप्त निर्याय करने की स्वतन्त्रता होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाये और चलाये जाने वाले स्कूलों के सम्बन्ध में उनके अधिकार सीमित होते हैं, तब भी वह स्कूल के लिए पर्याप्त कार्य कर सकते हैं और वास्तव में वह शिक्षा-हित का कार्य करने की अधिक उत्कट अभिलाषा रखते हैं तो वे सह-राष्ट्रिय सम्बन्धी कार्यों में बहुत सहायता कर सकते हैं अतः—नेल, सामाजिक कार्य, नाटक इत्यादि का स्टेज कराना और कबिता या गायन-सम्मेलन इत्यादि।

प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक को अपना स्कूल सगठित करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता है। वह विभिन्न विषयों के विभाग, और प्रत्येक की कितना समय दिया जाता चाहिए वा निर्णय करता है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अकेला या गवर्नरों और स्थानीय शिक्षा अधिकारी की सहायता में सहायक अध्यापकों को चुन लेता है। उसी प्रकार अध्यापक-वर्ग की भी पाठ्य-पुस्तकों के चुनने तथा शिक्षण-विधि के विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता है। इस प्रकार स्थानीय शिक्षा-अधिकारी, गवर्नरम और प्रधानाध्यापकों के सम्बन्ध में तब भी सहयोग-पूर्ण है। यह राष्ट्र का बहुधा माना हुआ सिद्धान्त है "कार्य करने हुए व्यक्ति के कार्य में अक्षरण ही वाधा नहीं पहुँचाई जानी चाहिए।"¹

शिक्षा की आर्थिक-व्यवस्था

शिक्षा पर किये हुये व्यय का अधिकतर भाग सांख्यिक-बोध में मिलता है अर्थात् ससद द्वारा जनता से वसूल किए गए टैक्सों में और इसी प्रकार स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा वसूल किए गए टैक्सों में दिया जाता है इसका समानुपात बराबर २ है। स्वेच्छा प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाए गए कुछ स्कूलों को शिक्षा-संगठन की अधिक आर्थिक सहायता देना है, मुख्य रूप से ट्रैनिंग कॉलेज, पामर-स्कूल, टेक्नीकल और प्रोफ़ो की संस्थाएँ, विशेष प्रकार के विद्यालयों, शिशु पाठशालाओं तथा सुबक मदरसों को जिन वर्गों पर आर्थिक सहायता दी जानी है और जिन सिद्धान्तों पर उनका हितकर सदाया जाना है। व सब शिक्षा-

1. "One must not interfere with the man at wheel,"
W. L. D. Stephens, 1947 p. 22. Orient Longmans & Co.

मंत्रालय द्वारा स्थिर नियमों के अनुसार निर्णित किए जाते हैं। ये नियम बहुत ही सामान्य प्रकार के होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय की यह नीति है कि स्कूलों को चलाने में स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा अध्यापकों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय। किसी शिक्षा-संस्था को सहायता प्राप्त (Grant Aided) उम्मीदना में कहा जाता है जब उसको या तो मंत्रालय से सीधे सहायता मिलती है या स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा समूल किए गए कर (टैक्स) में से सहायता दी जाती है। दूसरी दशा में मंत्रालय उसे सीधे सहायता न देकर स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा देती है जिन्हें स्वीकृत व्यय के अनुसार सहायता दी जाती है। शिक्षा पर हुए व्यय का ५० प्रतिशत शिक्षा-मंत्रालय और ५० प्रतिशत स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बहुधा प्राप्त होता है !!

अध्याय ५ प्रारम्भिक—शिक्षा^१

ब्रिटेन में ५ वर्ष की अवस्था में १५ वर्ष की अवस्था तक बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप में प्रदान की जाती है। पर्याप्त आर्थिक साधनों, स्कूल-इमारतों तथा पर्याप्त मन्त्रियों में अध्यापकों के उपलब्ध होते ही यह आयु-सीमा १६ वर्ष की अवस्था तक बढ़ दी जायगी।

यदि ब्रिटेन के शिक्षा-इतिहास को ध्यान में अध्ययन किया जाय तो ज्ञान होगा कि 'शिक्षा का क्रमिक-विकास और उन्नति' ही वहाँ की शिक्षा-प्रणाली की विशेषता है। इंग्लैण्ड की प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली का आरम्भ बारतव में समानुसार १८ वीं शताब्दी में पहले नहीं हुआ था। आरम्भ में परीरकारी युग में शेरबदा में काम करने वाली महिलाओं में शिक्षा-देना कुछ स्वयं-आरम्भ किए। १८ वीं शताब्दी में चैरिटी-स्कूल की स्थापना 'ईगार्ड-जान' का प्रचार करने के लिए एक मन्त्रा द्वारा की गई। कुछ धार्मिक-मन्त्रियों ने भी कई स्थानों पर स्कूल बनाये। निर्धन विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए

1. Primary Education (according to the Act the word Primary has been substituted for the "Elementary.") 2. Philanthropic Period (1800-1833)

निःशुल्क स्कूलों का आयोजन किया गया। यद्यपि इस समय बहुत से वैंगिश तथा डेम-स्कूल थे, परन्तु अग्रिमता निवारण करने में वैंगिश तथा मन्दे-स्कूलों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। मन्दे-स्कूलों का आरम्भ भवर्त रैम ने सन् १७८० में किया। इन स्कूलों ने अपना कार्य केवल धार्मिक-ज्ञान तथा ही सीमित नहीं रक्खा, परन्तु इन्होंने गणना, विज्ञान और गणित भी सिखाया।

सन् १८०३ ई० में मन्दे-स्कूल-यूनियन ने स्कूलों की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाय। सन् १८११ तथा सन् १८१४ ई० में दो धार्मिक-संस्थाओं—दी नेशनल सोसाइटी फार प्रमोटिंग दी एजुकेशन आफ् दी पुअर तथा ब्रिटिश कोरिन-स्कूल-सोसाइटी की स्थापना प्राइमरी-स्कूलों के आयोजन के लिए हुई। सन् १८३३ ई० में राज्य ने प्राइमरी-शिक्षा में प्रथम बार खर्च दिखाई और पहली बार ही प्राइमरी शिक्षा के लिए खस हज़ार रुपये की निधि प्रदान की। यह धन दोनों संस्थाओं में विभाजित किया गया। इसी अवधि में दूसरी संस्थाओं ने भी कार्य जारी रक्खा, और प्राइमरी शिक्षा के लिए नियमित-रूप में आर्थिक-सहायता का आयोजन किया गया। सन् १८३९ ई० में प्रिवी-काउंसिल की एक विशेष कमेटी की स्थापना की गई जिसका विषय 'इंग्लैंड की जनता की शिक्षा-सम्बन्धी विषयों का अध्ययन था।' सर जेम्स के० शट्टिलवर्थ^१ शिक्षा-सम्बन्धी प्रिवी काउंसिल कमेटी के प्रथम सेक्रेटरी थे। उनकी कार्य अवधि बहुत कम थी, परन्तु उन्होंने इस अल्प समय में इंग्लैंड में प्रारम्भिक-शिक्षा की नींव डाल दी। इसके पहले सर जेम्स-ग्रैहम^२ (१८५३) के विल का आयोजन किया गया था, जिसके अनुसार कारखानों में काम करने वाले बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाय; उनको प्रतिदिन ३ घण्टे शिक्षा प्रदान की जाय और कार्य करने की अवधि कम करके ६½ घण्टे कर दी जाय। राज्य स्कूलों के निर्माण और पोषण के लिए कर्जा देने का आयोजन करे। प्रत्येक विधानसभा की प्रबन्ध-कारिणी समिति में मात ट्रस्टी हो जिसमें एक क्लर्कमेन, एक वर्ष बाईन, मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किये हुये दो ट्रस्टी, तथा एक मिल-मालिक और एक मेम्बर पद-कारणात (Ex-officio) हो। स्कूले अध्यापक इंग्लैंड के वर्ष के सदस्य हों और उनकी नियुक्ति 'विषय' की अनुमति के अधीन हो, इसके पश्चात् सेकूलरिस्ट विम्व का आगमन हुआ तथा १८६१ में न्यू-वेमिल कमीशन

1. Sir James-key-Shuttleworth. 2. Sir James Groham.
New-castle Commission.

किन्ही क्षेत्रों में ये संस्थाएँ अमफल रहें तो यह कार्य स्कूल-बोर्ड्स द्वारा ले लिया जायगा और स्कूलों की जनता-धन (स्थानीय-कर) द्वारा चलाया जायगा ।¹

(2) जिन स्थानों में चर्च-एजेन्सी नहीं थी, वहाँ पर स्थानीय बोर्ड्स स्थानीय कर से प्राप्त हुए धन द्वारा स्कूल स्थापित करें ।

(3) जिन स्कूलों को स्कूल-बोर्ड्स द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हें किसी प्रकार की धार्मिक तथा साम्प्रदायिक-शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जायगी ।*

सन् १८७० के एक्ट ने स्वेच्छा-प्रणाली को समाप्त नहीं किया, परन्तु इसे राज्य-सहायता द्वारा सुसंगठित तथा शक्तिशाली बनाया । साथ ही साथ स्कूल बोर्ड्स द्वारा स्थापित किये हुये स्कूलों की सहायता की । यह डि-प्रणाली ब्रिटेन के शिक्षा-क्षेत्र में कुछ परिवर्तनों सहित आज तक विद्यमान है ।

राज्य द्वारा दिये गये १½ वर्ष के समय में बच्चों ने स्कूलों की स्थापना में बड़ी सीढ़ना और उत्साह से कार्य किया तथा २८८५ नये स्कूल स्थापित किये जिनमें बच्चों की एक बड़ी संख्या प्रविष्ट हुई । सन् १८७३ ई० से एक उपबन्ध लगाया गया जिसके अनुसार १० साल में कम अवस्था के बच्चों को कारखाने में या दूसरी नीकरियों में नें लगाया जाय, और १० वर्ष में १४ वर्ष के उन बच्चों को काम में न लगाया जाय जिन्हें पढ़ने, लिखने और गणित का ज्ञान न हो । अनिवार्य-शिक्षा आयु १८७० ई० में ५ वर्ष में १२ वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य-शिक्षा और बाद में १९०० ई० में बढ़ाकर अनिवार्य आयु-सीमा १४ वर्ष तक कर दी गई । सन् १८८० के शिक्षा-एक्ट के अनुसार प्रारम्भिक-शिक्षा सभी स्थानों में अनिवार्य हो गई । इस प्रकार १८७० ई० के एक्ट ने प्राचीन स्वेच्छा-संस्थाओं और राज्य द्वारा नाबोझिन स्कूल-बोर्ड्स में मार्मन्त्रय स्थापित किया : इस विन द्वारा गुरे देश को स्कूल-शिक्षित करने में

1 Forsters expressed "We propose to complete the Present voluntary system to fill gaps, sparing the public money where it can be done without, procuring as much as we can the assistance of the parents and welcoming as much as we rightly can the Co-operation and assistance of those devoted men who desire to assist their neighbours."

2 The famous 'Cooper Temple' clause stated, "No religious catechism or religious formula which is distinctive of any particular denomination shall be taught." (Education Act. 1870.

विभाजित किया गया और एक नये स्थानीय अधिकारी (स्कूल-बोर्ड्स) की स्थापना की गई । ये स्कूल-बोर्ड्स केवल उन स्थानों में स्थापित किये गये जहाँ स्वेच्छा से प्रेरित होकर काम करने वाली संस्थाओं के प्रयत्न किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को सफलता से पुरा नहीं कर सकते थे । इस एक्ट द्वारा पर्याप्त स्कूल स्थापित किए गए और इंग्लैंड शिक्षा-क्षेत्र में रुच इत्यादि दूसरे योरोपीय देशों से पीछे नहीं रहा । स्कूल-बोर्ड्स ने स्वेच्छा-संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया और तबों द्वारा बहुत से स्कूल स्थापित किए गए ।

क्रोस-कमीशन (१८८८) ने प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिये सुझाव दिए । स्कूलों में योग्य अध्यापकों की आवश्यकता, विरवविद्यालयों में अध्यापक-प्रशिक्षण कासेजों की स्थापना तथा पाठ्यक्रम में सुधार पर अधिक जोर दिया गया ।

सन् १८९१ के की स्कूनिंग एसीमेन्टरी एजुकेशन एक्ट के अनुसार मरछकों को अपने बच्चे नि.शुल्क पढ़ाने का अधिकार दिया गया । ३ वर्ष से १५ वर्ष तक के पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को १० दिनिंग की सरकारी आर्थिक सहायता दी गई ।

१९०२ के शिक्षा-एक्ट द्वारा स्कूल-बोर्ड्स को समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी की स्थापना की गई । इनका नाम काउन्टी-बाउमिस्ल^१ और काउन्टी-बोरो काउमिस्ल था ।^२ यह अधिकारी अपने क्षेत्र की शिक्षा आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर, बोर्ड आफ एजुकेशन के सहयोग से शिक्षा का आयोजन करे । इस एक्ट द्वारा पाठ्यक्रम में भी सुधार किया गया । शारीरिक-शिक्षा पर अधिक महत्व दिया गया और स्कूल पाठ्यक्रम में भूगोल, इतिहास, विज्ञान, इस्तकसा, बागवानी को भी पढ़ने, लिखने और गणित के साथ सम्मिलित करने का आयोजन किया गया ।

सन् १९१८ में और भी अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । शिक्षा-एक्ट (१९१८) द्वारा प्रारम्भिक-स्कूलों में फ्रीग सेवा समाप्त कर दिया गया । अर्थात् शिक्षा नि.शुल्क हो गई और स्थानीय शिक्षा अधिकारी को २ साल से ५ साल के बच्चों के लिए नर्सरी-स्कूलों के आयोजन करने का निर्देश दिया गया ।

1. The Local Education Authority for the county will be the "County Council" and for the Country borough, it will be known as "County borough Council.

2. Borough is the town having more than 50,000 population.

आशिक-रूप से बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में समाप्त कर दी गई और उन्हें पूर्ण समय १४ वर्ष की अवस्था तक स्कूल में रहना अनिवार्य कर दिया गया। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु-सीमा १५ वर्ष तक करने का अधिकार दिया गया।

तत्पश्चात् हैडो-कमीशन (१९२६) ने दंगलिश शिक्षा-प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। पुरानी प्रारम्भिक प्रणाली को पुनर्संगठित कर प्राइमरी-स्तर के लिए ५ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आत्म-निर्भर प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया और ११ वर्ष की अवस्था के बाद के विद्यार्थियों के लिए मिश्र-मिश्र प्रकार के अलग आत्म-निर्भर माध्यमिक-विद्यालय स्थापित किये जाने की सिफारिश की। ११ वर्ष की अवस्था के समय बच्चे विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा बौद्धिक-मिश्रता के आधार पर प्रविष्ट हों। बालकों की ऊपरी आयु-सीमा १५ वर्ष तक बढ़ा देने की भी सिफारिश इन कमेटी ने की जिससे ४ वर्ष तक यह शिक्षा निरन्तर बालक प्राप्त कर सकें। मई १९३३ की स्पेन्स-रिपोर्ट ने टेक्नीकल हाईस्कूल की स्थापना का सुझाव रखा, इसके पहले १९३६ के शिक्षा-एक्ट ने स्कूल छोड़ने की अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाना चाहा, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होने के कारण इसके बटुन से उपदन्धों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

१९४४ का शिक्षा एक्ट और वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा—इस महान शिक्षा-एक्ट ने शिक्षा के तीनों स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च-शिक्षा) को प्रभावित किया और इङ्ग्लैण्ड में शिक्षा के पुनर्निर्माण द्वारा देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उन्नति की नींव डाली। विश्व के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट कम मिलते हैं H. C. Dent ने कहा है—“The Act makes possible as important and substantial an advance in public education as this country has ever known.”

यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस महान् एक्ट ने प्राइमरी-शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला और इसके अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली क्या है।

इस एक्ट द्वारा वह आयोजित किया गया कि २ साल से ५ साल के बच्चों के लिये स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा नर्सरी-स्कूलों की स्थापना की जाय। इनमें बच्चों की उपस्थिति ऐच्छिक होगी, अनिवार्य नहीं। नर्सरी-स्कूलों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जहाँ उनकी वास्तविक आवश्यकता अनुभव की जायगी, उदाहरण के लिए औद्योगिक-क्षेत्रों में जहाँ मानव्य कारखानों में, या दूसरे प्रकार की नौकरियों में संलग्न रहती हैं और बच्चों की टीक देल-भाज

नहीं कर सकती हैं। ऐसे बच्चों का धरेलु वातावरण उनके विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है, नर्सरी स्कूल इस वातावरण सम्बन्धी कमी को पूरा कर बच्चों के प्रारम्भिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। /

१९४४ एक्ट ने नर्सरी स्कूलों की आयोजना स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य और उत्तरदायित्व बनाया।

नर्सरी-शिक्षा का आयोजन स्थानीय शिक्षा-अधिकारी ने द्वितीय महायुद्ध के बाद विस्तृत ढंग से किया। शिक्षा-शास्त्रियों के मत में नर्सरी और इनफैंट स्कूल ही भविष्य में प्राप्त की जाने वाली उच्च शिक्षा की नींव डालने हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नर्सरी-स्कूलों की स्थापना सबसे पहले सन् १९११ ई० में राइकेल और भारगेट मैकलिन ने इंग्लैंड में की थी। कुछ समय तक बोर्ड आफ एजुकेशन ने ५ वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों की स्कूल-उपस्थिति की अच्छा नहीं समझा और इनको अधिक उस्ताहिन नहीं किया तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में ऐसे बालकों के प्रवेश के लिए आदेश नहीं दिया; परन्तु ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता वास्तव में औद्योगिक क्षेत्रों में थी। सन् १९१८ में श्री फिडर ने इंग्लैंड में स्वेच्छा गृहस्था द्वारा स्थापित नर्सरी स्कूल देखा और उनके कार्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए, इस पर सन् १९१८ में फिडर-एक्ट द्वारा स्थानीय शिक्षा-अधिकारी को नर्सरी स्कूल स्थापित करने के अधिकार दिए। सन् १९३६ में नर्सरी स्कूलों की वृद्धि होकर उनकी संख्या ११४ तक पहुँची, इनमें से आधे से अधिक स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाले परोपकारी लोगों और संस्थाओं द्वारा चलाये जाते थे। ६० से ८० बालकों की संख्या वाले पृथक् नर्सरी स्कूल आदर्श समझे जाते हैं क्योंकि उनमें बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। कुछ समय बाद दो साल से ५ साल के बालकों के लिए स्थापित किए जाने वाले ऐसे स्कूलों को सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। कुछ ऐसे अध्यापक-प्रशिक्षण विद्यालयों की भी स्थापना की गई जहाँ भविष्य में नर्सरी-स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय।

इस समय इंग्लैंड में स्कूलों की व्यवस्था अच्छी और आदर्शपूर्ण है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने नर्सरी-शिक्षा को शिक्षा-प्रणाली में मिलाकर उसे एक 'विशेष प्रकार की सेवा' से कलन कर दिया। इस समय यह अनुभव किया गया कि घर के अधिक सहयोग से नर्सरी-स्कूल के काम करने का उद्देश्य छोटी अवस्था में ही बालकों का उत्तम विकास करना है और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और प्रगल्भ प्रारम्भिक जीवन निश्चित हो जाता है। जहाँ नर्सरी-स्कूल उत्तम रूप में चल रहे हैं वहाँ बालक स्वस्थ, मजबूत, आत्म-

आधिक-रुप से बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में समाप्त कर दी गई और उन्हें पूर्ण समय १४ वर्ष की अवस्था तक स्कूल में रहना अनिवार्य कर दिया गया। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु-सीमा १५ वर्ष तक करने का अधिकार दिया गया।

तत्पश्चात् हैबो-कमीशन (१९२६) ने इंग्लिश शिक्षा-प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए। पुरानी प्रारम्भिक प्रणाली को पुनर्संगठित प्राइमरी-स्तर के लिए ५ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आरम्भ-निर्भर प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया और ११ वर्ष की अवस्था के बाद के विद्यार्थियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलग आरम्भ-निर्भर माध्यमिक-विद्यालय स्थापित किये जाने की गिफारिश की ११ वर्ष की अवस्था के समय बच्चे विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में अपनी स्थिति-गत आवश्यकताओं तथा बौद्धिक-भिन्नता के आधार पर प्रविष्ट हों। बालकों की ऊपरी आयु-सीमा १२ वर्ष तक बढ़ा देने की भी गिफारिश इस कमेटी ने की जिसने ४ वर्ष तक यह शिक्षा निर्भर बालक प्राप्त कर सकें। सन् १९१८ की हेग-रिपोर्ट ने टैक्नीकल हार्डस्कुल की स्थापना का सुझाव रखा, इसके पक्ष में १९१६ के शिक्षा-एक्ट ने स्कूल छोड़ने की अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाया जाह, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के कारण इसके बहाने में आवश्यकता को कार्यरित नहीं किया जा सका।

१९०६ का शिक्षा एक्ट और वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा—इस महान शिक्षा-एक्ट ने शिक्षा के तीनो स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च-शिक्षा) को प्रभावित किया और इंग्लैण्ड में शिक्षा के पुनर्निर्माण द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक उन्नति की नींव डाली। विश्व के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्त्वपूर्ण एक्ट कम मिलते हैं H. C. Dent ने कहा है—'The Act makes possible an important and substantial advance in public education as this country has ever known.'

यहाँ पर हमें केवल यह देवना है कि इस महान् एक्ट ने प्राइमरी-शिक्षा पर बड़ा प्रभाव डाला और इसके अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली क्या है।

इस एक्ट द्वारा यह आशयित किया गया कि ५ साल से ५ साल के बच्चों के लिए स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए। इनमें बच्चों की उपस्थिति लेब्लिग होनी, अनिवार्य नही। नर्सरी स्कूलों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाही उनको वास्तविक आवश्यकता अनुभव होवनी, उदाहरण के लिए ओल्डहैम-क्षेत्रों में जाही मान्य कारणों द्वारा प्रसार की नीतिरिक्तों में सम्मिलित नही है और बच्चों की

पेन्टिंग ड्राइंग, सुन्दर गीत तथा नृत्य आदि में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सलग्न रहते हैं। वास्तव में यह धारणाओं तथा स्वस्थ आदतों के निर्माण का समय है। मायाश्रिक, व्यवहार तथा शारीरिक स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है इस प्रकार के स्कूलों की संख्याएं बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही हैं १९३६ में यह संख्या १२० थी, परन्तु यह बढ़कर १९५६ में ४०५ हो गई।

नर्सरी स्कूल

१. Maintained nursery Schools

(स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा
द्वारा स्थापित तथा पूर्ण रूप से
आर्थिक प्राप्ति)

२ Grant in aided nursery schools

(स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा
आर्थिक आर्थिक सहायता
सहायता प्राप्ति)

ये स्कूल योग्य शिक्षा-निरीक्षकों की देख रेख में काम करते हैं (Qualified superintendent teacher) अधिकांश से अधिक बच्चों की संख्या एक कक्षा में २० होती है। यह संख्या प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं से १० कम होती है।

इंग्लैंड स्कूल नर्सरी शिक्षा—(२ साल से ५ साल तक) समाप्त करके बच्चे इंग्लैंड-स्कूलों में प्रविष्ट होते हैं। किंग्डी जगहों में इन इंग्लैंड विद्यालयों में ही नर्सरी-कक्षाएं होती हैं। इन स्कूलों में बच्चे ५ वर्ष की अवस्था से ७ वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करते हैं। ये इंग्लैंड विद्यालय कहीं पर पृथक् और आत्म-निर्भर होते हैं और कहीं-कहीं पर जूनियर-स्कूल के साथ ही होते हैं। इंग्लैंड स्कूलों में बच्चे पढ़ना, निलना और गणित सीखते हैं, इसके साथ-साथ गाना, खेलना और हस्तकर्म का महत्त्व अधिक रहता है। पढ़ाई की विधियों में एकलपठ नहीं होती है परन्तु इंग्लैंड और जूनियर स्कूलों में अधिक सत्रिय-विधि द्वारा अध्ययन प्राप्ति की जाती है। जहाँ पर परिस्थितियाँ उपयुक्त हों, वहाँ विभिन्न स्कूल विधियों में सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और बच्चों के जीवन अनुभव के साथ ही अधिक धनिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इंग्लैंड स्कूलों में बच्चों के ज्ञान-अनुभव-आत्म-प्रेमीय सम्बन्ध का विकास करना, श्रम तथा निरीक्षण-शक्ति को जागृति करना एवं ज्ञानको के सम्बन्ध-बोध को बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। नर्सरी स्कूलों की तरह बच्चों में अच्छी आदतों का विकास भी इनका उद्देश्य है। इंग्लैंड के इंग्लैंड स्कूल उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण-जीवन की तैयारी के स्थान हैं जहाँ प्रत्येक बच्चे का उपयुक्त शारीरिक एवं मानसिक-विकास हो सकता है और उसकी आवश्यकता-निर्धारण और आध्यात्मिक चेतना बढ़ सकती है। ये शक्तिपूर्ण आवश्यकता-

मुनाफ़ नैसर्गिक-रूप में उसमें विकसित होती है। ऐक्टिविटी-मेथड में बालक वातावरण उसके पूर्ण विकास में सहायक और उत्साह-बर्धक होता है। बालक के अनुसार प्रगति करने है, उनको कोई विमोह बौध्दिक मिथ्याया जाता और संगीत, कठानों व शारीरिक व्यायाम जैसे सामूहिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिसमें उन्हें सामाजिक उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव प्राप्त होता है।

नर्सरी-शिक्षा ऐन्ड्रिक थी, आवश्यक प्राथमरी शिक्षा ५ वर्ष की अवस्था से आरम्भ होती है। ७ या ८ वर्ष की अवस्था के बीच इन्फेन्ट स्ट्रेज समाप्त हो जाती है और उनके बाद Junior education शुरू होती है। कभी कभी यह अलग अलग स्कूल-भवनो में आयोजित होती है।

सभी इन्फेन्ट स्कूलों में सह-शिक्षा (Co-education) का आयोजन होता है और बहुधा महिलायें अध्यापन कार्य करती हैं।

इन्फेन्ट स्कूल की प्रथम वर्ष की शिक्षा नर्सरी-स्कूल से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बच्चों के कार्य अधिक सुस्यवस्थित होने लगते हैं। यहाँ formal-learning आरम्भ होता है। स्वतन्त्र खेल का आयोजन तो रहता ही है, परन्तु उसकी व्यवस्था अधिक नियोजित होने लगती है। बच्चों की नये अनुभवों के आनन्द प्राप्त करने की उत्सुकता तथा उन अनुभवों की खोज की उत्सुकता को कभी भी इन स्कूलों में दबाया नहीं जाता है। यहाँ बच्चों को ऐसे वातावरण से परिचित कराया जाता है जिसमें वे विकसित हो सकें, अपने वातावरण में खोज कर सकें और विभिन्न प्रकार की सामग्री से वस्तुओं का निर्माण कर सकें, अपनी बढ़ती हुई शारीरिक-कुशलता को गायन में तथा मातृ-भाषा के उपयोग तथा आनन्द में प्रयोग कर सकें। जैसे ही बच्चा लिखने, पढ़ने, तथा गिनने के सीखने के लिये तैयार हो जाता है, यह उसे पढ़ाया जाता है। शिक्षा विधियों की विविधता रहती है। यह वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा कठिन होता है कि यह ज्ञात कर लिया जाय कि बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से कब सीखने, पढ़ने, लिखने और गिनने के लिये तैयार है। इस स्कूल का सबसे कठिन कार्य यही है। यहाँ के अध्यापक बड़ी ही सतर्कता और उत्सुकता से बच्चों में 'signs for readiness of learning' (सीखने की तैयारी के चिन्ह) देखने का प्रयत्न करते हैं, और उनके कमरों को ऐसी सामग्री से भर देते हैं जिससे सीखने के लिये बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। नर्सरी स्कूल की तरह स्वस्थ आदतों को निर्माण और सामाजिक प्रशिक्षण को लगातार ध्यान मिलता रहता है।

इंग्लैंड में इन्फेन्ट स्कूल (५-७) प्रायः अलग-अलग हैं लेकिन कुछ जूनि-

पर स्कूलों के साथ भी जुड़े हुये हैं। युद्धोपरान्त १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार घनाभाव के कारण सब प्रबन्ध करना असम्भव था। आज इस दशा में बड़े ही महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। नये स्कूलों का प्रबन्ध हो रहा है और नये प्रयोगों से पाठन-विधि की गति दी जा रही है।

जूनियर स्कूल—७ वर्ष से ११ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों का प्रबन्ध जूनियर स्कूलों में किया जाता है। कभी-कभी यह पृथक होते हैं और कहीं पर नर्सरी-कक्षा और इन्फैंट स्कूल के साथ होते हैं। जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, ५ से १५ वर्ष की अवस्था तक किसी भी प्रकार के प्राइमरी स्कूलों में जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाये जाते हैं, पढाई की फीस नहीं ली जाती है। निर्धन विद्यार्थियों के लिए स्कूल-भोजन की व्यवस्था भी की जाती है।

जूनियर-स्कूलों में बालकों की सबसे लम्बी और अन्तिम प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, इनमें बालक शिशु-अवस्था में भर्ती होते हैं और बड़े होकर स्कूल छोड़ देते हैं। यही बालकों को घर की अपेक्षा अधिक जगह मिलनी है, उन्हें सीढ़ने, कूदने और स्पोर्ट्समक खेल खेलने का अवसर मिलना है। उनसे अभिनय कराने के साथ कहानियाँ कहलाई जाती जाती हैं, और इसके लिये आवश्यक सामान दिये जाते हैं। बालक अपने आम-यास की दुनियाँ की खोज करते हैं। प्रकृति-निरीक्षण का इसमें बहुत महत्त्व है। जूनियर विद्यालय उन्हें आम पास की वस्तुओं को देखने, निरीक्षण करने और समझने में सहायता देना है। बालक मातृभाषा का प्रयोग सीखते हैं। मुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना आदि कार्य सिखाये जाते हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, प्राइमरी-शिक्षा को समाप्त करने के बाद बालकों में शिक्षा के प्रति काफी रुचि उत्पन्न हो जाय, और सामग्री तथा विभिन्न यन्त्रों के प्रयोग से उन्हें आत्म-विश्वास हो जाय जिससे वह अवसर हो सके। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित, संगीत, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि विषय इन विद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं। सड़कियों को गृह-बसा, भोजन बनाना और कपड़े धोना भी शामिल है। बागवानी तथा अन्य कार्य भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षक बालकों को ज्ञान की खोज करने में सहायता करता है। बालकों को भावनाओं प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न हुए गुण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चा में अपने को प्रकट करना शिक्षा सम्बन्धी विषयों को जानने का प्राकृतिक साधन ही नहीं है बल्कि इससे सामाजिक सम्बन्धों की समस्याओं को हल करने में भी बालकों को आत्म-विश्वास हो जाता है।

✓ प्राथमरी-शिक्षा—

२ वर्ष से ३ वर्ष तक के बालकों के लिए—

पृथक् नर्सरी-स्कूल, नर्सरी-शालाएँ ।

बालकों की उपस्थिति-ऐन्ड्रॉल

५ वर्ष से ७ वर्ष तक के बालकों के लिए—

+

इनफैंट-स्कूल, अनिवार्य उपस्थिति ।

७ वर्ष से ११ वर्ष तक के बालकों के लिए—

+

जूनियर स्कूल, अनिवार्य उपस्थिति ।

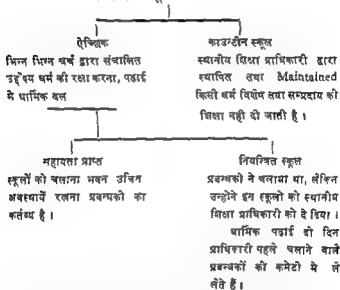
उपयुक्त विद्यालय पृथक् भी होते हैं तथा एक दूसरे से सम्बन्धित एक ही विद्यालय-भवन में भी होते हैं ।

जूनियर-स्तर पर कार्य अधिक नियमित होने लगता है और बच्चों से आशा की जाती है वे तिसरा, पढ़ना, तथा गणित लगाना सीखें, भूगोल, इतिहास का आरम्भ किया जाता है, और बच्चों की अवस्था के उपयुक्त शारीरिक क्रियाएँ भी शामिल की जाती हैं । बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर ही यह जूनियर स्कूल शिक्षा देते हैं । प्रत्येक जूनियर स्कूल के प्रबन्ध का मुख्य उत्तरदायित्व वहाँ के प्रधान या मुख्याध्यापक पद ही रहना है । छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार भेजा जाय, यह उसकी जिम्मेदारी है । अध्यापकों के सहयोग से स्कूल का पाठ्यक्रम निश्चित करना तथा अध्यापकों के कार्य का निरीक्षण करना उसी का कार्य है । विभिन्न स्कूलों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता पाई जाती है, और किन्हीं दो स्कूलों का पाठ्यक्रम एकसा नहीं है । पाठ्यक्रम में बहुत लचीलापन है क्योंकि प्रत्येक हैडमास्टर अपने आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का आयोजन करता है, इसीलिये इस क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है । यह लचीलापन ही इंग्लैंड की शिक्षा की शक्ति तथा प्राण है । “विषयो से हटकर शिक्षा में बालक पर दिया जाने लगा है । स्कूल का काम छात्रों के लिये ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये ही उपयुक्त हो, जिससे द्वारा स्वस्थ — विकास सम्भव हो, ताकि छात्रों की आवृत्ति, कौशल, Skill, ज्ञान, रुचि तथा मस्तिष्क का भ्रूणव अच्छे और पूर्ण जीवन के योग्य हो सकें, और स्कूल को व्यवहार, प्रदत्त तथा सफलता के लिये ऐसा पैमाना देना चाहिये जिससे प्रत्येक छात्र अपने आचार विचार को उसके अनुसार जान सके, छात्रों में केवल ज्ञान इकट्ठा

करना नहीं, परन्तु क्रिया और अनुभवों द्वारा उनका विकास करता ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है।

प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः छात्र संख्या ४० से अधिक नहीं होती। लेकिन कभी-कभी स्थानाभाव तथा अध्यापकों के अभाव में यह संख्या बढ़ता जाती है।

प्राथमिक स्कूलों का संगठन



मह स्मरण रहे कि शिक्षा में लचीलापन, छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान, अध्यापकों की राय का महत्व, मनोविज्ञान की खोजें, स्थानीय शिक्षा प्राधिकार तथा शिक्षा-मन्त्रालय का अपने कर्तव्य का ध्यान आदि बातें इस इंग्लैंड की शिक्षा-प्रणाली की विशेष बातें हैं।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी (प्राधिकारी) द्वारा चलाये गये उपर्युक्त विद्यालयों में शिक्षा नि शुल्क दी जाती है।

११ वर्ष की अवस्था के बाद प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके (११+Plus) परीक्षा के निर्णय के द्वारा तीन विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाते हैं।

अध्याय ६ माध्यमिक-शिक्षा

‘माध्यमिक शिक्षा सभी बच्चों का प्राप्त होनी चाहिये’ ब्रिटेन का यह आदर्श शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जा रहा है। १९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार यह शिक्षा पृथक स्कूलों में बच्चों की अवस्था, मानसिक-शक्ति तथा अभिरुचि के अनुसार दी जानी चाहिये। ११ वर्ष की अवस्था के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके बच्चे अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार आवश्यक विभिन्न प्रकार के पृथक-पृथक माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने जाते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अवसर समानता मिलनी चाहिये, परन्तु शिक्षा में अवसर-समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी को एकात्मक शिक्षा-अवसर दिये जाय और बच्चों की बौद्धिक-भिन्नताओं को ध्यान में न रखकर उनको एक ही शिक्षा दी जाय। माध्यमिक स्तर पर बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार तीन भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं।

हेडो कमीशन (१९२६) रिपोर्ट ने बच्चों के स्कूल जीवन को दो भागों में विभक्त करने की सिफारिश की थी। ५ से ११ वर्ष तक प्रारम्भिक-शिक्षा और ११ वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों को दूसरे स्कूलों अर्थात् माध्यमिक स्कूलों में भेजा जाय, वहाँ १५ वर्ष की अवस्था तक वे शिक्षा प्राप्त करें। उद्देश्य यह था कि सभी किशोरावस्था वाले बच्चों को माध्यमिक-शिक्षा

प्रदान की जाय : यह माध्यमिक-शिक्षा वास्तव में प्रजातन्त्र की शक्ति है और उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक है ! बच्चों को बौद्धिक-भिन्नताओं के अनुसार ही तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का विकास हुआ ।

१—सैंकिन्डरी ग्रामर स्कूल—जो प्राचीन समय से ही विद्यमान थे ।

२—सैंकिन्डरी माडर्न स्कूल—जो स्थापित किए गए हैं और सीनियर एलीमेन्टरी स्कूल से विकसित हुए हैं ।

(३) सैंकिन्डरी टेक्नीकल स्कूल—जो पहले 'जूनियर टेक्नीकल' कहे जाने वाले स्कूलों से विकसित होगे । सन् १९३६ के एक्ट ने अनिवार्य शिक्षा आयु १५ वर्ष कर दी, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के कारण शिक्षा-प्रगति ठीक नहीं हुई और अनिवार्य शिक्षा की अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाने में सफलता न मिल सकी ।

सन् १९४४ एक्ट के अनुसार ११ वर्ष से १५ वर्ष तक या उससे अधिक १७ वर्ष तक के बालकों के लिए माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन विस्तृत रूप से किया गया । राज्य ने यह पूर्ण निश्चय कर लिया कि इंग्लैंड में शिक्षा और सांस्कृतिक-स्तर को ऊँचा उठाया जाय और अब माध्यमिक-शिक्षा पर केवल कुछ ही घनवान व्यक्तिओं का एकाधिकार न रहे । शिक्षा में प्रजा-तांत्रिक भावना का विकास हुआ । यद्यपि १९४४ का ब्रिटेन सन् १९१८ (प्रथम-युद्ध फिगर-एक्ट) के ब्रिटेन से अधिक निर्धन हो गया था, परन्तु वे सभी सम्भव प्रयत्न किये जिससे विस्तृत पैमाने पर किछोरावस्था वाले बालकों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो । ब्रिटेन के शिक्षा-इतिहास में पहलीवार ११ वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालकों को वास्तविक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होने लगी ।

माध्यमिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास

इंग्लैंड की माध्यमिक शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है । प्राचीन समय अर्थात् सत्रह-अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामर तथा पब्लिक स्कूलों (Nine Great Public Schools) में दी जाती थी । परन्तु बीसवीं शताब्दी में राज्य द्वारा आयोजित शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । इस शताब्दी में तीन मुख्य कमीशनों की नियुक्ति हुई (१)—दी पब्लिक स्कूल कमीशन (१८६१-१८६४) जिसने इंग्लैंड में ६ महान् पब्लिक-स्कूलों के प्रबन्ध के विषय में जाँच की; (२) दी स्कूल इनस्थापरी कमीशन (१८६४-१८६८) जिसने 'माध्यमिक विद्यालयों का विषय अपने अध्ययन के लिए चुना था; (३) वाइस-कमीशन (१८६४-

१८६५) जिसको इंग्लैण्ड में सुसंगठित माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली की स्थापना करने की सबसे उत्तम विधियों पर विचार करने का आदेश दिया गया था। ब्राडम कमीशन की कुछ सिफारिशों के आधार पर ही बीमबी सलाहरी में माध्यमिक-शिक्षा में होने वाले विकास और सुधार आधारित रहे। इस दृष्टि-कोण में ब्राडम-कमीशन का अधिक महत्त्व है क्योंकि उसने माध्यमिक-शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया। दो स्कूल इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन अपर्याप्त था और इसका स्तर भी अधिक अच्छा और ऊँचा नहीं था। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक था कि 'माध्यमिक-शिक्षा' का अच्छे स्तर पर विस्तृत आयोजन किया जाय।

ब्राडम-कमीशन (१९०२) ने माध्यमिक-शिक्षा के लिए प्रत्येक काउन्टी और काउन्टी बोरो में स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी की स्थापना का आदेश दिया। ये स्थानीय शिक्षा अधिकारी क्रमशः अपने क्षेत्रों में माध्यमिक और औद्योगिक-शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायी होने चाहिए। मई १९०४ में 'माध्यमिक-विद्यालयों के नियम' में 'माध्यमिक-विद्यालय' की परिभाषा इस प्रकार से की गई—'दिन में पढ़ाने वाले (Day-School), छात्रावास से सम्बन्धित स्कूल जो अपने प्रत्येक विद्यार्थी को १६ वर्ष तक या इससे आगे की अवस्था तक सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं और ठीक प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा शारीरिक, मानसिक और नैतिक-विकास का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, यह शिक्षा प्रारम्भिक-स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा अधिक उन्नत और अधिक व्यापक उद्देश्य की होती है।' सामान्य शिक्षा में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा ब्राडम आदि सम्मिलित थे। १९०२ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा के प्रोग्रामार्न कार्य के लिए अच्छे विद्यालयों को स्कूल में आने की उम्मादित करने के लिए, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिए बहुत उदारतापूर्वक छात्र-वृत्तियों का आयोजन किया। कुछ नि-गुल्क स्थान भी निर्धन विद्यार्थियों के लिए सरक्षित रखे गए। छात्रों को ११-अवस्था पर नि-गुल्क स्थान के लिए एक प्रसिद्ध परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया।

परन्तु जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, माध्यमिक-शिक्षा क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण सुधार १९२६ के हेडो-एक्ट, तथा १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने किये। यद्यपि १९१८ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक-शिक्षा-क्षेत्र में प्रयोग और गवेषणा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया, इसलिये कुछ स्थानों में 'सीनियर-स्कूलों' की स्थापना हुई जिसमें ११ वर्ष की अवस्था के बाद बालक शिक्षा के विषय आने लगे। परन्तु ११ वर्ष की अवस्था के बाद के बालकों के विषय मुख्य स्कूलों

की स्थापना की प्रवृत्ति को वास्तविक प्रोत्साहन सन् १९२६ की हेडो-रिपोर्ट से मिला। जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्न थी—

- (१) ११ वर्ष के बाद की शिक्षा माध्यमिक-शिक्षा कहो जानी चाहिये।
- (२) बालकों की भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के पृथक माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए।
- (३) यदि बालक ११-५ की अवस्था के बाद बौद्धिक-भिन्नताओं के कारण किसी एक प्रकार के माध्यमिक विद्यालय में भेजे जाय और वह उस शिक्षा से लाभ न उठा सके तो उन्हें १२ या १३ वर्ष की अवस्था के लगभग उस स्कूल से दूसरे प्रकार के स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाय।
- (४) स्कूल छोड़ने की आयु बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी जाय। यह अनिवार्य-रूप से लागू हो।

इस रिपोर्ट के फलस्वरूप देश में अधिकतर अधिकारियों ने ११ वर्ष से अधिक अवस्था वाले बच्चों के लिए पर्याप्त-शिक्षा सुविधायें प्रदान करने के मन्थे प्रयत्न किए। कुछ अधिकारियों ने माध्यमिक-शिक्षा की सुविधायें अपने प्रारम्भिक-स्कूलों में ११-५ की अवस्था के बालकों को जुटाने का प्रयत्न किया। अधिक सेन्ट्रल और सीनियर-स्कूल्स बनाये गये और कई काउन्टीज में सग्लोब-जनक माध्यमिक-शिक्षा-प्रणाली काम करने लगी, परन्तु १९१६ में युद्ध आरम्भ होने से इन विकासों की प्रगति में बहुत बाधा पहुँची, और अधिक कठिनाइयों के कारण माध्यमिक शिक्षा प्रगति में अधिक उन्नति न हो सकी।

परन्तु १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक-शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये। इस एक्ट की पृष्ठ-भूमि बनने में कई वस्तुओं ने सहयोग दिया—

- (१) युद्ध सकट-काल में राष्ट्र की रक्षा के लिए सभी सामाजिक स्तर के लोगों (धनवान् और निर्धन) ने युद्ध में भाग लिया और पूर्ण रूप से सहयोग दिया। लोगों में लोकतान्त्रिक भावना का विकास हुआ और वर्ग-भेद की भावना लुप्त होने लगी। देश की युद्ध में विजयी बनाने का ध्येय सभी लोगों को था, उनका अधिकार था कि उन्हें यह शिक्षा रूप में परितोषिक था।
- (२) शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पुनर्निर्माण का मुख्य माधन समझी जाने लगी।
- (३) युद्ध के बाद जन-आधारण में शिक्षा प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई।
- (४) जनता में व्यापक सुधार की भावना की जागृति हुई और शिक्षा-सुधार को प्रथम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
- (५) युद्ध-कालीन राष्ट्रीय संसद ने जनता को एकता के सूत्र में बाँध दिया और

सभी इस संकट-बालीन परिस्थिति का सहयोग से हृदय ज्ञात करने का बड़ा मालूम करने लगे ।

इसकी मुख्य धाराओं का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लोगों की शोचताधिक-भावना को १९४४ के शिक्षा-एक्ट द्वारा संतुष्ट किया गया । इसकी माध्यमिक-शिक्षा सम्बन्धित मुख्य धारायें ये हैं—

- (१) ११ वर्ष में अधिक अवस्था वाले प्रत्येक बालक को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्राप्य होनी चाहिए । सरकारों को इस आयोजन में अधिक संचर्न करना पड़े, यह ध्यान रखा गया, इसीलिए स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाये गये स्कूलों (County Schools) में शिक्षा १५ वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दी गई । यह अनिवार्य आयु १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी ।
- (२) 'माध्यमिक विद्यालय' प्रारम्भिक-विद्यालयों से गृह्यक होने चाहिए । शारी-और मानसिक दुर्बलता वाले बालकों के विशेष स्कूल हों ।
- (३) स्कूल की इमारत के लिए कम से कम आवश्यक बातें, अध्यापकों की योग्यता तथा कक्षा में छात्रों की संख्या नियत कर दी गई ।
- (४) स्वेच्छा से चलने वाले स्कूलों को कुछ शर्तों के अनुसार सार्वजनिक-कोष से सहायता प्राप्य हो गई ।
- (५) प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में प्राथमरी, सेकन्दरी और अग्रिम शिक्षा देने के लिये उत्तरदायी बना दी गई है । इसके फलस्वरूप स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा केन्द्रीय सरकार ने मिलकर स्कूल-योजना और निर्माण में अपनी शक्ति लगा दी । इस एक्ट के अनुसार हर स्थानीय शिक्षा अधिकारी को 'विकास-योजना' बनाकर शिक्षा मंत्री को देनी थी जिससे वह उचित आर्थिक-सहायता प्रदान कर सके । कोई विशेष शिक्षा योजना कितने समय में पूर्ण की जायगी इसकी भी शिक्षा-मंत्री को सूचना रहे ।
- (६) १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने बच्चों में विद्यमान मानसिक-विभिन्नताओं को पहचाना और यह भी स्वीकार किया कि उनकी योग्यता तथा अभिरूचियों में भिन्नता होती है, और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी से यह आशा की कि इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये पर्याप्त विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का आयोजन करे जिससे बच्चों का उचित मानसिक विकास हो सके । वास्तव में यह समस्या इंग्लैंड में बाद-विवाद का प्रश्न बनी रही है, और आधुनिक समय में इस पर बहुत बाद-विवाद होता रहा है । इंग्लैंड के शिक्षा इतिहास द्वारा इस बात का आभास होता है कि आयो-

जन इस प्रकार का था कि १५% से २०% प्रतिशत की शिक्षा के लिये ग्रामर स्कूल आयोजन करे,

अर्थात्

१५% से २०% छात्रों को ग्रामर स्कूल

१०% छात्रों को सैकंडरी टेक्नीकल स्कूल

७०% से ७५% छात्रों को सैकंडरी माडर्न स्कूल आयोजन करे

उपर्युक्त प्रणाली को 'त्रि-विभागीय-प्रणाली' (Tripartitesystem) कहा गया है, इसकी निजी समस्याएँ हैं, उनके से मुख्य यह है कि ११-की अवस्था पर यह कैसे ज्ञात किया जाय कि अमुक छात्र को किस प्रकार के विद्यालय में भेजा जाय। यह सलाह दी गई है कि इस समस्या का हल 'व्यापक-स्कूलों की स्थापना' (Comprehensive schools) से हो सकेगा। जो बहुत प्रकार के पाठ्यक्रम, अध्ययन-सामग्री छात्रों को प्रदान कर सकेंगे। जिससे उनकी विभिन्न प्रकार की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। व्यापक-स्कूलों तथा बहु-विभागीय (Multi-lateral schools) के पक्ष में लोग इसलिए भी हैं कि इस प्रकार के स्कूल राष्ट्र में सामाजिक-एकता में सहायता कर, छात्रों में वर्ग भेद की भावना की क्षुब्ध करते हैं।

परन्तु ऐसे स्कूल भी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उपस्थित कर रहे हैं इस प्रकार के व्यापक तथा बहुउद्देशीय स्कूल बहुत बड़े तथा विशाल होते हैं। और प्रभावव्यापक तथा शिक्षकों तथा शिष्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं स्थापित होने देते हैं और बहुत से छात्र अपने को ऐसे विस्तृत वातावरण में परिस्थित अनु-कूल नहीं बना पाते हैं। छात्रों की संख्या कभी कभी २,००० तक होती है। परन्तु इंग्लैंड के शिक्षा-इतिहास से प्रकट होता है कि छात्रों की सीमित क्रम संख्या और छोटे माइज के स्कूलों को पसन्द किया है। इस प्रकार के प्रश्न तथा समस्या का हल स्थानीय शिक्षा अधिकारी (Local Education Authority) पर ही छोड़ दिया जाता है। मन्त्री को स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी द्वारा दी हुई योजना में इस बात का विस्तृत ध्यान देना होगा कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी (Comprehensive schools) या (multilateral schools) प्रथम त्रिभागीय प्रणाली अपनायगी और तीनों प्रकार में से किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना पसन्द करेगी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी कभी कभी व्यापक स्कूलों (Comprehensive schools) की स्थापना करेगी, और बहुधा त्रिभागीय स्कूलों की स्थापना करेगी। इस प्रकार के प्रयोग शिक्षा-क्षेत्र में इस देश में सर्वत्र ही होते रहते हैं। किसी क्षेत्र में व्यापक या त्रिभागीय स्कूलों के विषय में प्रयोग होता है तो दूसरे क्षेत्र में ग्रामर तथा माडर्न स्कूल सम्बन्धी

शिक्षा प्रयोग । इन प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याओं में सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के हल खाने किए जाते हैं । सभी सभी बहु-भाषीय स्कूल (Multilateral schools) में छात्रों की संख्या २, ००० तक होती है ।

इन उपर्युक्त परिस्थितियों का अभिप्राय यह होगा कि अधिकतर बच्चों में विना पूर्ण रूप से एक नई शिक्षा सेवा का आयोजन करना होगा । नये अर्थों पर जो ट्रेनिंग देनी होगी और बहुत से भागों में नए स्कूलों का निर्माण करना होगा जिससे यह नई शिक्षा सेवा उपलब्ध हो सके । यह स्पष्ट है कि इन मामलों की समस्यापूर्वक पूर्ति में समय लगेगा । यद्यपि इन समय धर्म और धन की कमी है जब भी योजना इस कुशलता से कार्यान्वित की जाती है कि नये स्कूल जब बनकर तैयार हों तब यह गिना हो कि वे उचित स्थानों पर स्थित हैं तथा ठीक प्रकार बनाये गये हैं और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । उनमें रूप से अध्यापकों के अभाव की पूर्ति करने के लिए संकट-कालीन अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज (Emergency Training Colleges) स्थापित किए गये हैं ।

स्पानीश-शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र की विकास योजना को १ अप्रैल १९४५ तक शिक्षा-मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था । परन्तु परिस्थितियों तथा निज विवेक के अनुसार शिक्षा-मंत्री इस अल्पकालीन अवधि को बढ़ाकर आगे भी कर सकते हैं ।

इन 'विकास-योजनाओं' की शिक्षा-मंत्री द्वारा छानबीन की जाती है जिसमें वह परिवर्तन करने की सलाह दे सकता है । यदि यह विकास-योजना स्वीकृत हो जाती है तो उस क्षेत्र के लिये स्पानीश शिक्षा आज्ञा दी जाती है । इस आज्ञा में विशेष विवरण यह दिया जाता है कि योजना कब और भिन्न-भिन्न स्तरों पर कैसे पूरी की जायगी । आज्ञा रूप में दी हुई सभी बातों को वैधानिक शक्ति दी जाती है जो, अधिकारी को पालन करनी होती है । यद्यपि अधिकारी को पार्लियामेंट से अपील करके उसे बदलवाने तथा परिवर्तन कराने का अधिकार दिया जाता है ।

इस 'विकास-योजना' के द्वारा शिक्षा-मंत्री यह निश्चित कर लेता है कि योजना ठीक और सोच-विचार कर बनाई गई है । इससे शिक्षा-मंत्री को भी सन्तुष्ट होने का अवसर मिलता है कि एक्ट में लिखी बातों का देश में अच्छी तरह पालन किया जा रहा है, तथा सरकार को देश की कुल शिक्षा आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की आवश्यक मूचना भी मिल जाती है ।

आजकल इंग्लैण्ड में बच्चों की अवस्था, मानसिक-शक्ति, अभिरुचि तथा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये माध्यमिक-शिक्षा

भिन्न-भिन्न तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में दी जाती है। इन तीनों विद्यालयों में बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तथा अन्य शिक्षा सुविधायें हैं।

तीन प्रकार के माध्यमिक-स्कूल

११ वन के पश्चात् बच्चों को उनकी अवस्था, योग्यता, रुचि के अनुसार तीन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में भेजा जाता है। यह प्रणाली माध्यमिक-शिक्षा की त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite-system in Secondary Education) कही जाती है।

इंग्लैंड के माध्यमिक-शिक्षा में बहुत विविधता होने लगे थी, प्रत्येक प्रकार की माध्यमिक-शिक्षा में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक में समान रूप से हम समय पाई जाती हैं, और भविष्य में भी इन सब बातों में समानता रहेगी। उदाहरणार्थ सभी माध्यमिक स्कूलों में उनकी इमारतों के लिए समान नियम हैं। स्कूलों में जो भी भिन्नता है वह केवल पाठ्य-क्रम और बच्चों की विभिन्न आयु तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के फलस्वरूप है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकताएँ समान होती हैं। एक में विभिन्न नाप के स्कूलों के कमरों की कम से कम संख्या और नाप स्पष्ट रूप से दी हुई रहनी है। प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में एक असेम्बली-हॉल (बड़ा कमरा जिनमें किसी समय सब लड़के एकत्र हो सकें) एक व्यायाम-शाला, एक पुस्तकालय और एक आर्ट-क्राफ्ट-रूम (कला-कौशल का कमरा) होना आवश्यक है। व्यायाम-शाला में सब बच्चों के विधिपूर्वक होनी चाहिए, उसमें बाड़े बटलने और चौकारा से गढ़ाने के कमरे होने चाहिए। स्कूल में एक बड़ा बीरल खेल का मैदान होना चाहिए, जो स्कूल के बहाने में हो या स्कूल के इतना निकट हो कि छात्रों को वहाँ पहुँचने में असुविधा न हो और वह आसानी से पहुँच सकें। हर एक माध्यमिक विद्यालय की एक कक्षा में अधिक से अधिक ३० विद्यार्थी ही प्रविष्ट किए जाने का नियम है। हर प्रकार के स्कूल में एक 'योग्यता प्राप्त' (क्वालीफाइड) शिक्षक रखा जाता है और उसे एक नियत दर में (बर्नहम-स्केटी के अनुसार) वेतन देना पड़ा है। स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी द्वारा संचालित प्रत्येक प्रकार के स्कूल में अनिवार्य अवस्था में ऊपर वाले छात्रों को निर्वाह-भत्ता भी दिया जाना है और इन संस्थाओं को यह भी आदेश दिए गये हैं कि भत्ते की दर इनको नियत करें कि गरीब अभिभावक, जो अपने बच्चों की माध्यमिक अवस्था के बाद पैसे की कमी के कारण स्कूल से नहीं पढ़ा सकते, उन्हें स्कूल का पैसे सहाय्य करने से पढ़ने अपने बच्चों को स्कूल में न हटाना पड़े। ये सामान सम्बन्धी नियम हैं।

सभी माध्यमिक-विद्यालयों में समुचित पुस्तकालय रखने से यह निश्चय हो जाता है कि वहाँ के सभी विद्यार्थी पुस्तकालय का ठीक उपयोग करना सीख जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय के घण्टे का प्रबन्ध रहना है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय के विषय में साधारण बातें जानने, मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करने और स्कूल पुस्तकालय में जो सूचनायें नहीं मिल सकती उनके लिये सार्वजनिक पुस्तकालय का उपयोग करने की आदत डालने आदि बातों की शिक्षा दी जाती है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की तेज प्रगति के कारण आधुनिकतम सामानों और शिक्षा के नये साधनों का उपयोग किया जाता है। बितावें, नक्शे, चित्र आदि वस्तुयें प्राचीन समय से ही शिक्षक की सामग्री रही हैं, परन्तु अब नये आविष्कारों के कारण प्रयोग के लिये 'टैब्लीट साधन' भी उपलब्ध हो गए हैं। ब्लैक बोर्ड के अतिरिक्त अन्य दृश्यारमक साधन भी हैं जो हम समय इंग्लैण्ड के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। सिनेमा प्रदर्शक यंत्रों (प्रोजेक्टरों) का खूब प्रयोग किया जा रहा है और अधिक संख्या में उपयुक्त चल-चित्रों के उत्पादन के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। पुराने मैजिक्-लैंडर्न का अधिक उपयोग अब नहीं है, परन्तु अब उनका स्थान छोटे फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर ले रहे हैं। अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त दृश्यारमक साधनों (विजुअल-एड्स) का उपयोग होने लगा है। ये साधन विचारों को ठीक-ठीक और अधिक स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। उनसे भूगोल, इतिहास में सरयवा, स्पष्टता और समीक्षा आ जाती है और संगार का इस धोड़ कला के सम्पर्क में आ जाने से बच्चों की कल्पना-शक्ति भी बढ़ती है। माध्यमिक-स्कूलों में ब्राडकास्टिंग (रेडियो में क्विज प्रसारित करना) और ग्रामोफोन का भी प्रयोग होता है। आवाजवाणी द्वारा बच्चों को वर्तमान घटनाओं के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन की घटनाओं और समाचारों का पता लगता रहता है और उनके द्वारा विशेषज्ञों और प्रत्यक्ष-दर्शियों के अनुभव और उनकी आवाज स्कूलों में प्राप्त होती है। रेडियो और ग्रामोफोन से भाषणों का सम्पर्क गति के उत्तम संगीत में होता है। प्रत्येक स्कूल में केवल बच्चों के मानसिक विकास की ही नहीं बल्कि केवल ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उनको सामाजिक, नैवेद्यात्मक शारीरिक और सध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया जाता है।

माध्यमिक-विद्यालय अपने पाठ्यक्रम में नागरिक-शासन की महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिसमें बानकों की स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार, ईश्वर तथा मनुष्य-प्रणाली आदि के बारे में प्राग्मिक जानकारी कराई जाती है। इसके द्वारा

बालको को अपनी सामाजिक-स्थिति तथा देश के एक नागरिक के नाते से अपना उत्तरदायित्व एवं अपने देश और कामनवेल्थ देशों तथा राष्ट्री में परस्पर सम्बन्ध के विषय में विस्तृत विचार-धारा हो जाती है। स्कूल में उन्हें बहुत-सी जिम्मेदारियों का अनुभव हो जाता है जैसे स्कूल के चुनावों, स्कूल-काउन्सिलों तथा अन्य सम्बन्धित बातों। बहुत से सेकिंडरी-स्कूलों में एक 'इन्फार्मेशन-रूम' (सूचना का कमरा) होता है। बालक बड़े होकर इसके द्वारा समाज में अपना कर्तव्य पालन करने के योग्य हो जाते हैं। बालक दूसरों के साथ सहानुभूति और विचार-पूर्वक व्यवहार करना, दूसरों की भावना को समझना और उनका आदर करना सीख जाते हैं।

सह-शिक्षा के स्कूलों में जिनमें लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं; लड़के लड़कियों के एक साथ रहकर सद्व्यवहार, शिष्टाचार सीखने का अवसर मिलता है; विद्यार्थियों के लिये एक सामाजिक-वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसमें वे बहुत सी बातें सीखते हैं। उदाहरण के लिए उनको अतिथि बनाना, अतिथि सत्कार करना सिखाया जाता है। स्कूल-सोसाइटीज और क्लबों के द्वारा वे कमेटी में काम, उसका संचालन करना, और सहनशीलता के साथ प्रायोगिक कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में वाद-विवाद करना आदि सीखते हैं। साहसिक यात्राओं का भी कभी कभी प्रबन्ध किया जाता है जिनसे वे बाहरी संसार का भी अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बागवानी शारीरिक काम ड्रामा, बड़ई-गोरी, तसवीर खींचना, और रंगना या अन्य काम जैसे भीतर खेले जाने वाले खेल-खेलना, फोटोग्राफी या खरगोश पालने आदि के बन्ध बने हैं। इन क्लबों का स्कूल और समाज के प्रति विद्यार्थियों की भावना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा बाल अपराधों को रोकने में बड़ी सहायता मिलती है।

दोपहर के भोजन से उनको व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के करने का अवसर मिलता है। यहाँ बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जैसे किसी मेज या कमरे को सजाने का उत्तरदायित्व, पुस्तकालय की देख-भाल करने की जिम्मेदारी, समाचार इकट्ठा करना और आगे बया करना है आदि का उत्तरदायित्व। बड़े विद्यार्थियों को विद्यालय भवन और क्रीडा-स्थल को ठीक प्रकार से देखने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। इस प्रकार सभी माध्यमिक विद्यालयों में अच्छे सामाजिक वातावरण को उत्पन्न करने का अवसर प्रदान किया जाता है और हर एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्साहित किया जाता है।

विद्यार्थियों में यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि स्कूल में एक साथ रहने वाले बच्चों का एक समुदाय है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं और

एक दूसरे से कुछ सीखने हैं। सामाजिक-जीवन की यह भावना प्रतिदिन की सामूहिक प्रार्थना में, विशेष उम्हड़ों के दिन व्याख्यानों में, स्कूल खेलों तथा स्कूल-जंगल में, ग्राह्यिक यात्राओं तथा अन्य कार्यों में जिनमें स्कूल के हर व्यक्ति की सहायता अपेक्षित होती है, दृढ़ हो जाती है।

छात्रों की भावनाओं परिराजनी प्रवृत्तियों को प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। यह अनुभव किया जाता है कि, जो कुछ भी हो, ये प्रवृत्तियाँ हम प्रसार प्रकट की जाँच कि समाज को किसी प्रकार की हानि न हो बल्कि लाभ ही हो। छात्रों को अपनी भावनाओं को प्रकट करने और अनुशासन में रखने के लिए कक्षाओं का प्रयोग किया है। अनुभव में यह पता चला है कि उनका सामग्र प्रभाव मरुट नहीं हुआ है। शिक्षा के इस भाव से सम्बन्धित स्कूल के पाठ्यक्रम में कला, संगीत, ड्रामा, नाय और हस्तकौशल आदि विषय विस्तृत धर्म में सम्मिलित रहने हैं। इन कार्यों में छात्र वास्तविक रूप में अपनी भावनाओं का अनुभव करते हैं और आत्मप्रकाशन का उन्हें सुन्दर अवसर मिलता है।

कला की शिक्षा देकर उनकी रुचि को बढ़ाया जाता है जिनसे वे अच्छी-पुरी कला की पहिचान कर सकें और अपने सामी समय में उसका उपयोग कर सकें। दूसरा उद्देश्य उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जो कला को अपनी जीविका कमाने का साधन बनाना चाहते हैं। कला की शिक्षा से उनकी सामान्य कलात्मक-भावना विकसित होती है, और अनुभव द्वारा धीरे-धीरे वे अपने धर्मों को अधिकार में कर लेते हैं। इससे उनकी काल्पनिक और प्रायोगिक उत्साह रुचि बढ़ती है और उनके आत्म-संयम में सहायता मिलती है। कला का किसी न किसी रूप में सामान्य-शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों के कला-कौशल कार्य अन्य विषयों से सम्बन्धित रहते हैं और इसीलिए सब को मिलाकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इंग्लैण्ड के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र चित्रकारी में बहुत रुचि लेते हैं।

इंग्लैण्ड के माध्यमिक-स्कूलों में शारीरिक-शिक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। यह शारीरिक-शिक्षण स्वास्थ्य-विज्ञान के पाठ और स्कूली खेलों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। शारीरिक-शिक्षा का कार्यक्रम जिम्नेस्टिक (शारीरिक व्यायाम-क्रीड़ा, और मांस-पेशियों को बढ़ाने वाली) पर आधारित रहता है इसमें खेल भी सम्मिलित रहते हैं। बहुत से माध्यमिक स्कूलों में बाह्य खेलों में व्यायाम और समूह या टोलियों में खेले जाने वाले खेल भी सम्मिलित रहते हैं। छात्रों के लिए क्रिकेट, फुटबाल तथा छात्राओं के लिए हाकी, नेट-बाल, राउडर्स (बैट और बाल से खेला जाने वाला खेल), टेनिस और कभी-

कभी क्रिकेट भी सम्मिलित रहती है। अन्तर्विद्यालय मैच भी खेले जाने हैं और अधिकतर स्कूलों में वार्षिक खेलों का आयोजन किया जाता है। किन्हीं सुविधा प्राप्त स्थानों में योग्यता प्राप्त शिक्षकों की देख-रेख में तैरने की शिक्षा भी दी जाती है। जहाँ योग्य शिक्षक हैं मुक्केबाजी और कुस्ती लड़ना भी खूब सिखाया जाता है। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी खेल के लिए सब सामानों का प्रवन्ध करते हैं और शारीरिक शिक्षा-योजना सम्मिलित कार्यक्रमों के लिए उचित वस्त्रों और जूतों की खरीदने का भी उन्हें अधिकार दिया गया है।

नियमित रूप से छात्रों की शारीरिक-परीक्षा, दाँतों की परीक्षा योग्य डाक्टरों द्वारा की जाती है। स्कूलों में भोजन-योजना और दूध दिए जाने की विस्तृत योजना से बच्चों का स्वास्थ्य निरन्तर ही अच्छा रहता है। माध्यमिक-स्कूलों में बच्चों के भोजन, खाने, बैठने तथा चलने के ढंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कक्षा में हवा और प्रकाश आदि के प्रबन्ध पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इन सब बातों के कारण इंग्लैंड के माध्यमिक-विद्यालयों के छात्रों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।

इन माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के आध्यात्मिक विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। यह भरसक प्रयत्न किया जाता है कि माध्यमिक-स्कूलों में अच्छा नैतिक वातावरण स्थापित किया जाय। छात्रों को सुन्दर पुस्तकें दी जाती हैं और वे उन्हें पढ़कर साहित्यिक आनन्द उठा सकते हैं। उनके चारों ओर महान् पुरुषों के चित्र लगे रहते हैं और स्कूल इसी विषय में ऊँचा आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार प्रत्येक विद्यालय का दैनिक-कार्यक्रम सामूहिक प्रार्थना के बाद आरम्भ होता है।

स्कूल में बच्चों को अच्छा संगीत सुनने और उसमें भाग लेने के लिए अवसर दिया जाता है। उन्हें सदैव प्राकृतिक सुन्दरता देखने को मिलती है। छात्रों को इससे सन्तोष मिलता है, उन्हें आश्चर्य और जीवन की सार्वभौमिकता का आभास होता है। लड़कों को प्राकृतिक सुन्दरता केवल प्राकृतिक दृश्यों में ही नहीं बल्कि पत्तियों, फूलों, रंगों, छाल की रचना और घास में भी देखने को मिलती है।

लड़कों को जो कुछ भी गृह-कार्य दिया जाता है, उसका मौलिक-सिद्धान्त यह है कि वे स्कूल के बाहर भी चीजों के संग्रह और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने, तसवीरें खींचने और वस्तुयें आदि बनाने वाले स्कूल के काम को घर पर भी चलाते जाय।

बच्चों के घरों का सहयोग प्राप्त करने पर भी बहुत जोर दिया जाता है। बच्चों के माता-पिता का सहयोग और अभिवृत्ति प्राप्त करने और उन्हें स्कूल के उद्देश्यों को समझाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का संघ स्कूल के लिए बहुत सहायक समझा जाता है।

छात्रों को व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन (Vocational Guidance) भी किया जाता है। छात्रों को काम दिलाने वाली संस्था अभिभावकों को और नौकर रखने वालों को उचित परामर्श देने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार उन्हें बच्चों के योग्य नौकरियों, उनकी रुचि और उनके अभिभावक क्या चाहते हैं आदि पूरी बातों का विवरण मिल जाता है। जब कोई लड़का स्कूल छोड़ता है तब वह अपने साथ स्कूल का एक प्रमाणपत्र भी ले जाता है जिसमें यह लिखा रहता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, जिसे नौकर रखने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ मानता है। इससे छात्रों को उचित नौकरी मिलने में सहायता मिलती है।

यह लगभग सभी जानते हैं कि कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते। इसलिए विद्यालयों में भी विभिन्नता होनी चाहिए, नहीं तो १९४४ का शिक्षा-एक्ट सफल नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार बच्चों की रुचि और योग्यता में विभिन्नता होनी है, इसी प्रकार उनको पढ़ाये जाने वाले स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-विधि में भी विभिन्नता होनी चाहिये। इसलिए माध्यमिक स्कूल प्रणाली में भी विभिन्नता अनिवार्य है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-विधि में विभिन्नता होने पर ही भिन्न-भिन्न बुद्धि तथा रुचि वाले छात्र स्कूल-शिक्षा में लाभ उठा सकेंगे। छात्रों की स्कूल में रहने की अवधि में भी यही अन्तर होगा। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की आशा रखने वाले छात्र माध्यमिक स्कूलों में उन छात्रों की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरेंगे, जो केवल १५ या १६ साल की आयु के लगभग ही शिक्षा पाने (Apprenticeship), भवषा मौकरी पाने के इच्छुक हैं। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए जिससे वह समाज के उपयोगी नागरिक बन सकें और प्रगति में अपना जीवन-दान कर सकें।

१९६४ के महान् शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार किया, शिक्षा में 'संस्कृत-विद्यार्थी' को स्थान दिया। इसका अर्थ यह है कि देश में अधिक व्यक्तियों को शिक्षा-सुविधा प्राप्त हो तथा शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में कृत्रिमता होनी चाहिए। परन्तु १९६६ के एक्ट को मनचने के लिए उनमें सम्मिलित रहने के एक्ट भी समझना आवश्यक है। बांग्ला में यह एक्ट सन् १९७२, सन् १९९५, ईशो रिपोर्ट (१९९६)

स्नेल्स एक्ट [१९३६], तथा नीरबुड कमेटी रिपोर्टों और एक्टों से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है, और यहाँ पर उनके प्रमग बिना नहीं गमना जा सकता है।

हेडो-रिपोर्ट ने 'माध्यमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानकर उसे एक नया अर्थ दिया। माध्यमिक शिक्षा बाल छात्रों की उम्र अवस्था की सम्मिलित करता है जिसे हम 'रिपोरावस्था' के नाम से पुकारते हैं, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक और मवेगात्मक विकास सीधता से होता है और प्रत्येक बच्चे का विकास एक दूसरे से भिन्न भी होता है। इसलिए हेडो-रिपोर्ट ने एक प्रकार के ही प्रामर-स्कूलों में ही जाने वाली माध्यमिक-शिक्षा अपर्याप्त समझी। स्नेल्स रिपोर्ट (१९३६) ने इसे और सुमंगलित बनाया और तीन विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय (प्रामर, टैक्नीकल तथा मार्केन स्कूल) स्थापित करने की सिफारिश की। नीरबुड कमेटी ने इन प्रकार के विद्यालयों की उपस्थिति को मनोवैज्ञानिक रूप से उचित ठहराया। सन् १९४४ के एक्ट ने इन पहले एक्टों और रिपोर्टों को एकीकृत कर सुमंगलित किया और 'माध्यमिक-शिक्षा' को नया रूप दिया जिसका विकास २० की उमरावस्था में हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बच्चों की अवस्था, बुद्धि तथा योग्यता और रबि अनुसार ही जानी चाहिए। और स्थानीय शिक्षा अधिकारी को इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही तीनो (प्रारम्भिक, माध्यमिक और अग्र स्तरों) पर शिक्षा आयोजन करना चाहिए। शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'नई माध्यमिक शिक्षा' का अर्थ यह माना गया है—

“पूर्ण और उत्तर माध्यमिक शिक्षा वह है जो प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप में विकसित करने में सहायक होती है। इसका अर्थ यह होता है कि वह शिक्षा केवल मानसिक-विकास की ओर ही ध्यान नहीं देती है, बरन् छात्रों के भासात्मिक, मवेगात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का भी समान दृष्टि में ध्यान रखती है।”

इन सब बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा का आयोजन त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite-System) के आधार पर किया गया है। ३ वर्षों में ११ वर्ष तक प्राथमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में प्रविष्ट पाते हैं। इनके विभिन्न स्तरों में भेजे जाने का नियम ११ वर्ष के परभाव के परीक्षा पत्र (११+ examination) के आधार पर किया जाता है जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों को ११+ परीक्षा में एच इयर्स टेस्ट, अपेन्टेड टैट और एक बुद्धि परीक्षा टेस्ट दिया जाता है। छात्रों का विभाजन इन विभिन्न

स्कूलों में बुद्धि मन्द के आधार पर होता है। अध्यापकों का स्कूल रिफार्म भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ कान्ट्रीज में I. Q. के अनुसार विभाजन इस प्रकार है—

(1) मैट्रिकरी स्तर स्कूल—50 I. Q. से लेकर मध्यम 70 I. Q. तक के बच्चे इनमें प्रविष्ट होते हैं।

(2) मैट्रिकरी टेक्नीकल स्कूल—70 I. Q. से लेकर 99 I. Q.

(3) मैट्रिकरी सामर स्कूल—99 I. Q. से अधिक वाले बच्चे।

यदि छात्र इस विभिन्न प्रकार की शिक्षा में लाभ प्राप्त करते हुए नहीं पाएंगे तो उन्हें 13+ की अवस्था पर दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

मैट्रिकरी सामर स्कूल—ये स्कूल बहुत प्राचीन हैं और 1888 के शिक्षा-एक्ट के पास होने से पूर्व केवल यही माध्यमिक विद्यालय थे। इनमें सबसे अधिक बुद्धि-समिष्ट (I. Q.) वाले छात्र प्रवेश पाते हैं। इनमें विज्ञानों और विचारों पर अधिक और दिया जाता है। इनमें परम्परागत, साहित्यिक और वैज्ञानिक विषय पाठ्यक्रम में होते हैं और छात्र इनमें सम्मिलित अवधि तक ठहरते हैं। इनमें सामान्य रूप से 5 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है जिसमें सभी विषयों, विशेषकर भाषाओं (प्राचीन और आधुनिक), गणित और विज्ञान की शिक्षा के बाद 13+ परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों की शिक्षा दी जाती है जिसके बाद स्वाभाविक रूप से बहुत से लड़के और लड़कियाँ यूनीवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अन्त में डाक्टर, वकील या पादरी बनते हैं। अधिकतर पढ़ाये जाने विषय छात्रों को मानसिक अनुशासन सिखाते हैं। इन स्कूलों में अनुशासन-पूर्ण विचार और बौद्धिक प्रश्नों को हल करने की योग्यता की आवश्यकता है इसलिए उम्र में बढ़ते वाले बच्चों में सामान्य-बुद्धि अच्छी होनी चाहिए उन्हें विज्ञानों से प्रेम होना चाहिए व अमूर्त विचारों की ओर दीर्घ आकृष्ट होना चाहिए तथा स्कूल की पढ़ाई से लाभ उठाने के लिए उन्हें वहाँ अधिक समय तक रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्रामर स्कूलों में विविध कार्यों के लिए उपयुक्त और आराम देने वाले स्थान का प्रबन्ध रहना है। इन स्कूलों में छात्रों का जीवन पाठ-पढ़ीस के निवासियों से बहुत कुछ भिन्नता-भुक्तता है। क्योंकि इन स्कूलों का उनसे गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ग्रामर स्कूलों का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना है कि प्रथम चार-पाँच वर्ष में कई विषय बच्चों को देने पड़ते हैं और इन चार-पाँच वर्षों के बाद उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। छात्र बहुधा इनमें अठारह वर्ष की अवस्था तक रहते हैं।

ग्रामर स्कूल—“वह माध्यमिक विद्यालय है जिसने और नये स्थापित किये हुए माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा अधिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रतिष्ठा एकत्रित करली है।” इसकी इस प्रतिष्ठा-बुद्धि का कारण यह है कि दसने प्राचीन समय से अब तक अधिक योग्य बुद्धि वाले विद्यार्थियों की शिक्षा-आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसकी प्रतिष्ठा माने वाले युग में भी कम नहीं होगी क्योंकि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की ग्रामर स्कूल कुंजी है और उन लाभदायक व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को योग्य बनाते हैं जिनका समाज में बहुत आदर तथा मान है।

ग्रामर-स्कूलों की स्थापति के मुख्य कारण निम्नांकित हैं। (१) उनकी प्राचीनता (२) अधिक बुद्धि वाले योग्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना (३) जब किसी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, ग्रामर स्कूल प्राचीन समय से ही माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में एक बड़े ‘अभाव’ की पूर्ति करते रहे हैं।

आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार ग्रामर स्कूलों का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। उनको कठोर मानसिक-अनुशासन वाले विषय पढ़ाकर अधिक बुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकता पूरी करना है।

शिक्षा मन्त्रालय के आधुनिक मतानुसार ग्रामर स्कूल शिक्षा का लाभ छात्रों के अधिक प्रतिशत को उठाना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रामर स्कूलों की 6th. form में कोसे अधिक होता है यद्यपि विषयों की संख्या कम हो जाती है। इस छठवें फॉर्म में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के लिए ‘विशेष-योग्यता’ प्राप्त करनी होती है।

इन स्कूलों की अन्तिम वर्ष (Sixth form) में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है। इस कक्षा की पढ़ाई की सफलता से ही प्रायः स्कूल का स्तर मापा जाता है। इस कक्षा में विशेष योग्यता (special) प्राप्त कराने की चेष्टा की जाती है। “इस छठे वर्ष की (sixth form) की शिक्षा ही ग्रामर-स्कूलों की विशेषता है, जिससे चरित्र-निर्माण, आत्म-निर्भरता आदि के गुण छात्रों में उत्पन्न किये जाते हैं, और इसी शिक्षा पर निर्भर हैं ग्रामर स्कूल की अच्छी परम्पराएँ।” आज भी इन स्कूलों में देश के सबसे अच्छे अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ काम करते हैं। इनमें लगभग १/३ लोग ही अध्यापन कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त है। हान में ही इन स्कूलों में सर्वोत्तम छात्रों में यह भावना आ गई है कि अध्यापकों की आय कम है, इसीलिए उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना या अध्यापक बनना उचित नहीं। विज्ञान तथा गणित को छोड़ कर अन्य विषयों

के प्रशिक्षित अध्यापकों की इन स्कूलों के लिये संख्या पर्याप्त मात्रा में है। इन स्कूलों में आदर्श कक्षाओं में ३० छात्र या छात्रायें होनी चाहिये लेकिन प्रायः ऐसा होना सम्भव नहीं। ग्रामर स्कूल केवल छात्रों को ही नहीं छात्राओं को भी उनके जीवन के लिये तैयार करते हैं। छात्राओं के स्कूलों में प्रायः छात्रों से भिन्न कुछ विषय पढ़ाये जाते हैं जो स्वाभाविक ही हैं।

इन ग्रामर स्कूलों में आने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों और मंत्रियों में प्रतियोगिता और होड़ लगी रहती है और जो छात्र इन स्कूलों में आ जाते हैं उनके लिये विश्वविद्यालय के द्वार खुल जाते हैं। १९४४ से पूर्व इन स्कूलों में मुरक्षित स्थान थे जिनमें केवल योग्य छात्र ही आते हैं सेप माता-पिता अपने सपने पर अपने यहाँ बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अब सब स्थान (Competition) के आधार पर भरे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो माता-पिता इन स्कूलों में अपने बच्चों (Competition) के कारण भेजने में असमर्थ होते हैं, यदि वह धनी हों, तो सचलित पब्लिक-स्कूलों में भेजते हैं अन्यथा वहाँ जहाँ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी भेज दें। इन स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कुल संख्या की $\frac{1}{2}$ होगी।

सेकेंडरी टेक्नीकल स्कूल—यह दूसरे प्रकार का माध्यमिक विद्यालय है। यह उन छात्रों के लिए है जो अपने जीवन में काफी शीघ्र ही किसी उद्योग, सेवा, कारखाने का व्यवसाय चुनना चाहते हैं, ऐसे विषयों में विशेष विज्ञान और गणित की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी टेक्नीकल स्कूलों में विद्यार्थी सेकेंडरी मार्बल स्कूलों की तरह १५ वर्ष तक ही रहते हैं परन्तु अधिकांश टैक्नीकल स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र ग्रामर स्कूलों के समान ही लगभग १० या १२ वर्ष तक टहरते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य किसी उद्योग तथा व्यवसाय के लिए बच्चों को तैयार करना है। सभी सेकेंडरी शिक्षा कुछ सीमा तक व्यावसायिक होती है, क्योंकि सामान्य शिक्षा जीवन के किसी विशेष अंश के लिए नहीं, परन्तु पूरे जीवन के लिए तैयार करती है। यह प्रत्येक बालक-बालिका से अपेक्षित है कि वह सामरिक होने के साथ ही, जिन्हें दूसरों के साथ रहना और काम करना है, सम्बन्ध रखता है। सेकेंडरी टेक्नीकल स्कूल अन्य प्रकार के सेकेंडरी स्कूलों से, जीवन से निरुद्ध सम्बन्ध होने के कारण ही भिन्न नहीं है बल्कि छोड़ दुनियाँ से सम्बन्ध रखने के लिए किसी व्यवसाय या उद्योग को चुनना है। सामाजिक तथा जातीय जीवन के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब व्यावसायिक स्कूलों में उतना ही सम्बन्ध रखता है जितना अन्य स्कुलों के साथ। कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, नाविक-शिक्षा और सारीरिक-शिक्षा आदि विषय वहाँ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों

में। सेकिन्डरी व्यावसायिक स्कूल केवल उद्योग या व्यवसाय में जिम्मेदारी के पदों को दिलाने का मार्ग नहीं है। बहुत से लड़के और लड़कियाँ जो ग्रामर या माइन स्कूलों में पढ़ने में बहुत कुशाग्र होते हैं वे भी व्यावसायिक और औद्योगिक जीवन का अनुसरण कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि टैक्नीकल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त छात्रों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

माइन-स्कूलों के समान, जो सीनियर एलिमेन्टरी स्कूल के प्रारम्भिक कार्यों के लक्ष्य हैं, सेकिन्डरी टैक्नीकल स्कूलों की भी अपनी एक परम्परा है। जूनियर टैक्नीकल स्कूलों की स्थापना १९०५ ई० में हुई, १३ वर्ष की अवस्था से २ या ३ वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए उनका आयोजन किया गया था जिससे किसी उद्योग या व्यवसाय की मुख्य शाखा में प्रवेश पाने के लिए अच्छी साधारण शिक्षा दी जाती थी। ये स्कूल १९४४ के एक्ट से पहले स्थानीय शिक्षा-अधिकारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा दिये जाने का अङ्ग माने जाते थे। जूनियर टैक्नीकल स्कूलों के क्षान यह समझते थे कि उनका स्कूल का काम स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाह्य दुनिया से भी उनका सम्बन्ध है जिससे उनको आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। स प्रचार एक वास्तविकता का वातावरण फैला हुआ था। इन स्कूलों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के साथ उसी तरह के होते थे जैसे कि सवमुख उद्योग धन्धों में प्रयुक्त होते थे। ये स्कूल छात्रों को बड़े पैमाने पर मूल प्रशिक्षण देते थे और उन्हें परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने, उन्हें परिधर्मी और काम सीखने के लिए इच्छुक बनाने की कोशिश करते थे। जूनियर औद्योगिक स्कूल टैक्नीकल कॉलेजों से भी निकट सम्पर्क रखते थे। अधिकतर जूनियर टैक्नीकल स्कूल इन्जीनियरिंग पर आधारित थे। ये स्कूल निर्माण व्यवसाय के लिए भी थे। इन स्कूलों में टैक्नीकल विषयों के अतिरिक्त और विषयों में भी शिक्षा दी जाती थी जैसे ड्राइंग, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पाठ्य-विषयों के अतिरिक्त खेल-कूद आदि भी होते थे।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार ये विद्यालय बन्द नहीं हुए, उनमें से अधिकतर पहले की तरह ही चल रहे हैं लेकिन इस एक्ट से उनकी स्थिति ऊँची हो गई है और उनकी उन्नति का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। अब वे ग्रामर और माइन स्कूलों की समान श्रेणी में पहुँच गए हैं। पहले जूनियर टैक्नीकल स्कूलों में प्रवेश आयु १३ वर्ष की और १५ या १६ वर्ष की अवस्था तक २ या ३ वर्ष का कोर्स था, परन्तु अब ११ से १५ या १६ वर्ष की आयु तक ४ या ५ वर्ष तक का कोर्स है। सभी सेकिन्डरी टैक्नीकल स्कूलों को इमा-

रत बनाने के नये नियमों का पालन करना पड़ता है और अब टेक्नीकल स्कूल एक विशेष प्रकार की माध्यमिक शिक्षा देते हैं। पढ़ने और काम करने में उच्च-स्तर का ध्यान रखा जाता है। कुछ विषयों पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं दिया जाता जिससे अन्य आवश्यक विषयों की पढ़ाई को हानि पहुँचे। स्कूल के पाठ्यक्रम का उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्ध रखने का उद्देश्य कुछ विशेष लड़कों की शिक्षा को और लाभ पहुँचाना है न कि शिक्षा पर उनका प्रभुत्व स्थापित करना। वास्तव में, यद्यपि टेक्नीकल स्कूल किसी न किसी व्यवसाय से सम्बन्धित होता है फिर भी, लड़कों को दी जाने वाली शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि उनसे वे उत्साहित और सामान्वित हों। कुछ स्कूल केवल एक व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ अन्य स्कूल एक या अधिक से। अधिकतर विद्यालयों में छात्रावास होते हैं और कुछ विद्यालयों ने १६ वर्ष से ऊपर लड़कों के लिए भी प्रवर्धन किया है। दूसरे प्रकार के विद्यालय में उद्योग, व्यवसाय या कलाओं की थोड़े-थोड़े समय की शिक्षा के हेतु एक साथ पूरे पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम में कभी-कभी विदेशी भाषा, ड्राइंग, स्वतन्त्र कला का काम, गणित, इतिहास और भूगोल आदि भी सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार आजकल के टेक्नीकल स्कूलों में बच्चों का अनुमानतः स्तर ऊँचा है और स्कूल में भरती करने के समय उनकी विशेष रुचि वाले विषय पर भी ध्यान दिया जाता है।

तीसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय 'सेकिण्डरी माडर्न' हैं। इनकी उत्पत्ति आधुनिक-काल में ही हुई है। इनका उद्देश्य विभिन्न योग्यता, रुचि और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में पले बच्चों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम का प्रवर्धन करना है।

अनुभव द्वारा यह निश्चय हुआ है कि अधिज्ञान बच्चे प्रत्यक्ष वस्तुओं (Concrete things) के द्वारा सरलता और शीघ्रता से सीख लेते हैं और ऐसे पाठ्यक्रम द्वारा जो उनके अनुभव पर आधारित हैं, वह शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ११ वर्ष की अवस्था तक उनकी विशेष रुचियाँ व्यक्त नहीं हों पाती जिनके आधार पर उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा सके। ऐसे अधिज्ञान विद्यार्थी उन स्कूलों में ठीक प्रकार पढ़ सकते हैं जो अच्छी सर्वज्ञा-शिक्षा ऐसे बालावस्था में प्रदान कर सकें जो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार स्वतन्त्र रूप से विकसित कर सकें। सेकिण्डरी माडर्न स्कूल इस प्रकार के अधिज्ञान विद्यार्थियों की शिक्षा आवश्यकता पूर्ण करता है। और छात्रों को all round general Education प्रदान करता है।

इंग्लैण्ड के शिक्षा शासकों के मत में सेकिण्डरी माडर्न स्कूल एक बढ़ते

हुए वृक्ष के समान है जिसकी शक्तिशाली जड़े हैं, परन्तु जिसकी शाखाओं की संख्या सीमित है। परिस्थितियों, स्कूल-मवनों और सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार वास्तविक आदर्श स्तर तक पहुँचने वाले ऐसे स्कूल अभी बहुत कम हैं। स्थानों तथा अध्यापकों की कमी के कारण इन स्कूलों का स्तर उचित सीमा तक नहीं पहुँच पाया है।

इन स्कूलों को तीव्र-बुद्धि वाले लड़के-लड़कियों, क्रियात्मक कार्यों में विशेष रुचि वाले बालकों और पिछड़े हुए बालकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रबन्ध करना पड़ता है। कुछ औसत से कम बुद्धि वाले बच्चे भी इन स्कूलों में पड़ते हैं। माइनें स्कूलों को भिन्न-भिन्न योग्यता वाले बच्चों का प्रबन्ध करना पड़ता है इसीलिए उनकी पाठ्यक्रम और शिक्षा विधि में पूरी स्वतन्त्रता रहती है। माइनें स्कूलों का उद्देश्य पूर्ण सेकिन्डरी शिक्षा देना है, परन्तु इसमें स्कूल के पाठ्यक्रम के परम्परागत विषयों पर जोर न देकर ऐसे विषयों पर अधिक बल दिया जाता है जो बच्चों की रुचि से विकसित होते हैं। इस रुचि से बच्चों में सीखने की, इच्छा पैदा होती है और उन्हें अच्छे विचार, अभिव्यक्त करने तथा कला कौशल की भी शिक्षा मिलती है। यहाँ बच्चों को वर्तमान संसार का आभास मिलता है और अवकाश के समय का पूरा उपयोग करने, परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने, प्रत्येक काम को अच्छी तरह ठीक-ठीक करने और उसके अच्छा न होने पर सन्तुष्ट न होने और ठीक-ठीक कहने और काम करने की शिक्षा देना ही उद्देश्य है। इनमें विस्तृत और संतुलित पाठ्यक्रम का प्रबन्ध रहता है और अनेक प्रकार के क्रियात्मक कार्यों के द्वारा उसकी वपार्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। एक दिशा में तो ये स्कूल बच्चों में काम करने की योग्यता का स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर पिछड़े हुए बालकों की आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। ये स्कूल बच्चों के सन्तुलित विकास की ओर ध्यान देने हैं जिसमें केवल मानसिक-उन्नति पर ही विशेष बल नहीं दिया जाता। मानसिक उन्नति तो पूर्ण बच्चे का केवल एक अंग है।

जिन बातों का अवसर सामाजिक और आध्यात्मिक-विकास पर पड़ता है उनका माइनें स्कूलों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। धार्मिक, शारीरिक शिक्षा तथा खलिश कला जैसे विषयों को भी स्कूल में स्थान मिलता है। माइनें स्कूलों की कला में, खेल-कूद के कमरे, नारखाने तथा खेल के मैदान में ही

जाने वाली शिक्षा भिन्न-भिन्न नहीं होनी। वे एक दूसरी से ऐसी मिलती रहनी है कि उनको अलग करना कठिन होता है।

माइर्न स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय अंग्रेजी, गणित, भूगोल और विज्ञान हैं। बहुत से स्कूलों में आधुनिक भाषा भी पाठ्यक्रम का विषय है। इसके अतिरिक्त सांख्यिक-शिक्षा, संगीत-कला, दस्त-कौशल, गृह-कला, अनेक प्रकार के कला-कौशल, सामाजिक तथा मनु-पालन आदि विषय भी सिनाये जाते हैं। प्रधानाध्यापक ही अपने स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के उत्तरदायी हैं। इस पाठ्यक्रम में सरकारी निरीक्षक परामर्श, मार्ग-प्रदर्शन तथा आलोचना करते हैं; परन्तु आदेश कभी नहीं मिलते। अपनी मातृ-भाषा को सीखना और उससे आनन्द उठाना सभी बच्चों की शिक्षा का एक अंग है। विदेशी भाषाएँ भी सिखाई जाती हैं। पारोरिक चित्रों और द्रामा के सुन्दर प्रयोग और बच्चों के व्येटर भुलाये नहीं जाने तथा बहुत से स्कूलों में भाषा की शिक्षा में प्रामोफन रेकार्ड-बल-चित्र, नक्शों और रेडियो की सहायता ली जाती है। विदेशी समाचार-पत्रों का भी उपयोग होता है।

इतिहास और भूगोल में बच्चों को उनके पूर्वजों के रहन-सहन के विषय में मगर या गाँव के बाहर की बड़ी दुनियाँ के समाचारों के विषय में तथा महान् पुरुषों की आशाओं और उपलब्धियों के विषय में जानकारी कराई जाती है। इस प्रकार की वर्तमान बातों को सम्भलते हुए मनुष्य के मुख्य विकास-क्रमों और वर्तमान इतिहास का कुछ आभास करते हैं। माइर्न स्कूल में इतिहास तथा भूगोल के महान् उद्देश्य बच्चों में निरन्तर स्थिर क्रियाशील तथा गतिशील विकास एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तताओं की पूर्णता की उदात्त भावना जागृत करना है। पाठ पढ़ाई की सेवा एक साधारण बात है। अजायबघरों और ऐतिहासिक तथा भू-गर्भ विद्या सम्बन्धी प्रसिद्ध स्थानों को देखने का प्रबन्ध किया जाता है। अच्छे स्कूलों में गणित को प्रयोगिक-क्रियाओं द्वारा सम्बन्धित किया जाता है और गणित की उन क्रियाओं को प्रयोग में लाते हैं जिनके विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जिसे इस संसार से दिलचस्पी है, कुछ ज्ञान होना चाहिये। रसायन के विचारों और वीजगणित के सूत्रों का भी माइर्न स्कूलों में ध्यान रखा जाता है।

विज्ञान में बालकों को प्राकृतिक नियमों और मनुष्य की वैज्ञानिक शक्तताओं का ज्ञान कराया जाता है। ऐसा करने से बालकों की उत्कंठा बढ़ती है

और विषय से उनकी वैज्ञानिक भावना उत्थाहित होती है। माईन स्कूलों में जीव-विद्या को भी स्थान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीव-विद्या पर अधिक बल दिया जाता है और सहरी-क्षेत्रों में भौतिक-विज्ञान पर। बागवानी और पशु-पालन भी गिनाया जाता है। बहुत से विद्यालयों में छात्रों को स्थानीय उद्योग धर्मों तथा उनमें काम करने की प्रणाली को भी दिखाया जाता है। इस प्रकार बच्चे को अपनी दुनियाँ के विषय में, उसमें होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के विषय में और उनसे सम्बन्धित प्राकृतिक-नियमों के विषय में जानकारी कराई जाती है। स्कूलों में 'प्रोजेक्ट-प्रणाली' का अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक एक पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है। बच्चे उद्देश्य विधियों को लेकर कार्य करते रहते हैं और उनकी प्रगति ठीक प्रकार होती रहती है। पढ़ाने में विभिन्न विषयों के परस्पर सम्बन्ध का स्थान रखा जाता है और बालकों को यह अनुभव कराया जाता है, कि वे किसी क्षेत्र में अधिक गहन नहीं हो सकते जब तक वे आवश्यक पण्डित नहीं जान लेते हैं और यह नहीं समझ लेते कि भूगोल और इतिहास एक दूसरे पर प्रभाव डालने रहते हैं। क्या और विज्ञान मनुष्य के सामाजिक जीवन में इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि उतने भ्रम नहीं किए जा सकते। माईन स्कूलों का उद्देश्य बहुत बड़े विद्वान् और विशेषज्ञ उत्पन्न करना नहीं है, परन्तु सर्वसामान्य सामान्य शिक्षा प्रदान करना है।

सर्वेकारक विकास में वृद्धि करने के अतिरिक्त माईन स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय बच्चों को ठीक-ठीक काम करने, काम को करने में पहिले उगके बारे में आयोजन बनाने, चीजों का माप-इष्ट नियंत्रण करने तथा उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने की शिक्षा देने हैं जो उनके सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या-जीवन शिक्षा का आवश्यक भाग है। यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चे क्या-जीवन का घरेलू कामों में प्रौढ़ों जैसे बनुर हो जाय, परन्तु उन्हें कम से कम क्या-जीवन का उद्देश्य जानना, उसकी अच्छाई समझना और हाथों में निष्कलना माना अवश्य सम्भवता जाता है। इस प्रकार माईन स्कूलों में बच्चों को हाथों का प्रयोग करने तथा मन और मान-वेगियों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए काम करने का अवसर दिया जाता है।

Secondary Modern schools का मुख्य उद्देश्य सर्वसामान्य शिक्षा all round general Education प्रदान करना है।

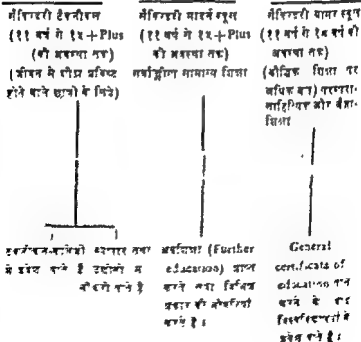
ब्रिटेन की माध्यमिक शिक्षा में त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite system)

प्राथमरी शिक्षा

(५ वर्ष की अवस्था से ११ + तक)

११ + (Plus) परीक्षा (स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है)

माध्यमिक-शिक्षा



पब्लिक स्कूलों के समान ही ब्रिटेन की त्रिभागीय-प्रणाली की बहुत आलोचना की गई है, और उसे सामाजिक तथा प्रज्ञानत्रीय दृष्टिकोण से अनुचित बताया है, और (Comprehensive School) की एक प्रणाली को कुछ लोगों ने उचित समझा है।

- (१) समालोचकों के मतानुसार ब्रिटेन के तीनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों (माडर्न, टेक्नीकल तथा ग्रामर) को समाज में 'समान आदर' नहीं मिला है। ग्रामर स्कूल माडर्न स्कूलों की अपेक्षा अधिक आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं।
- (२) ११+ की अवस्था पर बालकों का विभिन्न स्कूलों में विभाजन करना, अधिक धीप्रता करना है। बालक का इतना धीप्र और इतनी कम अवस्था पर भाग्य-निर्णय कर देना अधिक उचित नहीं है। इतनी धीप्रता से इस अवस्था पर बालकों की रुचि, बुद्धि का पता लगाना इतना सरल कार्य नहीं है।
- (३) बालकों को विभिन्न स्कूलों में भेजने से भविष्य में सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामर स्कूल से जाने वाले छात्र माडर्न स्कूल के छात्र की प्रगति की दृष्टि से देखेगा और अपने को उनसे नहीं उच्च समझेगा। इस तरह समाज में एकता-संगठन के स्थान पर विभिन्न तीन प्रकार के स्कूल एकता में बाधक होंगे। यह प्रजातान्त्रिक-सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है। इस प्रणाली में समाज में छिद्र-भ्रष्टता होने का भय प्रकट किया गया है।
- (४) ११+ Plus की परीक्षा जिसके द्वारा बालकों का विभिन्न तीन प्रकार के स्कूलों में भेजा जाना निर्णय किया जाता है, इसके मनो-वैज्ञानिक कारण हैं। इन परीक्षा के लिए जाने के अधिकतर कारण ऐतिहासिक तथा शासकीय हैं। इन अवस्था पर परीक्षा लेने के कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं हैं।
- (५) ११+ की परीक्षा में दिए गए बुद्धि-मापक परीक्षाओं पर निजी रूप से पढ़ाने का प्रभाव पड़ता है, इससे ठीक निर्णय नहीं हो पाता कि कौन बालक अधिक बुद्धिमान है, तथा उसे ग्रामर स्कूलों में जाना चाहिए। अध्ययन तथा अधिक निजी कोचिंग से बुद्धि-सन्धि (I. Q.) में वृद्धि हो जाती है। घनवान माँ बाप अपने बच्चों का (Private Coaching) कराते हैं। इससे वे परीक्षा में अधिक नम्बर पा जाते हैं।

(६) ग्रामर स्कूल में स्थान प्राप्त करने की चिन्ता के कारण बालक के ऊपर बुरा दारीरिक और मानसिक-प्रभाव पड़ता है।

(७) घनवान घरों के बालक घरों पर अच्छे सामाजिक वातावरण के कारण ११-+ की परीक्षा में अधिक नम्बर पाने हैं।

यदि भविष्य में समाज को छिन्न-भिन्न करने वाली इस त्रिभागीय प्रणाली को नष्ट करना है तो हमें ऐसे स्कूल स्थापित करने चाहिए जहाँ प्रत्येक वर्ग के छात्र बिना किसी सामाजिक भेद-भाव तथा बुद्धि भेद-भाव के एकत्रित होकर एक साथ मंत्री-पूर्ण वातावरण में मिलकर अध्ययन करें। ऐसे स्कूल तीनों प्रकार की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करें परन्तु इस प्रकार के विद्यालयों का तीन विभिन्न प्रकार के भागों में स्पष्ट धृष्टकीकरण न हो। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ऐसे स्कूलों के स्थापन विचार का बहुत स्वागत किया। और लन्दन काउन्टी काउन्सिल ने इसी प्रकार के कुछ कम्प्रेहेन्सिव स्कूलों (Comprehensive Schools) की स्थापना की।

दूसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ तीनों प्रकार की माध्यमिक शिक्षा विभिन्न विभागों में दी जाती है। इन्हें मल्टीलेटरल स्कूल (Multilateral Schools) कहते हैं। तया दो प्रकार की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले बाई-लेटरल स्कूल (Bilateral Schools) कहलाते हैं। बाई-लेटरल स्कूल कभी-कभी माइनर स्कूल तथा टेक्नीकल स्कूल को मिलाकर बनाया जाता है।

तीसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय 'पब्लिक स्कूल' हैं। ये स्कूल वास्तव में जनसाधारण के स्कूल नहीं हैं और न संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के पब्लिक स्कूलों के समान ही हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, और जनता के धन द्वारा चलाये जाते हैं।² वास्तव में ब्रिटेन के पब्लिक स्कूलों का आरम्भ प्राचीन समय में हुआ। पब्लिक स्कूल वास्तव में वैयक्तिक (निजी) हैं और इंग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली में उनका बहुत महत्त्व है, क्योंकि इनमें शिक्षित व्यक्ति अधिकांश महान् पुरस्कार हैं। राष्ट्र की उन्नति में इन स्कूलों ने उच्च स्थेरी के विज्ञान, पुरस्कार, राजनीति, डाक्टर, वकील, बनाकर बहुत सहाय्य दिया है। इंग्लैण्ड को अपने पब्लिक स्कूलों का बहुत गर्व है और बहुधा वहाँ के लोग इन्हें महान् पब्लिक स्कूलों के नाम से पुकारते हैं। पनेमिण-नमेट्री की रिपोर्ट

1. Public School Or Comprehensive High School of America is tax-supported and open to all children irrespective of their parents financial condition.

के अनुसार पब्लिक स्कूल की परिभाषा यह है, 'वे स्कूल हैं जो गवर्निंग बीडीज एग्रीजेशन' तथा प्रधानाध्यापक समिति (हैडमास्टरस कान्फरेन्स) में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुके हों। ये वास्तव में 'स्वतन्त्र स्कूल' हैं। यह छात्रों से प्राप्त की हुई फीस और दान पर निर्भर रहते हैं परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाये जाते। इनकी प्राचीन स्थापना के कारण परम्परागत-विशेषतायें पाई जाती हैं। जैसा पिछले अध्यायों में बताया गया है कि विनचेस्टर (१३८२) और ईटन (१४४०) की स्थापना मध्य-युग में हुई। आरम्भ में इन दोनों स्कूलों का यह उद्देश्य था कि 'घनवान् व्यक्तियों के बच्चों के साथ-साथ ही कुछ गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाये। घनवान् व्यक्तियों को हम शिक्षा के लिए व्यय करना पड़ना था। विनचेस्टर और ईटन के आदर्श पर १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में उस समय के ग्रामर स्कूलों में से ही कुछ पब्लिक स्कूलों की पुनर्संस्थापना हुई। इनमें हैरो, रगबी, थूबरी, वेस्ट-मिन्स्टर, सेण्टपाल, मर्चेंट टेयलर्स इत्यादि हैं। ये स्कूल भी कुछ निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। १९ वीं शताब्दी के मध्य में इनकी वास्तविक उन्नति और वृद्धि हुई। आयरलैंड के ८९ पब्लिक स्कूलों में से ५४ स्कूल उस युग में स्थापित हुए।

ग्रामर स्कूल तथा पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अन्तर हमें नहीं मिलता है। दोनों ही परम्परागत साहित्यिक और वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्त्व देते हैं। पब्लिक स्कूलों में छात्रावास जीवन अधिक महत्त्वपूर्ण है और बच्चों के चरित्र-विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। इन स्कूलों में ग्रीक, तथा लैटिन अनिवार्य विषय हैं।

बच्चों का प्रवेश इनमें बहुधा १३-१४ वीं अवस्था में (प्रवेश-परीक्षा) पाम करने के बाद होता है और १८ वर्ष की अवस्था तक वे इन स्कूलों में अध्ययन करते हैं और प्रतिवर्ष छात्रों की कुछ समस्या आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्व-विद्यालयों में प्रवेश पाती है।

पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए तैयारी करने वाले छात्र पहले 'प्राइवेट प्रीपेरी स्कूलों' (Preparatory Schools) में पढ़ते हैं। प्रवेश पाते समय विद्यार्थी की अवस्था १३ वर्ष की होनी चाहिए, और उते १३-१४ के समय प्रवेश परीक्षा पाम करनी चाहिए। शिक्षा पास्नीयो ने इन पब्लिक स्कूलों की प्रविष्टि के निम्नांकित कारण बताये हैं।

2. Governing Bodies Association.

- (१) ये स्कूल चरित्र-विकास पर अधिक महत्त्व देने हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन स्कूलों की राय में 'चरित्र-निर्माण' और चरित्र 'विकास' है। विद्या-भियों में स्वावलम्बन, आत्म-श्लाघ, मस्वाई और ईमानदारी की भावनाओं का विकास करना चाहिये। ऐसे छात्र धर्म की श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और दूसरे व्यक्तियों और राष्ट्र के लिए वह आत्म-श्लाघ की भावना में कार्य करते हैं।
- (२) इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों की राष्ट्रीय-उन्नति लक्ष्य में बहुत देन है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार करना इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन स्कूलों में कई विभिन्न विद्यार्थी जो महान् पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन भर राष्ट्र के समस्त अनुष्ठान आदर्श कार्यान्वित किए हैं।
- (३) इन स्कूलों का आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज के प्राचीन विश्वविद्यालयों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। प्रतिवर्ष इन स्कूलों की शिक्षा समाप्त करने के बाद कुछ विद्यार्थी इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं।
- (४) इन स्कूलों की गवर्निंग-बोडी तथा हेडमास्टर स्वतन्त्र होते हैं और राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।
- (५) चरित्र-शिक्षा और नेतृत्व की शिक्षा छात्रावास में अच्छी प्रकार दी जाती है और सहयोग, सामूहिक-जीवन और साहचर्य का वातावरण भी-भीति उत्पन्न किया जा सकता है। यद्यपि कम संख्या में कुछ ऐसे भी पब्लिक स्कूल हैं जिनमें छात्रावास नहीं है, उन्हें 'डे-पब्लिक स्कूल' कहते हैं।^१ परन्तु अधिकतर स्कूलों में छात्रावास हैं। आधुनिक काल में ऐसे पब्लिक स्कूलों की भी स्थापना हुई है जो 'सड़कियों की शिक्षा' के लिए हैं और प्राचीन पब्लिक स्कूलों के आदर्श पर ही इनकी स्थापना हुई है।
- (६) स्कूल में पर्याप्त शिक्षा साधनों की उपलब्धता, उदाहरणार्थ अधिक योग्य अध्यापक, और उपयुक्त शिक्षा सामग्री की प्राप्ति तथा अध्ययन के लिए आदर्श वातावरण इनकी विशेषताएँ हैं।
- (७) इन स्कूलों की प्राचीन स्थापना के कारण एक विशेष प्रकार की अच्छी परम्परा विकसित हो गई है।
- (८) अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन पब्लिक स्कूलों में दूर-दूर से आने वाले छात्र प्रवेश पाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी धनवान् पुरुष अपने

1. Day Public School. 2. St. Paul's, Westminster and, Merchant Taylor's are in London and are mainly 'Day School'.

बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए हैरो, रगबी इत्यादि पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं।

- (६) इन पब्लिक स्कूलों में अधिकतर धनवान घरों के बच्चे आते हैं और प्रविष्ट होने के पहले प्रीप्रेटरी स्कूल में पढ़कर आते हैं। अधिकांश बच्चे अधिक बुद्धि वाले और धनवान घरों के बच्चे वातावरण से आते हैं जहाँ मानसिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएँ भी होती हैं क्योंकि धनवान होने के कारण उनके संरक्षक सभी प्रकार के उचित माध्यमों का आयोजन कर सकते हैं।

१०—इस स्कूलों की शिक्षा-विधि की उत्तमता

इन स्कूलों में हाउस (House) और प्रीफेक्ट (Prefect) विधियों का प्रचलन है यद्यपि आजकल इंग्लैंड के अधिकांश दूसरे प्रकार के स्कूलों में इन विधियों को अपनाया है, परन्तु इस प्रणाली का आरम्भ पब्लिक-स्कूलों से ही हुआ है। इस प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय 'रगबी' पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर आरमोल्ड को है।

हाउस-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक स्कूल की विद्यार्थी-संख्या का सम्बन्ध (Vertically) विभाजन किया जाता है। प्रत्येक समूह में लगभग ५० छात्र होते हैं जिसमें सभी कक्षा के विद्यार्थी हो सकते हैं क्योंकि सम्बन्ध विभाजन में विद्यार्थी की भौली तथा अवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये सभी छात्र हाउस-मास्टर की संरक्षकता में रहते हैं, तथा विद्यार्थियों और हाउस मास्टर में निकट सम्पर्क रहता है। इन ५० या ६० विद्यार्थियों को साथ रहने का अवसर मिलता है। साथ ही खेल और दूसरे कार्यों में भाग लेने का सुबबसर मिलता है। हाउस-मास्टर अपने मरक्षण में रहने वाले प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से जानता है। छात्रों के नैतिक, मानसिक और धारीरिक भलाई के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करता रहता है। दैनिक जीवन में प्रत्येक प्रकार की सहायता उसके द्वारा प्रदान की जाती है, और बच्चों की भलाई के लिए वह कुछ उठा नहीं रखता, बल्कि सहर्षता से उनकी धारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई के सर्वे कार्य करता रहता है। उनके स्वास्थ्योन्नति, चरित्र विरास और स्कूल-उन्नति की ओर हाउस-मास्टर का सर्वे ध्यान रहता है। इस प्रकार के हाउसेज (Houses) पब्लिक स्कूलों के अनिवार्य अंग हैं। इनके सम्बन्ध खेल-कूद आदि में प्रतियोगी होते हैं।

प्रीफेक्ट-प्रणाली (Prefect System) भी पब्लिक स्कूलों का मुख्य अंग है। मुख्य रूप से इस प्रणाली के जन्मदाता 'रगबी' पब्लिक स्कूल के डॉ॰

भारमोटड थे । इस प्रणाली के अनुसार स्कूल के उच्च कक्षा और अधिक अवस्था वाले कुछ छात्रों को निम्न कक्षा और कम अवस्था वाले छात्रों की देख-भाल करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है । प्रीफेक्टेड कुछ चुने हुए छात्र हो बनाये जाते हैं, और उनको अनुशासन, खेल, पुस्तकालय तथा स्कूल जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों का उत्तरदायित्व दिया जाता है । प्रीफेक्टेड को अपने से छोटी अवस्था वाले छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं । स्कूल के अनुशासन को ठीक रखने में इनसे पर्याप्त सहायता मिलती है । इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों में उत्तरदायित्व, नेतृत्व और सामाजिक-गुणों का विकास करना प्रजातन्त्रोप-युग में अत्यन्त गायरिक के लिए आवश्यक है । 'प्रीफेक्टेड' का चुनाव कभी-कभी छात्रों द्वारा होता है, और कभी-कभी इनकी नियुक्ति प्रधानाध्यापक द्वारा होती है । इस प्रणाली द्वारा आत्म-निर्भरता और रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है । यह प्रणाली भारतीय 'कक्षा-मान्दिर-प्रणाली' से बहुत कुछ मिलती-जुलती है ।

पञ्चिक स्कूलों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं (Co curricular activities) का बहुत महत्व है । खेलों का आयोजन भी प्रचार किया जाता है । इन खेलों के द्वारा ही कक्षाओं में समुदाय तथा सहयोग भावना सम्बन्धी बांझीय गुणों का विकास होता है । क्रिकेट, रणवी कुटवाल, हाकी और टेनिंग इत्यादि खेल लुब ही खेल जाते हैं । विद्याविषयों को तैरने, नाच खेलने की शिखा भी जाती है । अधिकतर खेल खेलने वाले खेल समुदाय खेल (Team-games) होते हैं । इन खेलों द्वारा बहुरक्तुर्ण चरित्र-निर्माण की शिखा मिलती है, निम्न निम्न हाउसों में प्रतियोगितामें भी होती है । विद्याविषयों के समय का समुदाय इन खेलों द्वारा होता है, छात्रीय-आयाम तथा चरित्र-विभाग के भी खेल उगम साधन हैं । आशक्य कुछ स्कूल गायन-विद्या, आटे, हस्तकला पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं । इन सभी कार्यों द्वारा विद्याविषयों के स्वाभाविक गुणों का पूर्ण रूप से विकास करना ही पञ्चिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य है ।

प्राचीन समय में ही हुई शिखा इन स्कूलों में उच्चकोटि के गायिक की की । निम्न ५ वर्षों में यह परम्परा कुछ बदल गई है, परन्तु अब भी उच्च-कोटि के शाली के अध्ययन का महत्व है; परन्तु अब विद्याविषयों का विकास, निम्न आधुनिक भाषाओं के पढ़ने का उचना ही अध्ययन प्राप्त होगा है, शिक्षा मंत्रालय तथा शीघ्र पढ़ने का । प्रत्येक कक्षा में लगभग २० विद्यार्थी होते हैं जिसमें उच्च शिक्षार्थी की जो आधुनिक ध्यान दिया जा सकता है । निम्न विद्यालयों में प्रविष्ट पढ़ने के इच्छुक छात्रों को ४ या ५ के छोटे समुदायों में पढ़ाया जाता है ।

ये स्कूल आजकल के पेन्टिंग, गायन-विद्या तथा ड्रामा इत्यादि की शिक्षा भी देते हैं। विद्यार्थियों में कुछ कार्यों में विशेष रुचि विकसित करने का भी प्रयत्न किया जाता है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पब्लिक स्कूलों की इतनी विस्तृत स्थािति का श्रेय यहाँ के प्रधान अध्यापकों की है। डा० आरनोल्ड का नाम इंग्लैंड के शिक्षा-इतिहास में आज भी बड़ी धृद्धा के साथ लिया जाता है। अधिकतर प्रधान अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय-स्तर पर स्थािति प्राप्त की है। ये प्रधान अध्यापक ही सहायक अध्यापकों को नियुक्ति करते हैं और उन्हें नौकरी से अलग करने का भी अधिकार होता है। यदि प्रधान अध्यापक अपने विचारों से स्टाफ तथा गर्बनिंग बोर्डों को प्रभावित कर सकता है, तो उसके ओदर्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकते हैं।

बहुत से इन स्वतन्त्र पब्लिक स्कूलों का किन्ही विशेष धार्मिक सम्प्रदायों से निश्चित सम्बन्ध होता है। धार्मिक शिक्षा इनका आवश्यक अंग है और स्कूल के विर्जों में प्रार्थना अनिवार्य है। ६१ पब्लिक स्कूलों का इंग्लैंड के चर्च से, ७ पब्लिक स्कूलों का रोमन कैथोलिक चर्च से सम्बन्ध है। रोप स्कूल प्रोटेस्टैंट डिसेन्ट्स तथा चर्च आफ वेल्स से सम्बन्धित है। तीन पब्लिक स्कूल मैथोडिस्ट कांफेस से सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ धार्मिक-शिक्षा चरित्र-शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है।

इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण 'गर्बनिंग बोर्ड' के हाथ में होता है। 'पब्लिक' शब्द का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि यह स्कूल राज्य के नियन्त्रण में हैं या सभी वर्ग के लोगों को यह शिक्षा प्रदान करते हैं। इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल केवल धनवान् व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसलिए कुछ लोगों की राय में इनका वर्तमान नाम 'पब्लिक-स्कूल' उपयुक्त नहीं है। वास्तव में ये वैयक्तिक और निजी (Private) हैं।

इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों के विषय में एडवर्ड गिवन ने अपने स्मृति पत्रों में गर्ब के साथ लिखा था :—

"I shall always be ready to join in the opinion that our Public Schools which have produced so many eminent characters, are the best adapted to the genius and constitution of English People."

सङ्क्रियों की शिक्षा के लिए स्थापित किये हुए पब्लिक स्कूलों की संख्या इंग्लैंड और वेल्स में इस समय ८० है। ये स्कूल सड़कों को शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूलों के आदर्श पर स्थापित किये गए हैं। इनमें से बहुत कम की स्थापना हुए १०० वर्ष से अधिक हुए हैं। पाठ्यक्रम के विषयों

में भी कोई अन्तर नहीं है और अनेकों महिलाओं इस शिक्षा के बाद विद्व-विद्यालयों में प्रवेश पाती हैं।

१६४४ के शिक्षा एक्ट ने पब्लिक स्कूलों की स्वतन्त्रता में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया है परन्तु सभी निजी तथा स्वतन्त्र स्कूलों का अब हर मैनेस्टीर एन्डोवमेंट द्वारा निरीक्षण होता है। इनमें से कुछ अब आर्थिक रूप से सरकारी आर्थिक सहायता भी पाते हैं। स्थानीय शिक्षा अधिकारी पोंग बच्चों को पब्लिक स्कूल में अध्ययन करने के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं।

प्रीपेरेटरी (Preparatory School) भी पब्लिक स्कूलों के भाग है, ये पब्लिक स्कूलों की तरह के प्रीपेरेटरी स्कूल भी हैं। यदि बच्चा बोर्डिंग पब्लिक स्कूल में प्रवेश चाहता है तो वह ८ या १० वर्ष की अवस्था में बोर्डिंग प्रीपेरेटरी स्कूल में जायगा। कुछ पब्लिक स्कूलों के निजी प्रीपेरेटरी स्कूल होते हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश निजी और उनमें सम्बन्धित हैडमास्टरों की सम्पत्ति है। ये प्रीपेरेटरी स्कूल 'पब्लिक स्कूलों' के आदर्श पर ही चलते हैं क्योंकि ये 'पब्लिक स्कूलों' में प्रविष्ट पाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और बच्चे ८ वर्ष की अवस्था से १३ वर्ष की अवस्था तक इनमें अध्ययन करते हैं। ये छोटे ही स्कूल होते हैं और इनमें कम से कम २० से १०० तक विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं।

इन प्रीपेरेटरी स्कूलों के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला यह कि इन अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों द्वारा आयोजित कामन-एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन पास कर सकें, जिससे पब्लिक स्कूलों में वे प्रवेश पा सकें और इनमें से अधिक योग्य विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों द्वारा ही हुई छात्र-वृत्तियाँ प्राप्त कर सकें। यह बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रीपेरेटरी स्कूल भी पब्लिक स्कूलों की तरह निजी और स्वतन्त्र होते हैं।

प्रोग्रेसिव स्कूल (Progressive Schools):—निजी और स्वतन्त्र प्रकार के दूसरे प्रोग्रेसिव स्कूल हैं। इनसे अधिकतर पब्लिक स्कूलों की तरह छात्रावास स्कूल हैं परन्तु अन्य सभी बातों में पब्लिक स्कूलों से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ पब्लिक स्कूल प्राचीन-विधियों में अधिक धृष्ट रहते हैं और प्रोग्रेसिव स्कूल इससे भिन्न नई विधियों का अधिक स्वागत करते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल में मंद शिक्षा होती है परन्तु पब्लिक स्कूल इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते। पब्लिक स्कूल अपने विद्यार्थियों पर वैत और शारीरिक दण्ड द्वारा कड़ा अनुशासन रखते हैं और प्रोग्रेसिव स्कूल विद्यार्थियों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देते हैं और शारीरिक दण्ड को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

1. Common Entrance Examination.

प्रोग्रेसिव स्कूलों को आरम्भ हुए १०० वर्ष से अधिक नहीं हुए, बहुत से इसी शताब्दी में स्थापित हुए हैं। ये स्कूल ऐसे व्यक्तियों द्वारा आरम्भ हुए जो उस समय के स्कूलों से असन्तुष्ट थे कुछ प्रोग्रेसिव स्कूलों के संस्थापन में धार्मिक संस्थाओं, फियोमोफिस्टम और सोसाइटी आफ फ्रेंड्स ने भी बहुत सहयोग दिया। ये स्कूल व्यक्तिगत हैं, हैडमास्टर्स और प्रिन्सिपलों के व्यक्तित्व की विभिन्नता के कारण स्कूलों में भी विभिन्नता मिलती है यदि वह स्कूल छोड़ देना है तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में स्कूल बिम्बकुल विभिन्न प्रकार का हो जाना है; परन्तु मुख्य आधारभूत सिद्धान्त सभी शिक्षालयों में एक से ही होते हैं। लड़के और लड़कियाँ आरम्भ से ही साथ-साथ अधिक से अधिक स्वतन्त्रता में पालित-प्योषित किये जाते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी समान-स्तर पर ही एक दूसरे से मिलते हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऐच्छिक होती है और बच्चों को अपने अध्ययन के लिए पाठ्य-क्रम चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

कला, गायन-विद्या तथा पेन्टिंग इत्यादि को अधिक महत्व दिया जाता है। परन्तु इसके साथ ही साथ चमड़े का कार्य, सुई तथा बर्तन बनाने का कार्य, जिस्ड बाँधना तथा लकड़ी का कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। रविवार बहुधा भूमने तथा शिविर-क्रियाओं में व्यतीत किया जाता है। खेल खेलें जाने हैं। लेकिन पब्लिक स्कूलों के समान अत्यधिक ओर उन पर नहीं दिया जाता है, परन्तु आधुनिक शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन दिया जाता है। वास्तव में इन स्कूलों का पूर्ण दृष्टिकोण अधिक सीमा तक बुद्धिमानी और आदर्शवाद पर आधारित रहता है। ऐसे स्कूलों में बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और उनका दृष्टिकोण अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। इन स्कूलों के कुछ विचार, सिद्धान्त और शिक्षा विधियाँ दूसरे स्कूलों ने अपनाई हैं। उदाहरणार्थ सभी प्रकार की हस्त-कला का विचार सभी स्कूलों में लाभदायक समझकर स्वीकार कर लिया है। इन स्कूलों में पब्लिक स्कूलों के समान ही छात्रों को अधिक घन व्यय करके शिक्षा प्राप्त करनी होती है क्योंकि इनमें बालकों की सहाय के अनुपात से नहीं अधिक अध्यापक रहने पड़ते हैं। इसलिए ये स्कूल भी पब्लिक स्कूलों के समान केवल घनी व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा प्रदान करते हैं और राज्य द्वारा आयोजित स्कूलों में जाने वाले बच्चों के बहुत से संरक्षक ऐसे प्रोग्रेसिव स्कूलों के विषय में कुछ भी नहीं जानते।

इस समय इनकी धीमे-धीमे गति से नहीं बढ़ा जा सकता कि इन स्कूलों का प्रभाव भविष्य में कितना होगा? यह निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रवेश इन स्कूलों द्वारा होता रहेगा।

पब्लिक-स्कूल और उनकी आलोचना—द्वितीय युद्ध के समय जब लोगों में लोकतान्त्रिक-भावना का अधिक विकास हुआ, इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूल जन-साधारण के वाद-विवाद का विषय हो गये। लोगों द्वारा व्यक्त किए विचारों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है :

प्रथम श्रेणी उन अल्प-संख्यक लोगों की थी जो पब्लिक स्कूलों के पुराने छात्र रह चुके थे और इन स्कूलों की समालोचना तथा बुराई करने वालों को ये पुराने छात्र अप्रसन्नता की दृष्टि से देखते थे। इन पब्लिक स्कूलों के पुराने छात्रों की राय में पब्लिक स्कूलों द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा अति उत्तम, पूर्ण-रूप से आदर्श थी। पब्लिक स्कूल पवित्र हैं और राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये छात्र पब्लिक स्कूलों के विषय में किसी प्रकार की आलोचना नहीं सुनना चाहते थे। उनके विचार से पब्लिक स्कूलों की बुराई, आलोचकों के द्वेष, अज्ञानता, जलन और दुर्भावना के कारण उत्पन्न हुई है।

द्वितीय श्रेणी उन लोगों की थी, जो साहस पूर्वक कहते थे कि प्रजा-तंत्रीय-राज्य में 'पब्लिक-स्कूल' अरक्षणीय हैं और उनको प्रजातंत्रीय समुदाय में बनाये रखना भारी त्रुटि है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। उनकी समाप्त करना ही इस समस्या का हल करने का सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि पब्लिक स्कूल 'जन-साधारण' की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा न करके केवल कुछ उच्च घनी-वर्ग के बच्चों को शिक्षा देते हैं। पब्लिक स्कूल सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा दें, यदि यह सम्भव नहीं, तो उन्हें समाप्त करना ही समस्या हल करने का सर्वोत्तम उपाय है।

तृतीय श्रेणी के वह व्यक्ति हैं जो दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों की तरह ही इन स्कूलों की कटु-आलोचना करते हैं। उनकी राय में पब्लिक स्कूल छात्रों पर इतना नैतिक प्रभाव डालते हैं और जीवन के मूल्यों का त्रुटिपूर्ण माप-दण्ड देने हैं। इनमें शिक्षित छात्र 'सेवों में दक्षता' की ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझते हैं। अहंकार तथा असम्यक्ता के बाधावरण को प्रदान कर ये पब्लिक स्कूल समाज के लिए अहंकारी व्यक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल राष्ट्र के लिए इनने व्यर्थ हैं कि उनकी ओर विस्तृत 'ध्यान न देना' ही, सबसे अच्छी नीति होगी और उनको 'भाव्य के भरोसे' और उनके छात्रों के आचारों पर ही छोड़ देना चाहिए। स्वभावतः उनका प्रभाव और संख्या कम हो जायगी और बहुत से इस प्रकार मरणात् भी हो जायेंगे।

इन अल्पमत भागों के अनादि बाने व्यक्तियों के अतिरिक्त, बहुत श्रेणी उन बहु-संख्यकों की थी जिसका हृदय विश्वास था कि पब्लिक स्कूल राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्र की उन्नति में उनका महान् योग है। उनका

नष्ट करना राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। उनके नष्ट करने, राज्य को दे देने तथा 'भाग्य के भरोसे' उनको अपने साधनों पर छोड़कर समाप्त कर देने से राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा, वरन् हानि अधिक होगी। इन व्यक्तियों ने अपने विचार पब्लिक स्कूलों के विषय में अधिक रचनात्मक-विधि से प्रकट किए और अधिकतर लोग इनसे सहमत हो गये। इन व्यक्तियों की राय में इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल एक श्रेष्ठ परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक विशेष प्रकार की शिक्षा में आस्था रखती है और इन उत्तम और महान् स्कूलों का प्रतिस्पर्ध संसार के किसी भाग में नहीं मिलता। इन लोगों की राय में पब्लिक स्कूल शिक्षा बेबस उच्च वर्ग के लोगों का ही विशेषाधिकार और एकाधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिभूल है, परन्तु यदि धनवान् व्यक्ति इस बात के इच्छुक हैं कि वह अपने साधन जुटाकर अपने बच्चों को इच्छानुसार शिक्षा दें, तो यह अनुचित बात नहीं। उन्हें ऐसा करने से रोकना उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर असहनीय नियन्त्रण होगा। डोनेल्ड ह्यूज के विचार में 'पब्लिक स्कूल उस श्रेष्ठ ब्रिटिश जीवन और समाज का महत्वपूर्ण अङ्ग है जिसका विकास धर्म, धर्म और धर्म के साथ किया गया है।' मेरी राय में इंग्लैंड की अधिक उत्तम और प्रभावशाली शिक्षा की आवश्यकता है। भविष्य में हमें अवश्य ही उत्तम और आदर्श शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की आवश्यकता होगी। यह उचित होया कि इस देश के दूसरे प्रकार के विद्यालय इन महान् पब्लिक विद्यालयों से प्रोत्साहन प्राप्त कर अपना कार्य अधिक उत्तम और प्रभावशाली बनायें। शिक्षा-क्षेत्र में 'पब्लिक विद्यालय' दूसरे काउन्टी तथा बोलेन्टरी विद्यालयों के लिये आदर्श प्रदान कर उन्हें अच्छा कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते रहेंगे।

"पब्लिक विद्यालयों की शिक्षा से अधिक छात्र लाभ उठावें और उन्हें किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का भाग बनाया जाय।" वर्तमान समस्या यह है कि किस प्रकार पब्लिक विद्यालय तथा राष्ट्रीय प्रणाली के विद्यालयों के सम्पर्क को अधिक घनिष्ठ बनाया जाय। इन दोनों प्रणालियों के सम्पर्क बिन्दुओं को किस प्रकार विस्तृत और घनिष्ठ बनाया जाय जिससे दोनों प्रणालियों में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। इस समस्या पर 'पेल्लिंग-कमेटी' (१९४२) ने विचार करके हल ज्ञात करने का प्रयत्न किया, तथा १९४४ में कुछ लाभदायक अनुमतियाँ दी। इस कमेटी ने पब्लिक विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रशंसा की। कमेटी का राय में इन विद्यालयों की समाप्ति करना बहुत बड़ी भूल होगी परन्तु सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से पब्लिक विद्यालयों का निकट सम्बन्ध स्थापित

किया जाय। ऐसी सम्पर्क विधि स्थापित की जानी चाहिये जिससे बालकों की अधिक संख्या प्राथमरी पाठशालाओं से पब्लिक शिक्षालयों में प्रविष्ट की जा सके। इसी विधि में बालकों के संरक्षकों को राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाय या ऐसे बच्चों से पब्लिक स्कूलों में कम फीस ली जाय। पब्लिक स्कूलों को कम से कम २५ प्रतिशत छात्र राज्य स्कूलों से प्रविष्ट करना चाहिये। इन छात्रों का चुनाव स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जाना चाहिये। स्थानीय शिक्षा अधिकारी इनकी फीस दें और संरक्षकों को इनके छात्रावास व्यय का कुछ भाग देना हो। इस धन की देन संरक्षक की आय पर निर्भर रहेगी।

फ्लेमिंग कमेटी ने यह सिफारिश की कि राज्य द्वारा बहुत से नये छात्रावास खोले जाय जो पब्लिक स्कूलों की विधियों पर ही शिक्षा प्रदान करें। कमेटी ने यह सिफारिश भी की कि योग्य बालकों को पब्लिक स्कूल शिक्षा का अवसर देना चाहिये चाहे उनके माँ-बाप निधन ही क्यों न हो। जो राज्य सहायता में ही सम्भव हो सकता है।

फ्लेमिंग-कमेटी ने उन सभी सम्भव विधियों को खूँडा जिससे 'पब्लिक स्कूल' तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के स्कूल' निश्चय सम्पर्क में आ सकें। उदाहरणार्थ इस कमेटी को एक समस्या का सामना करना पड़ा। प्राइमरी स्कूल से मेकिन्डरी स्कूल में स्थानान्तरित होने की आयु ११ + थी, परन्तु पब्लिक स्कूलों में प्रवेश आयु १३ + थी। कमेटी ने राय दी कि इस समस्या के हल करने की विधि यह भी हो सकती है कि विद्यार्थी को पब्लिक स्कूल छात्रावास में भेजने के निर्णय को दो वर्ष स्वयंसेवक करके उसे शायद स्कूल की निम्न कक्षाओं में पढ़ाया जाय। यदि ११ वर्ष की अवस्था ही में स्थानान्तरित करने का निर्णय कर लिया गया है, तो विद्यार्थी को किसी 'प्रोटेक्टरी-स्कूल' में भेजा जा सकता है।

(ब) स्वीम कमेटी ने यह सिफारिश की कि शिक्षा विभाग में एग्रीगेटेड स्कूलों की सूची तैयार करें जो सीधे राज्य से सहायता पाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सम्मिश्रित होकर अपना कार्य करना चाहते हैं। यदि उनको इस विधि द्वारा एग्रीगेटेड स्कूल बना लिया जाय तो उन्हें शिक्षा शुल्क समाप्त कर देना होगा या सरकारी की आयु के अनुसार उसकी दर निर्धारित कर देनी पड़ेगी। यदि किसी संरक्षक की आय बहुत कम हुई तो शिक्षा-शुल्क में उसे मुक्त करना पड़ेगा। यह शिक्षा-शुल्क तथा छात्रावास व्यय स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जायगा।

(ब) स्वीम उन स्कूलों के लिए है जिन्हें कोई स्वीकार करने और केवल

उन छात्रावास स्कुलों के लिए लागू होगा है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाते हैं। ऐसे छात्रों को जो योग्य हैं और कम से कम दो साल तक राज्य में आर्थिक सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल में अध्ययन कर चुके हैं, राज्य द्वारा पब्लिक बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी। इस (६) स्थीय वाले स्कूल २५ प्रतिशत वार्षिक दाखिले इन प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले छात्रों को होंगे। इस दाखिले की योजना प्रति ५ वं परचासु परिवर्तन की जा सकती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को इन विद्यालयों में स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। संरक्षकों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ठीक प्रकार प्रार्थना पत्र देना होगा।

कारण से यह उचित होगा कि इन्फेंट के पब्लिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अधिक नियंत्रण बनाकर उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाय। उनको समाप्त करना बड़ी भूल होगी क्योंकि यह वास्तव में राष्ट्र के लिए शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं, और शिक्षा द्वारा महान् पुरुषों का निर्माण किया है। प्रत्येक देश में ऐसे आदर्श स्कूल यदि हो तो और विद्यालय भी उनसे प्रोत्साहन प्राप्त कर अपना कार्य सुधार सकते हैं।

इंग्लैंड के स्कूलों का विभाजन और भी कई प्रकार से किया जाता है। उपर्युक्त विभाजन उनके द्वारा विशेष प्रकार की शिक्षा दिए जाने के आधार पर किया गया है। मुख्य रूप से उन सभी स्कूलों (प्राइमरी तथा सेकेंडरी) का विभाजन निम्नान्वित आधार पर किया जाता है।

- (१) ऐसे प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्कूल जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाये जाते हैं (और जो नर्सरी तथा 'विशेष स्कूल' नहीं हैं), ऐसे स्कूल 'बोर्डिंग-स्कूल' कहलाते हैं।
- (२) यदि स्वेच्छा संस्था द्वारा कोई विद्यालय प्रारम्भ में चलाया गया हो, और इस समय 'स्थानीय शिक्षा अधिकारी' द्वारा सहायता प्राप्त हो तो उसे बालिग्टरी स्कूल कहेंगे। इन बालिग्टरी स्कूलों की तीन श्रेणियाँ होंगी। विभिन्न श्रेणियाँ—कन्ट्रोल्ड स्कूल, एडेड स्कूल तथा स्वेचल एपी-मेंट स्कूल हैं।
- (३) ऐसे स्कूल जो सीधे केन्द्र से सहायता पाते हैं, वे 'सीधे सहायता प्राप्त' (Direct Grant Schools) कहलाते हैं। स्थानीय शिक्षा अधिकारी से इन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलती।
- (४) चौथे प्रकार के स्वतन्त्र तथा निजी स्कूल हैं, उदाहरणार्थ प्रीपरेटरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल तथा दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं।

स्थापना, प्रबन्ध तथा आधिक-सहायता देने के आधार पर स्कूलों का विभाजन (प्राइमरी तथा माध्यमिक)

(A) आधिक-सहायता प्राप्त स्कूल

(B) स्वतन्त्र स्कूल

नर्मरी स्कूल (स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित या ऐदिक-संस्थाओं (Voluntary Bodies) द्वारा स्थापित किये हुए)

- (१) नर्मरी तथा किडरगार्टन
- (२) प्रीपेरेटरी-स्कूल
- (३) पब्लिक-स्कूल
- (४) स्वतन्त्र ग्रामर स्कूल
- (५) अन्य

वाउन्टी स्कूल (राज्य, स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किये हुए तथा उनसे पूर्ण रूप से आधिक-सहायता प्राप्त)

वाउन्टी स्कूल तीन प्रकार के

(१) गृहपूजा प्राप्त वाउन्टी स्कूल
(Aided Voluntary School)

(२) नियन्त्रित वाउन्टी स्कूल
(Controlled Voluntary School)

(३) विशेष सहमति स्कूल
(Special Agreement School)

(C) सीधे केन्द्रीय कोष से आधिक-सहायता प्राप्त स्कूल
(Direct Grant Schools)

अध्याय ७

अग्रिम-शिक्षा (Further-Education)

इंग्लैण्ड में 'अग्रिम-शिक्षा' का शब्द बहुत व्यापक, महत्वपूर्ण तथा विभिन्नता-पूर्ण है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने इसे और भी महत्व दिया है। यह बात स्मरणनीय है कि सन् १९४४ से पहले अग्रिम शिक्षा बग्टी निपुनेशन स्कूलों (Continuation School), और टैक्नीकल स्कूलों में प्रदान की जाती थी। दिन में मीकरी करने वाले व्यक्ति सायं-कालीन बग्टीनिपुणेन स्कूलों में अध्ययन करने आया करते थे। इन सायं-कालीन स्कूलों का कार्य कई दृष्टिकोणों से अधिक महत्वपूर्ण था। वास्तव में ये स्कूल अधिक आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते थे जिनको प्रारम्भिक जीवन में स्कूल-शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। सन् १९७० ई० के बाद परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ। क्रॉस-कमीशन^१ ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार के स्कूलों की अब भी आवश्यकता थी, परन्तु धीरे-धीरे यह आवश्यकता कम हो रही थी। इस कमीशन ने सायं-कालीन कक्षाओं को शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा देने का उत्तम साधन समझा। वर्किंग मेन्स कालेज (Working Men's College) की स्थापना सन् १८४४ में हुई थी,

1. Cross Commission.

भी। इंगरी अभिदूत ज्ञान के साधन न हुआ। वही भी : अभिमान न था। विद्वत् इंगरी ने अपना साधन ज्ञान विज्ञान प्रदान दिया।

सन् १८७० में विश्वविद्यालय प्रणाली प्रारम्भ न भी अभिदूत-विज्ञान प्रणाली में वर्गीकृत हो गया। यह प्रणाली है कि मिग कन्क (Miss (Jough) ने उसी इंगरी के बड़े बड़े नगरों में स्त्रियों के लिए भाग्यो का आयोजन किया। जेम्स स्टुअर्ट न भी इंगरी के उत्तरी भाग के नगरों में स्त्रियों तथा नौकरी करने वाले स्त्रियों को भाग्यो दिया। विश्वविद्यालय प्रणाली-प्रणाली ने भी अभिदूत-विज्ञान को वर्गीकृत प्रणाली दिया। इन प्रणाली का सम्बन्ध मुख्य रूप से साहित्यिक ऐतिहासिक तथा आर्थिक विषयों में था, वहीं-वहीं वे दर्शन तथा विज्ञान के विषय में भी होते थे। इन प्रणाली न वास्तव में विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय-विकास में महत्वपूर्ण स्थान का ज्ञान कराया और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के महत्त्व उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया। आन्दोलन दोनवीं न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में अभिदूत दृष्टि प्रकट की, और मन्दन के पूर्वी भागों में छोटे समय में ही मजदूर-वर्ग की प्रथमा के पास बन गई। आन्दोलन का दायित्व-ज्ञान उनके अभूत्य कार्य और (याग) की स्मृति दिवाना है।

पिछले १०० वर्षों में यह 'जारी रहने वाली शिक्षा' का नाम करने के बाद सायकाल में विभिन्न रूपों में दी जाती रही है। वी मैकेनिक् इन्स्टीट्यूट (The Mechanic Institute) ने भी अपना शिक्षा कार्य सायकाल में आरम्भ किया था। सन् १८२६ में ऐसे विभिन्न प्रकार के स्कूल जो अभिदूत-विज्ञान प्रदान करते थे उनको अधिकार पूर्वक 'ईवनिंग इन्स्टीट्यूट' कहा जाने लगा। बीसवीं शताब्दी में इन विद्यालयों में आधुनिक प्रकार की टेक्नीकल और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाने लगी। विश्वविद्यालयों ने प्रसार-आन्दोलन के आरम्भ-काल में अब तक प्रौढ़-विज्ञान क्षेत्र में पर्वतित कार्य किया है। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के केम्ब्रिज स्टुअर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ स्त्रियों को उपलब्ध कराने के प्रयत्नपूर्ण प्रयत्न और आन्दोलन किये। परन्तु इन आन्दोलनों को डा० अलबर्ट मान्सविज द्वारा सन् १८०३ में स्थापित की हुई दो वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन से और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। इस एसोसिएशन का उद्देश्य मजदूर वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को विश्वविद्यालय अध्यापकों के निर्देशन में विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करना था, और विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन संस्थाओं ने अभूत्य कार्य किया।

1. Arnold Toynbee (1852—83).
2. Continuitive Education.
3. The Workers Educational Association (Briefly known as W. E. A.)

सर रिचार्ड लिबिग्टन ने डेनमार्क के (Folk schools) आदर्श पर ही प्रौढ-गिशा के लिए कान्फे्रों की स्थापना की राय दी। यह कालेज स्थानीय गिशा अधिकारी द्वारा चलाये जायेंगे और सांस्कृतिक तथा औद्योगिक गिशा प्रदान करेंगे।

बेल्जियम-नायर में कुछ समय पहले ही ग्राम्य-कालेज आन्दोलन^१ का आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन का अधिक्य बहुत उज्ज्वल है। इन कान्फे्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्राम्य-निवासियों को उत्तम गिशा प्रदान की जाय और कई गाँवों का एक समूह मिलकर ऐसे कान्फे्रों की स्थापना करे। बड़े-बड़े गाँवों में सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना की जाय और वहाँ ग्राम्य कान्फे्र हों। इन गाँवों में एक सांस्कृतिक पुस्तकालय, व्यायाम-माला, खेलने और नहाने का तालाब भी हो। इन कान्फे्रों में मनोरंजन आदि माधनों का भी उचित आयोजन हो।

प्रौढ गिशा मात्रात्मक युग में अति आवश्यक है और इंग्लैंड ने इस गिशा के महत्व को अती भाँति समझा है। ईरविंग इन्स्टीट्यूट ने इस गिशा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। परन्तु प्रौढ गिशा क्षेत्र में कुछ ऐसे कालेज भी हैं जो प्रौढ़ों को पूर्ण समय छात्रावासों में रहने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इस समय आम्बकोर्ड में स्थित रस्किन कालेज (Ruskin College) इसी प्रकार का है। यह बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली है। इस प्रकार के लगभग १० कालेज हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। डेनमार्क तथा स्वीडन की जनता के हाईस्कूलों के आदर्श पर स्थापित किए हुए स्कूलों में यह दिग्दर्शक जा रही है। सर रिचार्ड लिबिग्टन के शब्दों में 'प्रौढ-गिशा का क्षेत्र' राष्ट्र के लिए सर्वत्र महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रौढ-गिशा के क्षेत्र में कार्य करने वाली मुख्य संस्थाएँ निम्नांकित हैं।

- (१) दी वर्कर्स एजुकेशन एसोसियेशन।
- (२) इन्स्टीट्यूट आफ अडल्ट एजुकेशन।
- (३) दी एजुकेशनल सेंट्रलबोर्ड एसोसियेशन।
- (४) दी वीमैन इन्स्टीट्यूट।
- (५) दी रूरल कम्युनिटी काउन्सिल।
- (६) दी नेशनल अडल्ट स्कूल यूनियन।
- (७) यूनीवर्सिटी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट।
- (८) दी ग्राम्य-कालेज।

1. Village College Movement.

(६) दी काउन्टी कालेज ।

(१०) रैजीडेंट्स अटल्ट एजुकेशन कालेज । जेमे, रस्किन कालेज, आवसफोर्ड ।

(११) यग-मैन्स कडिचयन एसोसियेशन ।

(१२) यग-वोमेन्स कडिचयन एसोसियेशन ।

(१३) ब्रिटिश बोर्डकास्टिंग कारपोरेशन की रेडियो वार्ता (B.B.C.)

(१४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित ईवनिंग कक्षाएँ ।

‘अग्रिम-शिक्षा’ राज्य का वास्तव में बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक अर्थ है । सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के शब्दों में प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह ‘अग्रिम-शिक्षा’ के लिए अपने क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं का प्रवर्धन करे अर्थात् (अ) स्कूल की अनिवार्य अवस्था से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिये पूरे समय तथा छोटे समय की शिक्षा का प्रवर्धन अर्थात् १५ वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का आयोजन; (ब) अवकाश प्राप्त या खाली समय में किसी काम में लगाना । ऐसी सांस्कृतिक शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाओं का आयोजन करना जो उनकी भाव-इच्छा के उपयुक्त हों । ऐसी अनिवार्य अवस्था के ऊपर की आयु वाले छात्र ऐसी सुविधाओं में लाभ उठाने के लिए इच्छुक भी होने चाहिए । १५ वर्ष से १८ वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए काउन्टी कालेजों की स्थापना करना जो नवयुवकों के लिए ‘अग्रिम-शिक्षा’ का आयोजन करे । इस प्रकार ‘अग्रिम-शिक्षा’ का अभिप्राय उन सभी मानवीय-क्रियाओं से है जिसमें किसी अवस्था तथा प्रीप्-अवस्था के व्यक्ति भाग लेते हैं । इन शिक्षा सुविधाओं का आयोजन करना ‘स्थानीय शिक्षा अधिकारी’ का कर्त्तव्य है । इन सुविधाओं में मनोरंजन, सामाजिक और शारीरिक शिक्षा की सुविधाएँ इत्यादि सम्मिलित हैं । यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि ‘अग्रिम-शिक्षा’ का क्षेत्र असीमित है, केवल यह कहा जा सकता है कि यह उनके लिए है जिन्होंने १५ वर्ष की अवस्था के बाद स्कूल छोड़ दिया है । शिक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के परस्पर सहयोग से इन शिक्षा सुविधाओं का आयोजन होता है । इन अग्रिम-शिक्षा क्षेत्र में बहुत सी स्वच्छता से प्रेरित होकर कार्य करने वाली समस्याएँ भी सहयोग देती हैं । कम अवस्था वाले नवयुवकों के लिए बहुत सी सुवा-संस्थाएँ शिक्षा सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं । अधिक अवस्था वाले नवयुवकों के लिए ‘उद्योग तथा व्यापार’ प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त होता है । रंगमंच विष-मानिक, उद्योगपति तथा कार्य करने वाले मजदूर मंत्री का सहयोग आवश्यक है । प्रौढ़-शिक्षा सुविधाएँ प्राप्त करने में विश्वविद्यालय और कृषि प्राचीन समय

से स्थापित स्वेच्छा संस्थायें सहयोग से कार्य करती हैं। प्राचीन समय से स्थापित मुख्य स्वेच्छा-संस्था का उदाहरण वर्कर्स एजुकेशनल एसोसियेशन (Worker's Educational Association) है जिसने प्रौढ-शिक्षा-प्रसार में पर्याप्त सहयोग दिया है।

वास्तव में अग्रिम-शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। व्यवस्थापित विद्यान के अनुसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह पक्ष व्यक्त हो जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अग्रिम शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का आयोजन करे अर्थात्

(घ) पूर्ण तथा आंशिक समय की शिक्षा उन व्यक्तियों के लिये जो १५ वर्ष से अधिक है तथा व, अवकाश प्राप्त या खाली समय में सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियायें। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की क्रिया जो वयस्क तथा किशोरावस्था के व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालयों शिक्षा-संस्थानों और दूसरी संस्थाओं द्वारा प्रदान की हुई सुविधाओं का ध्यान रखती हैं और एक दूसरे से सम्पर्क रखती हुई परामर्श करती रहती हैं। वास्तव में इस प्रकार के परामर्श के पश्चात् वह अपनी योजना शिक्षा-मंत्रालय को देती हैं तथा यह प्रदर्शित करती हैं कि किम प्रकार वे इस बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगी। १९४४ शिक्षा-एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाना है कि वे अपने क्षेत्र में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा अग्रिम-शिक्षा का आयोजन करेंगी। इस प्रकार की सुविधाओं में मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक-शिक्षा आदि की सुविधाओं भी सम्मिलित हैं।

यह स्पष्ट है कि 'अग्रिम-शिक्षा कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, केवल यह कहा जा सकता है कि यह उन व्यक्तियों के लिये है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

अग्रिम-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारी तो कार्य करते ही हैं, परन्तु वे दोनों ही विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक तथा स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य करता है। कम अवकाश स्तर पर बहुत से नवयुवक-संघ तथा संस्थायें जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण प्रौढशिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा बहुत सी अन्य ऐच्छिक शिक्षा-संस्थायें सहयोग के आधार पर कार्य करती हैं। जिन्हो क्षेत्रों में औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी समय-समय सहयोग देने रहते हैं।

यह स्पष्ट है कि शिक्षा-मंत्रालय के नियम केवल सामान्य रूप से बनाये जाते हैं और स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारी को अपना विवेक प्रयोग करने का बहुत

अवसर मिलता है। अपनी स्वीय को स्थानीय शिक्षा अधिकारी जब मंत्रालय को देने हैं, तो इस बात का विवरण भी देने हैं कि वे संस्थाएँ जिनमें वे सहयोग करेंगी, दूसरे सुविधाएँ जो विश्वविद्यालयों द्वारा या ईच्छिक-संस्थाओं द्वारा प्रदान की जायेगी और अन्त में वे स्वयं उम क्षेत्र की 'अग्रिम-शिक्षा' के लिये स्वयं किन सुविधाओं का आयोजन करेंगी। इन सभी बातों का ध्यान रखकर यह देखा जायगा कि यह सभी पूरी व्यवस्था किनी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है या नहीं।

इतने विस्तृत और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में, सहयोग केवल स्थानीय-स्तर पर ही आवश्यक नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-मंत्री ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की है जो उनका इस विषय में उचित परामर्श देती है और राष्ट्र के औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन के लिये उचित सुविधाओं के विकास का आयोजन करती है।

वास्तव में यदि देखा जाय तो स्थानीय शिक्षा अधिकारी पर ही यह मुख्य उत्तरदायित्व रहता है कि उचित सुविधाओं का आयोजन किया जाय और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को सम्पर्क में लाया जाय। ऐच्छिक संस्थाएँ तथा दूसरे हितों को निकट सम्पर्क में लाकर उनसे सभी सुविधाओं का आयोजन कराना कठिन कार्य है।

प्रौढ शिक्षा क्षेत्र में तथा अग्रिम शिक्षा के दूसरे क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालयों तथा अन्य ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कार्य करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय प्रौढ-शिक्षा—विद्यालय' की स्थापना की गई है जो उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जो इस प्रकार की सेवा में रुचि रखते हैं। यह विद्यालय समय-समय पर परामर्श दायी समिति का कार्य करता है और शिक्षाभार्यों को उचित सलाह देता रहता है। उद्योग और व्यवसाय दोनों के ही प्रतिनिधि इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवक मंडो की एक कांउंसिल होती है जो नवयुवक सेवा संघों की हर प्रकार की सलाह देती है।

'अग्रिम-शिक्षा' को निम्नलिखित वर्गों में बाँटकर उन पर विचार किया जा सकता है।

- (१) 'औद्योगिक तथा व्यापार' के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा।
- (२) कृषि सम्बन्धी शिक्षा।
- (३) लिबरल अटल्ट-एजुकेशन (प्रौढ-शिक्षा)।

(४) युव-सर्विस (युवक-सेवा) ।

(५) मनोरंजक तथा सामाजिक-सुविधायें ।

(१) 'औद्योगिक तथा व्यापारिक-शिक्षा' का आयोजन उस क्षेत्र के उन व्यक्तियों के सहयोग से किया जाता है जो वहाँ के 'उद्योग तथा व्यापार' में लगे होते हैं । इस प्रकार की प्रदान की हुई औद्योगिक तथा व्यापारिक-शिक्षा पर 'उस क्षेत्र' का प्रभाव सदैव रहता है । सामकालीन कक्षाओं में या टैक्नीकल कालेजों में यह उच्च प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा दी जाती है । सदैव उद्योगों और कालेजों में परस्पर सम्बन्ध रहता है । इन सम्बन्धों और प्रतिक्रियाओं को उद्योगों या किसी व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाली परामर्शदात्री समिति सहायता देती है जिससे वे किसी टैक्नीकल कालेज के विभिन्न विभागों के साथ काम कर सकें । यह सम्बन्ध इस प्रकार भी बना रहता है कि पूरे समय तक काम करने वाले सदस्य किसी कारखाने या कार्यालय में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तथा अंश-कालिक अध्यापकों में बहुत से औद्योगिक या व्यावसायिक जिम्मेदारी की जगहों पर काम कर रहे हैं ।

जैसे ही कार्य अधिक उन्नत और विशेष प्रकार का होता जाता है, कक्षाएँ टैक्नीकल, कामशियल, आर्ट या होमोस्टिक साइंस के कालेजों में होती हैं । कभी-कभी यह विभिन्न प्रकार के कालेज एक ही बड़े विद्यालय में आयोजित होते हैं । अग्र-शिक्षा के लिए विशेष प्रकार से आयोजित कालेजों में कुछ विद्यार्थी पूर्ण समय अध्ययन करते हैं और बाद में वे योग्यता प्रमाण प्राप्त करने के बाद उपर्युक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन में प्रविष्ट होते हैं । कुछ छात्र आंशिक-समय (Part time) तक उपस्थित रहते हैं और उनसे कार्य लेने वाले मिल मासिक थोड़े समय की छुट्टी उनको अध्ययन करने के लिए देते हैं जिससे वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने चुने हुए काम को अच्छी प्रकार कर सकें । इस प्रकार की सामकालीन कक्षाओं में उपस्थित रहने वाले छात्रों की बहुत सख्या होती है, प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा का महत्व होगा । शीफील्ड जैसे सोहे और इस्पात के कारखानों वाले नगर में, अधिकतर सोहे और स्टील सम्बन्धी उद्योगों का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जायगा । 'स्टोक' जैसे 'चीनी के वर्तन' सम्बन्धी औद्योगिक नगर में 'वर्तन-सम्बन्धी' ज्ञान प्रदान किया जायगा । स्नानों वाले क्षेत्र में छात्रों को विभिन्न 'ज्ञान सम्बन्धी ज्ञान पर अधिक महत्व दिया जायगा । यह स्मरण रखना चाहिए कि औद्योगिक शिक्षा का आयोजन सदैव स्थानीय व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाएँ, स्थानीय शिक्षा अधिकारी, शिक्षा-मन्त्रालय तथा स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है ।

कुछ टेक्नीकल कालेज भीधे शिक्षा-मंत्रालय से आर्थिक सहायता पाते हैं। सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के पास होने के बाद इस दिशा में पर्याप्त उन्नति हुई है और कुछ समय पहले ही 'इम्पीरियल कालेज आफ साइन्स' को टेक्नीकली-कल-यूनीवर्सिटी बना दिया गया है। कुछ कालेज भवन-निर्माण सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये विद्यालय साथ ही साथ सामाजिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों के लिए पर्याप्त अवसर देने हैं। इसलिए 'अग्र-शिक्षा के कालेज' केवल व्यावसायिक उद्देश्य ही ध्यान में नहीं रखते परन्तु छात्रों को भविष्य की नागरिकता की शिक्षा प्रदान करके उनमें अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। इन प्रकार के गुण लोकतान्त्रिक-युग में सकल जीवन के लिए आवश्यक हैं।

सन् १९४४ का शिक्षा एक्ट १५ वर्ष की अवस्था से १८ वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए 'काउन्टी-कालेजों' की स्थापना के लिए आयोजन करता है। एक्ट के अनुसार यह अनिवार्य होगा कि उद्योगपति कार्य करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक दिन के लिए इन कालेजों में सामान्य तथा व्यावसायिक-शिक्षा प्राप्त करने भेजे। आर्थिक-संकट, स्कूल-भवन तथा अध्यापकों की कमी के कारण पर्याप्त काउन्टी कालेजों की स्थापना नहीं हो सकी है। इन योजनाओं को कार्यान्वित होने में समय अवसर लगेगा।

अग्रिम शिक्षा के सभी क्षेत्रों में छात्रों द्वारा पीस ली जाती है। गरम्बु जो पीस ली जाती है वह नाम-मात्र की ही होती है और उनका प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं के तर्जों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। कभी कभी केवल १ क्राउन रजिस्ट्रेशन पीस ही ली जाती है। यदि किसी प्रकार की बठिनाई होती है, तो यह पीस भी माफ कर दी जा रही है। पूरे समय के दोनों के नियम भी पीस नाम मात्र की ही ली जाती है।

इस प्रकार के कुछ कालेज भीधे शिक्षा-मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हैं। वास्तव में यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इंग्लैण्ड में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दूसरे क्षेत्रों की शिक्षा में बहुत पीछे रह गई है। १९८४ के शिक्षा एक्ट के पास होने के बाद पर्याप्त उन्नति होगई है और टेक्नीकली में उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रम देने में मिलने हैं। राष्ट्र की दृष्टि का यह प्रतीक है कि थोड़े दिनों पहले ही शिक्षा-मंत्रालय ने योजना किये आर्थिक सहायता स्थानीय शिक्षा अधिकारी को देने के लिए बनाई है। टेक्नीकली में उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों के लिये ७३ प्रतिशत महारत राश्व में मिलती है। इस प्रकार की सहायता प्राप्ति से आशा की जाती है कि इस प्रकार के सुविधा आयोजनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। सामान्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं बढ़ती ही रही हैं और अधिक प्राप्त होती रही

है क्योंकि इस की आवश्यकता है और आसानी से सुविधाये प्रदान भी की जा सकती है क्योंकि स्थान की सुविधा तो प्राप्त होई जाती है और सभी साधन भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं ।

यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार की कोई भी सुस्था अपने उद्देश्य में तब तक सफल नहीं होती है यदि छात्रों को सामाजिक तथा मनोरंजन आदि कार्यों की सुविधा प्रदान नहीं करती है । 'अग्रिम शिक्षा' विद्यालय केवल पेशे और उद्योग की ही केवल शिक्षा नहीं देता है । लेकिन छात्रों को भविष्य का अच्छा नागरिक-और उस्ताही व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करता है और अपने साधियों के साथ सामाजिक सम्पर्क में साने का प्रयत्न करता है । अच्छा और कुशल कार्य करने वाला बनाकर प्रजातन्त्र में अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं ।

वास्तव में सभी 'अग्रिम-शिक्षा' छात्रों के लिये ऐंज्युक्त (Voluntary) है, लेकिन पर्याप्त सुविधाये प्रदान करना स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी का कर्तव्य है ।

(२) कृषि सम्बन्धी शिक्षा—'कृषि तथा उद्यान-विद्या' भी औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंग हैं । इंग्लैंड में कृषि शिक्षा शिक्षा-मंत्रालय तथा कृषि-मंत्रालय दोनों से ही सम्बन्ध रखती है । ३१ स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ 'कार्म-इंस्टीट्यूट्स' स्थापित किए गये हैं । उच्च स्तर पर कृषि शिक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है । ग्राम्य-क्षेत्रों में रहने वाला छात्र जो कृषि में लगा हुआ है, अग्र-शिक्षा के साथ-साथ पूर्ण व्यावसायिक-शिक्षा (कृषि-शिक्षा) प्राप्त करने का अवसर पाता है । उसकी सामान्य शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाये साथ-साथ उन्नति करती रहती हैं । ग्रामीण-क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम भी कृषि-वातावरण से प्रभावित होता रहता है । ऐसे स्थानों में अग्रिम-शिक्षा की सुविधाये कृषि-शिक्षा से घनिष्ठ रूप से उसी प्रकार सम्बन्धित रहती है जैसे एक विद्यालय इंजीनियरिंग केंद्र का कोर्स उसके निकटवर्ती उद्योग से प्रभावित होता है । उपर्युक्त औद्योगिक-शिक्षा तथा कृषि-शिक्षा मनुष्य को व्यापार-व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन में सहायता देती है ।

यह स्वीकार करना उचित ही होगा कि कृषि शिक्षा का विकास आवश्यकतानुसार नहीं हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधा प्रदान करने का अर्थ यह होगा कि सेती तथा उद्यानों में लगे हुए व्यक्तियों को आर्थिक शिक्षा देना है ।

वास्तव में कृषि-शिक्षा-स्थानीय शिक्षा अधिकारी, कृषि-मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के सम्मिलित सहयोग से ही विकसित हो सकती हैं ।

उच्चस्तर पर विश्व विद्यालयों तथा कालेजों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसके बाद व्यक्तियों को कृषि-स्नातको की डिग्री प्रदान की जाती है ।

(३) प्रौढ़ शिक्षा—इंग्लैंड में प्रौढ़-शिक्षा उनकी प्रानोप्रति के लिए है ।

इस शिक्षा द्वारा जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान होता है। इस क्षेत्र में वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन (W.E.A.) ने प्रशंसनीय कार्य किया है। यूनीवर्सिटी एक्सटेन्शन डिपार्टमेन्ट ने इस दिशा में विभिन्न स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं को सहयोग दिया है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा Y. M. C. A. तथा Y. W. C. A. ने इस क्षेत्र में मदद करने प्रयत्न किए हैं। प्रौढ़-शिक्षा का विस्तृत अर्थ यह है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें भी इसमें सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से ऐसे होते हैं कि उनसे उधार तथा गम्भीर शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रौढ़-शिक्षा में वास्तव में लगभग सभी सामाजिक क्रियायें तथा सामुदायिक-केन्द्रों के कार्य सम्मिलित हैं, जो प्रौढ़ों को ज्ञान-प्राप्ति में सहायता देते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रकार-विभागों से लेकर स्त्रियों के विद्यालयों की सामाजिक तथा ज्ञान-प्राप्ति क्रियायें भी सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालयों तथा वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशनों को सीधे शिक्षा मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी इस कार्य में और भी आगे सहायता देती हैं। प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं का सबसे अधिक महत्त्व है।

६ प्रकार की और ऐच्छिक संस्थायें इस क्षेत्र में कार्य करती हैं।

- 1 Workes Educational Associations
- 2 National Council of Y. M. C. A.
- 3 The Educational Centres Associations
- 4 The University of Wales Council of music
- 5 Sea farer's Education service
- 6 Residential Colleges Committee

कुछ ऐच्छिक संस्थायें अपने धन पर तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी पर निर्भर रहती हैं। स्थानीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ही यह कार्य चलता है। National Institute of Adult Education इस कार्य में सहायता करता रहता है और 'प्रौढ़-शिक्षा' नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करता रहता है जिसमें समय समय पर प्रौढ़-शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर वाद-विवाद, विचार-विमर्श होता रहता है। एक वार्षिक-सम्मेलन भी बुलाया जाता है जिस में इस क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति भी बुलाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार से इन क्रियाओं में ताल-मेल स्थापित किया जाता है, इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं में 'शक्ति का वितरण' समान रूप से हुआ है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कार्यों का विस्तार इस क्षेत्र में अत्यधिक है और कार्य के स्तर में भी बहुत भिन्नता है। जो प्रौढ़ वास्तव में आरम्भ में सामुदायिक-केन्द्र पर जाकर दिन के कार्यों के विषय में वाद-विवाद करते हैं

और विभिन्न घटनाओं में रुचि लेते हैं। वे प्रजातन्त्र समुदाय में अच्छे नागरिक बन जाते हैं। वे ही धीरे धीरे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में रुचि लेने लगते हैं।

इस प्रकार बच्चा स्थापित हो जाती है, स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी सामुदायिक केन्द्र में एक शिक्षक (tutor) भेजने का आয়োजन कर देते हैं।

इन क्षेत्र में ऐच्छिक-संस्थाओं ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। विस्तार-विद्यालयों तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी की अपेक्षा उन्हें इस क्षेत्र में अधिक सकलता मिली है। इसका कारण यह है कि उन्हें जन-सम्पर्क का अच्छा अवसर मिलता है। यह निकट जन-सम्पर्क ही उनकी सकलता की कुंजी है जिससे प्रीतों की रुचि बनी रहती है। वास्तव में ऐच्छिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य ठीक प्रकार मूल्यांकन नहीं किया जाता है और सरकारी-संस्थाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इस गलत धारणा को दूर किया जाना चाहिये। सरकारी और ऐच्छिक संस्थाओं दोनों के सहयोग से ही इस क्षेत्र में सकलता प्राप्त हो सकती है। इन दोनों में विरोध होने से हानि की अधिक संभावना हो सकती है। इंग्लैंड की पूरी शिक्षा-प्रणाली में ऐच्छिक संस्थाएँ सर्वत्र ही महत्वपूर्ण रही हैं।

(४) यूथ-सर्विस—अग्र-शिक्षा क्षेत्र में पिछले १० वर्षों के बहुत से ऐसे विभिन्न प्रकार तथा विस्तार की क्रियाओं का विकास हुआ है जिन्हें 'यूथ-सर्विस' के नाम से पुकारते हैं। बी. बाय स्काउट तथा गर्ल गाइड्स आदि ऐसी स्वेच्छा संस्थाएँ हैं जिन्होंने नवयुवकों की रुचि का विकास सामूहिक कार्यों में किया है। ऐसे सामूहिक कार्य उनके प्रोत्साहना में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यूथ-सर्विस का अधिक सम्बन्ध, मनोरंजन क्रियाओं तथा शिक्षा से हैं।

स्काउट्स तथा गाइड्स संस्थाएँ बच्चों को अच्छे सगने वाले खेलों में लगाती हैं। कैंबेट-आन्दोलन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

युद्ध-काल में युवकों की सामाजिक और शारीरिक प्रशिक्षा की सुविधाएँ प्रदान कर उनका खूब विस्तार किया। युवकों के हितों और आवश्यकताओं की देख-भाल भनी-भाँति स्वेच्छा संगठनों ने की थी। इनको सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

आजकल 'यूथ-सर्विस' राष्ट्रीय शिक्षा सेवा है। इंग्लैंड में 'यूथ-सर्विस' के इतने विकास का कारण युवकों में गुणों और उन सभी-गुणों में गुणों का होना है जो इन युवकों को सहायता देते आये हैं और स्थानीय शिक्षा अधिकारी स्वेच्छा संगठनों के सदस्यों को उत्साहित और उनके पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सकलता के कारण शिक्षा मंत्रालय, स्थानीय शिक्षा

अधिकारी, स्वेच्छा संगठनों तथा युवकों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध हैं। बहुत से युव सविनय कार्यों के लिए पर्याप्त धन दिया गया है और उसे व्यय करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गई है।

ड्रामा, दारोरीक-शिक्षा तथा हस्त-कला क्रियाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्य आधारभूत विद्वान्त यह है कि 'समाज-सेवा' की भावना का विकास किया जाय। युव-सर्विग बान्दोतन का उद्देश्य है कि 'व्यक्ति का उसकी मानसिक शक्तियों के अनुसार विकास किया जाय तथा अपने साथियों की सेवा की जाय।' विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियायें तथा मनोरंजन नव-युवकों को प्रदान की जाती हैं जिससे वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर समाज की सेवा कर सकें।

तीन प्रकार की संस्थाओं के समूहों द्वारा इन प्रकार की क्रिया का ज्ञान हमें मिल सकेगा। सबसे प्रथम वह संस्थाएँ हैं जिन्हें स्काउट्स और गाइड्स के नाम से पुकारते हैं जो ऐसे क्रियात्मक कार्यों में जिनमें नवयुवक तथा नवयुवनियों की प्राकृतिक—रुचि होती है। प्राइमरी स्कुल-स्तर पर Brownie or Cubs बच्चों की इस क्रिया से सम्बन्धित हैं, परन्तु विद्योरावस्था के समय इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरे प्रकार की संस्थाएँ कंडेंट आन्वीनन संस्थाएँ हैं और तृतीय प्रकार की Club Activities संस्थाएँ हैं। लड़कियों तथा लड़कों के clubs और मिथिनजनक भी हैं जो गीथे, ही स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किये जाते हैं। यहाँ पर हमारा तात्पर्य नवयुवकों को लिये सामाजिक नेट्र से है यहाँ पर मनोरंजन तथा सामाजिक उद्देश्यों को लेकर जा सकते हैं। यहाँ वह भिन्नता स्थापित करते हैं। कभी-कभी गाने, नाच, ड्रामा आदि का आयोजन किया जाता है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी बहुत एक youth organizer को रखती है। जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में ताल-मेल रखता है। ईंष्ट्रिफ संस्थाओं के स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपने निजी समझन होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि youth clubs की लगभग ९०% प्रतिशत सक्रिय ईंष्ट्रिफ संस्थाओं में होती और १०% प्रतिशत संस्था स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित संस्थाओं में होती।

सामान्य रूप से इन कार्यों को तीन प्रकार में आविष्ट महापना मिलती है। शिक्षा महापन मोधी आविष्ट महापना देना है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की महापना दी जाती है—और तीसरे प्रकार की महापना वह है जो ईंष्ट्रिफ-आपनों द्वारा प्राप्त होती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी ५० प्रतिशत आर्थिक व्यय सहन करते हैं, और कभी भी, संगठन का नियंत्रण करने की नहीं सोचते हैं। इस कार्य का तात्पर्य समाज की सेवा है और, अवसर पड़ने पर ये नवयुवक बड़े ही काम आते हैं। इस पूरे आन्दोलन का व्यक्ति का विकास करना है और अपने साथियों की सेवा करना है। इस क्षेत्र में भी शक्ति का समान रूप से वितरण हुआ है।

५—मनोरंजक तथा सामाजिक सुविधायें—

सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह विशेष कर्तव्य हो गया कि वह अपने क्षेत्र में मनोरंजक तथा सामाजिक कार्यों की सुविधा का आयोजन करें। स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने बहुत से स्वेच्छा संगठनों की सहायता से यह कार्य पूर्ण किया। स्कूलों के खेलने के मैदान विद्यार्थियों को मनोरंजक तथा सामाजिक क्रियायें प्रदान करने का अच्छा साधन हैं। नवयुवक-संस्थायें भी अपने सदस्यों के लिए ये सभी आयोजन करती हैं और प्रौढ़-शिक्षा का अधिकतर कार्य इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इनके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकतायें पूर्ति के लिये रह जाती हैं।

इसलिए स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में जनता के लिए 'खेल के मैदान प्रदान करे। तैरने की सुविधाओं को स्थानीय शिक्षा अधिकारी जुटाये, और कैंप के लिए बाहर जाने वालों की सहायता करे। छोटे बच्चों के लिए उनके घरों के निकट ही खेल के मैदानों का आयोजन हो।

इस आयोजन में भी स्वेच्छा संगठन जैसे दी नेशनल प्लेइंग फील्ड्स एसोसियेशन (The National Playing Fields Association) का कार्य महत्वपूर्ण है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी पार्क-विभागों द्वारा मनोरंजक सामग्री और खेल के मैदानों का आयोजन करते हैं।

कला-प्रोत्साहन तथा मनोरंजक अध्ययन सुसंगठित तथा स्थापित पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत से स्थानों में स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपना द्रुमा तथा गायन संगठन-कर्त्ता नियुक्त करते हैं। उत्सवों के समय पर सुन्दर नाटक आयोजित किये जाते हैं।

टेनिस, फुटबाल, क्रिकेट, हॉकी तथा बीक्सिंग क्लब प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि इस देश के निवासी किस प्रकार खेल-कूद आदि में कितनी रुचि रखते हैं। पुस्तकालयों द्वारा की हुई सेवा भी इस क्षेत्र में अति उत्तम है। जनता का कोई भी व्यक्ति कोई भी पुस्तक बिना मूल्य अध्ययन के लिए प्राप्त कर सकता है।

यह एक विशेषता है कि मनोरंजन तथा सामाजिक सुविधाओं के आयोजन

में अब शिक्षा का पूरा क्षेत्र सर्वत्र समान योग प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो इन प्रकार की सुविधाओं के आयोजन में रूचि रखती हैं।

शिक्षा-संचालन द्वारा प्रकाशित पैरामेटर नं० ३ (पुस्तकों का उपयोग) के अनुसार अब शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं।

- (१) गहनपठों का शारीरिक विभाग करना तथा उम्दू स्वस्थ तथा सुखी जीवन स्वीकार करने के दृढ़ बनाना।
- (२) शारीरिक व्यायाम द्वारा 'शारीरिक विभाग' करने में उनकी सहायता करना।
- (३) उनके ज्ञान तथा बुद्धि का विभाग।
- (४) गाना, ड्रामा, कला, ग्राहिय तथा वैज्ञानिक अभ्यस्त द्वारा उनकी कलात्मक विभाग करना।
- (५) उनके श्रेष्ठों के ज्ञान को बढ़ाना।
- (६) परिवार तथा समाज में उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान करना।
- (७) देश की सेवा का ज्ञान करना तथा उसे सुधार करने के उपाय बताना।
- (८) दूसरे देश के निवासियों के विषय में ज्ञान करना।
- (९) लोकतान्त्रिक समाज में नेतृत्व तथा सहयोगी सेवा का महत्त्व बताकर अच्छे नागरिक बनाना।
- (१०) उन्हें सच्चाई, महत्त्वशीलता तथा अपने मायियों के प्रति दया-पूर्ण जीवन स्वीकार करने योग्य बनाना।
- (११) जीवन के प्रति स्वतन्त्र तथा संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में उनकी सहायता करना।

मनोरंजन तथा सामाजिक सुविधायें प्रदान करने में अधिम-शिक्षा का पूरा क्षेत्र ही योगदान करता है। टेक्निकल कालेजों और भवनयुक्त संघों के सदस्यों के अतिरिक्त किसी क्षेत्र की सामान्य आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। इसकी पूर्ति का कर्तव्य स्थानीय शिक्षा-प्रधिकारी का है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएँ हैं जो सीधे ही इन सुविधाओं के आयोजन में रुचि रखती हैं और स्तरों के विकास में सहायता करती हैं। सन्दन से चलने वाला यात्री एक खेल के मैदान के बाद दूसरा देखता, गाता है और उन विज्ञापनों को पढ़ता जाता है जिनसे प्रकट होता है कि बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं ने खेल की सुविधा के महत्त्व को भली प्रकार पहचाना है। खेलों की सुविधायें बाहरी खेलों तथा Indoor games दोनों को सम्मिलित करती हैं।

अध्याय ८

विश्वविद्यालय शिक्षा (University Education)

‘विश्वविद्यालय शिक्षा’ शिक्षा-मंत्रालय के अधिकार तथा निर्वहन में नहीं है। सन् १९४४ का शिक्षा एक्ट विश्वविद्यालय शिक्षा मुविषाओं के विषय में कुछ आदेश नहीं देता है परन्तु स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य यह अवश्य निर्धारित करता है कि वे योग्य तथा उपयुक्त छात्रों को छात्रवृत्तियों द्वारा विश्वविद्यालय-स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता पहुँचावे। कहने का सारांश यह है कि शिक्षा-मंत्रालय का इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालयों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय स्व-शासित संस्था है जो शासन-पत्र (Charter) द्वारा स्थापित किया गया है। वे स्वतन्त्र हैं, यद्यपि वे सरकार से ‘यूनीवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटी’^१ के आदेशानुसार आधुनिक काल में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। यह यूनीवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटी शिक्षा-मंत्रालय के आधीन न होकर स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। इसके सदस्य शिक्षा विशेषज्ञ होने हैं और उनमें से कुछ शिक्षा-मंत्रालय, विश्वविद्यालयों तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि भी होते हैं। यह मन्त्रालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति समय-समय पर सरकार को विश्वविद्यालयों की घन-

1. University Grants Committee (U. G. C. established in 1919.)

सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में परामर्श देते रहते हैं और राज्य-कोष द्वारा विश्वविद्यालयों की आवश्यकतानुसार धन-प्रदान करने के उत्तरदायित्व को पूरा करते रहते हैं। इन कार्यों के पूरा करने में यूनीवर्सिटी-ग्रांट्स कमेटी विश्वविद्यालयों पर सीधा नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करती है। विश्वविद्यालय अपनी भविष्य योजनाओं के लिए धन सम्बन्धी सहायता इस कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तावों और भविष्य-योजनाओं के व्यय की स्वीकृति इस कमेटी को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु यह स्मरणीय बात है कि 'विश्वविद्यालय' पूर्ण रूप से स्वायत्त-संस्था है जो अपने न्यायालय तथा सीनेट से शासित होती है। चार्टर के अनुसार इसे डिग्री प्रदान करने और पाठ्य पुस्तक आदि निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होता है।

इस प्रकार प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रविष्ट करने की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। पढाई की फीस का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ही होना है।

इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त यूनीवर्सिटी कालेजों की भी एक बड़ी संख्या है। ये कालेज विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, परन्तु उन्हें अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। सामान्य रूप में वे लन्दन विश्वविद्यालय की वाह्य-परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करते हैं।

विश्वविद्यालय' दाखिले की शर्तें तथा फीस का निर्णय करते हैं, ये परिस्थितियाँ बहुधा प्रत्येक विश्वविद्यालय में भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होता है। 'आक्सफोर्ड' तथा 'केम्ब्रिज' विश्वविद्यालय में सम्बन्धित कालेजों की फीस तथा दाखिले का निर्णय इन कालेजों के द्वारा ही होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के प्राचीन विश्वविद्यालय आधुनिक-युग में स्थापित विश्वविद्यालयों से बहुत भिन्न हैं। आक्सफोर्ड से सम्बन्धित ३३ कालेज हैं, और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय का २३ कालेजों से सम्बन्ध है। इसी प्रकार लन्दन विश्वविद्यालय भी ३ इन्स्टीट्यूट्स और ७० कालेजों से सम्बन्धित है और ये कालेज लन्दन क्षेत्र में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं।

इंग्लैण्ड में १० प्रांतीय विश्वविद्यालय हैं। वेस्म यूनीवर्सिटी ५ कालेजों से सम्बन्धित है जो एक दूसरे में पर्याप्त दूरी पर हैं और इंग्लैण्ड में ५ यूनीवर्सिटी कालेज हैं। यह सभी शिक्षा संस्थाएँ 'विश्वविद्यालय शिक्षा' प्रदान करती हैं।

इस समय यह भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि 'इन्वीर्सिटी कालेज'

आफ साइन्स' को 'यूनीवर्सिटी आफ टेक्नोलोजी' बनाया जाय, जिससे टेक्नोलोजीकल अध्ययन क्षेत्र में यह स्वतन्त्र रूप से अपनी डिग्री प्रदान कर सके।

इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी-जीवन में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकतर सख्या अधिक समय तक छात्रावासों में रहती है। नवीन प्रान्तीय विश्वविद्यालयों में अधिकतर छात्रों की संख्या 'डे-स्टूडेन्ट्स' की होती है जो छात्रावास में नहीं रहते हैं और कुछ संख्या 'होम आफ रेजीडेन्स' में स्थान पाती है।

विश्वविद्यालयों की आय के ४ मुख्य साधन हैं।

(१) दान द्वारा।

(२) सरकार से यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के द्वारा।

(३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी की ग्रांट्स द्वारा।

(४) छात्रों की फीस द्वारा।

समय-समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति मिलकर विश्व-विद्यालय-शिक्षा समस्याओं पर विचार कर उनका हल ज्ञात करते हैं। विश्व-विद्यालय अध्यापकों की, 'एसोसिएशन' भी होती है तथा नेशनल यूनियन आफ स्टूडेन्ट्स' विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा करती है। 'यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी' विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्पर्क स्थापित करने में सहायता देती है। परन्तु यह सत्य है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने कार्यों का स्वतन्त्र रूप से प्रवर्ण करता है। 'व्यक्तिगत स्वराज्य' ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषता है।

यू.के. से पहले लगभग £,००० हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष इंग्लैंड के विश्व-विद्यालयों में प्रवेश पाते थे। इनमें से कुछ छात्र योग्यता के कारण विश्व-विद्यालयों या कालेजों द्वारा दी हुई छात्रवृत्तियाँ पाने में सफल होते थे। कुछ छात्र राज्य द्वारा (बोर्ड आफ एजुकेशन) द्वारा प्रदान की हुई छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करते थे। कोई भी छात्र अपने क्षेत्र के 'स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी' से छात्र-वृत्ति दी जाने की प्रार्थना कर सकता था। यह आर्थिक-सहायता बृद्धा छात्रों के संरक्षकों की आय के अनुसार ही दी जाती थी। यह आर्थिक सहायता राज्य से छात्रवृत्ति द्वारा प्राप्त आय का पूरक होती थी, और कभी-कभी राज्य से छात्र-वृत्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय तब पहुँचाने में सहायता देती थी।

1. Individual Autonomy.

युद्ध के बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन नवयुवकों तथा स्त्रियों को जो युद्ध के बाद मेना में वापस आये थे, उन्हें भी विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करनी थी। बहुत से युद्ध में वापस आने वाले व्यक्ति विश्वविद्यालय-शिक्षा पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सरकार के अधीन एक 'नेशनल-सर्वीस' ने इन सभी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया। 'व्यवसायों के लिए दी जाने वाली शिक्षा' का पूरा व्यय राज्य द्वारा ही दिया गया था। यूनीवर्सिटी-शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुभव सब प्रत्येक क्षेत्र में होने लगा था। इन सब बातों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या अब पहले से दुगुनी हो गई थी। इन समय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की वार्षिक संख्या लगभग १८,००० है जो युद्ध के पहले की संख्या से लगभग दूनी है।

यह स्पष्ट है कि युद्ध से पहले की प्राप्त शिक्षा सुविधायें इन परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं हो सकती थी। शिक्षा-मन्त्री ने एक कमेटी स्थापित की जिसमें शिक्षा-मन्त्रालय के प्रतिनिधि, स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी के प्रतिनिधि, विश्व-विद्यालयों के प्रतिनिधि तथा अभ्यासकों की एगोसियेशन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। इन प्रतिनिधियों का कर्तव्य विश्वविद्यालय-छात्रों की बड़ी हुई संख्या के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधायें प्राप्त कराने की विधियों पर विचार कर शिक्षा-मन्त्री को परामर्श देना था। इस कमेटी द्वारा दी हुई रिपोर्ट के आधार पर ही विश्वविद्यालय-शिक्षा में होने वाले सुधार आधारित हैं। व्यवसायों तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए आवश्यक व्यक्ति विश्वविद्यालयों में प्रति वर्ष शिक्षा पाते हैं। सरकार ने इन शिक्षा में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है। विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा प्रदान की हुई छात्र-वृत्तियाँ और स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा दी हुई आर्थिक सहायता ने विश्वविद्यालय छात्रों की पर्याप्त सहायता की है। आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज आदि प्राचीन विश्वविद्यालयों में आधुनिक युग में स्थापित प्रान्तीय विश्वविद्यालयों (तिवरपूल, डरहम, बर्निथम, मानचेस्टर सोइथ, सैफील्ड, त्रिस्टल रीडिंग) की अपेक्षा विद्यार्थी-जीवन अधिक व्यय-पूर्ण है।

यह कहना उपयुक्त होगा कि इंग्लैंड और वेल्स में योग्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के पूरे अवसर प्रदान किये जाते हैं। बहुत कम आय वाले संरक्षकों को कुछ अधिक आय वाले संरक्षकों की अपेक्षा छोट अवसर मिलता है। कुछ लोगों के मत में इस देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रति सप्ताह ७ या ८ पाँइ कमाने वाले व्यक्ति के पुत्र को पूर्ण आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण यूनीवर्सिटी शिक्षा अधिक सुगमता

से प्राप्त हो सकेगी और २००० पीण्ड प्रति घण्टे कमाने वाले व्यक्ति के पुत्र को विश्वविद्यालय की शिक्षा देने में इतनी सुगमता नहीं होगी जितनी कम आय वाले व्यक्ति को । इङ्ग्लैंड और वेल्स में 'शिक्षा अवसरों की समानता' में विश्वविद्यालय शिक्षा सुविधायें भी सम्मिलित हैं और इन शिक्षा सुविधाओं के आयोजन में छात्रों के जन्म-जात कारण, आर्थिक तथा सामाजिक-स्थिति का कोई मूल्य नहीं है और किसी छात्र का निर्धन-गृह में जन्म तथा उसकी निम्न सामाजिक-स्थिति, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधक सिद्ध नहीं होती हैं । शिक्षा अवसरों की प्राप्ति केवल, छात्रों की 'योग्यता' तथा 'चरित्र' पर निर्भर है ।

विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं, परन्तु 'विद्यार्थियों के पूर्ण-विकास के लिए सभी क्षेत्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है । 'शक्ति' तथा उत्तरदायित्व का उत्तम रीति से वितरण हुआ है । कुछ लोग भ्रम के कारण यह समझ सकते हैं कि यह अशुभ होना कि विश्वविद्यालय राज्य से नियंत्रित होने और छात्रों को पूर्ण रूप से राज्य से ही आर्थिक सहायता मिलती । इस प्रकार की बातें इंग्लैंड के शिक्षा दार्शनिकों को रुचिकर नहीं लगती हैं । उनके मन में विश्वविद्यालय जीवन में इस प्रकार का केन्द्रीय नियन्त्रण और निर्देशन पूर्ण रूप से विचारों तथा उनके प्रकट करने की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगा । उनके मत में विश्वविद्यालय यह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है जिससे वे सरय की खोज कर सकें । इसलिए विश्व-विद्यालय 'राज्य तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के हस्तक्षेप से मुक्त रहने चाहिए । सरकार भी जनता के साथ इस मत से सहमत रहती है, और इसे उचित समझती है । विश्वविद्यालय भी इसीलिए स्वतन्त्र रहते हैं ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का इस क्षेत्र में स्पष्ट उत्तरदायित्व है कि अपने सन्दर्भ स्थित 'केन्द्रीय-आकर्म' द्वारा योग्य छात्रों का निर्धारण करने के बाद विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्ति में उनकी सहायता करे । इसी प्रकार स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के योग्य छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कराये ।

ब्रिटेन में शिक्षा क्षेत्र में बहुत समीक्षण है और आवश्यकता के समय अतिमत्त विद्यार्थियों तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है । यह बात महत्वपूर्ण है कि युद्ध-काल की भयान-स्थिति के दबाव के कारण उत्पन्न हुई आवश्यकताएँ भी पूरी होनी रही थीं । यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में युद्धोत्तर-काल में छात्रों की दुगुनी संख्या के लिए शिक्षा आयोजन किया जा

सका था। एक-दूसरे के सहयोग से कार्य चलाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वतन्त्र है तथा १४६ स्थानीय शिक्षा अधिकारी जो अपने उत्तरदायित्व में सहायित हैं, और १८,००० विद्यार्थी प्रति वर्ष विभिन्न विभागों में अपनी आवश्यकतानुसार अध्ययन करते हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में उत्तम प्रकार का सहयोग हो।

ब्रिटिश विश्वविद्यालय मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। (१) प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज। (२) नवीन प्रान्तीय विश्वविद्यालय प्रिनसी स्थापना हुए १०० साल से अधिक नहीं हुए। जैसे लन्दन, डरहम, लीड्स, बर्मिंघम, लिबरपूल, मानचेस्टर, सैफील्ड ब्रिस्टल इत्यादि।

यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी शिक्षा-मंत्रालय के अधीन नहीं है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है यह अवश्य है कि यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी में शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि, अवश्य होता है। यूनीवर्सिटी के प्रतिनिधि शिक्षा-मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर ही यह बनती है। परन्तु यह प्रतिनिधित्व मनोनयन (nomination) द्वारा नहीं होता है। यह कदम अनुपयुक्त नहीं होगा कि यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी उन व्यक्तियों की कमेटी है जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, और उनका कर्तव्य होता है कि वे सरकार को समय समय पर विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं के विषय में परामर्श देने रहें और दूसरी ओर यह कार्य देनी है कि वे दिये हुये धन को विश्वविद्यालयों को वितरित करते रहें।

विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़नी जा रही है।

जे० एन० फुल्टन ने कहा है कि इन दशक में विश्वविद्यालयों की छात्र संख्या १,७५,००० हो आयी। उनका कथन है कि निरन्तर बढ़नी हुई संख्या में छात्र अब स्कूलों में अनिवार्य-शिक्षा आयु के पढ़ाई करने लगे हैं। विश्वविद्यालयों में अब स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ेगी। पाठकों को कदाचित् पता होगा कि ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज में १९२० तक स्त्रियों का प्रवेश बहिषक्त था। यद्यपि नये विश्वविद्यालयों में ऐसा प्रतिबन्ध कभी नहीं था। एक ओर भी बात अविध्य। विषय में कही जा सकती है अब विश्वविद्यालयों के कोर्स का आधार विस्तृत होगा। केवल एक विषय में संकीर्ण दिन्तु विषय योग्यता की सहायता करना अब सम्भव नहीं होगा। अविध्य में व्यवस्था करना विषय आगच्छ के दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र या केम्ब्रिज के मार्शल्व, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कानून तथा अर्थशास्त्र (यह केवल उदाहरण के तौर पर है) आदि जैसे हो सकता है। वि० फुल्टन सहोदर का कथन है कि विश्वविद्यालयी

शिक्षा सबके लिये नहीं है और संस्थाओं में बहुत से छात्र-छात्राएँ इनके अतिरिक्त भी दूसरे क्षेत्रों में अपनी शक्तियों की पूर्ण सफलता को प्राप्त होंगे। जहाँ छाँट का अवसर इतना विस्तृत है वहाँ ठीक छाँट का कराना भी आवश्यक है। (Education in universities is not for every body; many young men and women will reach their fullest powers in other institutions. Where the choice is so rich, it is of the greatest importance that individuals should be helped to choose right.)

आज विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा प्रोफेसरों के वेतन के संबंध में संघर्ष चल रहा है। प्रोफेसरों का वेतन २६०० से ३६०० पाउण्ड, सीनियर लेक्चरर तथा रीडर को २३२५ पाउण्ड तथा लेक्चरर का १०५० से १८५० पाउण्ड तथा असिस्टेंट लेक्चरर का वेतन ८०० से ९५० पाउण्ड प्रतिवर्ष माँगा जा रहा है। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का एसोसियेशन इस माँग को राग्य के सामने रख रहा है। उसका कथन है कि विश्वविद्यालयों के वेतन सिविल सर्विस के व्यक्तियों के जैसे होने चाहिये अन्यथा अच्छे योग्य व्यक्ति विश्वविद्यालयों में नहीं आयेंगे। यह बात ठीक भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों की माँग के जैसी है जिस पर भारत की सरकार में ध्यान देने की चेष्टा की है। यहाँ एक बात और कह दी जाय कि विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट लेक्चरर से अधिक वेतन इंग्लैण्ड में तकनीकी कालेजों के लेक्चरर पाते हैं। यह बात विश्वविद्यालय वालों को और भी खुशती है। आशा है शीघ्र ही उपर्युक्त ग्रेड उन्हें मिल जायगा क्योंकि वहाँ उनका एसोसियेशन शक्तिमान है।

अध्याय ६ औद्योगिक-शिक्षा

(Technical Education)

ब्रिटेन ने औद्योगिक-शिक्षा के महत्त्व को धीरे-धीरे समझा है। इसका मुख्य कारण है कि पहले प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता अधिक समझी गई, इसके पश्चात् माध्यमिक-स्कूलों की ओर ध्यान दिया गया; तत्पश्चात् औद्योगिक शिक्षा का महत्त्व समझा गया और उमकी ओर उचित ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना हुई। सन् १८२५ ई० में पहली बार औद्योगिक-शिक्षा प्रदान करने के लिए London Mechanics Institute की स्थापना हुई। प्रथम युद्ध के पहले ही औद्योगिक-शिक्षा का आशोधन किया जाने लगा था। इस प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा जूनिवर टेक्नीकल स्कूलों में दी जाती थी। कुछ विशेष टेक्नीकल कॉलेजों में साधारणीय कक्षाएँ लगनी थीं और कुछ टेक्नीकल कॉलेजों तथा आर्ट्स-स्कूलों में पूर्ण समय शिक्षा दी जाती थी।

ग्रेन्ग बमेटी (१९३६) के अनुसार स्थापित जूनिवर टेक्नीकल स्कूलों में केवल २३० के लगभग हैं, और उनमें ३०,००० छात्र अध्ययन करते हैं। औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में इन कॉलेजों का कार्य सामान्य से सराहनीय है। इन स्कूलों में वरुन लगभग ११ वर्ष की अवस्था में प्रवेश पाते हैं और लगभग २ या ३ साल अध्ययन करने हैं। १९४४ के गिला लुड के अनुसार इन स्कूलों

की संख्या और उनका महत्त्व और भी बढ़ जायगा। यह बात स्मरणीय है कि १९४४ का शिक्षा-एक्ट सभी बच्चों के लिए माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन करता है। यह शिक्षा-आयोजन इस समय १५ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के लिए है, उचित समय और सुविधा प्राप्त के अनुसार बाद में १६ साल की अवस्था तक बढ़ा दी जायगी। इस प्रकार जूनियर टेक्नीकल स्कूल माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित हो जायेंगे जो छात्रों को ११ मान की अवस्था में प्रविष्ट करेंगे जो बच्चों को ४ या ५ साल के समय तक रखेंगे। ये स्कूल बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ 'औद्योगिक-शिक्षा' भी प्रदान करेंगे। वास्तव में औद्योगिक शिक्षा भी इनका मुख्य उद्देश्य है। पहले इन स्कूलों में कम छात्र पड़ते थे परन्तु अब पर्याप्त सैक्रिन्डरी टेक्नीकल स्कूल स्थापित होने चाहिए जिससे 'टेक्नीकल शिक्षा' पाने के उपयुक्त छात्रों को अधिक संख्या में प्रविष्ट कर सके। 'सैक्रिन्डरी टेक्नीकल स्कूल' अब 'माध्यमिक-शिक्षा' की 'विभागीय-प्रणाली' का एक भाग है।

सायनासीन कक्षाओं में छात्रों को प्रत्येक विषय पढ़ाया जाता है और ये कक्षाएँ विभिन्न इमारतों में होती हैं। जूनियर कक्षाओं में वे लड़के और लड़कियाँ शिक्षा पाते हैं जिन्होंने 'प्रारम्भिक-स्कूल' को लगभग १४ साल की अवस्था में छोड़ दिया है। इन कक्षाओं को कभी-कभी 'इवनिंग-कन्टीन्यूएशन क्लास' भी कहते हैं। इन कक्षाओं में उपरिपि 'ऐम्बिड' होती है लेकिन कुछ लोग अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह बातें रखते हैं कि वे इन कक्षाओं में अनिवार्य रूप से अध्ययन करने जाय। इन कक्षाओं में अंग्रेजी, गणित तथा विभिन्न प्रकार के 'औद्योगिक और व्यापारिक विषय' पढ़ाये जाते हैं। परन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार जब स्कूल छोड़ने की अवस्था पहले १५ साल तथा बाद में १६ साल कर दी जायगी, तो 'सायनासीन' जूनियर कक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी।

औद्योगिक-शिक्षा मुख्य रूप से प्रदान करने वाली सीनियर और एडवान्स 'इवनिंग कक्षाएँ' हैं। ये कक्षाएँ 'टेक्नीकल-इंस्टीट्यूट' या टेक्नीकल-कॉलेजों में लगती हैं। इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का उद्देश्य कभी-कभी औद्योगिक व्यापारिक-विषयों के अध्ययन के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन जारी रखना तथा विदेशी भाषा का सीखना भी था। कुछ विद्यार्थी परीक्षा पास करने के उद्देश्य से भी जाते थे परन्तु अधिकतर व्यावसायिक जीवन में प्रविष्ट होने के लिये अध्ययन करते थे। इन कक्षाओं में कला तथा औद्योगिक-दृष्टिकोण पढ़ाई जाती थी।

इन 'टेक्नीकल-कॉलेजों' में दिन में पुरा समय शिक्षा-प्राप्त करने वाले

विद्यार्थी भी होते हैं। इस कोर्स की अवधि दो या ३ वर्ष तक की होती है। कुछ विद्यार्थी सप्ताह के कुछ दिनों ही अपने रोजगार देने वाले मालिकों की आज्ञा में अध्ययन करने आते हैं। आधुनिक-युग में मशीन-मानिक इम बान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि उनके अधीन काम करने वाले व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा प्राप्त करें और काम करने वाले व्यक्तियों को औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस समय लगभग ८० टेक्नीकल-कालेज हैं जो ६,००० छात्रों को शिक्षा देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तम प्रकार के टेक्नीकल-कालेजों की स्थापना हुई है। 'मान चेस्टर कालेज आफ टेक्नोलॉजी तथा बॉमिघम में बनाये गये नये कालेज इसके उदाहरण हैं। 'इसेक्स' की स्थानीय-शिक्षा अधिकारी ने दो नये टेक्नीकल-कालेजों की स्थापना की है। कुछ टेक्नीकल-कालेजों से सम्बन्धित माध्यमिक-विद्यालय तथा स्कूल आफ आर्ट्स भी हैं। इन विद्यालयों में अधिक ध्यान टेक्नीकल विषयों की ओर दिया जाता है। टेक्नीकल कानेज और सैकिंडरी-स्कूल इस प्रकार सहयोग से कार्य करते हैं कि सैकिंडरी स्कूल टेक्नीकल कालेजों की प्रयोगशालाओं और शिक्षण-सामग्री का उपयोग करते हैं।

कुछ टेक्नीकल-कालेज अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले कारखानों, उद्योगों और व्यापारों के सहयोग से कार्य करते हैं। लड्काशायर और मानचेस्टर, सूती-व्यवसाय के केन्द्र हैं, इसलिये इस प्रदेश में स्थिति टेक्नीकल का क्षेत्र 'यूनी-उद्योग' शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं। संपील्ड नगर जो लोहे और फौलाद के उद्योग का केन्द्र है, यहाँ अधिक महत्व इस उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा पर है। स्टोक सहर जो चीनी-मिट्टी के व्यवसाय का केन्द्र है, वहाँ अधिक महत्व (Ceramics) से सम्बन्धित औद्योगिक-शिक्षा का है। अधिकतर छात्र पाये जाने वाले क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय-परिस्थितियाँ ही टेक्नीकल कालेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का निर्णय करेंगी। इन टेक्नीकल कालेजों में कार्य करने वाले अध्यापकों को पर्याप्त उद्योगों का क्रियात्मक-अनुभव होता है।

यह स्पष्ट है कि युद्ध से पहले दी जाने वाली 'औद्योगिक-शिक्षा' में सुधार की आवश्यकता थी। यह शिक्षा-योजना अपूर्ण थी अधिकतर 'औद्योगिक-शिक्षा' सांयकालीन-बसाओं में दी जाती थी जहाँ पर दिन भर कार्य करने के बाद विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे त्रिनको विशिष्ट अध्यापक पढ़ाते थे। विद्यार्थियों पर इस प्रकार मानसिक दबाव पड़ता था क्योंकि इनने पछों कारखानों में काम करने के बाद रात्रि के दस बजे तक अध्ययन करना

विद्यालयों के लिए कठिन कार्य था। बहुत से विद्यार्थियों ने इस कठिन कार्य को किया और उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर स्याति प्राप्त की। परन्तु यह स्पष्ट था कि सांयकालीन कलायें केवल उस दशा में बलाई जाय जहाँ शिक्षा के दूसरे साधन उपलब्ध न हों।

१९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार इस परिस्थिति में पर्याप्त सुधार होगा। इस एक्ट के अनुसार काउन्टी कालेजों की स्थापना होगी जिनमें १८ वर्ष की अवस्था तक के विद्यार्थी दिन में आशिक-समय-शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी को दिये हुए अधिकारों के अनुसार पूर्ण समय औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को बिना व्यय औद्योगिक शिक्षा दी जा सकेगी। इस प्रकार मालिकों को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की औद्योगिक-शिक्षा से अधिक लाभ होगा क्योंकि इस शिक्षा की प्राप्ति के बाद उनकी कार्य-क्षमता अधिक हो जायगी।

इस प्रकार संकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल, काउन्टी-कालेज, टैक्नीकल कालेज तथा विश्वविद्यालय सभी सहयोग-पूर्ण-भाषना से कार्य करेंगे। इस प्रकार की प्रदान की हुई शिक्षा का आधार यद्यपि औद्योगिक होगा, परन्तु इन व्यक्तियों का दृष्टिकोण उदार तथा उन्नत होगा जो वास्तव में शिक्षित व्यक्ति के मुख्य गुण हैं।

विश्वविद्यालय और टैक्नीलोजीकल संस्थाओं के कार्य स्पष्ट हैं। विश्व-विद्यालय वैज्ञानिक भाग पर अधिक जोर देते हैं और टैक्नीलोजीकल संस्थायें क्रियात्मक-ट्रेनिङ्ग को अधिक महत्वपूर्ण समझती हैं परन्तु औद्योगिक शिक्षा-क्षेत्र में यह कार्य सहयोग से चलता है। औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि टैक्नीकल कालेजों के विभागों को समय-समय पर परामर्श देते हैं। सलाहकार-समितियाँ भी कालेजों को सलाह देती तथा पथ-प्रदर्शन का काम करती हैं।

अध्याय १०

अध्यापक-प्रशिक्षण

किसी भी शिक्षा-प्रणाली की सफलता मुख्यतः अध्यापकों पर निर्भर रहती है। यद्यपि स्कूल-भवन, अस्त्रा संगठन और दूसरी शिक्षा सामग्री की उपेक्षा नहीं की जा सकी, परन्तु सफलता का अधिकांश भाग अध्यापकों पर ही निर्भर रहता है। अध्यापकों के सहयोग से ही शिक्षा-प्रगति तथा उन्नति सम्भव हो सकती है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार लगभग ३ लाख अध्यापकों की और आवश्यकता होगी, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं और जुनाब में अधिक विस्तार कर दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध के कारण भी अधिक अध्यापक प्राप्त नहीं हो सके और उनकी नियुक्ति में बाधा पड़ी। दूसरे व्यवसायों जैसे व्यापार, उद्योग आदि में अधिक वेतन मिलने के कारण लोग उन्हीं व्यवसायों में नौकरी पाना पसन्द करते हैं।

साधारण रूप से दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ इंग्लैंड और वेल्स में हैं। (१) ट्रेनिंग कालेज जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये गये हैं। वे कालेज १८ साल या उससे ऊपर की आयु वाले छात्रों को दो साल की शिक्षा प्रदान करते हैं। उन छात्रों को जिन्होंने किसी ग्रामर-स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है तथा जिन्होंने उपयुक्त योग्यता की परीक्षा पास की है, ट्रेनिंग कालेजों में प्रायः इन छात्रों के लिए दो साल का

कोर्स होना है। शिक्षा और शिक्षण-व्यवसाय जैसे—क्रियात्मक शिक्षण (प्रोक्टिस इन टीचिंग) सम्मिलित रहते हैं। कुछ छात्र दो साल का कोर्स समाप्त करने के बाद विशेष योग्यता के लिए एक साल का कोर्स और लेते हैं। इन ट्रेनिंग कालेजों के अतिरिक्त गृह विज्ञान (डोमेस्टिक-साइन्स), अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग कालेज, शारीरिक-शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कालेज तथा कला-कौशल आदि के लिए भी ट्रेनिंग कालेज हैं। इस प्रकार के ट्रेनिंग कालेज लगभग १३० हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा स्थापित प्रशिक्षण विभाग हैं तथा इन्हीं विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से सम्बन्धित हैं। इनमें प्रविष्ट होने वाले छात्र पहले ही तीन साल यूनीवर्सिटी-डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत कर चुकते हैं। इन प्रशिक्षण-विभागों में १ साल की व्यावसायिक-प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित लगभग २३ विश्वविद्यालय प्रशिक्षण-विभाग हैं।

द्वितीय युद्ध के बाद कुछ Post-war emergency Training Colleges (युद्धोत्तर आकस्मिक आवश्यकता पूरक प्रशिक्षण विद्यालय) भी स्थापित किये गये हैं। ये कालेज सेना तथा अन्य प्रकार की राष्ट्रीय-सेवा के हेतु स्त्री-पुरुषों के लिए चलाये गये हैं जो शिक्षण-व्यवसाय पसन्द करते हैं। इन कालेजों में १ साल की शिक्षा दी जाती है। विशेष योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए ट्रेनिंग का समय बढ़ा दिया जाता है। इस कोर्स की समाप्ति के बाद २ साल का परीक्षा-काल होता है जिसमें अध्यापकों के काम की देख-भाल की जाती है। इस प्रकार के ट्रेन्ड अध्यापकों तथा पूर्ण योग्यता प्राप्त अध्यापकों के चुनाव में कोई अन्तर नहीं होता है। इन योजना द्वारा अधिक संख्या में अध्यापकों का प्रबन्ध किया जा रहा है, क्योंकि लड़ाई के समय में अध्यापन कार्य के लिए व्यक्तियों का चुनाव सम्भव नहीं हो सका था। इन 'हमरजेन्सी-कालेजों' का प्रबन्ध स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा-मंत्रालय के प्रतिनिधि की स्थिति से किया है जिसका सारा खर्च सरकारी कोष से दिया गया है। इन कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का चुनाव सब प्रकार के स्कुलों में पढ़ाने वाले अनुभवी अध्यापकों में से किया गया है (इनमें सेना के अनुभवी अध्यापक भी सम्मिलित हैं)। इस प्रकार के कालेजों की संख्या लगभग ५ है। मेडिकल कारणों से हटाये गये सेना के व्यक्तियों तथा मेकिन्दरी स्कुलों में अध्यापिका बनने वाली स्त्रियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है।

शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा और भी संस्थाएँ प्रत्येक प्रकार के अध्यापकों के लिए, जिनमें टैक्नीशियन और कामशियन

स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं, विविध प्रकार के छोटे-छोटे कोंगों का प्रबन्ध करती हैं।

विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी में निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो, इसके लिए Area Training Organisation A. T. O. (क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं) की स्थापना की गई है। ये तीनों सहयोगी प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा केन्द्र स्थापित करते हैं जो शिक्षा सम्बन्धी रुचि तथा शिक्षा क्रियाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इस स्थान पर ट्रेनिंग पाने वाले छात्र, ट्रेनिंग कालेज के प्राध्यापक और उस क्षेत्र के अध्यापक मिलकर शिक्षा समस्याओं पर विचार करके उनका हल ज्ञात करते हैं। यह एरिया ट्रेनिंग औरगेनार्जिजन्स बहुधा यूनीवर्सिटी केंद्रों से सम्बन्धित करके ही स्थापित किये जाते हैं। कई ट्रेनिंग कालेज मिलकर भी ऐसे केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।

यह स्मरण रहे कि ट्रेनिंग कालेज बहुधा स्थानीय-शिक्षा अधिकारी और स्पेसिअल-प्रेरित सभ्यता द्वारा स्थापित किये जाते हैं और प्रशिक्षण विभाग यूनीवर्सिटी या यूनीवर्सिटी कालेज से सम्बन्धित होते हैं।

ब्रिटेन शिक्षा-प्रणाली में बहुधा चार प्रकार के अध्यापक हैं :—

पहले अधिकांश योग्यता प्राप्त अध्यापक हैं, इसका निर्णय शिक्षा-मंत्रालय द्वारा बहुधा होता है; और इस विषय पर शिक्षा-मन्त्री को परामर्श 'नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल' देती है। इस काउन्सिल में स्थानीय शिक्षा अधिकारी और ट्रेनिंग संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार के योग्यता प्राप्त अध्यापक दो साल पूर्ण-समय ट्रेनिंग कालेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले अधिकतर अध्यापक योग्यता प्राप्त (Qualified teachers) हैं।

दूसरी श्रेणी में 'ग्रैजुएट-टीचर्स' हैं। ये स्कूल से विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित होते हैं और विश्वविद्यालय कोर्स की समाप्ति पर डिग्री प्राप्त करने के बाद १ साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

तीसरी श्रेणी में विशेष विषयों के अध्यापक हैं। इन लोगों की कम से कम शिक्षा योग्यता 'जनरल सर्टीफिकेट आफ एजुकेशन' है। यह प्रशिक्षण उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है जो उस विषय के पढ़ाने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ—गृह-विज्ञान अध्यापक होने के लिये आवश्यक है कि १ साल तक अध्यापक ने गृह-विज्ञान कालेज में शिक्षा प्राप्त की हो। शारीरिक शिक्षा के लिए भी ठीक इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा कालेज में तीन साल शिक्षा पाना आवश्यक है, जिससे वह उस विषय में विशेषज्ञ हो सके। इला के अध्यापकों

के लिए ४ साल की शिक्षा आवश्यक है। म्यूजिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अलग कालेज हैं।

चौथी थेंग्री के अध्यापकों को प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने की अनुभूति नहीं है। उपर्युक्त तीन थेंग्री के अध्यापक ही केवल 'प्राइमरी' तथा 'माध्यमिक' स्कूलों में कार्य कर सकते हैं। 'अप-शिक्षा' के लिए अध्यापक बहुधा औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं इसलिए किसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता का नियम इनके लिए कड़े रूप से लागू करना कठिन ही रहता है।

सभी अध्यापक पहली वर्ष प्रोवेशन पर नियुक्त किये जाते हैं और एक साल बाद अपनी स्थिति में स्थायी कर दिए जाते हैं। इस एक साल की अवधि में उन्हें अच्छा कार्य दिखाना होता है।

मैकनायर कमेटी ने जिसकी रिपोर्ट १९४४ में प्रकाशित हुई थी, अध्यापकों की प्रशिक्षण प्रणाली सुधारने के लिये महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं। कुछ सिफारिशों को क्रियारमक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अनुसार भविष्य में सार्वजनिक स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षण-व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति और उनकी मीकरी की बातों में काफी सुधार हो गया है। उनके वेतन-क्रम में भी वृद्धि हो गई है। स्थानीय शिक्षा संस्थाओं को आदेश दिया गया है कि वे ग्रामर स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में भर्ती किये गये बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी अवसर देती रहें जिससे वे आगे चलकर अध्यापक बन सकें। सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार विवाहित स्त्रियों को भी अध्यापिका बनने की अनुमति दी गई है। सन् १९४४ के एक्ट से पहले विवाहित स्त्रियाँ अध्यापिका नहीं बन सकती थीं। प्रशिक्षण-कोर्स दो साल के स्थान पर तीन साल का कर दिया गया है परन्तु अभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण इस सुधार को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

आजकल विशेष परिस्थितियों में बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोगों को भी अस्थायी रूप से अध्यापक नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दे दी जाती है। यह स्वीकृति केवल ५ साल के लिए दी जाती है। ऐसे अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे ट्रेनिंग लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे जिससे अस्थायी सेवा काल के बाद योग्यता-प्राप्त शिक्षक बन जायेंगे। 'मान्यता' देने के पहले प्रत्येक अध्यापक को एक साल परीक्षा-काल बिताना पड़ता है।

शिक्षकों को वेतन उस वेतन-क्रम के अनुसार दिया जाना है जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी और अध्यापक संघ की संयुक्त कमेटी ने तय कर दिया है।

स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं, विविध प्रवृत्तियों की होती हैं।

विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा री-सम्बन्ध स्थापित हो, इसके लिए Area Trai (क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं) की स्थापना प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा केन्द्र स्थापित व शिक्षा क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, ट्रेनिंग कालेज के प्राध्यापक और समस्याओं पर विचार करके उनका हल औरगेनाईजेशनस बहुधा यूनीवर्सिटी में किये जाते हैं। कई ट्रेनिंग कालेज में सकते हैं।

यह स्मरण रहे कि ट्रेनिंग कालेज स्वेच्छा-प्रेरित सस्था द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी या यूनीवर्सिटी कालेज से सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली में बहुत पहले अधिकांश योग्यता प्राप्त द्वारा बहुधा होता है; और इस एडवाइसरी काउन्सिल देती है। और ट्रेनिंग संस्थाओं को प्रति प्राप्त अध्यापक दो साल पूर्ण-प्रशिक्षण तथा माध्यमिक स्तर प्राप्त (Qualified teachers)

दूसरी थ्रेणी में 'प्रैक्टिस' होते हैं और विश्वविद्यालय साल की व्यावसायिक शिक्षा तीसरी थ्रेणी में शिक्षा योग्यता 'जब उस विशेष उद्देश्य की' है। उदाहरणार्थ—गृह-तक अध्यापक ने गृह-के लिए भी ठीक इसी आवश्यक है, जिससे

युवक-कलकों और सामाजिक केन्द्रों की सेवा के लिए अपना पूरा समय देने हैं।

बर्नहम-कमेटी की सफलता के लिए शिक्षकों की सद्भावना, सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। समय-समय पर बर्नहम-कमेटी को कठिनायों का सामना करना पड़ता है, परन्तु यह सब समस्याएँ सभी हल हो जाती हैं। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन पाँच मुख्य सिद्धान्तों पर निर्भर रहता है।

(१) वैयक्तिक-क्रम जो पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अलग-अलग है, जो गभीर योग्यता-प्राप्त शिक्षकों के लिए लागू होता है।

(२) अध्यापक की योग्यता।

(३) ट्रेनिंग की अवधि।

(४) उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन-वृद्धि।

(५) सन्दन क्षेत्र में नौकरी करने वाले व्यक्ति।

वेतन निश्चित करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

अध्यापक सामान्य रूप से १८ वर्ष की अवस्था पर स्कूलों से भर्ती किये जाते हैं और कम से कम २ वर्ष की शिक्षा और प्राप्त करते हैं जिसमें सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में पढ़ाने का क्रियात्मक अनुभव भी इसमें सम्मिलित है। अध्यापकों की भर्ती केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं है परन्तु बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ भी भर्ती होती हैं जिन्होंने एक या दो साल उद्योग तथा व्यापार में कार्य किया हो। 'अग्र-शिक्षा' के लिए व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों से सीधी भर्ती होती है।

माघारण योजना तथा नीति बनाना 'नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल' के अधिकार में है। यह विभाग शिक्षा-मन्त्री को दो विषयों पर परामर्श देता है।

(१) भर्ती की समस्या जिसमें कालेज में विद्यार्थियों की वित्तीय संख्या प्रविष्ट हो जिससे नियमित रूप से अध्यापक मिल सकें।

(२) पाठ्यक्रम, प्रविष्ट होने का मापदण्ड और योग्यता प्राप्त अध्यापक के बनने के लिए आवश्यकताएँ। प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या इस समय २,३०,००० के लगभग है। युद्ध के बाद सेना में लौटे हुए व्यक्तियों को युद्धोत्तर आकस्मिक आवश्यकता-पूरक प्रशिक्षित विद्यार्थियों में अध्यापकों की शिक्षा देने के बाद शिक्षा व्यवसाय में ले लिया गया।

इस समय इंग्लैंड में योग्यता प्राप्त अध्यापिकाओं की बहुत कमी है, इसके दो कारण हैं—(१) ५ वर्ष की अवस्था वाले बच्चों की आवादी में वृद्धि, जिनके

पढ़ाने के लिये स्त्री अध्यापिकाओं की आवश्यकता है। (२) अधिकतर एमर-जेन्सी स्कीम में लिए जाने वाले पुरुष थे।

यूनीवर्सिटी-क्षेत्रों में स्थिति क्षेत्रीय प्रशिक्षण संगठनों का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वे शिक्षा-कार्य में प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस संगठन में विश्वविद्यालय, उस क्षेत्र के ट्रेनिंग कालेज तथा स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। यह संस्था उस क्षेत्र के अध्यापक-प्रशिक्षण के सामान्य संगठन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार प्रत्येक ट्रेनिंग कालेज किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहता है जिसे 'इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन' के नाम से पुकारते हैं। इससे शिक्षा-क्षेत्र में गवेषणात्मक मुविधायें प्राप्त होती रहती हैं और अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विगत होने रहते हैं। 'लन्दन इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन' इस प्रकार A. T. O. का अच्छा उदाहरण है।

अध्याय ११

विशिष्ट सेवायें

(Special Services)

ब्रिटेन में लगभग पिछले चालीस वर्षों से यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है और शिक्षा-प्रणाली द्वारा इस उत्तरदायित्व का निर्वाह भली-भाँति किया जा सकता है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट सेवायें शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा-उद्देश्य के सफल होने में सहायता करती हैं। इन विशिष्ट सेवाओं में पाठशाला स्वास्थ्य सेवा, बच्चों को भोजन तथा दूध दिये जाने का आयोजन, निर्वन विद्यालयों को जूने तथा वस्त्र दिये जाने का प्रबंध तथा धारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिये विशिष्ट स्कूलों में विशेष शिक्षा-व्यवस्था इत्यादि का आयोजन सम्मिलित हैं।

भूले, दुर्बल तथा रोग-ग्रस्त बच्चे धारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते, इसलिये यह आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाय। निर्वन बच्चों को सन्तुलित भोजन तथा दूध दिया जाय जिससे वे स्वस्थ रहकर ठीक प्रकार अध्ययन कर सकें। धारीरिक तथा मानसिक रूप से अयोग्य बच्चों को अन्य भाग्यवान बच्चों की सी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसे पिछड़े बच्चों के लिये स्पेशल एड्युकेशन ट्रीटमेन्ट (विशेष-शिक्षा-व्यवस्था) की भी व्यवस्था की गई है।

प्रजातांत्रिक-सिद्धान्तों के अनुसार इन बच्चों को भी उचित शिक्षा अवसर प्रदान किये जाने चाहिये जिससे वे अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यता अनुसार उन्नति कर सकें।

इसके अतिरिक्त शिक्षालय स्वास्थ्य सेवा में विद्यार्थियों के दाँतों की रक्षा तथा सेवा और उनकी उचित भोजन-सेवा भी सम्मिलित है।

(१) स्कूल चिकित्सा तथा दाँत सेवा :—१९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे शिक्षालयों में उपस्थित बच्चों के लिये निःशुल्क चिकित्सा निरीक्षण की व्यवस्था करें। विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क दाँत-सेवा का प्रबन्ध करें। इस कर्त्तव्य का पालन शिक्षालय चिकित्सा सेवा की स्थापना द्वारा किया जा सकता है जिसके अनुसार बच्चों का स्वास्थ्य-निरीक्षण तथा छोटे-छोटे रोगों की चिकित्सा की जा सकेगी। यदि आवश्यकता समझी जाय तो अस्पताल की सेवा तथा विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त की जा सके। यह मुख्य सिद्धान्त स्मरणीय है कि स्कूल में अध्ययन करने वाला बच्चा प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा-सेवा प्राप्त कर सके, और उसके संरक्षकों को कुछ व्यय न करना पड़े। निधमिन रूप से बालकों का स्वास्थ्य निरीक्षण हो और आँख, कान, दाँत गले की बीमारियों की दवा की जाय। राष्ट्र की उन्नति उसके भावी नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर है, इसलिये इन शिक्षालय चिकित्सा तथा दाँत सेवाओं का अधिक महत्त्व है। सन् १९४५ में स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से शिक्षालय के बालकों को और अधिक सुविधायें प्राप्त हो गई हैं और शिक्षालय चिकित्सा गृहों में दंत चिकित्सा की पूरी-पूरी व्यवस्था रखी गई है। साधारणतः प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षालय चिकित्सा-गृह की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्थानीय-शिक्षा अधिकारी का नियमित चिकित्सा निरीक्षण विभाग होता है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि बालकों के स्वास्थ्य के हित में सभी प्रकार की डाक्टरों-परीक्षा तथा चिकित्सा का आयोजन करें। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बालकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जाता है।

(२) शिक्षालय भोजन तथा दुग्ध-सेवा :—निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा भोजन के अभाव के कारण ठीक प्रकार नहीं हो पाती थी। सन् १९०६ से स्थानीय शिक्षा अधिकारी स्कूल में निर्धन बालकों को भोजन, दुग्ध की व्यवस्था करती थीं, जिससे बापक शिक्षा द्वारा पूरा लाभ उठा सकें। युद्ध के आरम्भ होने से पहले भोजन केवल उन बालकों को दिया जाता था जिन्हें स्वास्थ्य-दायक भोजन घर पर नहीं मिलता था और वे दोहर के भोजन के लिये स्कूल में घर पर नहीं जा सकते थे। युद्ध के समय में शिक्षालय भोजन सेवा का बहुत

विचार हो गया है और सभी बच्चों को इस सुविधा प्रदान की जाने लगी है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बढता रह सके । यह राज्य की नीति है कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमानित सभी स्कूलों में बच्चों को भोजन और दूध उनके संरक्षकों के बिना किसी व्यय के दिया जाय ।

प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी को एक शिक्षालय भोजन-सेवा की स्थापना में शिक्षालय भोजन व्यवस्थापक की नियुक्ति आवश्यक है जो इस भोजन-सेवा के निम्न आवश्यक सुविधाओं तथा मामूवियों की व्यवस्था करे । इस समय यह भोजन योजना सफल हो रही है, शिक्षालयों में रसोई घरों की व्यवस्था भी करी है और इंग्लैंड की सरकार शिक्षालय भोजन व्यवस्था पर पर्याप्त धन-राशि व्यय करती है । बच्चों के स्वास्थ्योन्नति के अनिश्चित भी इस शिक्षालय भोजन-व्यवस्था से उनसे दूधरे मायात्रिक गुणों का भी विकास होता है । एक मास भोजन प्राप्त करने से अच्छी आदतों का विकास होगा है । इंग्लैंड में शिक्षालय भोजन व्यवस्था शिक्षा-सेवा का आवश्यक घटक बनी रहेगी ।

(१) शारीरिक या मानसिक रूप से निरुद्ध बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा-सेवा : इस शिक्षा-क्षेत्र द्वारा स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए विशेष शिक्षा चिह्नित का आयोजन करें, क्योंकि ऐसे बच्चे और साधारण बच्चों को ही जाने वाली शिक्षा से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं । सन् १९४४ के शिक्षा ऐक्ट ने शिक्षा-भरती तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को ऐसे असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए अधिकार प्रदान किए और 'विशेष स्कूलों की स्थापना' उनका कर्तव्य बनाया गया । कहते का अर्थ है कि बच्चों को उनकी अवस्था, योग्यता तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए शैक्षणिक विभागों के अनुसार इन दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए उचित शिक्षा अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है । इस प्रकार के विशेष स्कूलों के आयोजन के लिए निरुद्धवर्ती स्थानीय-शिक्षा अधिकारी का परस्पर सहयोग आवश्यक है । कभी एक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी कम मुनने वाले (बहिरे) बच्चों के लिये स्कूल स्थापित कर सकती है और उसकी निरुद्धवर्ती शिक्षा-अधिकारी अन्य बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना कर सकती हैं । दोनों ही एक दूसरे के असमर्थ बच्चों के लिए सहयोग भावना से शिक्षा दे सकते हैं ।

मित्र प्रकार के वास्तव जिनके लिये 'विशिष्ट शिक्षक उपचार' की आवश्यकता है, निम्नांकित हैं—

(अ) 'अन्ध बालक वे हैं जो या तो देख नहीं सकते या उनकी दृष्टि इतनी

खराब है कि वे ऐसी प्रणाली से शिक्षा पाते हैं जिसमें दृष्टि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती उन्हें साधारणतया अन्धों के स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जिनमें लिखना पढ़ना घेस (उमरे हुए अक्षरों) माध्यम द्वारा सिखाया जाता है।

- (ब) अपूर्ण दृष्टि-पात छात्र वे हैं जो अपनी खराब दृष्टि के कारण साधारण पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। यदि वह अधिक प्रयत्न करते हैं तो उनकी दृष्टि को हानि होने की सम्भावना रहती है।
- (ग) बहिरे तथा अपूर्ण बहिरे छात्र—इनकी शिक्षा के लिए विशेष विधियों अथवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है तथा दोनों को अलग-अलग शिक्षालयों में शिक्षा दी जाती है।
- (द) कमजोर बच्चे—सुनी हवा में स्कूलों का आयोजन इनके लिए किया गया है। इन बच्चों के स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षकों का मन है कि प्राथमिक प्रारम्भिक विद्यालय, शिक्षालय स्वास्थ्य, भोजन तथा दूध सेवा द्वारा सभी छात्र कुछ समय बाद स्वस्थ हो सकेंगे और ऐसे स्कूल अनावश्यक हो जायेंगे।
- (घ) मधुमेह से पीड़ित बच्चे—ऐसे छात्रों की छात्रावास में रक्खा जाना है। ऐसे छात्रावास बहुधा स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। यह समस्या शिक्षा में इनकी सम्मिश्रण नहीं है जिनकी स्वास्थ्य तथा युद्ध में सम्मिश्रण है। छात्रावास में रखकर साधारण शिक्षालयों में इनकी शिक्षा दी जाती है।
- (ङ) शिक्षा में जीवन से नीचे के छात्र हैं जो अपनी सीमित योग्यता के कारण उनकी शिक्षा साधारण कुठि वाले बच्चों के साथ नहीं हो सकती है। एक मन्द कुठि छात्र एक अधिक कुठि वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा तथा शिक्षण-विधि से लाभ नहीं उठा सकता है। इनके लिए सरल पाठ्य-क्रम तथा अधिक साक्षानु तथा सजीव शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। व्यवहार की समस्या प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए भी विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है।
- (च) मृगी रोग सम्बन्धी छात्रों की व्यवस्था विशेष विद्यालयों में की जाती है। मृगी रोग के यह छात्र जो व्यवहार-समस्या भी प्रदर्शित करने हैं, विशेष विद्यालय योजना उनके लिए आवश्यक है।
- (ज) असतर्क बच्चे जो संवेदनशील रूप से उत्थित तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि-कोण से सम्मिश्रित होते हैं—इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। यह व्यवस्था समस्या भी दिखाने है तथा बच्चे-बच्चे

मपराध भी करते हैं। गुट के कारण बाल-अपराधों की समस्या ने उप-रूप धारण कर लिया था और यह आवश्यकता समझी गई कि ऐसे बच्चों का पथ-प्रदर्शन किया जाय। बाल अपराधों में मजिस्ट्रेट सामाजिक कार्य-कर्ता, शिक्षालय, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक सभी से परामर्श लेकर कार्य करता है।

- (स) शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों की शिक्षा-समस्या का प्रबन्ध विशिष्ट शिक्षालयों में किया गया है जिनको अस्पताल सहित विशिष्ट शिक्षालय कहते हैं।
- (घ) बाली दोष युक्त बच्चे—ऐसे छात्रों के लिए स्थानीय शिक्षा अधिकारी बाली बिकिरसकों का परामर्श तथा सेवा प्राप्त करते हैं। हकलाने तथा अन्य बाली के विकार वाले बच्चों को उनका दोष दूर करने में सहायता करते हैं।
- (प) अधिक असुविधा प्राप्त बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षा-मन्त्रालय, स्वेच्छित्त संस्थाओं तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के सहयोग से होता है।

(४) मनोवैज्ञानिक सेवा : यह सेवा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा विस्तृत की गई है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करती है जो पीक एजुकेशन अफसर के स्टाफ पर काम करता है जो बच्चों का पथ-प्रदर्शन करता है। व्यवहार-समस्या वाले बच्चों, मन्द-बुद्धि वाले बच्चों तथा बाल अपराधों की समस्याओं को सुलझाने में मनोवैज्ञानिक से सहायता मिलती रहती है। यह वैज्ञानिक व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन में भी सहायता करता है। बच्चों की पथ-प्रदर्शन सेवा का शिक्षा-सेवा में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

वास्तव में शिक्षक को इस क्षेत्र का वास्तविक अनुभव होता है, और जहाँ विशेष कठिनाइयाँ समझ आती हैं, वहाँ पर उसे विशेषज्ञ की सलाह लेनी होती है और इसी उद्देश्य से बालक के विषय में मनोवैज्ञानिकों से सलाह लेनी पड़ती है और बच्चों को 'अच्छा पथ-प्रदर्शक' बिलम्बित में भेजा जाता है। यह पथ-प्रदर्शन शिक्षा का आवश्यक अङ्ग है।

(५) शिक्षा में श्वेपरात्मक कार्य : अनुसन्धान शिक्षा का आवश्यक अंग है, कोई भी शिक्षा-प्रणाली इस श्वेपरात्मक कार्य के बिना उन्नति नहीं कर सकती। प्रत्येक विश्वविद्यालय का शिक्षा-विभाग इस शिक्षा-श्वेपरा में संलग्न रहता है। इंस्टीट्यूट्स आफ एजुकेशन, एरिया ट्रेनिंग और नेनाइज्ड ट्रेनिंग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की निवट सम्पर्क में होते हैं जिससे

शिक्षा गवेषणा कार्य को प्रोत्साहन मिलता रहता है। इंग्लैण्ड और वेल्स विस्तृत रूप से शिक्षा विषयों पर खोज होती रहती है। विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा अधिकारियों तथा अध्यापकों के सहयोग से शिक्षा-गवेषणा लिए राष्ट्रीय-संस्था की स्थापना हुई है। इस संस्था को स्थानीय अधिकारियों से आर्थिक सहायता मिलती है।

(६) युवकों को कार्य दिलाने की सेवा (यूथ एम्प्लायमेंट सर्विस) :- यह सेवा शिक्षा-मन्त्रालय तथा श्रम-मन्त्रालय का सम्मिलित उत्तरदायित्व है। नवयुवक लड़के तथा लड़कियों को स्कूल छोड़ने के बाद औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन में प्रविष्ट होने के लिए पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। इससे यह आवश्यक है कि एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन करे और लड़कों तथा लड़कियों को उपयुक्त कार्य दिलाने में सहायता करे। इस सेवा का नाम 'यूथ एम्प्लायमेंट सर्विस' है और श्रम-मन्त्रालय पर प्रभाव डालती है, स्कूलों तथा शिक्षा-मन्त्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक यूथ एम्प्लायमेंट अफसर होता है जिसकी सहायता के लिए उसके अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं जो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों को परामर्श देते हैं। स्कूल में ही इन छात्रों का इन्टरव्यू कर लिया जाता है।

नवयुवकों को उपयुक्त कार्य 'यूथ एम्प्लायमेंट-सर्विस' द्वारा दिया जाता है और १८ साल की अवस्था तक छात्रों की सहायता ये संस्थाएँ करती रहती हैं। यूथ एम्प्लायमेंट अफसर संक्षेप में अध्यापक तथा नीजरी पर रखने वाले मालिक के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करता है। वह नाम पर नियुक्त करने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में रहता है और पता लगता रहता है कि किस प्रकार के नवयुवकों की उन्हें आवश्यकता है और उनके लिए क्या अवसर हैं। यूथ एम्प्लायमेंट अफसर स्कूलों के सम्पर्क में भी रहता है और स्कूल छोड़ने वाले लड़के जो काम तलाश कर रहे हैं का पता लगाता रहता है। यह उद्योग तथा व्यवसाय में अनुभवी व्यक्तियों को विभिन्न नौकरियों के भविष्य के बारे में बताते रहते हैं। प्रभावशाली 'यूथ एम्प्लायमेंट सर्विस' शिक्षा तथा व्यवसाय तथा व्यापार में सगे हुए व्यक्तियों के मध्य 'सहभावना' तथा 'सहयोग' भावना स्थापित करती है और लोगों को उपयुक्त व्यवसायों पर लगा देती है अर्थात् ये व्यक्ति अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुरूप किसी काम में लग जाते हैं। स्वास्थ्य या चरित्र के लिए हानिकारक या अनुपयुक्त कार्यों में ये लड़के नहीं लगते हैं। जहाँ तक सम्भव होगा है राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। यूथ-एम्प्लायमेंट अफसर लड़के-लड़कियों

के नौकरी करने के आरम्भिक-काल में उनके सम्पर्क में रहने हैं। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि उन्हें सन्तोषजनक काम मिल गया है।

(७) शिक्षा-कल्याण-सेवा (एजुकेशन वेलफेयर सर्विस) . यहाँ उन पदाधिकारियों से सम्बन्ध है जो स्कूलों तथा घरों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। स्कूल अवस्था के बालकों को कारखाने इत्यादि में कार्य करने आदि के प्रतिबन्धों को देखते हैं कि उनका पालन ठीक प्रकार किया जा रहा है या नहीं। प्रभावशाली कल्याण-सेवा वास्तव में अपराधी तथा कुसंगति बच्चों के सुधार में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। बच्चों के घरों से सम्पर्क में उनकी समस्याओं का समर्थन कर सुलझाया जा सकता है। स्कूल से भागने वाले बालक का द्वािघातिघोघ्न पता लगना आवश्यक है। ऐसे बालक के सरशकी तथा स्कूल अधिकारियों को भी इस बात का पता लग जाना चाहिए जिससे वे उसे बुरे साधियों की संगत से बचा सकें।

(८) नर्सरी स्कूल तथा नर्सरी कक्षाएँ : इसमें पृथक् नर्सरी स्कूल २ से ५ साल की अवस्था वाले बालकों के लिए सम्मिलित हैं। नर्सरी कक्षाएँ जो प्राइमरी स्कूलों से सम्बन्धित हैं। बहुधा ३ साल से ५ साल की अवस्था के बालकों के लिए हैं। इनमें उपस्थिति सरशकी की इच्छा पर निर्भर है। (अनिवार्य उपस्थिति नहीं है)। परन्तु स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है कि वे आवश्यकता के क्षेत्रों में इनकी स्थापना करें।

राष्ट्रीय-स्तर पर 'नर्सरी-स्कूल एसोसियेशन' नर्सरी स्कूलों के विकास का प्रोत्साहन देती रही है। इस समय कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण नर्सरी स्कूल तथा कक्षाएँ उन बच्चों के लिए हैं जिनकी माताएँ कार्य करती हैं या दूसरे कारणों से उन बच्चों की दिन में देख-भाल की जानी चाहिए। नर्सरी स्कूल शिक्षा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को रचनात्मक खेल व कार्यों में लगे रहने की प्रवृत्ति का विकास करती है।

वास्तव में 'विशेष-सेवा' का ब्रिटेन शिक्षा-प्रणाली में विशेष अर्थ होता है। पहले स्कूल चिबिरमा-सेवा, दाँत-सेवा तथा शारीरिक या मानसिक रूप में पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा-व्यवस्था का अर्थ था। परन्तु उपर्युक्त 'विशेष-सेवाएँ' भी शिक्षा-प्रणाली का आवश्यक अंग हैं क्योंकि इन सभी का प्रभाव स्कूलों पर पड़ता है।

अध्याय १२

१९४४ का शिक्षा-एक्ट

संसार के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट बहुत कम मिलते हैं, यह एक्ट इङ्ग्लैण्ड की राष्ट्रीय-शिक्षा प्रणाली में उन्नति का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस एक्ट ने शिक्षा-क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं, और इङ्ग्लैण्ड की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक-उन्नति के लिए आवश्यक पृष्ठ भूमि तैयार की है। इस एक्ट को 'बटलर-एक्ट' के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इस एक्ट का उस समय के धोरे आफ एजूकेशन के प्रेसीडेन्ट श्री० बर० ए० बटलर ने पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया था। इङ्ग्लैण्ड के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण की ओर यह पहला कदम है। पिछले पृष्ठों में इस एक्ट की पृष्ठ भूमि के विषय में बताया गया है और इङ्ग्लैण्ड की उस समय की राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के विषय में उल्लेख किया गया है।

इस एक्ट द्वारा साधे गये प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित हैं।

- (१) इस एक्ट के अनुसार सन् १९०० में स्थापित 'बोर्ड आफ एजूकेशन' का स्थान मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन ने ले लिया और इसके 'प्रेसीडेन्ट' को शिक्षा मंत्री का नाम दिया गया।

सन् १९०० में बोर्ड आफ एजूकेशन की स्थापना में इसका प्रेसीडेन्ट "प्रेसीडेन्ट आफ दी बोर्ड आफ एजूकेशन" कहलाया।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार "शिक्षा मन्त्रालय" हुआ इसके अध्यक्ष "शिक्षा-मन्त्री"

- (२) शिक्षा-मन्त्री का कर्तव्य इंग्लैण्ड तथा वेल्स निवासियों के हेतु शिक्षा की उन्नति करना है ।
- (३) शिक्षा-मन्त्री का कर्तव्य इंग्लैण्ड की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना तथा यह देखना कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा में राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं ।
- (४) शिक्षा-मन्त्री, समा-सचिव तथा ऐसे अफसरों की नियुक्ति करे जिनको आवश्यक समझे ।
- (५) शिक्षा-मन्त्री प्रति वर्ष संसद के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और संसद के समक्ष पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे ।
- (६) दो केन्द्रीय परामर्श परिषद (Two Central Advisory Councils) का कार्य शिक्षा-मन्त्री को शिक्षा-विषयों पर परामर्श देना होगा । उनमें से एक सभा इंग्लैण्ड के लिये तथा दूसरी वेल्स के लिये होगी ।
- (७) 'काउन्टी' के लिये स्थानीय शिक्षा अधिकारी का नाम 'काउन्टी काउन्सिल' होगा तथा काउन्टी-बरो के लिये अधिकारी का नाम 'काउन्टी बरो काउन्सिल' होगा ।
- (८) यदि शिक्षा-मन्त्री उचित समझे तो वे 'ओइन्ट-बोर्ड' भी स्थापित कर सकते हैं ।
- (९) सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था तीन भागों में की जायगी—
 - (अ) प्रारम्भिक, (ब) माध्यमिक, (स) उच्च-शिक्षा ।
 स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों की सीमा के अन्दर आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये उत्तम-शिक्षा का प्रवर्धन करें जो उस क्षेत्र की जनसंख्या के लिये पर्याप्त हो ।
- (१०) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च-शिक्षा के लिये अपने क्षेत्र में उचित आयोजन करे । ऐसे शिक्षालय शिक्षा-स्तर तथा शिक्षा सामग्री दृष्टि से पर्याप्त हो ।
- (११) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित शिक्षा विद्यालयों की आयु, योग्यता तथा अभिरूचि के अनुसार होनी चाहिये ।
 - (अ) प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षण अलग-अलग विद्यालयों में दी जाय ।

- (व) २ से ५ वर्ष के बालकों के लिए 'नर्सरी स्कूलों' की स्थापना ।
 (स) शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के लिये विशेष विद्यालयों का आयोजन तथा उनके लिये विशिष्ट-शिक्षा-चिकित्सा का प्रबन्ध अर्थात् ऐसी सरल शिक्षा-विधियों से पढ़ाना जो उनके उपयुक्त हों ।

- (द) जिन बालकों के लिये छात्रावास में रहकर शिक्षा-प्रदान करने की आवश्यकता समझी जाय, उनके लिये छात्रावास की उचित व्यवस्था करना ।
 (य) 'एलीमेन्टरी' शब्द की जगह पर 'प्राइमरी' शब्द का प्रयोग किया गया है ।
 (र) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपालित 'प्रारम्भिक' तथा 'माध्यमिक विद्यालय, जो शिशु-विद्यालय' या 'विशेष विद्यालय' नहीं हैं, काउन्टी-स्कूल बहे जायेंगे ।

यदि इस अधिकारी के अतिरिक्त किसी और संस्था ने उनकी स्थापना की है तो उन्हें स्वेच्छा-प्रेरित स्कूल (Voluntary Schools) कहा जायगा ।

- (११) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपनी-अपनी शिक्षा आवश्यकताओं के अनुसार 'विकास-योजना' बनाकर एक नियत-अवधि में शिक्षा-मन्त्री को प्रस्तुत करेंगे ।

- (१२) स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं के स्कूलों की निर्माणांकित तीन श्रेणियाँ होंगी ।

- (अ) नियन्त्रित स्कूल—वह स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये स्कूल हैं जिन्हें स्थानीय शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से अनुपालित करती है । भवन बनाना, उसकी मरम्मत इत्यादि का पूर्ण व्यय देनी है । केवल इनके प्रबन्धकों को अध्यापक-नियुक्ति तथा धार्मिक-शिक्षा सम्बन्धी कुछ अधिकार दिये जाते हैं ।

- (ब) सहायता प्राप्त स्कूल : जिनमें प्रबन्धक अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, धार्मिक शिक्षा के लिये उत्तरदायी होते हैं तथा आधा सर्वा भवन-निर्माण तथा भ्रमण में करते हैं ।

- (स) विशेष समझौते वाले स्कूल : स्थानीय शिक्षा-अधिकारी से भवन-निर्माण, परिवर्तन और सुधार व्यय प्राप्त करते हैं ।

- (१३) शिक्षा-मन्त्री द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार ही अनुपालित शिक्षा-संस्थों की विद्यालय स्थिति, भवन, सेत के मैदान आदि होंगे ।

यह आवश्यकतायें सभी स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को मान्य होंगी।

(१४) प्राइमरी स्कूल के प्रबन्धक 'मैनेजर' तथा माध्यमिक, स्कूलों के प्रबन्धक 'गवर्नर' कहलायेंगे।

(१५) प्रत्येक संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अनिवार्य स्कूल अवस्था के बच्चे को उसकी अवस्था, योग्यता और अभिरूचि के अनुसार शिक्षा दिये जाने का आयोजन करें।

५ से १५ वर्ष की अवस्था तक के बालकों के लिये शिक्षा तथा निःशुल्क है।

५ से ११ वर्ष तक 'प्रारम्भिक शिक्षा'

११ से १५ 'माध्यमिक शिक्षा'

१५ से १८ वर्ष तक 'अग्रिम शिक्षा'।

(१६) स्थानीय शिक्षा अधिकारी १५ से १८ साल के बालकों के लिये पर्याप्त अग्रिम शिक्षा का आयोजन करें।

(अ) अनिवार्य शिक्षा-आयु से अधिक अवस्था वाले बालकों के लिए पूर्ण या आंशिक समय की शिक्षा आयोजन करें।

(ब) सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाओं का आयोजन जो इनकी आवश्यकता के अनुकूल हों।

(स) 'अग्रिम-शिक्षा' के लिए काउन्टी कालेजों की स्थापना करना तथा १५ से १८ साल के नवयुवकों की पूर्ण या आंशिक समय की शिक्षा इनमें हाजिरी आवश्यक है।

(१७) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे नियमित रूप से बालकों की स्वास्थ्य परीक्षा करावें और निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करें।

(२०) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने द्वारा अनुपालित स्कूलों में शिक्षामन्त्री द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार दूध तथा भोजन का आयोजन करेंगे।

(२१) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपालित विद्यालयों में गरीब बालकों के लिये कपड़ों की व्यवस्था करना, जिससे वे ठीक प्रकार अध्ययन कर सकें।

(२२) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उनके क्षेत्र में दी जाने वाली प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा अग्रिम शिक्षा में पर्याप्त मनोरंजक,

सामाजिक तथा शारीरिक व्यायाम क्रियाओं के लिए सुविधाएं सम्मिलित हैं।

- (२३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मेडिकल अफसर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य कपड़ों की सफाई के हित के लिये निरीक्षण कराये।
- (२४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अधिक दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क यातायात की सुविधाओं का प्रबन्ध करें।
- (२५) शिक्षा-मन्त्री 'स्वतन्त्र-विद्यालयों' के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे और इन विद्यालयों का निरीक्षण उचित समय पर हुआ करेगा।
- (२६) जहाँ तक सम्भव होगा विद्यार्थी अपने संरक्षकों की इच्छानुसार ही पढ़ाये जायेंगे। शिक्षा-मन्त्री तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।
- (२७) स्थानीय शिक्षा अधिकारी छात्र-वृत्तियों तथा अन्य साधनों द्वारा विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
- (२८) स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री की अनुमति से शिक्षा-भवेपणा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- (२९) स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री की अनुमति से किसी भी विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित कालेज को अग्रिम-शिक्षा सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- (३०) स्थानीय शिक्षा अधिकारी को 'चीफ़ ऐजुकेशन अफसर' की नियुक्ति करने का अधिकार होगा।
- (३१) बर्नहम-कमेटी की सिफारिश शिक्षा-मन्त्री द्वारा स्वीकार हो जाने पर प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी उसी के अनुसार अध्यापकों को वेतन देगी।
- (३२) प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री को आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करेगी।
- (३३) उचित साधन प्राप्त होते ही अनिवार्य-आयु नीचा १२ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष कर दी जायगी।
स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपासित किसी भी विद्यालय में शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जायगा।
- (३४) धार्मिक-निरीक्षण तथा सामूहिक-प्रायश्चात प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य कर दी गई। किसी भी विद्यार्थी को सामूहिक प्रायश्चात से मुक्ति पाने की व्यवस्था रखी गई है।
- (३५) सन् १९४५ के शिक्षा-एक्ट ने 'ट्रिनिटी नियंत्रण' सम्बन्धी सम्-

भोता स्थापित किया। स्वीच्छक-शिक्षालयों के तीन वर्ग बना दिये गये। (क) नियन्त्रित, (ख) सहायता प्राप्त (ग) विशिष्ट समझौते वाले। ये शिक्षालय विशेष शर्तों के अनुसार शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट की किन्हीं शिक्षा-क्षेत्रों में आलोचनायें की गई हैं। आलोचकों के मत में यह एक्ट सफल नहीं हो सका है क्योंकि अनिवार्य आयु सीमा १६ साल तक नहीं बढ़ाई गई है।

'काउन्टी काउन्सिलों' की स्थापना की योजना भी अधिक सफल नहीं हो सकी है।

इस एक्ट के समर्थकों के मत में आलोचनायें निराधार हैं। उचित समय, आर्थिक साधन प्राप्त होते ही ये सभी बातें कार्यान्वित की जायेंगी। अध्यापकों की कमी को भी अधिक प्रशिक्षण संस्थाएँ खोलकर पूरा किया जा रहा है। समर्थकों के मत में इस एक्ट ने उस सुधार का पथ तैयार कर दिया है जिससे इंग्लैंड अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा-उन्नति करता रहेगा।

परिक्षिप्त—१

१९४६ का शिक्षा-एक्ट

इस शिक्षा-एक्ट ने १९४४ के शिक्षा-एक्ट की धाराओं को स्पष्ट तथा संशोधित किया और २२ मई सन् १९४६ को इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इसकी मुख्य धारायें यह हैं :—

- (१) स्थानीय शिक्षा अधिकारी को विशेष परिस्थितियों में एक नियन्त्रित शिक्षालय के ऐसे विस्तार के अर्थ देने का अधिकार होगा जो वास्तव में एक नवीन शिक्षालय की स्थापना के बराबर हो।
- (२) स्थानीय शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्वेच्छिक स्कूलों के लिए अस्थायी रूप से स्थान प्रदान कर सकते हैं।
- (३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे नियन्त्रित स्कूल के शिक्षालय-भवन बनवायें, तथा उन्हे मरम्मत का कार्य कराने का भी अधिकार होगा।
- (४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है कि अनुमानित छात्रावास शिक्षालय तथा नर्सरी स्कूल के विद्याधियों को बिना मूल्य लिए हुए भस्त्र प्रदान करें। इसके लिए संरक्षकों की आवधिक दशा की जाँच करना आवश्यक नहीं है।
- (५) अपने क्षेत्र से बाहर यात्रा करने वाले डिवीजनल-एक्जीक्यूटिव अफसरों को यात्रा व्यय प्रदान करें।

- (६) स्वेच्छिक स्कूलों के मैनेजर या गवर्नर स्कूल-भवन के अतिरिक्त किसी भाग को किराये पर उठाये जाने की आमदनी को स्थानीय शिक्षा अधिकारी को देगे ।
- (७) अलग-अलग विभाग रखने वाले स्कूल यदि दो या अधिक भागों में विभाजित किए जायें तो उनके फाउन्टी और बोलेन्टी स्कूल नाम बने रहेंगे ।
- (८) सभी सामूहिक प्रार्थना कार्य स्कूल की सीमा के अन्दर होंगे । यदि १४ दिन की पहली सूचना दे दी गई है तो स्कूल-सीमा के बाहर भी सामूहिक प्रार्थना की जा सकती है ।

कानून में १९४६ का एक्ट पहले १९४४ के शिक्षा-एक्ट की बहुत सी धाराओं को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था । इस एक्ट ने स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अधिक अधिकार दिये जैसे—नियन्त्रित स्कूलों के स्कूल-भवन को बढ़ाये जाने का अधिकार दिया गया ।

- (९) अध्यापक, कमेटी या सब-कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं—जैसे किसी क्षेत्र में मानसिक दोष वाले बच्चों की कमेटी की सदस्यता प्राप्त कर सकता है । अर्थात् स्थानीय राज्य-विधान १९३३ में इसके द्वारा संशोधन हुये कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अध्यापक हो अथवा अन्य प्रकार के पद पर नियुक्त हो वह किसी भी स्थानीय संस्था की सभा का सदस्य होने का अधिकार रखता है । चाहे उसकी नियुक्ति :—

क—राज्य आशानुसार शिक्षा के हेतु ।

ख—मस्तिष्क अभाव की रक्षा हेतु ।

ग—जनता पुस्तकालय विधान के प्रबन्ध हेतु हुई हो ।

- (१०) 'पाठशाला-भवन' का अर्थ होगा कोई भी भवन अथवा भवन का कोई भी भाग जो पाठशाला के काम में लाया जावे जिसमें चौकीदार का निवास-स्थान, खेल का मैदान, बिकिस्ता-निरीक्षण जगह, भोजन वितरण की सुविधा हेतु जगह सम्मिलित नहीं है ।

परिशिष्ट—२

सन् १९४८ का शिक्षा-एक्ट

इस एक्ट की विशेषता यह है कि इसने प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा में संशोधन किया।

प्राइमरी शिक्षा—'यह शिक्षा है जो उन विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप है, जिन्होंने अभी तक १०½ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।' १०½ वर्ष की आयु के बाद उन्हें जूनियर स्कूलों में शिक्षा देना उपयुक्त है।

माध्यमिक शिक्षा—यह शिक्षा है जो १०½ की आयु से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों के उपयुक्त होती है जिसको अधिक आयु वाले छात्रों के साथ पढ़ाना उचित है। इस एक्ट के अनुसार अधिक योग्य विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में १ माह पहले भी भेजे जा सकते हैं।

शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना की है। उनकी आलोचना का आधार है कि इतनी कम आयु में इतनी गीघ्रता की आवश्यकता की विशेष रूचि तथा योग्यता को ज्ञात करना सम्भव नहीं है। स्मरण रहे हैडो-कमीशन रिपोर्ट ने यह अवस्था ११+ बतलाई थी। ११+ की अवस्था के बाद बच्चे भिन्न-भिन्न माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाते थे। स्कॉटलैंड में माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाने की अवस्था १२+ है।

स्पानीय शिक्षा अधिकारी प्रत्येक ऐसे बच्चे को जो उसके द्वारा मंचालित पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता है, उस पाठशाला के छात्रागण के छात्र को

नि.शुल्क वस्त्र प्रदान करेगा । विशिष्ट पाठशाला वाले छात्रों के लिए भी वस्त्रों का प्रबन्ध करना होगा ।

यदि संरक्षकों पर इस कारण अभियोग लगाया जाता है कि उनका बालक नियमित रूप से पाठशाला में उपस्थित नहीं होता तो संरक्षकों की बाध्य किया जायगा कि वे पाठशाला आयु तक अवश्य ही अपने बालकों को शिक्षा दिलायें । यदि मुक्ति चाहें तो संरक्षक पूरा-पूरा प्रमाण दें ।

स्थानीय शिक्षण संस्था को शिक्षा-निमित्त भूमि क्रय अधिकार प्राप्त है ।

परिशिष्ट—३

जनरल सार्टीफिकेट आफ एजुकेशन

[General Certificate of Education]

सन् १९५१ में स्कूल-सार्टीफिकेट तथा हायर सार्टीफिकेट परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक स्कूलों में 'जनरल-सार्टीफिकेट आफ एजुकेशन' की संस्थापना की गई। स्कूल-सार्टीफिकेट तथा हायर-सार्टीफिकेट परीक्षाओं की समाप्ति कर दी गई। यह नई परीक्षा शिक्षा-मंत्री ने माध्यमिक परीक्षा परिषद् (सन् १९४७) की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की थी। यह परिषद् विश्वविद्यालयों, अध्यापकों तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी। इस परीक्षा में वह छात्र भी बैठ सकते हैं जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं। विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित परीक्षण संस्थायें इस परीक्षा के संचालन की उत्तरदायी हैं।

इस परीक्षा की विशेषताये ये हैं—

- (१) सभी विषयों में चर्चे तीनों स्तरों पर बनाये जाते हैं। 'साधारण', 'उच्च' तथा 'छात्र-वृत्ति' स्तरों पर परीक्षा के पक्ष बनाये जाते हैं।
- (२) सभी विषय वैकल्पिक होते हैं और इस परीक्षा के लिए न्यूनतम तथा वर्ग-सम्बन्धी आवश्यकताएँ नहीं बोली जाती हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल वही छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हों जिनकी सफलता के के पर्याप्त अवसर हों।

किसी ऐसे छात्र का परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाता है जिसकी अवस्था उस वर्ष की पहली सितम्बर को १६ वर्ष से कम होती है।

परीक्षार्थियों को लगभग ४० या उससे अधिक विषय चुनने की स्वतन्त्रता 'साधारण-स्तर' पर रहती है। उच्च तथा छात्र वृत्ति स्तर पर छात्र ३० विषयों में से कोई परीक्षा-विषय चुन सकता है। साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त छात्र कला, गायन, हस्तकला, गृह सम्बन्धी तथा व्यापारिक विषय भी ले सकता है। लिखित तथा क्रियात्मक दोनों ही परीक्षार्थ ले जा सकती हैं।

विश्वविद्यालयों तथा व्यवसायों ने 'जनरल सर्टीफिकेट आफ एजुकेशन' के आधार पर अपनी प्रारम्भिक परीक्षाओं की आवश्यकताओं की फिर से निश्चित किया है। इंग्लैंड और वेल्स के ग्रामर विद्यालयों के अधिकांश छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। विदेशों में भी कुछ संस्थाएँ इस परीक्षा को लेती हैं जिसे बाहर रहने वाले इंग्लैंड के नागरिक इसमें बैठ सकें।

परीक्षा लेने वाली संस्थाएँ विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित रहती हैं।

परिशिष्ट- ४

ब्रिटेन-निशा में कुछ उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ

Advisory Council (केन्द्रीय सलाहकार समिति)—यह भी समितियाँ हैं जो एक दृष्टिकोण तथा दूसरी केन्द्र के लिए नियुक्त हुई हैं।

Aided School (सहायता-शास्त्र-संस्थान)—ये स्वेच्छा प्रेरित संस्था द्वारा स्थापित किए हुए स्कूल हैं जिनके प्रबंधक सरकारों की नियुक्ति हैं, या शिक्षा-विज्ञान के लिए उपायग्राही होने हैं, तथा बाहरी सहायता निर्धारित लाभांशों के अन्तर्गत में प्राप्त लाभ करते हैं ।

Board of Education (शिक्षा-समिति) का केन्द्रीय वि
 १९२६ के १२६६ नम्बर का आदेश का १९२६ के १२६६ नम्बर का शिक्षा-स
 मिति का नम्बर दिया गया ।

Bornham Scales - यह वेनच-सम की मापन-प्रतिष्ठान्तरणों में प्रयोग होता है। सर्वप्रथम-संवेदी में स्व-प्रतिष्ठान्तरणों द्वारा मापन-प्रतिष्ठान्तरणों में प्रयोग होता है।

Calcutta School (विद्यया विमुक्तये) - वास्तविकता के वा सत्य विज्ञान पर विचार करने के लिये हमें एक बर्तन के से बर्तन के लिये के लिये करने हैं।

[illegible]

Chief Education Officer—स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी द्वारा वेतन प्राप्त मुख्य अधिकारी—

Community Centre—मुख्य रूप से प्रौढ़ों के लिए सामाजिक, मनोरंजक तथा शिक्षा-सुविधाओं का केन्द्र । यह स्थानीय शिक्षा-अधिकारी या स्वेच्छा-संस्था द्वारा प्रदान किया जा सकता है ।

County College—स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित शिक्षा-लय जिसमें १५ से १८ वर्ष की अवस्था तक के नवयुवक पूर्ण समय या आंशिक-समय अध्ययन करते हैं ।

Director of Education—यह श्रीक ऐंजुकेशन अफयर के दूसरे पद का नाम है ।

Evening Institutes—प्रतिम शिक्षा के वे सापेक्षकालीन शिक्षालय जो नवयुवकों की व्यावसायिक तथा अभ्यावसायिक शिक्षा देते हैं ।

Her Majesty's Inspectors—शिक्षा-मन्त्रालय स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा दूसरी शिक्षा संस्थाओं में सम्पत्क स्थापित करने वाले शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त शिक्षालय-निरीक्षक ।

Independent Schools—स्थानीय-शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा-मन्त्रालय से सहायता न प्राप्त करने वाले स्कूल ।

Infants School—५ से ७ वर्ष के बच्चों के लिये स्थापित प्रारम्भिक विद्यालय ।

Nursery Classes—३ से ५ वर्ष के लिए प्राथमिक स्कूलों से सम्बन्धित कक्षाएं ।

Nursery School—आत्म-निर्भर स्कूल जो २ वर्ष से ५ वर्ष के बच्चों के लिए है ।

Preparatory School—८ से १३ वर्ष के बच्चों के लिए स्वतन्त्र तथा छात्रावासीय स्कूल जो पब्लिक स्कूल में प्रविष्टि पाने वाले बच्चों की तैयार करते हैं ।

Public School—स्वतन्त्र, माध्यमिक छात्रावासीय स्कूल ।

Training College—अध्यापक-प्रशिक्षण कालेज ।

Special Schools—शारीरिक तथा मानसिक रूप से विप्लव बच्चों का स्कूल ।

Technical College—व्यावसायिक तथा अधिक-शिक्षा का मुख्य कालेज ।

Voluntary School—स्वेच्छा प्रेरित संस्थानों जैसे धार्मिक या परोपकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित स्कूल ।

Approved Schools—गृह-कार्यालय द्वारा अपराधी बच्चों के स्वीकृत-स्कूल । ये स्कूल छात्रावास से सम्बन्धित होते हैं ।

Local Education Authority—काउन्टी के लिये काउन्सिल तथा काउन्टी-बरो के लिये काउन्टी-बरो काउन्सिल स्थानीय शिक्षा अधिकारी हैं ।

Juvenile Court—अपराधी बच्चों के मुकद्दमे सुनने का न्यायालय ।

Children's Care Committees—बच्चों के कल्याण तथा भरण-पोषण के लिये यह कमेटी है । स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाई हुई यह कमेटी बच्चों को अच्छे घरों में प्रतिपोषकों के पास भी रखती है और बच्चों की भाल करती है ।

परिशिष्ट—५

एल० टी० परीक्षा प्रश्न-पत्र १९५४

(१) "ब्रिटिश-शिक्षा की विशेषता है कि राष्ट्र ने ऊपर से लादी हुई समानता को पसन्द नहीं किया है। स्व-इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रयत्न को राष्ट्र ने पसन्द किया है। प्रचलित संस्थाओं को धीरे-धीरे पूर्वक और व्यावहारिक-योग्यता के साथ सुधारा दिया है और उन्हें दीर्घतः से बिना सोचे समझे नष्ट नहीं किया है। राष्ट्र का विभिन्न धर्मों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार है।" इस कथन की सत्यता को अंग्रेजी-शिक्षा के इतिहास से उदाहरण देकर सिद्ध करिये।

(२) ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के छात्रों के लिये ब्रिटेन में कौन-कौन सी शिक्षा-संस्थायें हैं ? प्रत्येक के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिये।

ग्रामर स्कूल तथा पब्लिक-स्कूलों में क्या अन्तर है।

(३) निर्धन विद्यार्थियों को इन्डलैन्ड में क्या-क्या शिक्षा-सुविधायें प्राप्त हैं ? भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का वर्णन करिये।

(४) १९४४ के शिक्षा एक्ट द्वारा शिक्षा में लाये गये परिवर्तनों का वर्णन करिये।

(५) निम्नलिखित में से चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—

(1) Approved Schools.

- (2) L. E. A.
- (3) Her Majesty's Inspectors.
- (4) The General Certificate of Education.
- (5) Juvenile Court.
- (6) 1946 Education Act.
- (7) Children's Care Committee.

एल० टी० परीक्षा १९५५

(१) १९४४ के शिक्षा कानून द्वारा सुधार किये गये ब्रिटिश शिक्षा के मुख्य दोष बताइये । इस शिक्षा-एक्ट की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालिये ।

(२) ब्रिटेन की प्रारम्भिक-शिक्षा-प्रणाली के संगठन का पूर्ण विवरण दीजिये और माध्यमिक-शिक्षा के लिये बच्चों को चुनने की प्रणाली का वर्णन कीजिये ।

(३) ब्रिटेन में धार्मिक-शिक्षा की समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया है ?

(४) ब्रिटेन की प्रौढ़-शिक्षा-व्यवस्था का पूर्ण विवरण दीजिये ।

(५) किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिये—

(क) पाठशाला से बाहर की क्रियायें ।

(ख) शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधायें ।

(ग) अग्रिम-शिक्षा ।

(घ) 'पब्लिक-स्कूल्स' ।

(ङ) द्वि-संख्य-प्रणाली ।

(च) युवा-नवतन ।

एल० टी० परीक्षा १९५६

(१) सन् १९४४ ई० के शिक्षा-विधान द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्तनों की व्याख्या कीजिये ।

(२) इंग्लैण्ड की प्रौढ़ शिक्षा के संगठन तथा प्रणालियों की विवेचना कीजिये ।

(३) इंग्लैण्ड की निम्न-शिक्षा तथा बाल-शिक्षा व्यवस्था का वर्णन

(४) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इंग्लैंड ने अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य में प्रविष्ट अध्यापकों की शिक्षा का पुनः संगठन किस प्रकार किया ?

(१) निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) School Medical Service.
- (ii) Methods of Selection of pupils for Secondary Education.
- (iii) Secondary Schools Examinations Council.
- (iv) Child Guidance Clinics.

BIBLIOGRAPHY

- Birchenough : History of Elementary Education in England and Wales from, 1800.*
- Colleges of Further Education, Pamphlet No. 3, H. M. S. O.*
- Community Centres, H. M. S. O., 1944.*
- Education Act 1944 ; H. M. S. O. Publications.*
- " " 1946 ; " " "
- " " 1948 ; " " "
- Education in Britain ; Central Office of Information, London.*
- Further Education ; Pamphlet No. 8, H. M. S. O.*
- H. C. Barnard : History of English Education from 1760 to 1944.*
- H. C. Dent : British Education.*
- " " : *Education Act. 1944.*
- " " : *Secondary Education for All.*
- I. L. Kandel : Studies in Comparative Education.*
- " " : *History of Secondary Education.*
- Ministry of Education, Pamphlet No. 2, A Guide to the Educational system of England and Wales.*
- " " Pamphlet No. 3, 'Youth's Opportunity'.
- Ministry of Education ; Pamphlet 1947, Examinations in Secondary Schools.*

- N. Hans : Comparative Education.
 Norwood Committee Report, 1943.
 Our Changing Schools, H. M. S. O. 1952.
 P. Sandiford : Comparative Education.
 Public Schools and National System Feemng Committee
 Report. (1944).
 Report of the Royal Commission on Secondary Education
 (1896).
 S. J. Curtis : A Short History of English Education in Britain
 since 1900.
 Spens Report 1938.
 Special Education Treatment, H. M. S. O. 1946.
 Training of Teachers and Youth Leaders, H. M. S. O. (Mc.
 Nair Report, 1944).
 The New Secondary Education, H. M. S. O. 1947.
 The Year Book of Education, Evans Brothers.
 U. N. E. S. Co. (Publications).
 1. Compulsory Education in England.
 2. Primary Teachers Training.
 3. Compulsory Education in England & Wales.
 4. The Education of Teachers in England, France and
 U. S. A.
 W. E. D. Stephens : English Education.
 W. P. Alexander : Education in England.

